रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 21, 1985/भाद्र 30, 1907
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 21, 1985/BHADRA 30, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1985

सूचना

का. आ. 4374—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री अरविन्द नरेन्द्र पाटिल, अधिवक्ता, बैलगांव ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए किया जा रहा है कि उसे बैलगांव व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(31)/85-न्या.]
एस. गुप्तु, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 4th September, 1985

NOTICE

S.O. 4374.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Arawind Narendra Patil, Advocate Mahaveernagar (Hindwadi) Belgaum (Karnataka State) for appointment as a Notary to practise in Belgaum.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(31)/85-Judl.]
S. GOOPTU, Competent Authority

गृह मंत्रालय

(गृह विभाग)

(पुनर्वास प्रभाग)

नई दिल्ली, 25 मई, 1985

का. आ. 4375.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा भारत सरकार में भूतपूर्व पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय की दिनांक 3 नवम्बर, 1977 की अधिसूचना संख्या-14(9)/77-दण्ड. में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

"उक्त अधिसूचना की सारणी में कालम (2) में क्रम संख्या-7 के सामने दी गई प्रविष्टि "निदेशक (टी एण्ड एम), अम्बागुडा", के स्थान पर "कर्मशाला प्रबन्धक (टी एण्ड एम), अम्बागुडा" प्रतिस्थापित किया जाएगा।"

[सं. 14(10)/85-दण्डक (डेस्क)]

संजीव गोयल, उप सचिव,

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Home Affairs)

(Rehabilitation Division)

New Delhi, the 25th May, 1985

S.O. 4375.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Supply and Rehabilitation No. 14(9)|77-DNK, dated the 3rd November, 1977, namely :—

"In the Table to the said notification, against serial number 7, in column (2), for the entry "Director (T&M) Ambaguda", the entry "Works Manager (T&M), Ambaguda" shall be substituted."

[No. 14(10)/85-DNK Desk]

SANJIVA GOEL, Dy. Secy.

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1985

का. आ. 4376.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अपराधों को भी ऐसे अपराधों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिनका अन्वेषण विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किया जाएगा, अर्थात :—

(क) (1) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 124, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 190, 216, 216-क, 224, 225, 225-ख, 343, 346, 347, 393 और 507 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(2) विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 9-ख के अधीन दण्डनीय अपराध;

(3) भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 20 और धारा 25 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(4) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 126-क और 128 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(5) सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन अधिनियम, 1982 (1982 का 66) की धारा 3 और धारा 4 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(6) लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 (1984 का 3) की धारा 3 और धारा 4 के अधीन दण्डनीय अपराध; और

(ख) ऊपर उल्लिखित किसी एक अपराध या अधिक अपराधों और उन्हीं तथ्यों से उद्भूत वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध की बाबत या उसके संबंध में प्रयत्न, दुष्प्रेरण और षड्यंत्र।

[संख्या 228/24/85-ए. वी. डी. (ii)]

के. आर. गोपाल राव, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL AND TRAINING, ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 5th September, 1985

S.O. 4376.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government hereby specifies the following offences also as the offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Establishment, namely:—

(a) (i) Offences punishable under sections 124, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 190, 216, 216-A, 224, 225, 225-B, 343, 346, 347, 393 and 507 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860);

(ii) Offences punishable under section 9-B of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884);

(iii) Offences punishable under sections 20 and 25 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);

(iv) Offences punishable under sections 126, 126-A and 128 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890);

(v) Offences punishable under sections 3 and 4 of the Suppression of Unlawful Acts against Safety of Civil Aviation Act, 1982 (66 of 1982);

(vi) Offences punishable under sections 3 and 4 of the Prevention of Damage to Public Property Act, 1984 (3 of 1984); and

(b) Attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with, one or more of the offences mentioned above and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228/24/85-AVD.II]

K. R. GOPAL RAO, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1985

आयकर

का. आ. 4377.—इस कार्यालय की दिनांक 26.11.84 की अधिसूचना सं. 6059 (फा. सं. 203/205/84-आ. क. नि.-ii) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली

ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) (पैंतीस/एक/तीन) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात :—

1. यह कि विवेकानन्द निधि, कलकत्ता, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगी।

2. यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों का वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगी।

4. यह कि उक्त संस्थान अनुमोदन की समाप्ति के 3 महीने पहले समयावधि बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली को आवेदन करेगा। अनुमोदन की तारीख के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"विवेकानन्द निधि, कलकत्ता"

यह अधिसूचना 1.4.1985 से 31.3.87 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6306/फा. सं. 203/205/84-आ. क. नि.-II]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 10th July, 1985

INCOME-TAX

S.O. 4377.—In continuation of this Office Notification No. 6059 (F. No. 203/205/84-ITA.II) dated 26-11-1984, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Three) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

(i) That the Vivekananda Nidhi, Calcutta will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"Vivekananda Nidhi, Calcutta".

This Notification is effective for a period from 1-4-1985 to 31-3-1987.

[No. 6306/F. No. 203/205/84-ITA.II]

का. आ. 4378.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय की दिनांक 16.11.1964 की अधिसूचना संख्या 79 (फा. सं. 10/81/64-आ. क. नि.-i) द्वारा स्पेशल काफी एसोसिएशन, मद्रास को दिया गया अनुमोदन 30/4/1985 से एतद्द्वारा वापिस लिया जाता है।

[संख्या 6307/फा. सं. 203/126/85-आ. क. नि.-II]

S.O. 4378.—It is hereby notified for general information that the approval granted to Special Coffee Association, Madras vide Ministry of Finance Notification No. 79 (F. No. 10/81/64-ITA.I) dated 16-11-1964 is hereby withdrawn with effect from 30-4-1985.

[No. 6307/F. No. 203/126/85-ITA.II]

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1985

का. आ. 4379.—इस कार्यालय की दिनांक 14/1/1985 की अधिसूचना सं. 6108 (फा. सं. 203/217/83-आ. क. नि.-ii) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता कि विहित प्राधिकारी, अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) (पैंतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात :—

1. यह कि कन्वेस्ट जैन मेडिकल रिसर्च सोसाइटी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा।

2. यह कि उक्त "संगम" अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त "संगम" अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष, 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

4. यह कि उक्त "संगम" अनुमोदन के समाप्त होने से तीन माह पहले केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) नई दिल्ली, को आगे अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र भेजेगा। अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदन पत्र रद्द हो जाएगा।

संस्था

कन्वेस्ट जैन मेडिकल रिसर्च सोसाइटी, 8/10, निकडवाड़ी लेन कांदेवाड़ी, बम्बई-400004.

यह अधिसूचना 1/4/1985 से 31/3/1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[संख्या 6328/फा. सं. 203/52/85-आ. क. नि.-II]

आ. पी. श्रीवास्तव निदेशक

New Delhi, the 18th July, 1985

S.O. 4379.—In continuation of this Office Notification No. 6108 (F No. 203/217/83-ITA.II) dated 14-1-1985, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions :—

(i) That the Conwest Jain Medical Research Society will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the opproval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Conwest Jain Medical Research Society, 8/10, Nikadwari Lane Kandewadi, Bombay-400004.

This Notification is effective for a period from 1-4-1985 to 31-3-1986.

[No. 6328/F. No. 203/52/85-ITA.II]

O. P. SRIVASTAVA, Director

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1985.

आयकर

का.आ. 4380.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 27.7.83 की अधिसूचना सं. 5336 [फा. सं. 398/25/83-आ. क. (ब.)] का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस. एल. गुराबा को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना, श्री एस. एल. गुराबा द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[सं. 6339/फा. सं० 398/1/85-आ. क. (ब.)]

New Delhi, the 25th July, 1985

INCOME-TAX

S.O. 4380.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 5336 (F. No. 398/25/83-IT(B) dated the 27-7-85, the Central Government hereby authorises Shri S. L. Guraba, being a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri S. L. Guraba takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 6339 F. No. 398/1/85-IT(B)]

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1985

का.आ. 4381.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 24.05.1983 की अधिसूचना संख्या 5195 [फा. सं. 398/14/83-आ. क. (ब)] के अधिलंघन में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एच. सी. थिंड को जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना श्री एच. सी. थिंड द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

[संख्या 6367/फा. सं. 398/7/85-आ. क. (ब.)]

बी. ई. अलैक्जैंडर, अवर सचिव

New Delhi, the 8th August, 1985

S.O. 4381.—In pursuance of sub-clause (iii) of Clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of Government of India in the Department of Revenue No. 5195 F. No. 398/14/83-IT(B)] dated 24-05-1983 the Central Government hereby authorises Shri H. C. Thind, being a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri H. C. Thind, takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 6367/F. No. 398/7/85-IT(B)]

B. E. ALEXANDER, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1985

आयकर

का. आ. 4382.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात :—

1. यह कि विवेकानन्द चिकित्सा अनुसंधान सोसाइटी, लातूर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगी।

2. यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

4. यह कि उक्त संस्थान अनुमोदन की समाप्ति के 3 महीने पहले समयावधि बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली को आवेदन करेगा।

आवेदन की तारीख के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"विवेकानन्द चिकित्सा अनुसंधान सोसाइटी, लातूर"

यह अधिसूचना 7.9.1984 से 31.3.1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6354/फा. सं. 203/166/84-आ. क. नि.-II]

New Delhi, the 31st July, 1985

INCOME-TAX

S.O. 4382.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

(i) That the Vivekananda Medical Research Society, Latur will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and eexpenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Institute will apply to Central Board Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"The Vivekananda Medical Research Society, Latur".

This Notification is effective for a period from 7-9-1984 to 31-3-1986.

[No. 6354/F. No. 203/166/84-ITA.II]

का. आ. 4383.—इस कार्यालय की दिनांक 2-3-83 की अधिसूचना सं. 5119(फा. सं. 203/27/82-आ. क. नि.-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (I) के खंड (ii) (पैंतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि भारतीय रसायन इंजीनियर संस्थान, कलकत्ता वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

2. यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियों, देनदारियों दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

4. यह कि उक्त संस्थान अनुमोदन की समाप्ति के 3 महीने पहले समयावधि बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली को आवेदन करेगा। अनुमोदन की तारीख के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"भारतीय रसायन इंजीनियर संस्थान, कलकत्ता"

यह अधिसूचना 1-4-1985 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6353/फा.सं. 203/97/85-आ. क. नि.-II]

S.O. 4383.—In continuation of this Office Notification No. 5119 (F. No. 203/27/82-ITA.II) dated 2-3-1983, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

(i) That the Indian Institute of Chemical Engineers, Calcutta will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year

(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue) New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"Indian Institute of Chemical Engineers, Calutta".

This Notification is effective for a period from 1-4-1985 to 31-3-1988.

[No. 6353/F. No. 203/97/85-ITA.II]

का. आ. 4384.—इस कार्यालय की दिनांक 9-9-1981 की अधिसूचना सं. 4215 (फा. सं. 203/178/78—आयकर निदेश-II) के सिलसिले में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) (पैंतीस/एक/तीन) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1 यह कि स्टैटिस्टिकल पब्लिशिंग सोसायटी कलकत्ता, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगी।

2. यह कि उक्त सोसायटी अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के

संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्रपत्र में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त सोसायटी अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी, तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगी।

4. यह कि उक्त सोसायटी अनुमोदन की समाप्ति के 3 महीने पहले समयावधि बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग नई दिल्ली को आवेदन करेगी। अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"स्टेटिस्टिकल पब्लिशिंग सोसायटी, कलकत्ता"।

यह अधिसूचना 9-9-1984 से 31-3-1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6352/फा. सं. 203/73/85-आ. क. नि-II]

S.O. 4384.—In continuation of this Office Notification No. 4215 (F. No. 203|178|78-ITA. II) dated 9-9-1981, it it hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five|One|Three) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conidtions:—

(i) That the Statistical Publishing Society, Calcutta will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Society will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Society will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Society will apply to Central Board of Directs Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"Statistical Publishing Society, Calcutta".

This Notification is effective for a period from 9-9-1984 to 31-3-1986.

[No. 6352/F. No. 203/73/85-ITA.II]

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1985

का.आ. 4385.—इस कार्यालय की दिनांक 10-8-1982 की अधिसूचना सं. 4862 (फा. सं. 203/111/82—आ. क. नि.-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात्, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (II) (पैंतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है अर्थात् :—

1 यह कि इन्डियन रजिस्टर आफ शिपिंग, बम्बई वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

2 यह कि उक्त आई. आर. एस. अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त आई. आर. एस. अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

4. यह कि उक्त आई. आर. एस अनुमोदन की समाप्ति से तीन मास पहले केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को समयावधि बढ़ाने के लिए और आवेदन करेगा। अनुमोदन की समाप्ति के बाद प्राप्त प्रार्थनापत्र को रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"इन्डियन रजिस्टर आफ शिपिंग, 72, मेकर टावर्स 'एफ' (सातवीं मंजिल) कुफे परेड, बम्बई-400005"।

यह अधिसूचना 1-4-1985 से 31-3-1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6358/फा. स. 203/28/85-आ. क.नि. II]

New Delhi, the 5th August, 1985

S.O. 4385.—In continuation of this Office Notification No. 4862 (F. No. 203/111/82-ITA.II) dated 10-8-1982, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five|one|two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:—

(i) That the Indian Register of Shipping, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said I.R.S. will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said I.R.S. will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said I.R.S. will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Application received after the date of expiry of approval liable to be rejected.

INSTITUTION

"Indian Register of Shipping, 72, Maker Towers 'F' (7th Floor), Cuffe Parade, Bombay-400005".

This Notification is effective for a period from 1-4-1985 to 31-3-1986.

[No. 6358/F. No. 203/28/85-ITA.II]

का. आ. 4386.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नीचे उल्लिखित व्यापारिक प्रतिष्ठान को व्यवहार्यता रिपोर्ट या परियोजना रिपोर्ट तयार करने या बाजार का सर्वेक्षण करने या कारबारों के लिए कोई अन्य सर्वेक्षण करने से संबंधित कार्य को पूरा करने के प्रयोजनार्थ जैसा कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35-घ की उप-धारा (II) के खण्ड (क) के उप-खंड (i) से (iii) में उल्लेख किया गया है, एतद्द्वारा अनुमोदित किया है।

व्यापारिक प्रतिष्ठान

मैसर्स आर. एम. लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट,
1, कैन्टोन्मेन्ट रोड,
कैसर बाग सर्कस,
लखनऊ-226001

यह अधिसूचना 1-4-1985 से 31-3-1987 तक की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

[सं. 6359/फा. सं. 203/90/83-आ.क.नि.-II]

S.O. 4386.—It is hereby notified for general information that the concern mentioned below has been approved by Central Board of Direct Taxes for the purposes of carrying out the work in connection with the preparation of the feasibility report or the project report or the conducting of market survey or any other survey for the business, as it is referred to in sub-clause (i) to (iii) of clause (a) of sub-section (2) of Section 35D of the Income-tax Act, 1961.

CONCERN

M/s. R. M. Lall & Co.,
Chartered Accountants,
1, Cantonment Road,
Kaiser Bagh Circus,
Lucknow-226001.

This Notification is effective for a period from 1-4-1985 to 31-3-1987.

[No. 6359/F. No. 203/90/83-ITA.II]

का. आ. 4387.—इस कार्यालय की दिनांक 13-7-1982 की अधिसूचना सं. 4801 (फा. सं. 203/49/82-आ.क.नि.-II) के सिलसिले में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (I) खण्ड (II) (पैंतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर, अनुमोदित किया है, अर्थात्:—

1. यह कि सड़क परिवहन संस्थान, मद्रास वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

2. यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

4. यह कि उक्त अनुमोदन की समाप्ति के 3 महीने पहले समयावधि बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली को आवेदन करेगा। अनुमोदन की तारीख के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"सड़क परिवहन संस्थान, तारामनी, मद्रास-600113"

यह अधिसूचना 9-4-1985 से 31-3-1987 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6356/फा. सं. 203/50/85-आ.क.नि.-II]

S.O. 4387.—In continuation of this Office Notification No. 4801 (F. No. 203/49/82-ITA. II) dated 13-7-1982, it is hereby notified for general information that the Instutution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:—

(i) That the Institute of Road Transport, Madras will maintain a separate accoount of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

The Institute of Road Transport, Taramani, Madras-600113,"

This Notification is effective for a period from 9-4-1985 to 31-3-1987.

[No. 6356/F. No. 203/50/85-ITA.II]

का. आ. 4388.—इस कार्यालय की दिनांक 17-7-1982 की अधिसूचना सं. 4805 (फा. सं. 203/134/82-आ. क. नि.-II) के सिलसिले में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (I) के खंड (II) (पैंतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात्:—

1. यह कि हैदराबाद साइंस सोसायटी, हैदराबाद वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

2. यह कि उक्त सोसायटी अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष

के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त सोसायटी अपने कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगी।

4. यह कि उक्त संस्था अनुमोदन की समाप्ति से तीन मास पहले समयावधि बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय नई दिल्ली को आवेदन करेगी। अनुमोदन की समाप्ति तारीख के बाद प्राप्त प्रार्थनापत्र को रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"हैदराबाद साइंस सोसायटी, हैदराबाद"

यह अधिसूचना 1-4-1985 से 31-3-1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6351/फा. सं. 203/54/85-आ.क.नि.-II]

गिरीश दवे, अवर सचिव,

S.O. 4388.—In continuation of this Office Notification No. 4805 (F. No. 203/124/82-ITA. II) dated 17-7-82, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:-

(i) That the Hyderabad Science Society, Hyderabad will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Society will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Society will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Society will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"Hyderabad Science Society, Hyderabad".

This Notification is effective for a period from 1-4-1985 to 31-3-1986.

[No. 6351/F. No. 203/54/85-ITA.II]

GIRISH DAVE, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

नई दिल्ली, 27 जून, 1985

आय-कर

का.आ. 4389—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 122 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रेंजों के अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर परिमण्डलों, वार्डों और जिलों में आयकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय के संबंध में अपने-अपने कार्य करेंगे:—

अनुसूची

क्र. सं.	रेंज	आयकर परिमण्डल/वार्ड या जिला
1	2	3
1.	कटक रेंज, कटक	1. आयकर परिमण्डल (सिटी), कटक
		2. आयकर परिमण्डल, (ग्रामीण), कटक
		3. आयकर परिमण्डल, देवगनाल
		4. आयकर परिमण्डल, बारीपाड़ा
		5. आयकर परिमण्डल, बालासोर
		6. आयकर परिमण्डल, राउरकेला
		7. आयकर परिमण्डल, सम्बलपुर
		8. आयकर परिमण्डल, बरगढ़
		9. आयकर परिमण्डल, झारसुगुडा
		10. आयकर परिमण्डल, कोहनझार
2.	बेरहामपुर रेंज, बेरहामपुर	1. आयकर परिमण्डल बेरहामपुर
		2. आयकर परिमण्डल, भुवनेश्वर
		3. सम्पदा शुल्क, भुवनेश्वर
		4. विशेष जांच वार्ड-I, भुवनेश्वर
		5. विशेष जांच वार्ड-II, भुवनेश्वर
		6. विक्री परिमण्डल, भुवनेश्वर
		7. अधिकर परिमण्डल, भवानीपाटना
		8. आयकर परिमण्डल, बोलनगीर
		9. आयकर परिमण्डल, जैपोर
		10. आयकर परिमण्डल, फूलबनी
		11. आयकर परिमण्डल, पुरी

यदि कोई आयकर परिमण्डल वार्ड या जिला अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज में अंतरित कर दिया जाता है, उस आयकर परिमण्डल, वार्ड अथवा जिले अथवा उसके किसी भाग में किए गए कर-निर्धारितों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें, जिनके क्षेत्राधिकार से उस परिमण्डल, वार्ड अथवा जिला या उसका कोई भाग अंतरित किया गया हो, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त को अंतरित की जाएंगी और उसके द्वारा निपटाई जाएंगी, जिसके अधिकार-क्षेत्र में उक्त परिमण्डल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अंतरित किया गया हो।

यह अधिसूचना 1-7-1985 से लागू होगी।

[सं. 6296/फा. सं. 261/9/85-आ. क.न्या.]

सुरेन्द्र पाल, अवर सचिव।

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 27th June, 1985

INCOME-TAX

S.O.4389.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in

supersession of all previous Notifications in this regard the Central Board of Direct Taxes hereby direct that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specifed in column 2 of the schedule below shall perform their functions in respect of all persons and income assessed to Income-tax or Super-Tax in the Income-tax Circles, Wards or District specified in the corresponding entry in column 3 thereof :—

SCHEDULE

Sl. No.	Range	Income-tax Circle/Ward or Districts
1.	Cuttack Range, Cuttack	1. I.T. Circle, (City), Cuttack : 2. I.T. Circle, (Rural), Cuttack : 3. I.T. Circle, Dhenkanal : 4. I.T. Circle, Baripada : 5. I.T. Circle, Balasore : 6. I.T. Circle, Rourkela : 7. I.T. Circle, Sambalpur : 8. I.T. Circle, Bargarh : 9. I.T. Circle, Jharsguda : 10. I.T. Circle, Kehonjhar :
2.	Berhampur Range, Berhampur:	1. I.T. Circle, Berhampur : 2. I.T. Circle, Bhubaneswar : 3. Estate Duty, Bhubaneswar : 4. Spl. Investigation ward-A, Bhubaneswar : 5. Spl. Investigation, Ward-B Bhubaneswar : 6. Salary Circle, Bhubaneswar : 7. I.T. Circle, Bhawanipatna : 8. I.T. Circle, Bolangir : 9. I.T. Circle, Jeypore : 10. I.T. Circle, Phulbani : 11. I.T. Circle, Puri.

Whereas an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward, or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Asstt. Commissioner of the Range from whom that Income-tax Circle Ward or District or part thereof is transferred shall, from the date of this Notification takes effect be transferred to and dealt with by the Appellate Asstt. Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 1-7-1985.

[No. 6296/F. No. 261/9/85-ITJ]

SURENDER PAUL, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 जून, 1985

आयकर

का.आ. 4390—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 121–क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकार-क्षेत्र के आयकर आयुक्त (अपील) स्तम्भ (2) और (3) की तत्संबंधी की प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आयकर वार्डों, परिमण्डलों, जिलों और रेंजों में आयकर अथवा अतिकर या ब्याजकर से निर्धारित ऐसे व्यक्तियों के बारे में, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (ज), कम्पनी अधिनियम, के खण्ड 2 की उपधार (1) ब्याजकर अधिनियम 1964 (1964 का 45) की धारा 15 में उल्लिखित किसी भी आदेश से व्यथित हुए हैं और ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों की बाबत भी जिनके लिए बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार निदेश दिया है या भविष्य में निदेश दें, कार्य निर्वहन करेंगे ।

अनुसूची

अधिकार-क्षेत्र तथा प्रभारी कार्यालय	आयकर वार्ड और परिमण्डल	निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त की रेंज
आयकर आयुक्त (अपील) विशाखापट्नम	1. श्रीकाकुलम परिमण्डल 2. विजिआग्राम परिमण्डल 3. विशाखापट्नम परिमण्डल 4. वेतन परिमण्डल, विशाखापट्नम 5. आयकर अधिकारी (एस. आई. सी.) विशाखापट्नम 6. अनकापल्ल परिमण्डल 7. राजामुन्दरी परिमण्डल	निरीक्षी सहायक आयुक्त, विशाखापट्नम
	8. परिमण्डल–I काकीनाडा 9. परिमण्डल–II काकीनाडा 10. अमालपुरम् परिमण्डल 11. पालाकोले परिमण्डल 12. भीमावरम् परिमण्डल 13. टानुकू परिमण्डल 14. ईलूरू परिमण्डल	निरीक्षी सहायक आयुक्त काकीनाडा
आयकर आयुक्त (अपील) विशाखापट्नम	15. विजयवाड़ा परिमण्डल–I विजयवाड़ा 16. विजयवाड़ा परिमण्डल–II विजयवाड़ा 17. विशेष जांच परिमण्डल, विजयवाड़ा 18. गुडीवाड़ा परिमण्डल 19. मछलीपट्नम परिमण्डल	निरीक्षी सहायक आयुक्त विजयवाड़ा
	20. तेनाली परिमण्डल 21. ओंगोले परिमण्डल 22. बापतला परिमण्डल 23. नेल्लोर परिमण्डल	निरीक्षी सहायक आयुक्त नेल्लोर

यह अधिसूचना 1-7-1985 से लागू होगी ।

[सं. 6303/फा.सं. 261/8/85-आ.का.–न्या.]

New Delhi, the 28th June, 1985

INCOME-TAX

S.O. 4390.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121-A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of all the previous notifications in this regard the Central Board of Direct Taxes hereby direct that the Commissioner of Income-tax (Appeals) of the charges specified in column (1) of the schedule below shall perform their functions in respect of such persons assessed to Income-tax or surtax or interest tax in the Income-tax Wards, Circle, Districts and Ranges specified in the corresponding entries in column(2) and column (3) thereof as are aggrieved by any of the orders mentioned in clauses (a) to (h) of sub-section (2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961, in sub-section (1) of

Section II of Companies AOP section 15 of the Interest Tax Act, 1964 (45 of 1964) and also in respect of such persons or clauses of persons as the Board has directed or may direct in future in accordance with the provisions of clause (i) of sub-section (2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961.

SCHEDULE

Charge with Headquarters	Income-tax Wards and Circles	Ranges of Ins. Asstt. Commrs. Income-tax
Commissioner of Income-tax (Appeals), Visakhapatnam	1. Srikakulam Circle 2. Vizianagram Circle 3. Visakhapatnam Circle 4. Salary Circle, Visakhapatnam 5. ITO (SIC), Visakhapatnam 6. Anakapalle Circle. 7. Rajahmundry Circle	IAC, Visakhapatnam
	8. Circle-I, Kakinada 9. Circle-II, Kakinada 10. Amalapuram Circle 11. Palacole Circle 12. Bhimavaram Circle 13. Tanuku Circle. 14. Eluru Circle	IAC, Kakinada
	15. Vijayawada Cir. I, Vijayawada 16. Vijayawada Cir. II, Vijayawada 17. Special Investigation Circle, Vijayawada 18. Budivada Circle 19. Machilipatnam Circle	IAC, Vijayawada
	20. Tenali Circle 21. Ongole Circle 22. Bapatla Circle 23. Nellore Circle.	IAC, Nellore

This Notification shall take effect from 1-7-1985.

[No. 6303/F. No. 261/8/85-ITJ]

का.आ. 4391-आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 122 के उपखंड (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अभिलंघन करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रेंजों के अपीलीय महायक आयकर आयुक्त आयकर से निर्धारित उन सभी व्यक्तियों और आय को छोड़ कर जिन पर क्षेत्राधिकार आयकर आयुक्त (अपील) में निहित है, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर परिमण्डलों, वार्डों और जिलों में आयकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय से संबंध के अपने अपने कार्य करेंगे ।

अनुसूची

क.सं.	अपीलीय महायक आयुक्त की रेंज	आयकर परिमण्डल वार्ड और जिला
1	2	3
1.	अपीलीय महायक आयकर आयुक्त "ए" रेंज, हैदराबाद ।	कोई परिवर्तन नहीं
2.	अपीलीय महायक आयकर आयुक्त, "बी" रेंज, हैदराबाद ।	कोई परिवर्तन नहीं ।
3.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, "ए" रेंज, विजयवाड़ा	1. विजयवाड़ा परिमण्डल 1, विजयवाड़ा 2. विजयवाड़ा परिमण्डल- 2 के ए तथा बी वार्ड, विजयवाड़ा । 3. केन्द्रीय परिमण्डल, विजयवाड़ा । 4. विशेष जांच परिमण्डल, विजयवाड़ा 5. गुडीवाड़ा । 6. मछलीपट्नम । 7. तेनाली 8. ओंगोले । 9. बापतला । 10. गुन्टुर । 11. विशेष जांच परिमण्डल, गुन्टुर । 12. ईलूरू । 13. टानुकू । 14. पालाकोले । 15. भीमावरम् । 16. नेल्लोर ।
4.	अपीलीय महायक आयकर आयुक्त, "बी" रेंज विजयवाड़ा ।	1. वेतन परिमण्डल, हैदराबाद । 2. विजयवाड़ा परिमण्डल- 2 के "सी" तथा "डी" वार्ड, विजयवाड़ा ।
5.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, विशाखापट्नम	1. आमलापुरम । 2. राजामन्द्री । 3 अन्कापल्ली । 4 विशाखापट्नम परिमण्डल, विशाखापट्नम 5. वेतन परिमण्डल विशाखापट्नम । 6. विशेष जांच परिमण्डल, विशाखापट्नम 7. श्रीकाकुलम । 8. विजिआग्रामं । 9. परिमण्डल- I काकीनाडा 10. परिमण्डल-II, काकीनाडा 11. केन्द्रीय परिमण्डल, काकीनाडा
6.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, अन्नतपुर ।	कोई परिवर्तन नहीं ।

यत: कोई आयकर परिमण्डल/वार्ड या जिला अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से अन्य रेंज में अंतरित कर दिया जाता है, उस परिमण्डल, वार्ड अथवा जिले अथवा उसके किसी भाग में किए गए कर-निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व रेंज के उस अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें, जिनके अधिकार-क्षेत्र से उस परिमण्डल वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अंतरित किया गया हो इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से रेंज के उस अपीलीय के लागू होने की तारीख से अपीलीय सहायक आयुक्त को अंतरित हो जाएंगी और उसके द्वारा निपटाई जाएंगी जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिमण्डल, वार्ड जिला अथवा उसका कोई भाग अंतरित किया गया है ।

यह अधिसूचना 1-7-1985 से लागू होगी ।

[सं. 6302/फा. सं. 261/8/85-आ.क.-न्या.]

ए. के. गर्ग, अवर सचिव

S.O.4391.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of all the previous notifications in this regard the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column (2) of the schedule below shall perform their functions in respect of all persons and income assessed to income-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column (3) thereof excluding all persons and incomes assessed to income-tax over which the jurisdiction vest in the Commissioner of Income-tax (Appeals).

SCHEDULE

Sl. No.	Appellate Assistant Commissioner's Range	Income-tax Circle, Ward and District
1	2	3
1.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax 'A' Range, Hyderabad.	No Change
2.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'B' Range, Hyderabad.	No Change
3.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'A' Range, Vijayawada.	1. Vijayawada Cir. I, Vijayawada. 2. A & B Wards of Vijayawada Circle, II, Vijawewada. 3. Central Cir., Vijayawada 4. Special Investigation Circle, Vijayawada. 5. Gudiwada. 6. Machilipatnam. 7. Tenali. 8. Ongole. 9. Bapatla. 10. Guntur. 11. Special Investigation Circle, Guntur. 12. Elurue. 13. Tanuku. 14. Palacole. 15. Bhimavaram. 16. Nellore.
4.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'B' Range, Vijayawada.	1. Salary Circle, Hyderabad. 2. C & D-Wards of Vijayawada Circle-II, Vijayawada.
5.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Visakhapatnam.	1. Amalapuram. 2. Rajahmundry. 3. Anakapalle. 4. Visakhapatnam Circle, Visakhapatnam. 5. Salary Cir. Visakhapatnam. 6. Special Investigation Circle, Visakhapatnam. 7. Srikakulam 8. Vizianagaram. 9. Circle-I, Kakinada. 10. Circle-II, Kakinada. 11. Central Cir., Kakinada.
6.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Anantapur.	No Change

Whereas an Income-tax Circle/Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Circle, Ward or District or part thereof and before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1-7-1985.

[No. 6302/F. No. 261/8/85-ITJ)]

A.K. GARG, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1985

आदेश

का०आ० 4392—केन्द्रीय सरकार की राय है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि खेल का सामान, निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होने चाहिये;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाये है और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त उपनियम के अनुसरण में उक्त प्रस्तावों को ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ।

सूचना दी जाती है कि यदि उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई व्यक्ति कोई आक्षेप या सुझाव भेजना चाहता है तो वह उन्हें इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पंतालीस दिन के भीतर भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद् (वाणिज्य मंत्रालय) 11वीं मंजिल, प्रगति टावर, 26 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008 को भेज सकता है ।

प्रस्ताव

(1) अधिसूचित करना है कि खेल का सामान निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगा;

(2) इस आदेश के उपाबंध-1 में दिए गए खेल के सामान के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1984 के प्रारूप के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को, क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना है जो निर्यात से पूर्व ऐसे खेल के सामान पर लागू होगा;

(3) निम्नलिखित को मान्यता देना—

(क) संबंधित भारतीय मानक अथवा अन्य किसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक ।

(ख) निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य निकायों के मानक;

(ग) इस आदेश के उपाबन्ध-II में दिये हुए न्यूनतम विनिर्देशों को पूरा करने हुए उत्पाद के अधीन संविदात्मक विनिर्देश;

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में, ऐसे खेल के सामान के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उनके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अभिकरणों में से किसी एक के द्वारा जारी किया गया इस आशय का निरीक्षण प्रमाणपत्र न हो कि खेल का सामान मानक विनिर्देशों के अनुरूप है तथा निर्यात योग्य है।

2. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को भू मार्ग, जल मार्ग या वायु मार्ग द्वारा खेल के सामान के वास्तविक नमूनों के निर्यात पर लागू नहीं होगी परन्तु यह तब तक जब कि ऐसे नमूनों का कोल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के पांच हजार रुपये से अधिक न हो।

3. इस आदेश में खेल के सामान से नीचे दी गई कोई भी वस्तु अभिप्रेत है :—

1. गेंद

(क) फुटबाल

(ख) बालीबाल

(ग) बास्केटबॉल

(घ) नेटबाल

2. क्रिकेट और हाकी बाल

3. क्रिकेट बैट्स

4. हाकी छड़ें

5. रैकेट्स

(क) बैडमिंटन

(ख) टेनिस

(ग) स्क्वाश

6. सुरक्षात्मक उपकरण

(क) बैटिंग करने के लिये दस्ताने

(ख) बैट्स मैन तथा विकेटकीपर की टांगो के लिय कवच

(ग) उदर कवच।

उपाबन्ध—I

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963(1963 का 22) की धारा 17 के अधीन बनाये जाने वाले प्रस्तावित नियमों का प्रारूप ।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खेल के सामान का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1984 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है ;

(ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित कोई निर्यात निरीक्षण अभिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) "परिशिष्ट" से इन नियमों का परिशिष्ट अभिप्रेत है;

(घ) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है ;

(ङ) "अनुसूची" से इन नियमो से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(च) "खेल का सामान" से नीचे दी गई वस्तुओं में से कोई एक अभिप्रेत है :—

1. गेंद

(क) फुटबाल

(ख) बॉलीबाल

(ग) बास्केटबाल

(घ) नेटबाल

2. क्रिकेट और हाकी की गेंद (बॉल)।

3. क्रिकेट खेलने के बैट।

4. हाकी और छड़ें।

5. रैकेट।

(क) बैडमिंटन

(ख) टेनिस

(ग) स्क्वाश

6. सुरक्षात्मक उपकरण।

(क) बैटिंग करने वाले दस्ताने

(ख) विकेटकीपर और बल्समैन की टांगो के लिये सुरक्षात्मक कवच

(ग) उदर कवच

3. निरीक्षण का आधार :—खेल के सामान का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जायेगा कि खेल के सामान की क्वालिटी अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त विनिर्देशो के अनुरूप हैं, अर्थात् :—

(क) संगत भारतीय मानक या कोई अन्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अन्य मानक।

(ख) निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य निकायों के मानक।

(ग) उपाबन्ध II में दिये गये न्यूनतम विनिर्देशों को उत्पाद के पूरा करने के अधीन संविदात्मक विनिर्देश।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :—(1) खेल के सामान का निरीक्षण यह देखने की दृष्टि से किया जायेगा कि खेल का सामान अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है।

या

(क) यह सुनिश्चित करते हुए कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान नियम 4 के उप नियम 2(क) के अधीन परि I] में विनिर्दिष्ट के अनुसार उत्पाद के दौरान क्वालिटी नियंत्रण विधियों का प्रयोग किया गया है।

या

(ख) नियम 4 के उपनियम 2(ख) के अनुसार किये गये निरीक्षण के आधार पर।

या

(ग) दोनों के आधार पर।

(2) निम्नलिखित स्कीमों में से कोई एक या दोनों स्कीमें अपनाई जाएंगी, अर्थात् —

(क) उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण (आई पी क्यूसी)

(1) कोई भी विनिर्माण एकक जिसके पास परिशिष्ट-1 के अनुसार पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण हैं, अभिकरण के निकटतम कार्यालय को आवेदन करेगा।

(2) फिर अभिकरण विनिर्माण एकक का दौरा करेगा और यह देखेगा कि क्या वहां उत्पादन के दौरान प्रभावी क्वालिटी नियंत्रण पद्धति विद्यमान है, या

(ख) परीक्षणानुसार निरीक्षण —

कोई भी विनिर्माण एकक जो खंड (क) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो वह निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित या मान्यताप्राप्त किसी भी अभिकरण को निरीक्षण करने के लिए अपने निर्यात परेषण देगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि उसके द्वारा विनिर्मित उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

(3) खेल-कूद के सामान के परेषण का निर्यात करने का इच्छुक कोई भी निर्यातकर्ता अपने ऐसा करने के आशय की सूचना लिखित में देगा और ऐसी सूचना के साथ ऐसे निर्यात से संबंधित निर्यात संविदा में निर्दिष्ट के अनुसार सभी तकनीकी विशेषताओं का ब्यौरा देते हुए किसी भी अभिकरण को विनिर्देशों की घोषणा देगा ताकि वह नियम-4 के उपनियम (2) के खंड (क) या खंड (ख) या दोनों खंडों के अनुसार निरीक्षण कर सके।

(4) उपनियम (2) के खंड (क) के अधीन अनुमोदित एककों द्वारा विनिर्मित खेल-कूद के सामान का निर्यात करने के लिए निर्यातकर्ता ऐसी सूचना के साथ यह घोषणा भी देगा कि निर्यात के लिए आशयित खेल-कूद का सामान परिशिष्ट में यथा अधिकथित पर्याप्त, क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करते हुए विनिर्मित किया गया है तथा परेषण इस प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

(5) उप-नियम (2) और (4) के अधीन प्रत्येक सूचना और घोषणा अभिकरण के कार्यालय में परेषण के विनिर्माता के परिसर से भेजे जाने से कम से कम तीन दिन पूर्व पहुंचेगी।

(6) निर्यातकर्ता अभिकरण को निर्यात किए जाने वाले परेषण पर लगाए जाने वाले पहचान चिन्ह भी देगा।

(7) सूचना और घोषणा प्राप्त होने पर अभिकरण —

(क) नियम-4 के उप-नियम (2) के खंड (क) के अधीन अनुमोदित एककों द्वारा विनिर्मित उत्पादों का निर्यात करने वाले निर्यातकर्ता के मामले में अपना यह समाधान करने पर कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान एकक में ने परिशिष्ट के अंतर्गत दिए गए पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग किया है और इस संबंध में परिषद् द्वारा जारी किए गए अनुदेश, यदि कोई हों का पालन किया है तीन दिन के भीतर यह घोषणा करते हुए प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि परेषण निर्यात योग्य है। तथापि अभिकरण कालिक निरीक्षणों और स्थल पर जांच द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि विनिर्माण परिसरों पर पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग किया गया है तथा उत्पाद मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है, तथा

(ख) नियम-4 के उप-नियम (2) के खंड (ख) के अंतर्गत आने वाली एककों द्वारा विनिर्मित उत्पाद का निर्यात करने वाले निर्यातकर्ता के मामले में खेल-कूद के सामान का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जाएगा कि उत्पाद इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है।

(ग) निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात्, अभिकरण परेषण में पैकेजों को इस प्रकार से पैक करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि सीलबंद पैकेजों में फेर बदल न की जा सके।

(घ) परेषण की अस्वीकृति के मामले में यदि निर्यातकर्ता ऐसा चाहे तो अभिकरण द्वारा परेषण को सील बंद नहीं किया जाएगा।

(ङ) ऐसे मामलों में, तथापि निर्यातकर्ता अस्वीकृति के विरुद्ध अपील करने का हकदार नहीं होगा।

(च) यदि अभिकरण का समाधान हो जाता है कि खेल-कूद के सामान का परेषण इन नियमों के अधीन अपेक्षाओं को पूरा करता है तो वह निरीक्षण की समाप्ति के तीन दिन के भीतर यह घोषणा करते हुए प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि परेषण निर्यात योग्य है :

परन्तु जहां अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है तो वह निर्यातकर्ता को यह घोषणा करते हुए प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार कर देगा कि खेल-कूद के सामान का परेषण निर्यात योग्य है और ऐसे इंकार की सूचना निर्यातकर्ता को उसके कारणों सहित सात दिन के भीतर दे देगा।

5. निरीक्षण का स्थान —इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण या तो (क) ऐसे उत्पादों के विनिर्माताओं के परिसर पर या (ख) उन परिसरों पर किया जाएगा जहां निर्यातकर्ता ने सामान प्रस्तुत किया है परन्तु यह तब जब कि वहां परीक्षण और निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों।

6. निरीक्षण फीस —निर्यातकर्ता द्वारा अभिकरण को निरीक्षण फीस निम्नानुसार दी जाएगी —

(i) (क) उत्पाद के दौरान क्वालिटी नियंत्रण के अधीन निर्यात करने के लिए न्यूनतम 20/- रुपये प्रति परेषण के अधीन रहते हुए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.2 प्रतिशत की दर से।

(ख) परेषणवार निरीक्षण के अधीन निर्यात करने के लिए न्यूनतम 20/- रुपये प्रति परेषण के अधीन रहते हुए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से।

(ii) उन विनिर्माताओं-निर्यातकर्ताओं के लिए जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की संबंधित सरकारों के पास लघु उद्योग विनिर्माण एककों के रूप में रजिस्ट्रीकृत है न्यूनतम 20/- रुपये प्रति परेषण के अधीन रहते हुए (क) और (ख) के लिए क्रमशः 0.19 प्रतिशत और 0.36 प्रतिशत की दर से।

(iii) सर्वेट निर्यातकर्ताओं द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और उन एककों द्वारा विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिए जिनके पास उत्पादन के दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण स्टर है न्यूनतम 20- रुपये प्रति परेषण के अधीन रहते हुए पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.3 प्रतिशत की दर से।

7. अपील

(i) नियम–4 के उप-नियम (7) के खंड (घ) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करने के इंकार से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित तीन से अन्यून और सात से अनधिक व्यक्तियों के विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकता है।

(ii) पैनल में विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे।

(iii) विशेषज्ञों के पैनल की गणपूर्ति तीन से होगी।

(iv) अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर निपटा दी जाएगी।

परिशिष्ट I

[नियम 4(4) देखें]

खेल-कूद के सामान का प्रत्येक विनिर्माता इससे संलग्न अनुसूची में दिए गए नियंत्रणों के स्तरों सहित नीचे अधिकथित उत्पाद के विनिर्माण, परिरक्षण और पैकिंग के विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित नियंत्रणों के प्रयोग करके खेल-कूद के सामान का क्वालिटी नियंत्रण सुनिश्चित करेगा।

1. क्रय की गई सामग्री और संघटकों पर नियंत्रण,

(क) विनिर्माता, प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री या संघटकों की विशिष्टताओं को समाविष्ट करते हुए और उसके सहायताओं सहित ब्यौरेवार विर्माओं के क्रय विनिर्देश अधिकथित करेगा।

(ख) स्वीकृत परेषण के साथ या तो क्रय विनिदर्शों की अपेक्षाओं की संपुष्टि करते हुए उत्पादक का प्रमाण-पत्र होगा या ऐसे परीक्षण प्रमाण-पत्र की अनुपस्थिति में प्रत्येक परेषण में से क्रय विनिदर्शों से इसकी अनुरूपता की जांच करने के लिए नमूनों का नियमित परीक्षण किया जाएगा। उत्पादक परीक्षण प्रमाण-पत्र की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए पांच परेषणों में कम से कम एक बार प्रति जांच की जाएगी।

(ग) आने वाले परेषणों का सांख्यिकी नमूना योजना के विरुद्ध क्रय विनिर्देशों से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और परीक्षण किया जाएगा।

(घ) निरीक्षण और परीक्षण किए जाने के पश्चात् दोषपूर्ण माल का उचित पृथक्करण और निपटान करने के लिए व्यवस्थित पद्धतियां अपनाई जाएंगी।

(ङ) उपरोक्त वर्णित नियंत्रणों के बारे में पर्याप्त अभिलेख व्यवस्थित रूप से रखे जाएंगे।

2. प्रक्रिया नियंत्रण :—

(क) विनिर्माण के विभिन्न अनुक्रमों के लिए विनिर्माता द्वारा ब्यौरेवार प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देशों में अधिकथित प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने के लिए उपकरणों और उपस्करों की पर्याप्त सुविधाएं होंगी।

3. उत्पाद नियंत्रण :—

(क) विनिर्माता के पास मानक विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद की जांच करने के लिए या तो अपनी परख सुविधाएं होंगी या उनकी पहुंच वहां तक होगी जहां ऐसी परीक्षण सुविधाएं विद्यमान हों।

(ख) परीक्षण के लिए नमूना (जहां कहीं अपेक्षित हो) अभिलिखित अन्वेषण के आधार पर होगा।

(ग) किए गए परीक्षण के बारे में पर्याप्त अभिलेख विनिर्माता द्वारा नियमित और व्यवस्थित रूप से रखे जाएंगे।

4. माप संबंधी नियंत्रण :—उत्पादन और परीक्षण में प्रयुक्त मापकों और उपकरणों की कालिक जांच या अंशशोधन किया जाएगा और अभिलेख वृत्त कार्ड के रूप में रखे जाएंगे।

5. परिरक्षण नियंत्रण :—

(क) विनिर्माता द्वारा उत्पाद को मौसमी दशाओं के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए ब्यौरेवार विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे।

(ख) उत्पाद भंडार और अभिवहन दोनों के दौरान अच्छी तरह से परिरक्षित किया जाएगा।

6. पैकिंग नियंत्रण :—निर्यात के पैकेजों के साथ-साथ उत्पाद की पैकिंग के लिए विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे और उनका कठोरता से पालन करना होगा।

परिशिष्ट II

[नियम 2 (ख) देखें]

1. फुटबाल के लिए विनिर्देश :—

1. सामग्री, चमड़ा—बाल का विनिर्माण क्रेता और विक्रेता के मध्य हुए करार के अनुसार कटी हुई खाल और खुरदरेपन दोषों से मुक्त सब्जी/अर्धवर्णक या क्रोमशोधित, किसी भी रंग में रंगे हुए या रंगरूप किए हुए या भैंस चर्म की उचित खाल से किया जाएगा। चर्मशोधन कार्य के अंत में और सुखाने से पहले चमड़े में फफूंदी उत्पन्न होने की प्रतिरोधिता को उत्पन्न करने के लिए, चमड़े में उचित फंगस समाविष्ट की जाएगी। ये प्रभावी और अविषैले होंगे। शोधित चर्म या तेज द्रव या तैलीय ये दोनों होंगे तथा प्राप्त की गई सतह चिकनी और भली भांति सैट होगी। प्रयुक्त चमड़े की न्यूनतम मोटाई 2.0 मिली मीटर होगी।

3. सिलाई के लिए धागा :—

(i) लिनेन धागा—सिलाई के लिए विगलनरोधी और 5 गलाई वाला धागा प्रयुक्त किया जाएगा।

(ii) सूती धागा—98 टैक्स × 8(6 एस/8) के अनुरूप होगा।

(iii) लिनेन धागा—क्रेता और विक्रेता के मध्य हुए करार के अनुसार होगा।

3. विमाएं :—

(i) रबड़ 0.98 टैक्स (1 कि.ग्रा. एफसि.मी. 2) के वायु 910 से हवा भरी जाएगी। बाल 68 से 71 से.मी. की परिधि के लिए हुए गोलाकार रूप में होगी।

(ii) हवा भरे हुए ब्लेडर के साथ बाल का भार 397 से 453 ग्राम होगा।

(iii) गोलाई पर परिधि में 1 प्रतिशत सहायता अनुज्ञेय होगी।

4. रंग क्रेता और विक्रेता के मध्य हुए करार के अनुरूप होगा।

5. कारीगरी और फिनिश :—

(i) बाल लिनेन या सूती धागे से सिली जाएगी और प्रति डेसीमीटर 24±2 टांके होंगे। टांके अच्छी तरह से कसे होंगे। जब 1 कि० ग्राम एक से.मी. के वायु दाब से बाल भरी जाएगी।

दृष्टिगत धागे बाल की सतह से 2 मिली मीटर से अधिक गहरे नहीं होंगे ।

(ii) बॉल गोलाई देते हुए विशेष आकारों की उचित संख्याओं से बनी होगी ।

(iii) बॉल का मुंह इतना पर्याप्त होगा । कि हवा भरने वाले पम्प की टोंटी और सुई उसके अनुकूल हो तथा बॉल को हवा रहित करने के लिए उचित साधन दिए जाएंगे । ब्लैडर का गर्दन मुंह के अन्दर पूर्णतया फिट होगा ।

2. वालीबाल के लिए विनिर्देश :

1. सामग्री : चर्म : बॉल का निर्माण कटी हुई खाल और खुरदरे दोषों से मुक्त सब्जी/अर्धवर्णक या क्रोमशोधित, किसी भी रंग में रंगे हुए या रंगलेप किए हुए गोचर्म या भैंस चर्म की उचित खाल से किया जाएगा । चर्मशोधन के अंत में और सुखाने से पहले खाल में फफूदी होने की प्रतिरोधिता को उत्पन्न करने के लिए खाल में उचित पास समाविष्ट की जाएगा, ये प्रभावी और अविषैले होंगे । शोधित चर्म तेज द्रव या तैलीय दोनों होंगे तथा सतह चिकनी और भली-भांति सेट होगी ।

सिलाई के लिए धागा :

(i) लिनेन धागा :—सिलाई के लिए प्रयुक्त धागा विगलन रोधी और 4 प्लाई वाला होगा ।

(ii) सूती धागा 98 टैक्स 8 (6 एम/8) के अनुरूप होगा ।

(iii) अस्तरण कपड़ा क्रेता और विक्रेता के मध्य हुए करार के अनुसार ।

3. विमाएं :—

(1) जब 0.4? से 0.52 कि.ग्रा./सि. मीटर ^{2} के वायु दाब से भरी हुई बॉल 65 से 75 से. मीटर की परिधि किए हुए आकार में गोल होगी ।

(2) हवा भरे हुए ब्लैडर सहित बाल का 260 से 280 से मी. होगा ।

(3) गोलाई में परिधि पर 1 प्रतिशत की सहायता अनुमत होगी ।

4. रंग—क्रेता और विक्रेता के मध्य हुए करार के अनुसार होगा ।

5. कारीगरी और फिनिश :—

(1) बॉल लिनेन या सूती धागों से सिली होगी और टाँके 24±2 प्रति डेसीमीटर होंगे । टाँके अच्छी तरह से कसे होंगे । जब बॉल 0.48 से 0.52 कि.ग्रा. एफ/सि.मी. ^{2} के वायु दाब से भरी जाए, चाक्षुष धागे बॉल की सतह से 2 मिली मीटर से अधिक गहरे नहीं होंगे ।

(2) बॉल अच्छी तरह गोलाई देते हुए योग्य आकारों के पैनल की उचित संख्या से बनी होगी ।

(3) मुंह इतना बड़ा होगा कि उसमें हवा भरने वाले पम्प की टोंटी फिट हो या सुई उसके अनुकूल हो तथा हवा निकालने के लिए उचित साधन दिए गए हों । ब्लैडर की गर्दन मुंह के अन्दर तक पूरी तरह होगी ।

3. बास्किट बाल के लिए विनिर्देश

1. सामग्री :—

चर्म बॉल का विनिर्माण क्रेता और विक्रेता के मध्य हुए करार के अनुसार कटी हुई खाल और खुरदरेपन दोषों से मुक्त सब्जी/अर्धवर्णक या क्रोमशोधित किसी भी रंग में रंगे हुए या रंगलेप किए हुए गोचर्म या भैंसचर्म की उचित खाल से किया जाएगा । चर्म शोधन कार्य के अन्त में और सुखाने से पहले चमड़े में फफूदी उत्पन्न होने की प्रतिरोधिता को उत्पन्न करने के लिए चमड़े में उचित फास समाविष्ट की जाएगी, ये प्रभावी और अविषैले होंगे । चर्मशोधित चमड़ा तेज द्रव या तैलीय या दोनों का होगा और सतह चिकनी और भली भांति सेट होगी । प्रयुक्त चमड़े की न्यूनतम मोटाई 2.0 मिली मीटर होगी ।

2. सिलाई के लिए धागा :—

(1) लिनेन धागा—सिलाई के लिए विगलन रोधी और 5 प्लाई वाला धागा प्रयुक्त होगा ।

(2) सूती धागा—98 टैक्स (टांका) × 8 (6 एम/8) के अनुरूप होगा ।

(3) अस्तरण कपड़ा—क्रेता और विक्रेता के मध्य हुए करार के अनुसार होगा ।

3. विमाएं :—

(1) जब 0.90 किलो ग्राम एफ/सि. मीटर ^{2} को वायु दाब से भरी हुई बॉल आकार में गोल होगी और 75 78 से से.मी. परिधि होगी ।

(2) भरे हुए ब्लैडर सहित बॉल का भार 600 से 650 ग्राम होगा ।

(3) गोलाई पर परिधि में 1 प्रतिशत की सहायता अनुमति होगी ।

4. रंग :—क्रेता और विक्रेता के मध्य हुए करार के अनुसार होगा ।

5. कारीगरी और फिनिश :—

(1) बॉल लिनेन या सूती धागों से सिली होगी और टाँके 24±2 प्रति डेसीमीटर होंगे । टाँके अच्छी तरह से कसे होंगे । जब बॉल 0.90 कि.ग्राम/सि.मी. ^{2} के वायु दाब से भरी जाए, चाक्षुष धागे बॉल की सतह से 2 मिली मीटर से अधिक गहरे नहीं होंगे ।

(2) बॉल अच्छी तरह गोलाई देते हुए योग्य आकार के पैनल की उचित संख्या से बनी होगी ।

(3) बॉल का मुंह इतना बड़ा होगा कि उसमें हवा भरने वाले पम्प की टोंटी या सुई उसमें समायोजित होने के अनुमत हो, हवा निकालने के लिए उचित साधन दिए गए हों । ब्लैडर की गर्दन मुंह के अन्दर तक पूरी तरह फिट हो ।

4. नेट बॉल के लिए विनिर्देश

1. सामग्री :

चर्म—बॉल का विनिर्माण क्रेता और विक्रेता के मध्य हुए करारा के अनुसार कटी हुई खाल और खुरदरेपन दोनों से मुक्त, सब्जी/अर्धवर्णी या क्रोमशोधित किसी भी रंग में रंग हुए या रंगलेप किए हुए गोचर्म या भैंसचर्म की उचित खाल से किया जाएगा । चर्म शोधन कार्य के अंत में और सुखाने से पहले चमड़े में फफूदी उत्पन्न होने की प्रतिरोधिता को उत्पन्न करने के लिए चमड़े में उचित फास समाविष्ट की जाएगी । ये प्रभावी और अविषैले होंगे । चर्म शोधक चमड़ा तेज द्रव या तैलीय या दोनों का होगा और सतह चिकनी और भलीभांति सेट होगी ।

2. सिलाई के लिए धागा :—

(1) लिनेन धागा—सिलाई के लिए विगलनरोधी और 5 प्लाई वाला प्रयुक्त होगा ।

(2) सूती धागा —98 टक्स (टाँकों), × 8 (6 एम/8) के अनुरूप होगा ।

(3) अस्तरण कपड़ा क्रेता और विक्रेता के मध्य हुए करार के अनुसार होगा ।

3. विमाएं :

(1) जब बॉल में हवा भरी जाए तब बॉल 68 से 71 परिधि लिए हुए आकार में गोल होगी।

(2) पूरे भरे हुए ब्लैडर सहित बॉल का भार 397 से 454 ग्राम होगा।

(3) गोलाई पर परिधि में 1 प्रतिशत की सहयता अनुमत होगी।

4. रंग :—क्रेता के और विक्रेता के मध्य हुए करार के अनुसार होगी।

5. कारीगरी और फिनिश :

(1) बाल लिनेन या सूती धागों से सिली होगी और टांके 24 I 2 प्रति डेसी मीटर होंगे। जब बाल वायु दाब से पूर्ण हो तो दृष्टिगत धागे बाल की सतह से 2 मिली मीटर से अधिक गहरे नहीं होंगे।

(2) बाल अच्छी तरह गोलाई देते हुए योग्य आकारों के पैनल की उचित संख्या में बनी होगी।

(3) मुंह इतना बड़ा होगा कि उसमें हवा भरने वाले पम्प टोंटी या सुई उसके अनुकूल हो तथा हवा निकालने के लिए उचित साधन दिए गए हों। ब्लैडर की गर्दन मुंह के अन्दर तक पूरी तरह से फिट होगी।

5. क्रिकेट और बाल के लिए विनिर्देश

1. सामग्री :

(1) कोर-कोर कर्क की लकड़ी तथा नई ऊन, (3-4 प्लाई) से बनी होगी, 89 टैक्स (टांकों) उसी कपड़े पर धागे से होंगे कर्क की मात्रा तथा ऊन का अनुपात 2 : 1 (±5%) और 5 : 4 (±5%) होनी चाहिए। इसके साथ ही तैयार कर्क का भार 28±3 ग्राम होगा।

(2) कवर—आवरण मोटे चमड़े के उचित भाग से कटे हुए गोचर्म तथा भैंसचर्म से बना होगा। क्रिकेट बाल के लिए कवर चार काठरे में होगा और हाकी बाल के मामलों में 4/2 काठरें में होगी जो संपीड़ित चर्म के अन्दर उचित रूप से मजबूत होगी।

2. सिलाई के लिए धागा : आंतरिक सिलाई के लिए धागा पटसन या सूती अन्य किसी समतुल्य क्वालिटी का होगा।

(1) आंतरिक सिलाई: कटाई के प्रत्येक दो जोड़ों में सिलाई 19 से 22 दिखाई न देने वाले टांकों से होगी और गोलाकार कपों में दबाई जाएगी। सिलाई एकसार होगी।

(2) बाहरी सिलाई: बाहरी सिलाईयों की न्यूनतम संख्या कार्क के तैयार केन्द्र के बिना बालों के मामले में 80, और कार्क के तैयार केन्द्र वाली बालों के मामले में 75 होगी।

3. विमाएं :

(1) परिधि : क्रिकेट और हाकी बालों की परिधि 22.4 सें. मी. और 22.9 सें. मी. के मध्य होगी।

(2) भार : क्रिकेट और हाकी बालों का भार 156 ग्राम और 163 ग्राम के बीच होगा।

4. रंग : क्रिकेट बालों का रंग लाल और हाकी बालों का रंग सफेद होगा।

5 कारीगरी और फिनिश : तैयार बाले गोल होगा। तैयार क्रिकेट बाल पालिश की हुई या चमक दी हुई होगी। तैयार हाकी बाल या तो प्राकृतिक सफेद या कृत्रिम सफेद होगी।

6. क्रिकेट बैट के लिए विनिर्देश

1 सामग्री : प्रयुक्त बाल पर्याप्त हल्का होगा और गड्ढों; धब्बों दरारों या किसी अन्य विनिर्माण दोषों से मुक्त होगा।

2. हैंडल :

(1) हैंडल केन और रबड़ निवेशन के उचित कार्टों से बना होगा। प्रयुक्त केन खोखलेपन, बेधक छिद्रों और कीट आक्रमण से मुक्त होगा।

(2) प्रयुक्त केन का आर्द्रतापन अधिकतम 12 प्रतिशत होगा।

3 विमाएं :

(1) लम्बाई बैट की कुल लम्बाई 840 से 970 मि. मी. के बीच में होगी।

(2) ब्लेड की चौड़ाई: ब्लेड की चौड़ाई 105 और 110 मि. मीटर के बीच में होगी।

(3) हैंडल : जोड़ सहित हैंडल की लम्बाई 425 और 435 मि. मीटर के बीच में होगी।

(4) गोलाई के अधिकतम बिन्दु पर मोटाई-गोलाई के अधिकतम बिन्दु पर मोटाई 61 और 55 मिली मीटर के बीच में होगी।

(5) जोड़ की लम्बाई : क्रिकेट बैट के जोड़ की लम्बाई 125 और 180 मि. मीटर होगी।

(6) हैंडल की परिधि: हैंडल की परिधि 105 और 130 मिली मीटर के बीच में होगी।

4 भार : क्रिकेट बैट का भार 960 और 1100 ग्राम के बीच में होगा।

5. कारीगरी और फिनिश : हैंडल ब्लेड में सुरक्षित और एकसार फिट किया जाएगा। जोड़ सुरक्षित रूप में जुड़े होंगे। हैंडल लम्बाई की ओर रबड़ निवेशित होगा। जिससे कि बैट को लचक दे सके। हैंडल उचित रूप से बंधा होगा और रबड़ की ग्रिप से आवृत होगा। ब्लेड का मुख्य भाग और किनारे अच्छी तरह से गोल होंगे और इसका अग्र और पृष्ट भाग पर्याप्त चिकना होगा।

7. हाकी छड़ों के लिए विनिर्देश

1. ब्लेड : हाकी छड़ों की ब्लेड उपयुक्त लकड़ी से बनी होगी ताकि तैयार ब्लेड का आर्द्रता तत्व 12 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

2. हैंडल : हाकी छड़ों का केन के उपयुक्त काटों से बना होगा। प्रयुक्त केन खोखलेपन बेधक छिद्रों, कीट आक्रमण और धब्बों से मुक्त होगी प्रयुक्त केन का आर्द्रता तत्व 12 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा

3. विमाएं :

(1) लम्बाई: हाकी छड़ की कुल लम्बाई 865 और 965 मिली मीटर के बीच में होगी।

(2) ब्लेड की चौड़ाई: ब्लेड इस तरह से गठित किया जाएगा जिससे कि ये 51 मि. मी. के आंतरिक व्यास के घेरे से निकल सके और 49 मि. मीटर आंतरिक व्यास घेरे से न निकल सके।

(3) जोड़ की लम्बाई: हैंडल ब्लेड में 200 से 226 मिली मीटर लम्बे जोड़ से अच्छी तरह फिट होगा।

4. भार : हाकी छड़ का भार निम्नलिखित में से कोई एक होगा :

. . . . 340—535 ग्राम

. . . . 536—595 ग्राम

. . . . 596—650 ग्राम

. . . . 651—790 ग्राम

5. कारीगरी और फिनिश : हैंडल वैकल्पिक होते हुए काटों और स्वच्छ डिजाइन से बना होगा। जोड़ सुरक्षित रूप से चिपके होंगे। हैंडल पर्मेंट या उपयुक्त कपड़े से पहले लपेटा जाएगा। और फिर स्वच्छ खोल, चमड़े या कैंवा और विक्रेता के मध्य हुए करार के अनुसार आवृत्त होगा। जोड़ में किसी भी कील का प्रयोग नहीं किया जाएगा और छड़ों में धातु की फिनिश नहीं होगी। ब्लेड को खोलने वाली सतह किनारों के साथ समतल होगी और किनारे गोल होंगे। ब्लेड की अच्छी फिनिश और वार्निश होगी।

8. बैडमिंटन रैकेटफ्रेम के लिए विनिर्देश

1. सामग्री :

(1) यह लकड़ी गांठों, दरारों, क्षीणों, धब्बों तथा खुले छिद्रों से मुक्त होगी।

(2) लकड़ी की आर्द्रता तत्व 10 तथा 14% के बीच की होगी।

2. परिमाप :

(1) लम्बाई :—फ्रेम की पूरी लम्बाई शटल कॉक के साथ खेलने के लिए 660 ± 3 मिली मीटर तथा ऊनी गेंद (बाल) के साथ खेलने के लिए 660 मिली मीटर से 675 मिली मीटर तक होगी।

(2) फिनिश के पश्चात् घुमाव की मोटाई—फिनिश के पश्चात घुमाव की अधिकतम तथा न्यूनतम मोटाई क्रमश: 9 मिली मीटर तथा 7 मिली मीटर होगी।

(3) घुमाव के बड़े तथा छोटे सिरे —घुमाव के बड़े तथा छोटे सिरे 235 मिली मीटर तथा 247 मिली मी. तथा 187 मि. मी. तथा 194 मि. मी. के बीच क्रमश: होंगे।

(4) छिद्र —जाली बनाने वाले धागे के लिए छिद्रों की संख्या 66 तथा 72 के बीच में होगी। छिद्रों का व्यास 2 मिली मीटर होगा।

(5) हत्था :—फ्रेम के ग्रिप की लम्बाई 140 तथा 152 मिली मीटर के बीच में होगी।

(6) क्रिसेंट की चौड़ाई :—जैज बिन्दु पर क्रिसेंट की चौड़ाई 11 से 13 मिली मीटर होगी।

(7) वेज :—घुमावों के लिए कम से कम 4 प्लाई प्रयोग की जाएगी।

3. भार —

(1) शटल कॉक खेलने के लिए बैडमिंटन रैकेट फ्रेम का भार 120 ग्राम तथा 160 ग्राम के बीच में होगा।

(2) ऊनी गेंद से बैडमिंटन खेलने के लिए बैडमिंटन रैकेट का भार 175 ग्राम से 200 ग्राम के अन्दर होगा।

4 कारीगरी और फिनिश :—उचित घुमाव बनाने के लिए शेपिंग कलैम्प पर सभी प्लाई को उचित रूप से चिपकाया तथा एक के बाद एक सुरक्षात्मक रूप से फिट किया जाएगा। किनारों को "यू" आकार के आवरण के साथ मजबूत किया जाएगा जो कि झुका होगा तथा आकार को काटेगा नहीं। घुमाव की सतह तथा ऊपरी हिस्सा पूर्ण रूप से गोलाकार तथा हलका होगा। फ्रेम पूर्णत: चिकना, पालिश किया हुआ और उपर्युक्त रूप से कटा हुआ भी होगा। किनारों की तरफ के छिद्र जो कुल संख्या दो तिहाई छिद्रों से कम नहीं होंगे। बाहरी ओर से भी धंसे होंगे। छिद्रों के किनारे उचित रूप से गोल होंगे। स्टील की रॉड जब प्रयोग की जाए तो वह खोखले स्टील ट्यूब से बनी होगी, उपयुक्त रूप से पत्थर चढ़ाया गया हुआ होगा तथा प्रत्येक जोड़ पर सरेस लगा होगा या प्रत्येक जोड़ पर पिन लगी होंगी।

5. परख :—रैकेट मेज पर रखे जाएंगे तथा हैंडल को इस प्रकार दबाया जाएगा कि वह समान अवस्था में रहे। रैकेट का घुमाव मेज की तरह वर्गाकार होगा तथा रैकेट के किसी भी तरह के विभिन्न तत्स्थानी सिरों पर घुमाव की ऊंचाई बराबर होगी। रैकेट पलटे जाएंगे और पुनः परीक्षित होंगे।

9. टेनिस रैकेट फ्रेम के लिए विनिर्देश

1. सामग्री :—

(1) लकड़ी गांठों, दरारों, क्षणिक धब्बों तथा खुले छिद्रों से मुक्त होगी।

(2) लकड़ी की आर्द्रता तत्व 10 तथा 14 प्रतिशत के मध्य होगी।

2. परिमाप :—

(1) लंबाई—टेनिस रैकेट फ्रेम की पूरी लंबाई 685 ± 5 मिली मीटर होगी।

(2) फिनिश के पश्चात् घुमाव की मोटाई—फिनिश के पश्चात् घुमाव की मोटाई अधिकतम तथा न्यूनतम मोटाई क्रमश: 16 मिली मीटर तथा 12 मि. मीटर होगी।

(3) घुमाव के बड़े तथा छोटे सिरे—घुमाव के अन्दरूनी बड़े तथा छोटे सिरे 265 ± 5 मिली मीटर तथा 210 ± 5 मि. मीटर क्रमश: होंगे।

(4) छिद्र—जाल बनाने के लिए धागों की संख्या 62 तथा 66 के बीच में होगी। छिद्रों का व्यास दो जाली धागे के लिए 3 मि. मीटर तथा एक जाली धागे के लिए 2.5 मि. मी. होगा।

(5) हत्था—टेनिस, रैकेट फ्रेम के हत्थे की लंबाई 150 मि.मी. तथा 165 मि. मी. के मध्य होगी। हत्थे का घेरा 100 मि. मी. तथा 130 मि. मी. के बीच में होगा।

(6) क्रिसेंट की चौड़ाई—क्रिसेंट की चौड़ाई थेजबिन्दु पर 20 से 22 मि.मी. होगी।

(7) वेज—वेज के लिए कम से कम 5 प्लाई प्रयोग की जाएगी।

3. भार—टेनिस रैकेट फ्रेम का भार 350 ग्राम तथा 410 ग्राम के अन्दर होगा।

4. कारीगरी तथा फिनिश :—उचित घुमाव देने के लिए शेपिंग क्लैम्प पर सभी प्लाइयों को उचित रूप से चिपकाया तथा एक के बाद एक सुरक्षात्मक रूप से फिट किया जाएगा। किनारे को "यू" आकार के आवरण के साथ मजबूत किया जाएगा जो कि झुका होगा तथा कटे हुए आकार में नहीं होगा। घुमाव की सतह तथा इसके मुख का ऊपरी हिस्सा पूर्णरूप से गोलाकार तथा हलका होगा। फ्रेम की सतह चिकनी, चमकदार होगी तथा उपयुक्त झुकाव भी होगा। सभी छिद्र अन्दर धंसे होंगे। किनारों की तरफ के छिद्रों कुल संख्या दो तिहाई छिद्रों से कम नहीं होंगे बाहरी ओर से भी धंसे होंगे। छिद्रों के किनारे उचित रूप से मुड़े होंगे।

5 परख—रैकेट मेज पर रखे जाएंगे। तथा हैंडल को इस प्रकार से दबाया जाएगा कि यह समान अवस्था में रहे। रैकेट का झुकाव मेज पर बराबर होगा तथा रैकेट के दोनों तरफ के विभिन्न तत्स्थानी सिरों पर घुमाव की ऊंचाई बराबर होगी। रैकेट पलटे जाएंगे तथा परीक्षण को दोबारा दोहराया जाएगा।

10. स्क्वॉश रैकेट फ्रेम के लिए विनिर्देश

1 सामग्री :

(1) लकड़ी गांठों, दरारों, क्षीणों, धब्बों तथा खुले छिद्रों से मुक्त होगी।

(2) लकड़ी की आर्द्रता तत्व 9 तथा 12 प्रतिशत के अन्दर होगी।

2 परिमाण .

(1) लंबाई--स्क्वाश रैकेट फ्रेम की पूरी लंबाई 286±5 मि. मी. होगी।

(2) फिनिश के पश्चात् बैंड की मोटाई--फिनिश के पश्चात् घुमाव की अधिकतम तथा न्यूनतम मोटाई क्रमश: 11 मि. मी. तथा 13 मि. मी. होगी।

(3) घुमाव के बड़े तथा छोटे सिरे--घुमाव के बड़े तथा छोटे सिरे 195±5 मि. मीटर तथा 170±5 मि. मीटर क्रमश: होंगे।

(4) छिद्र--छिद्रों की संख्या 54 तथा 56 के अन्दर होगी। प्रत्येक छिद्र का व्यास 1.8 मि० मीटर होगा।

(5) हत्था--स्क्वाश रैकेट फ्रेम का हत्था 140 तथा 170 मि०मी० के अंदर होगा।

(6) क्रिमेट की चौड़ाई--क्रिमेट की चौड़ाई मेज बिंदु पर 15 से 18 मि. मी. होगी।

3. घुमाव:—घुमावों के लिए कम से कम 4 प्लाई प्रयोग की जाएगी।

4 हत्था:--हत्था चमड़े, चर्म कपड़े या क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार बना होगा।

5 कारीगरी तथा फिनिश.--उचित घुमाव बनाने के लिए सभी प्लाईयां उचित रूप से चिपकाई तथा गुणात्मक ढंग से फिट की जाएंगी। फिन्नर "यू" आकार की पट्टी का सरेस की सहायता से फ्रेम प्लाईयों को चिपकाया जाएगा। झुकाव की सतह तथा गर्दन पूर्ण रूप से गोलाकार तथा हलकी होगी। छिद्र के किनारे चिकनाई से मुड़े हुए होंगे। फ्रेम की सतह चिकनी चमकदार तथा संतुलित होगी।

11. बैटिंग दस्तानों के लिए विनिर्देश

1 सामग्री .

(1) क्रिकेट खेलने के बैटिंग दस्तानों के लिए प्रयोग आने वाली सामग्री क्रेता तथा विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होगी।

(2) निर्यात संविदा में विनिर्दिष्ट किसी भी अनुबंध के अभाव में, क्रिकेट बैटिंग दस्तानों के विनिर्माण के लिए सामग्री सुसंगत भारतीय मानक विनिर्देश के अनुरूप होगी।

2 परिमाप .

(1) क्रिकेट बैटिंग दस्तानों का परिमाप क्रेता और विक्रेता के मध्य हुए करार के अनुसार होगा।

(2) निर्यात संविदा में विनिर्दिष्ट किसी भी अनुबंध के अभाव में, क्रिकेट बैटिंग दस्तानों के विनिर्माण के लिए सामग्री सुसंगत भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुरूप होंगे।

3. सिलाई के लिए धागा:

दस्तानों की सिलाई के लिए धागा बेहतर पोंम साइज या सूती, कोर स्पन या अन्य कोई उपयुक्त धागा प्रयुक्त होगा।

4 रंग

विक्रेता तथा क्रेता के मध्य हुए करार के अनुरूप होगा।

5. कारीगरी तथा फिनिश:—दस्ताने कलाईयों में कसे हुए तथा हथेलियों तथा हाथों की अंगुलियों की जड़ों में उपयुक्त फिट होंगे। सिलाई पक्की होगी तथा सामान्य कारीगरी अच्छी क्वालिटी की होगी। दस्ताने पहनने में आरामदेह होंगे तथा बल्लेबाज को कलाईयों तथा अंगुलियों को चलाने में आसानी होगी।

12. क्रिकेट खिलाड़ी तथा विकेटकीपर के टांगों के कवच के लिए विनिर्देश

1. सामग्री:--

(1) क्रिकेट खिलाड़ी तथा विकेटकीपर के टांगों के कवच के लिए प्रयोग आने वाली सामग्री विक्रेता और क्रेता के मध्य हुए करार के अनुसार होगी।

(2) निर्यात संविदा में किसी भी विनिर्दिष्ट अनुबंध के अभाव में, क्रिकेट खिलाड़ी तथा विकेटकीपर के टांगों के कवच के विनिर्माण के लिए सामग्री सुसंगत भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुरूप होगी।

2. परिमाप:

(1) क्रिकेट खिलाड़ी तथा विकेटकीपर के टांगों के कवच के लिए परिमाप विक्रेता तथा क्रेता के मध्य हुए करार के अनुरूप होगा।

(2) निर्यात संविदा में किसी भी विनिर्दिष्ट अनुबंध के अभाव में, क्रिकेट खिलाड़ी तथा विकेटकीपर के टांगों के कवच के विनिर्माण के लिए परिमाप सुसंगत भारतीय मानक विनिर्देश के अनुरूप होंगे।

3. भार --

(1) क्रिकेट खिलाड़ी के लिए टांगों के कवच--क्रिकेट खिलाड़ी के लिए टांगों के कवच का भार 1.5 से 1.8 कि. ग्रा. के बीच प्रति जोड़ा होगा।

(2) विकेट कीपर के लिए टांगों का कवच--विकेट कीपर के लिए टांगों का कवच का भार प्रति एक जोड़ा 1.8 से 2.2 कि. ग्राम के बीच होगा।

4. रंग.--विक्रेता तथा क्रेता के मध्य हुए करार के अनुसार होगा।

5. कारीगरी और फिनिश.--टांगों का कवच जब टांगों से लपेटा जाए तो लचीला होगा तथा खिलाड़ी को हानि नहीं पहुंचाएगा। कैनवस की दोहरी परत, चमड़े तथा अन्य किसी उपयुक्त सामग्री का कवच टांगों के रखने वाले भाग को सुरक्षा देने के लिए दिया जाएगा इन-स्टेप का छोर उपयुक्त रूप से गद्देदार होगा। प्रत्येक टांगों के कवच में सात धारियां होंगी।

13 खेलने के प्रयोग के लिए उदर कवच के लिए विनिर्देश

1. सामग्री:--

(1) प्लास्टिक-उदर कवच के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक विशेषत: यूरिया फार्मोल्डिहाइड होगा या क्रेता और विक्रेता के मध्य हुए करार की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए अन्य कोई उपयुक्त प्लास्टिक होगा। प्रयुक्त प्लास्टिक अक्षोभक तथा अविषैला होगा।

(2) चमड़ा:--उदर कवच के लिए प्रयोग किया गया चमड़े का जब चाक्षुष निरीक्षण हो तो कोई भी फफूंदी की वृद्धि दिखाई नहीं देनी चाहिए। यह चिकनी प्रलाक्षा या तैलीय या दोनों का होगा।

2. परिमाप

(1) धातु निवेश के लिए काली प्लेट--काली प्लेट की कम से कम 0.56 मि. मीटर की मोटाई होगी।

(2) इलास्टिक टेप--उदर कवच के लिए प्रयोग किए गए इलास्टिक टेप की चौड़ाई 20 से 25 मिली मीटर के बीच होगी।

(3) चमड़े की मोटाई--उदर कवच के तैयार प्रक्रम में चमड़े की मोटाई 0.7 से 1.0 मिली मीटर के बीच में होगी।

(1) टाकों की लम्बाई—सभी टांके 10 तथा 15 मिली मीटर के बीच में होंगे ।

3 कारीगरी तथा फिनिश —प्लास्टिक उदर कवच साफ आकार के होंगे तथा दरारें, फफूंदी क्षति तथा अन्य कोई विनिर्माण दोषों से मुक्त होंगे । इसकी सतह चिकनी होगी । उदर कवच में धातु निवेश के टुकड़ों से बना होगा, तथा प्रयाप्त मजबूती देते हुए उपयुक्त स्लिप भी होंगे । यह चमड़े से उचित रूप से ढके हुए होंगे तथा उदर कवच का सामने का भाग उचित रूप से धातु निवेश पर चमड़े से चिपकाई होगी तथा भीतरी चमड़ा उचित रूप से कसा होगा । टांके पक्के और उचित होंगे तथा टांके कसे हुए होंगे । गाई बिना प्लास्टिक टैप के भी कवच हो सकते है । प्लास्टिक टैप यदि प्रयोग हो तो यह चमड़े के स्ट्रैप तथा उचित रूप से कवच मिले हुए होंगे ।

4 रंग.—विक्रेता तथा क्रेता के मध्य हुए करार के अनुसार।

5. परख :—

(1) कवच को अस्तरण सतह को छूते हुए समतल सतह पर रखें। 10 कि. ग्राम का भार 150 मि. मीटर की ऊंचाई से कवच पर गिराया जाए । यह दस बार किया जाएगा । कवच परख के अन्त तक नहीं टूटेगा ।

(2) 250 मि मी. लम्बा प्लास्टिक टैप का टुकड़ा लें । इस टुकड़े को 875 मि. मी. की लम्बाई तक खींचे तथा छोड़ें । यह तेज गति में 50 बार दोहराया जाए । इस परीक्षण के खत्म होने पर, इस टैप की लम्बाई नापें 25 मि. मी. से अधिक लम्बाई नहीं बढ़नी चाहिए ।

14. खेलने की सभी वस्तुओं के लिए नमूना लेना तथा अनुरूपता के लिए मापदंड :—प्रत्येक परेषण के लिए नमूना लेने तथा अनुरूपता का मानदंड नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगा :—

सारणी

लॉट आकार	चाक्षुक्ष तथा परिमापिय जांच के लिए नमूने का आकार	अन्य सभी परिक्षणों अनुज्ञेय के लिए नमुना आकार में से लिए जाने वाले उप-नमूना आकार	दोषों की संख्या	
			स्तंभ 2 के लिए	स्तंभ 3 के लिए
50 तक	3	1	0	0
51 से 100	5	5	0	0
101 से 300	8	2	0	0
301 से 500	13	3	1	0
501 से 1000	20	3	1	0
1001 से 3000	32	5	2	1
30001 से ऊपर	50	6	3	1

चिह्न :—जब तक कि विदेशी क्रेता द्वारा अन्यथा अनुबंधित न हो, टुकड़ों पर सुपाठ्य रूप से विनिर्माता का नाम, व्यापार चिह्न या पहचान चिह्न अंकित होंगे।

पैकिंग : टुकड़े क्रेता के अनुबंध के अनुसार इस ढंग से पैक किए जाएंगे जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि उत्पाद बिना किसी नुकसान के गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए।

अनुसूची

नियंत्रण का स्तर

[नियम 4 (2क) देखिए]

क्रम सं.	अपेक्षाएं	निर्देश	परख के लिए नमूनों की संख्या	लॉट आकार
1.	सामग्री	प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एस. क्यू. सी. के आधार पर पर्याप्त नंबर	प्रत्येक परेषण
2.	कारीगरी तथा फिनिश	प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	प्रत्येक	प्रत्येक बैच उत्पादन
3.	विमाओं सहित सहायता	प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	प्रत्येक	प्रत्येक बैच उत्पादन

1 2	3	4	5
4. भार	प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	प्रत्येक	प्रत्येक बैच उत्पादन
5. रंग	प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	प्रत्येक	प्रत्येक बैच उत्पादन
6. परीक्षण	प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	अभिलिखित जांच के आधार पर पर्याप्त संख्या	प्रत्येक बैच उत्पादन
7. पैकिंग * रूप सज्जा **ड्रॉप परख ***जल छिड़काव (यह परख नालीदार तंतु बोर्ड पैकिंग प्रयोग के लिए वर्जित किया जाएगा।) **** रोलिंग परख	क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट के अनुसार या राष्ट्रीय मानक के अनुसार	अभिलिखित जांच के आधार पर पर्याप्त संख्या	प्रत्येक परेषण

* रूप सज्जा—पैकेजों की फिनिश अच्छी होगी तथा पैकेज देखने में सुन्दर होंगे।

** ड्रॉप परख—ड्रॉप परख (37 कि. ग्राम तक के मुख्य भार तक निर्बन्धित) 150 सें. मी. की ऊंचाई से गिराया जाने वाला पैकेज एक बार बड़ी समतल सतह पर, एक बार लंबे किनारे पर और एक बार उसके किसी भी कोने पर गिराया जाएगा।

*** जल फुहार परीक्षण—पैकेज को एक मिनट के लिए सामान्य आकस्मिक मानसून बौछार के समतुल्य जल फुहार में रखा जाएगा।

**** रोलिंग परीक्षण—(केवल 500 कि. ग्राम की भार तक निर्बन्धित) पैकेजों को किसी भी ओर से 6 मीटर आगे की तरफ तथा 6 मीटर पीछे की तरफ या 12 मीटर एक ही दिशा में पैक किया जाएगा।

[मिसिल सं. 6/(11)/84-ई आई एण्ड ईपी]

एन.एस. हरीहरन, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 21st September, 1985

S.O. 4392.—Whereas in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India that sports goods should be subject to quality control and inspection prior to export ;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 ;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within forty five days of the date of publication of this Order in the Official Gazette to Export Inspection Council of India (Ministry of Commerce, Government of India), 11th floor, Pragati Tover, 26, Rajendra Place, New Delhi-110008.

PROPOSALS

(1) to notify that sports goods shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) to specify the type of quality control and inspection in accordance with the draft Export of the Sports Goods (Quality Control and Inspection) Rules, 1984 as set out in Annexure-I to this Order as the type of quality control and inspection which shall be applied to such sports goods prior to their export ;

(3) to recognise—

(a) relevant Indian Standard or any other national and international standards,

(b) standards of other bodies recognised by Export Inspection Council ;

(c) the contractual specifications subject to the product specifying the minimum of the specification set out in Annexure-II to this Order.

(4) to prohibit the export in the course of international trade of such sports goods unless the same are accompanied by a certificate of inspection issued by any of the agencies by the Central Government or established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that the sports goods conform to the standard specifications and are exportworthy.

2. Nothing in this Order shall apply to the export by land, sea or air of bonafide samples of sports goods to the prospective buyers provided the F.O.B. value of the samples does not exceed rupees five hundred.

3. In this Order, sports goods shall mean any of the article given below :—

1. Balls

(a) Football
(b) Volleyball
(c) Basket Ball
(d) Net Ball

2. Cricket and Hockey Balls

3. Cricket Bats

4. Hockey sticks

5. Rackets
(a) Badminton
(b) Tennis
(c) Squash

6. Protective Devices
(a) Batting Gloves
(b) Leg Guards for Wicket Keeper and Batsman
(c) Abdomen Guards

ANNEXURE—I

Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Exports of Sports Goods (Quality Control and Inspection) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) ;

(b) "Agency" means any of the Export Inspection Agencies established under section 7 of the Act at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras ;

(c) "Appendix" means the appendix to these rules ;

(d) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act ;

(e) "Schedule" means the schedule appended to these rules ;

(f) "sports goods" shall mean any of the articles given below :—

1. Balls
(a) Football
(b) Volleyball
(c) Basket Ball
(d) Net Ball

2. Cricket and Hockey Balls

3. Cricket Bats

4. Hockey Sticks

5. Rackets
(a) Badminton
(b) Tennis
(c) Squash

6. Protective Devices
(a) Batting Gloves
(b) Leg guards for Wicket Keeper and Batsman
(c) Abdomen Guards.

3. Basis of Inspection—Inspection of the sports goods shall be carried out with a view to ensuring that the quality of the sports goods conform to the specification recognised by the Central Government under section 6 of the Act, namely :—

(a) relevant Indian Standard or any other national and international standards.

(b) standards of other bodies recognised by the Export Inspection Council.

(c) the contractual specifications subject to the product meeting with the minimum of the specifications set out in Annexure-II.

4. Procedure of Inspection—(1) Inspection of the sports goods shall be carried out with a view to seeing that the sports goods conform to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act.

either

(a) by ensuring that during the process of manufacture the Inprocess Quality Control drills as specified in Appendix under sub-rule 2(b) of rule 4 have been exercise.

OR

(b) on the basis of inspection carried out in accordance with sub-rule 2(b) or rule 4.

OR

(c) by both.

(2) Any one or both of the following schemes shall be adopted namely :—

(a) In-process Quality Control (IPQC)

(i) any manufacturing unit having adequate IPQC as per Appendix shall apply to the nearest office of the Agency.

(ii) the agency shall then arrange a visit to the manufacturing unit and assess as to whether an effective IPQC system is existing therein, or

(b) Consignmentwise Inspection :

Any manufacturing unit not satisfying the requirements specified in clause (a) shall offer to any agency established or recognised under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 their export consignment for Inspection which shall be done to ensure that the product manufactured by it conforms to the specifications recognised by Central Government under section 6 of the Act.

(3) Any exporter intending to export a consignment of the sports goods shall give an intimation in writing of his intention so to do and submit alongwith such intimation a declaration of the specification giving details of all technical characteristics as stipulated in the export contract relating to such export to any of the Agencies to enable it to carry out inspection in accordance with clause (a) or clause (b) or both the clauses of sub-rule (2) of rule 4.

(4) For export of the sports goods, manufactured by units approved under clause (a) of sub-rule (2) the exporter shall also furnish alongwith such intimation a declaration that the sports goods intended for export have been manufactured by exercising adequate quality control as laid down in Appendix and that the consignment conforms to the requirements of the specifications recognised under section 6 of the Act for this purpose.

(5) Every intimation and declaration under sub-rule (2) and (4) shall reach the office of the Agency not less than three days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises.

(6) The exporter shall furnish to the Agency the identification marks applied on the consignment to be exported.

(7) On receipt of the intimation and declaration, the Agency—

(a) in the case of an exporter exporting products manufactured by units approved under clause (a) of sub-

rule (2) of rule 4 on satisfying itself that during the process of manufacture the unit has exercised adequate quality control as provided under the Appendix and followed the instructions, if any, issued by the Council in this regard, shall within three days issue a certificate declaring the consignment as export worthy. However, the Agency shall ensure through periodic inspection and spot-checks that adequate controls are exercise at the manufacturing premises and products conform to the recognised specification ; and

(b) in case of exporter exporting products manufactured by units falling under clause (b) of sub-rule (2) of rule 4 shall carry out inspection of the sports goods with a view to ensuring that the product conforms to the specifications recognised for the purpose.

(c) After completion of inspection, the Agency shall immediately seal packages in the consignment in a manner so as to ensure that the sealed packages cannot be tampered with.

(d) In case of rejection of a consignment, if the exporter so desires, the consignment may not be sealed by the Agency.

(e) In such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer any appeal against the rejection.

(f) If the Agency is satisfied that the consignment of the sports goods complies with the requirement under these rules it shall within three days of completion of inspection issue a certificate to the exporter declaring that the consignment is exportworthy :

Provided that where the Agency is not so satisfied it shall refuse to issue a certificate to the exporter declaring the consignment of sports goods as exportworthy and communicate such refusal within seven days to the exporter alongwith the reason therefor.

5. Place of Inspection—Every inspection under these rules shall be carried out either (a) at the premises of the manufacturer of such products, or (b) at the premises at which the goods are offered by the exporter provided adequate facilities for inspection and testing exists therein.

6. Inspection fee—Inspection fee shall be paid by the exporter to the Agency as under :—

(i) (a) For exports under inprocess quality control at the rate of 0.2% of the F.O.B. value subject to minimum of Rs. 20 per consignment.

(b) For exports under consignmentwise inspection at the rate of 0.4% of the F.O.B. value subject to a minimum of Rs. 20 per consignment.

(ii) Subject to a minimum of Rs. 20 per consignment the rate shall be 0.18% and 0.36% for (a) and (b) respectively for manufacturer-exporters who are registered as Small Scale Manufacturing Units with the concerned Governments of State/Union Territories.

(iii) For exports of items manufactured by the units having adequate inprocess quality control levels and exported by merchant exporters at the rate of 0.3% of F.O.B. value subject to a minimum of Rs. 20 per consignment.

7. Appeal—

(i) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under clause (f) of sub-rule (7) of rule 4 may within ten days of the receipt of the communication of such refusal, prefer an appeal to a panel of Experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

(ii) The Panel shall consist of atleast two thirds of non-officials of the total membership of the Panel of Experts.

(iii) The quorum for the Panel of Experts shall be three.

(iv) The appeal shall be disposed of within fifteen days of its receipt.

APPENDIX

[See rule 4 (4)]

Every manufacturer of sports goods shall ensure quality control of the sports goods by effecting the following controls at different stages of manufacture, preservation and packing of the products as laid down below together with the levels of control as set down in the Schedule appended hereto.

1. Bought out materials and components control :

(a) Purchase specification shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of materials or components to be used and the detailed dimensions thereof with tolerances.

(b) The accepted consignments shall be either accompanied by a producer's test certificates corroborating the requirements of the purchase specifications or in the absence of such test certificate, samples from each consignment shall be regularly tested to check up its conformity to the purchase specifications. The producer's test certificate shall be counterchecked at least once in five consignments to verify the correctness.

(c) The incoming consignment shall be inspected and tested for ensuring conformity to purchase specifications against statistical sampling plans.

(d) After inspection and tests are carried out, systematic methods shall be adopted for proper segregation and disposal of defective goods.

(e) Adequate records in respect of the above mentioned controls shall be systematically maintained.

2. Process Control :

(a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturers for various processes of manufacture.

(b) Equipment and instrumentation facilities shall be adequate to control the process as laid down in process specification.

(3) Product Control :

(a) The manufacturer shall either have his own testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to test the product as per the Sandard Specification.

(b) Sampling (whenever required) for testing shall be based on recorded investigations.

(c) Adequate records in respect of test carried out shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

4. Meteorological Control—Gauges and instruments used in the production and inspection shall be periodically checked or calibrated and records shall be maintained in the form of history cards.

5. Preservation Control :

(a) A detailed specification shall be laid down by the manufacturer to safeguard the product from adverse effects of weather condition.

(b) The product shall be well preserved both during storage and during transit.

6. Packing Control—Specifications shall be laid down for packing the product(s) and as well as for Export packages and the same shall be strictly adhered to.

ANNEXURE-II

1. SPECIFICATION FOR FOOTBALLS

Materials—Leather—The balls shall be manufactured from suitable portion of cowhide or buffalohide, free from flay cuts and grain defects, vegetable/semi-chrome or chrome tanned, dyed in any colour or pigmented as agreed to between the purchaser and the supplier. At the end of tanning operation, and before drying, suitable fungicides shall be incorporated into the leather for promoting resistance to mould growth in the leather, these shall be effective and non toxic. The tanned leather shall be substantially fatlaquored or oiled or both and the surface obtained shall be smooth and well set. The leather used shall have a minimum thickness of 2.0 mm.

2. Thread for Stitching :

(i) Linen thread-Rot-proofed and having 5 plies shall be used for stitching.

(ii) Cotton thread—Shall conform to (98 tax[1]x8 (6sx8)

(iii) Lining Cloth—As agreed to between the buyer and Seller.

3. Dimensions :

(i) When inflated to an air pressure of 0.98 tex (1 kgf/cm²) the balls shall be spherical in shape with circumference of 68 to 71 cm.

(ii) Weight of the ball with inflated bladder shall be 397 to 454 g.

(iii) A tolerance of 1 percent in the circumference on sphericity shall be allowed.

4. Colour—As agreed to between the buyer and seller.

5. Workmanship and Finish :

(i) The balls shall be stitched with linen or cotton threads and shall have 24 ± 2 stitches per decimetre. The stitches shall be well stretched. When the ball is inflated to the air pressure 1 kgf/cm² the visible threads shall be not more than 2 mm deep from the surface of the ball.

(ii) The balls shall be made from a suitable number of panels of shapes capable of giving sphericity.

(iii) The mouth of the balls shall be adequate and permit the nozzle of the inflating pump or needle to be accommodated and suitable means shall be provided to deflate the ball. The neck of the bladder shall be completely inside the mouth.

2. SPECIFICATIONS FOR VOLLEYBALLS

1. Material—Leather—The balls shall be manufatured from suitable portion of cowhide, free from flay cuts and grain defects, vegetable or chrome tanned, dyed in any colour or pigmented. But at the end of tanning operation and before drying, suitable fungicides shall be incorporated into the leather for promoting resistance to mould growth in the leather, these shall be effective and non-toxic. The tanned leather shall be substantially fat-laiquored or oiled or both and the surface obtained shall be smooth and well set.

2. Threads for Stitching :

(i) Linen thread-Rot-proofed and having 4 plies shall be used for stitching.

(ii) Cotton thread—Shall conform to 98 tex x8 (6s/8)

(iii) Lining cloth—As agreed to between the buyer and the seller.

3. Dimensions :

(1) When inflated to an air pressure of 0.48 to 0.52 kgf/cm² the ball shall be spherical in shape with circumference of 65 to 67 cm.

(2) Weight of the ball with inflated bladder shall be 260 to 80 g.

(3) A tolerance of 1 percent in the circumference on sphericity shall be allowed.

4. Colour—As agreed to between the buyer and the seller.

5. Workmanship and Finish :

(1) The balls shall be stitched with linen or cotton threads and shall have 24 ± 2 stitches per decimetre. The stitches shall be well stretched. When the ball is inflated to an air pressure of 0.48 to 0.52 kgf/cm² the visible threads shall be not more than 2 mm deep from the surface of the ball.

(2) The ball shall be made from a suitable number of panels of shapes capable of giving sphericity.

(3) The mouth shall be adequate to permit the nozzle of the inflating pump or needle to be accomodated and suitable means shall be provided to deflate the ball. The neck of the bladder shall be completely inside the mouth.

3. SPECIFICATIONS FOR BASKETBALLS

1. Materials :

Leather—The balls shall be manufactured from suitable portion of cowhide or buffalohide, free from flay cuts and grain defects, vegetable/semichrome tanned dyed in any colour or pigmented as agreed to between the buyer and the seller. At the end of tanning operation and before drying suitable fungicides shall be incorporated into the leather for promoting resistance to mould growth in the leather, these shall be effective and non toxic. The tanned leather shall be substantially fat laquored or oiled or both and the surface obtained shall be smooth and well set. The leather used shall have a minimum thickness of 2.0 mm.

2. Threads for Stitching :

(1) Linen thread-Rot-proofed and have plies shall be used for stitching.

(2) Cotton thread—Shall conform to 98 tex x8 (6s/8)

(3) Lining Cloth—As agreed to between the buyer and seller.

3. Dimensions :

(1) When inflated to an air pressure of 0.90 kgf/cm², the ball shall be spherical in shape with circumference of 75 to 78 cm.

(2) Weight of the ball with inflated bladder shall be 600 to 650 g.

(3) A tolerance of 1 percent in the circumference on sphericity shall be allowed.

4. Colour—As agreed to between the buyer and seller.

5. Workmanship and Finish :

1. The balls shall be stitched with linen or cotton thread and shall have 24 ± 2 stitches per decimetre. The stitches shall be well stretched. When the ball is inflated to the air pressure of 0.90 kgf/cm², the visible threads shall be not more than 2 mm from the surface of the ball.

2. The balls shall be made from a suitable number of panels of shapes capable of giving sphericity.

3. The mouth of the balls shall be adequate to permit the nozzles of the inflating pump or needle to be accommodated and suitable means shall be provided to deflate the ball. The neck of the bladder shall be completely inside the mouth.

4. SPECIFICATIONS FOR NETBALLS

1. Materials :

Leather—The balls shall be manufactured from suitable portion of cowhide, free from flay cuts and grains defects, vegetable or chrome tanned, dyed in any colour or pigmented as agreed to between the buyer and the seller. But at the end of tanning operation and before drying, suitable fungicides shall be incorporated into the leather for promoting resistance to mould growth in the leather, these shall be effective and non toxic. The tanned leather shall be substantially fat-laquored or oiled or both and the surface obtained shall be smooth and well set.

2. Threads for stitching :

(1) Linen thread-Rot-proofed and having 5 plies shall be used for stitching.

(2) Cotton thread—Shall conform to 98 tex x8 (6s/8)

(3) Lining cloth—As agreed to between the buyer and the seller.

3. Dimensions :

(1) When fully inflated the ball shall have an circumference of 68 to 71 cm and the ball shall be spherical in shape.

(2) Weight of the ball with fully inflated bladder shall be 397 to 454 gm.

(3) A tolerance of 1 percent in circumference on sphericity shall be allowed.

4. Colour—As agreed to between the buyer and the seller.

5. Workmanship and Finish :

(1) The balls shall be stitched with linen or cotton threads and shall have 24 ± 2 stitches per decimetre. When the ball is inflated fully the threads that are visible shall be not more than 2 mm deep from the surface of the ball.

(2) The ball shall be made from a suitable number of panels of shapes capable of giving sphericity.

(3) The mouth shall be adequate and shall permit the nozzle of the inflating pump or needle to be accommodated and suitable means provided to deflate the ball. The neck of the bladder shall be completely inside the mouth.

5. SPECIFICATION FOR CRICKET AND HOCKEY BALLS

1. Materials :

(1) Core—The core shall be made from corkwood and new wool, (3-4 ply), the yarn being 89 tex worsted. The proportion by mass of cork and wool shall either be 2 : 1 (5 percent) or 5 : 4 (±5 percent) alongwith a ready made centre of cork weighing 28 ± 3 gm.

(2) Cover—The cover shall be made from cowhide or buffalohide leather, cut from the suitable portion of butt. The cover shall be in four sections for cricket balls and in 4/2 sections in case of hockey balls which shall be suitably reinforced inside with compressed leather.

2. Thread for Stitching :

The thread used for inner stitching shall be flax or cotton or of any other equivalent quality.

(1) Inner stitching—The two pairs of sections shall be invisibly stitched with 19 to 22 stitches each and pressed into spherical cups. The stitches shall be even.

(2) Outer stitching—The minimum number of outer stitches shall be 80 in the case of balls without ready made centre of cork, and 75 in the case of balls with ready made centre of cork.

3. Dimensions :

(1) Circumference—The circumference of the cricket and Hockey balls shall be between 22.4 cm and 22.9 cm.

(2) Weight—The weight of Cricket and Hockey balls shall be between 156 g. and 163 g.

4. Colour—The colour shall be red in the case of cricket balls and white in the case of hockey balls.

5. Workmanship and Finish—The finished ball shall be round. The finished cricket balls shall be polished or given a shine. The finished hockey balls shall be either natural white or finished white.

6. SPECIFICATION FOR CRICKET BATS

1. Materials—The willow used shall be well seasoned and free from knots, splits, cracks and any other manufacturing defects.

2. Handle :

(1) The handle shall be made of suitable sections of cane and rubber insertions. The case used shall be free from hollowness, borer holes and insect attack.

(2) Moisture content of cane used shall be 12 percent. maximum.

3. Dimensions :

(1) Length—Overall length of the bat shall be between 840 and 970 mm.

(2) Width of blade—Width of the blade shall be between 105 and 110 mm.

(3) Handle—Length of handle including the joint shall be between 425 and 435 mm.

(4) Thickness at the maximum point of roundness—Thickness at the maximum point of roundness shall be between 61 and 65 mm.

(5) Length of the Joint—The length of the joint of the Cricket bat shall be between 125 and 180 mm.

(6) Circumference of handle—The circumference of the handle shall be between 105 and 130 mm.

4. Weight—The weight of the Cricket bat shall be between 960 and 1100 gms.

5. Workmanship and Finish—The handle shall be fitted securely and firmly into the blade. The joint shall be securely glued. The handle shall be provided with rubber insertions along the length so as to give resilience to the bat. The handle shall be suitably bound and covered with rubber grip. The face and edges of the Blade shall be well rounded and its face and the back shall be ground smooth.

7. SPECIFICATION FOR HOCKEY STICKS

1. Blade—The blade of the hockey stick shall be made from suitable timber so that the moisture content of the finished blade shall not exceed 12 percent.

2. Handle—The handle of the hockey stick shall be made of suitable sections of cane. The cane used shall be free from hollowness, borer holes, insect attack and split. Moisture content of the cane used shall not exceed 12 percent

3. Dimensions :

(1) Length—Overall length of the hockey stick shall be between 865 and 965 mm.

(2) Width of the Blade—The blade shall be so constructed that it passed through a ring of 51 mm internal diameter and not through a ring of 49 mm internal diameter.

(3) Length of the Joint—The handle shall be securely fitted into the blade with a joint of 200 to 225 mm long.

4. Weight—The weight of the hockey stick shall be one of the following :—

340—535 g.

536—595 g.

596—650 g.

651—790 g.

5. Workmanship and Finish—The handle shall be built up from section, rubber insertions being optional. The joint shall be securely glued. The handle shall be first wrapped with parchment or suitable cloth and then covered with rubber sleeve, leather, or as agreed to between the buyer and the seller. No nails shall be used in the joint and the sticks shall have no metal fittings. The playing surface of the blade shall be flat with edges and corners rounded. The blade shall be smooth finished and varnished.

8. SPECIFICATION FOR BADMINTON RACKET FRAMES

1. Material :

(1) The timber shall be free from knots, cracks, decay, stains and open splits.

(2) The moisture content of the timber shall be between 10 and 14 percent.

2. Dimensions :

(1) Length—The full length of the frame shall be 660 ± 3 mm for play with shuttlecock and 660 mm to 675 mm for play with woolen balls.

(2) Thickness of the bend after finish—The maximum and the minimum thickness of the bend after finish shall be 9 mm and 7 mm respectively.

(3) Major and Minor Axis of the Bend—The major and minor axis of the bend shall be between 235 mm and 247 mm and between 187 mm and 194 mm respectively.

(4) Holes—The number of holes for stringing the gut shall be between 66 and 72. The diameter of the holes shall be 2 mm.

(5) Grip—The grip of the frame shall be between 140 and 152 mm in length.

(6) Width of the crescent—Width of the crescent on the wedge point shall be 11 to 13 mm.

(7) Bends—A minimum of 4 plies shall be used for the bends.

3. Weight :

(1) The weight of the badminton racket frame for shuttle cock play shall be between 120 g. and 160 g.

(2) The weight of the badminton racket frame for woolen ball badminton play shall be between 155 g. and 220 g.

4. Workmanship and Finish—All the plies shall be properly glued and fitted securely one by one on the shaping clamps to form proper bends. Shoulders shall be reinforced with 'U' shape overlay which shall be bent and not cut to shape. The surface of the bends and the throat shall be thoroughly rounded or beveled. The frame shall be ground smooth, polished and shall be suitably trimmed also. All holes shall be countersunk from inside. Holes on the shoulder side, not less than one-third of the total number of holes, shall be counter-sunk from outside too. Edges of the holes shall be smoothly rounded off. The steel shaft when used shall be made of hollow steel tube, suitably plated or painted and shall be glued at each joint or pinned at each joint.

5. Test—The racket shall be placed on a table and the handle pressed so that it rests evently. The bend of the racket shall be square with the table and height of the bend at various corresponding points on either side of the racket shall be equal. The racket shall be reversed and the test repeated.

9. SPECIFICATION FOR TENNIS RACKET FRAMES

1. Material :

(1) The timber shall be free from knots, cracks, decay stains and open splits.

(2) The moisture content of the timber shall be between 10 and 14 percent.

2. Dimensions :

(1) Length—The full length of the tennis racket frame shall be 685 ± 5 mm.

(2) Thickness of the Bend After Finish—The maximum and the minimum thickness of the bend after finish shall be 16 mm and 12 mm respectively.

(3) Major and Minor Axis of the Bend—The inside major and minor axis of the bend shall be 265 ± 5 mm and 210 ± 5 mm respectively.

(4) Holes—The number of holes for stringing the gut shall be between 62 and 66. The diameter of the holes shall be 3 mm for two-gut string and 2.5 mm for one-gut string.

(5) Grip—The grip of the tennis racket frame shall be between 150 mm and 165 mm length. The girth of the grip shall be between 100 mm and 130 mm.

(6) Width of the cresent—The width of the cresent on the wedge point shall be 20 to 22 mm.

(7) Bends—A minimum of 5 plies shall be used for the bends.

3. Weight—The weight of the tennis racket frame shall be between 350 g. and 410 g.

4. Workmanship and Finish—All the plies shall be properly glued and fitted securely one by one on the shaping clamps to form proper bends. Shoulders shall be reinforced with 'U' shape overlay which shall be bent and not out to shape. The surface of the bends and the throat shall be thoroughly rounded of beveled. The frame shall be ground smooth polished, and shall be trimmed suitably. All holes shall be countersunk from inside. Holes on the shoulder side, not less than one-third of the total number of holes, shall be counter-sunk from outside too. Edges of the holes shall be smoothly rounded off.

5. Test—The racket shall be placed on a table and the handle pressed so that it tests evently. The bend of the racket shall be square with the table and the height of the bend at various corresponding points on either side of the racket shall be equal. The racket shall be reversed and the test repeated.

10. SPECIFICATION FOR SQUASH RACKET FRAMES

1. Material :

(1) The timber shall be free from knots, cracks, decay, and stains and open splits.

(2) The moisture content of the timber shall be between 9 and 12 percent.

2. Dimensions :

(1) Length—The full length of the squash racket frames shall be 685 ± 5 mm.

(2) Thickness of the bend after finish—The maximum and minimum thickness of the bend after finish shall be 11 mm and 13 mm respectively.

(3) Major and Minor Axis of the Bend—The inside major and minor axis of the bend shall be 195 ± 5 mm and 170 ± 5 mm respectively.

(4) Holes—Number of holes shall be between 54 and 56. The diameter of each hole shall be 1.8 mm.

(5) Grip—The grip of the squash racket frame shall be between 140 and 170.

(6) Width of the crescent—The width of the cresent on the wedge point shall be 15 to 18 mm.

3. Bend—A minimum of 4 plies shall be used for the bend.

4. Grip—The grip shall be made of leather, leather cloth or as agreed to between the buyer and the seller.

5. Workmanship and finish—All the plies shall be properly glued and fitted securely to form proper bend. The shoulders shall be reinforced with 'U' shape face plates by the help of glue. The surface of the bends and the throat shall be thoroughly rounded or beveled. The edges of the holes shall be smoothly rounded off. The frame shall be ground smooth, polished and trimmed.

11. SPECIFICATION FOR BATTING GLOVES

1. Materials :

1. The materials used for Cricket batting gloves shall be as agreed to between the buyer and seller.

2. In the absence of any specific stipulation in the export contract, the material for manufacture of Cricket Batting Gloves shall conform to relevant Indian Standard Specification.

2. Dimensions :

1. Dimensions of Cricket batting Gloves shall be as agreed to between the buyer and the seller.

2. In the absence of any specific stipulation in the export contract, the dimensions for manufacture of cricket batting gloves shall conform to the relevant Indian Standard speification.

3. Thread of Stitching—The thread for stitching of gloves shall preferably be polymide or cotton core-spun or any other suitable thread.

4. Colour—As agreed to between the buyer and seller.

5. Workmanship and Finish—The gloves shall be tight on the hands and fit the hands and the roots of the fingers of the hands properly. Stitching shall be strong and the general workmanship shall be of good quality. The gloves shall be conmfortable to wear and shall give freedom of movement to the fingers and the wists of the batsman.

12. SPECIFICATION FOR LEG GUARDS FOR CRICKET BATSMAN AND WICKET KEEPERS

1. Material :

(1) The material used for leg guards for cricket batsman and wicket keepers shall be as agreed to between the buyer and the seller.

(2) In the absence of any specific stipulation in the export contract, the material for manufacture of leg guard for cricket batsman and wicket keeper shall conform to relevant Indian Standard Specification.

2. Dimensions :

(1) Dimensions of leg guard for Cricket Batsman and Wicket Keeper shall be as agreed to between the buyer and the seller.

(2) In the absence of any specific stipulation in the export contract, the dimensions for manufacture of leg guard for cricket batsman and wicket keeper shall conform to relovant Indian Standard Specification.

3. Weight :

(1) Leg guards for cricket batsman—The weight of leg guards for cricket batsman shall be between 1.5 to 1.8 kg. per pair.

(2) Leg guards for wicket keepers—The weight of leg guards for wicket keepers shall be between 1.8 to 2.2 kg. per pair.

4. Colour—As agreed to between the buyer and the seller.

5. Workmanship and Finish—Leg guard shall be flexible when tied round the leg and shall not inpair the player. The ankle portion of the leg guard may be given double layer of canvas, leather or any other suitable material. The arch of the instep shall be properly padded. Each leg guard shall have seven ribs.

13. SPECIFICATION FOR ABDOMEN GUARDS FOR SPORTS USE

1. Material :

(1) Plastics—Plastics used for the manufacture of abdomen guards shall preferably be urea formaldehyde or any other suitable plastics satisfying the requirements as agreed to between the buyers and sellers. The plastic used shall be nonirritant and nontoxic.

(2) Leather—The leather used for abdomen guards shall not show any growth of mildew when examined visually. It shall be fat-lacquered or oiled or both.

2. Dimensions :

(1) Black Plate for Metal Insert—Black plate shall have a minimum thickness of 0.56 mm.

(2) Elastic Tape—The width of the elastic tape used for abdomen guards shall be between 20 to 25 mm.

(3) Thickness of Leather—The thickness of leather in the finished stage of abdomen guards shall be between 0.7 to 1.0 mm.

(4) The length of stitches—Each stitches shall be between 10 and 15 mm.

3. Workmanship and Finish—The plastic abdomen guard shall be cleanly moulded and shall be free from cracks, moulding flaws and any other manufacturing defects. It shall have a smooth surface. The metal insert in the abdomen guard shall be made of one piece and shall have suitable ribs for providing sufficient strength. It shall be properly covered with leather and the front side of the abdomen guard shall be properly glued with the leather to the metal insert and inner leather shall be properly taut. The stitching shall be sound and proper and the stitches shall be taut. The guards can be supplied without the elastic tapes also. The elastic tapes, if used, shall have leather straps and buckless properly stitched to it.

4. Colour—As agreed to between the buyer and the seller.

5. Tests :

(1) Keep the guard on a flat surface with the lining touching the surface. Drop a weight of 10 kg. from a height of 150 mm on the guard. This shall be done ten times. The guard shall not be damaged at the end of the test.

(2) Take a piece of the elastic tape 250 mm long. Stretch this piece to a length of 875 mm and release. This shall be done 50 times in rapid succession. On completion of the test, measure the length of the tape, the increase in length shall be not more than 25 mm.

14. SAMPLING AND CRITERIA FOR CONFORMITY FOR ALL SPORTS GOODS

Sampling for inspection of each consignment and the criteria for conformity shall be in accordance with the table given below :—

TABLE

Lot size	Sample-size for visual & dimensional check	Sub-sample size be drawn out of sample size for all other tests	Permissible No. of defects	
			For Col. 2	For Col. 3
Upto 50	3	1	0	0
51 to 100	5	1	0	0
101 to 300	8	2	0	0
301 to 500	13	3	1	0
501 to 1000	20	3	1	0
1001 to 3000	32	5	2	1
3001 to above	50	6	3	1

Marking --Unless otherwise stipulated by the foreign buyer, pieces shall be legibly marked with the manufacturer's name trade mark or identification.

Packing—Pieces shall be packed in accordance with the stipulation of the buyer in such a manner as to ensure safe arrival at the destination without any damage.

SCHEDULE

LEVELS OF CONTROL

[See Rule 4 (2a)]

Sl. No.	Requirements	Reference	No. of samples to be tested	Lot size
1.	Material	Standard specification recognised for the purpose	Adequate no. based on SQC	Each consignment.
2.	Workmanship Finish	—do—	Each	Each batch production.
3.	Dimension with tolerances	—do—	—do—	—do—
*4.	Weight	—do—	—do—	—do—
5.	Colour	—do—	—do—	—do—
6.	Tests	—do—	Adequate no. based on a recorded investigation	—do—
7.	Packing	As specified by the buyer or as per national standard.	—do—	Each consignment.

*Appearance

**Drop Test

***Water Spraying test

(This test may be excluded for packing using corrugated fibre board).

****Rolling Test

*Appearance —The packages shall be well finished and have a good appearance.

**Drop Test —Drop test (to be restricted to head load upto 37 Kgs). The package to be dropped from a height of 150 cms. Once on the largest at surface, once on the largest edge and once on any corner of its own.

***Water Spraying Test—The packages to be exposed against a water spray equivalent to a normal sudden monsoon shower for five minutes.

****Rolling Test—Rolling Test (to be restricted upto a weight of 500 kg The package to be subjected to rolling on its sides either 6 metres forward and 6 metres backward or twelve metres in one direction only.

[F. No. 6(11)/84-EI&EP]

N. S. HARIHARAN, Director.

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1985

का. आ. 4393.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के अनुलग्नक में उल्लिखित उपक्रमों के पंजीकरण को उक्त उपक्रमों के वह उपक्रम होने पर, जिन पर उक्त अधिनियम के अध्याय—III के भाग-क के उपबन्ध अब लागू नहीं होते हैं, के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं. 16/12/85—एम.-3]

एल. सी. गोयल, अवर सचिव

अधिसूचना सं. 16/12/85-एम.—3 का अनुलग्नक

क्रम सं.	उपक्रमों का नाम	पंजीकृत पता	पंजीकरण संख्या
1.	हर्ष इन्वैस्टमैन्ट्स लि.	9 ब्राबोर्न रोड, कलकत्ता 700001	2323/85
2.	मर्स डवलपर्स एण्ड कन्स्ट्रक्टर्स लि.	—यथोपरि—	2324/85
3.	श्री विन्ध्या पेपर मिल्स लि!	श्री ज. जं. सोमानी मार्ग, पंजाक नासिक रोड-422101	1403/78
4.	ट्रावनकोर इलैक्ट्रो केमिकल्स इंडस्ट्रीज लि.	पो. आ. चिंगवानम 686531 जि. कोटायाम (केरल)	1405/78
5.	दि एन्फल्ड इंडिया लि	सं. 29, एल्डेम्स रोड तेयनमपेट मद्रास-600018	674/70
6.	दि एन्फल्ड सेल्स लि.	सं. 29, एल्डम्स रोड, तेयनमपेट, मद्रास-600018	2291/85
7.	मैकनियोड रसल (इंडिया) लि.	नामबंग हाउस, शेक्सपियर सरणी कलकत्ता-700017	1407/78
8.	फैथ इन्वैस्टमैन्ट्स लि.	—यथोपरि—	2102/84
9.	माकुम टी कम्पनी (इंडिया) लि.	पो. आ. मारघेरिता, जिला डिब्रुगढ़ असम	1447/79

1	2	3	4
10.	नामडंग टी कम्पनी (इंडिया) लि.	—यथोपरि—	1448/79
11.	इंडिया सीमेन्ट्स लिमिटेड	दून बिल्डिंग, 827, अन्ना सलाई मद्रास-600002	559/70

MINISTRY OF INDUSTRY AND CO. AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 6th September, 1985

S.O. 4393.—In pursuance of sub-Section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of the undertakings mentioned in the Annexure to this notification, the said undertakings being undertakings to which the provisions of part A Chapter III of the said Act no longer apply.

[No. 16/12/85.M-III]

L. C. GOYAL, Under Secy.

Annexure to the Notification No. 16-12-85.M-III

S. No.	Names of the Undertakings	Registered address	Registration No.
1.	Harsh Investments Ltd.	9-Brabourne Road, Calcutta-700 001	2323/85
2.	Rubby Developers & Constructors Private Ltd.	9-Brabourne Road, Calcutta-700 001	2324/85
3.	Shree Vindhya paper Mills Ltd.	Shri G. D. Somani Marg, Panchak Nasik Road-422101	1402/78
4.	Travancore Electro Chemicals Industries Ltd.	P.O. Chingavanam-686 531. Distt. Kottoyary (Kerala)	1405/78
5.	The Enfield India Ltd.	No. 29, Eidams Road, Teynampet, Madras-600 018.	674/70
6.	The Enfield Sales Ltd.	No. 29-Eldams Road, Teynapmpet, Madras-600 018.	2291/85
7.	Mc Leod Russel (India) Ltd.	Namdang House, 27-Shakespeare Sarani Calcutta-700 017.	1407/78
8.	Faith Investments Ltd.	Namdang House, 27-Shakespeare Sarani Calcutta-700 017.	2102/84
9.	Nakum Tea Company (India) Ltd.	P.O. Margherita, Distt. Dibrugarh, Assam.	1447/79
10.	Namdang Tea Company (India) Ltd.	P.O. Margherita, Dist. Dibrugarh, Assam.	1448/79 559/70
11.	India Cements Ltd.	"Duun Building, 827-Anna Salai, Madras-600 002.	

पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1985

का.आ. 4394:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का.आ. सं. 1544 तारीख 15-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम दौराना तहसील राघोगढ़ जिला—गुना राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्रम. 1	खसरा नं. 1	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर में)
1	2	3
1.	18	0.355
2.	19	0.052
3.	20	0.292
4.	21	0.052
5.	26	0.270
6.	27	0.147
7.	28	0.366
8.	30	0.250
9.	67/1	0.062
10.	72	0.220
11.	74	0.021
12.	75	0.147
13.	76	0.292
14.	78	0.126

1	2	3
15.	84	0.031
16.	93	0.721
17.	99/2	0.184
18.	99/3	0.126
19.	10	0.302
20.	102	0.157
21.	111	0.043
22.	112	0.126
23.	123	0.031
24.	124	0.031
25.	125	0.031
26.	155	0.084
27.	156	0.043
28.	164	0.418
29.	15/2	0.021
30.	17	0.031
31.	80	0.083
32.	103	0.010
33.	99/1	0.010
34.	71	0.010
35.	165	0.073
36.	166	0.043
37.	167	0.021
38.	171/1	0.303
39.	173	0.536
40.	192	0.272
41.	193	0.320
	योग :—कुल क्षेत्रफल	7.163

[सं. ओ—14016/211/85-जे .प .]

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 10th September, 1985

S.O. 4394.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1544 dated 13-4-1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipeline Project
Village Dorana Tehsil Raghogarh Distt. Guna

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hector
1.	18	0.355
2.	19	0.052
3.	20	0.292
4.	21	0.052
5.	26	0.270
6.	27	0.147
7.	28	0.366
8.	30	0.250
9.	67/1	0.062
10.	72	0.220
11.	74	0.021
12.	75	0.147
13.	76	0.292
14.	78	0.126
15.	84	0.031
16.	93	0.721
17.	99/2	0.184
18.	99/3	0.126
19.	10	0.302
20.	102	0.157
21.	111	0.043
22.	112	0.126
23.	123	0.031
24.	124	0.031
25.	125	0.031
26.	155	0.084
27.	156	0.043
28.	164	0.418
29.	15/2	0.021
30.	17	0.031
31.	80	0.083
32.	103	0.010
33.	99/1	0.010
34.	71	0.010
35.	165	0.073
36.	166	0.043
37.	167	0.021
38.	171/1	0.303
39.	173	0.536
40.	192	0.272
41.	193	0.320
	Total Area	7.163

[No. O—14016/211/85-GP]

का.आ. 4395.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 1305 तारीख 30-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग के अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम अल्ली पुरा तहसील राघोगढ जिला गुना राज्य (मध्यप्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	40	0.271
2.	41	0.418
3.	43	2.251
4.	44/6	0.052
5.	53/5	0.485
6.	53/12	0.209
7.	53/13	0.272
8.	53/16	0.251
9.	53/17	0.125
10.	53/18	0.178
11.	72/1	1.254
12.	45	0.031
13.	53/6	0.021
14.	70	0.021
15.	73	0.031
योग:—कुल क्षेत्रफल		3.870

[सं. ओ.—14016/140/85-ज. पे.]

S.O. 4395.—Whereas by notification of the Government of India in the Minisrty of Petroleum S.O. 1305 dated 30-3-1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipeline Project

Village Allipura Tehsil Raghogarh Distt. Guna

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1.	40	0.271
2.	41	0.418
3.	43	0.251
4.	44/6	0.052
5.	53/5	0.485
6.	53/12	0.209
7.	53/13	0.272
8.	53/16	0.251
9.	53/17	0.125
10.	53/18	0.178
11.	72/1	1.254
12.	45	0.031
13.	53/6	0.021
14.	70	0.021
15.	73	0.031
Total Area		3.870

[No. O—14016/140/85-GP]

का.आ. 4396.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2321 तारीख 1-6-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम पिपारी तहसील पिछोर जिला—शिवपुरी राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

क्रम सं.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	1611	0.300
2.	1630	0.010
3.	1631	0.030
4.	1573	0.010
5.	1574	0.060
6.	926/1689	0.010
7.	1572	0.230
8.	904	0.030
9.	905	0.050
10.	1616	0.040
11.	1617	0.100
12	1618	0.030
13.	913	0.050
14	914	0.050
15.	1615	0.160
16.	918	0.120
17.	1623	0.010
18.	1626	0.110
19.	896	0.010
20.	897	0.010
21.	1627	0.070
22.	1629	0.020
23.	916	0.120
24.	898	0.570
25	915	0.050
26.	899	0.390
27.	999	0.040
28.	919	0.030
29.	911	0.080
30.	912	0.030
31.	903	0.250
32.	926	0.270
33.	1569	0.120
34.	884/1687	0.200
35.	1632	0.160
36.	1634	0.110
37	1622	0.010
38	1612	0.040
39.	1613	0.060
40.	920/1686	0.080
41.	900	0.030
42.	1575	0.320
43.	1653	0.030
44.	917	0.040
45.	1643	0.100
46.	1633	0.040
	योग: कुल क्षेत्रफल	4.850

[सं. ओ-14016/337/85-जी. पी.]

S.O. 4396.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 2321 dated 1-6-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Piparo Tehsil Pichhore Distt. Shivpuri

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in in Hectare
1.	1611	0.300
2.	1630	0.010
3.	1631	0.030
4.	1573	0.010
5.	1574	0.060
6.	926/1689	0.010
7.	1572	0.230
8.	904	0.030
9.	905	0.050
10.	1616	0.040
11.	1617	0.190
12.	1618	0.030
13.	913	0.050
14.	914	0.050
15.	1615	0.160
16.	918	0.120
17.	1623	0.010
18.	1626	0.120
19.	896	0.010
20.	897	0.010
21.	1627	0.070
22.	1629	0.020
23.	916	0.120
24.	898	0.570
25.	915	0.050
26.	899	0.390
27.	909	0.040
28.	910	0.080
29.	911	0.080
30.	912	0.030
31.	903	0.250
32.	926	0.270
33.	1569	0.120
34.	884/1687	0.200
35.	1622	0.160
36.	1634	0.110
37.	1622	0.010
38.	1612	0.040
39.	1613	0.060
40.	900/1686	0.080
41.	900	0.030
42.	1575	0.320
43.	1653	0.030
44.	927	0.040
45.	1643	0.100
46.	1633	0.040
	Total Area	4.830

[No. O–14016/337/85-GP]

का०आ० 4294.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० 1314 तारीख 30-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम अहीरखेड़ी तहसील राघोगढ़ जिला गुना राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र.	खसरा न.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1	2	3
1.	233	0.376
2.	234	0.596
3.	213/1 मीन	0.314
4.	200	0.195
5	19	0.031
6.	189/2	0.262
7.	191	0.121
8.	146	0.010
9	192	0.596
10.	232	0.039
11.	119	0.052
12.	193	0.919
13.	213/1/3	0.261
14.	215	0.261
15.	199	0.095
16.	190	0.083
17	198/3	0.104
	योग : कुल क्षेत्रफल	3.207

[सं. ओ-14016/179/85-जी. पी.]

S.O. 4297.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1314 dated 30-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village: Aheera Khedi Tehsil: Raghogarh

Distt. Gunta (MP)

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
1.	233	0.376
2.	234	0.596
3.	213/1 Mean	0.314
4.	200	0.105
5.	195	0.031
6.	189/2	0.262
7.	191	0.021
8.	146	0.010
9.	192	0.596
10.	232	0.030
11.	119	0.052
12.	193	0.010
13.	213/1/3	0.261
14.	215	0.261
15.	199	0.95
16.	190	0.083
17.	198/3	0.014
	Total :—Area	3.207

[No. O-14016/179/85-GP]

का. आ. 4398.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1496 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का. आ. स. 1495 तारीख 1?-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : कुचलोन तहसील : करेरा जिला: शिवपुरी, राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	638	0.031
2.	639	0.857
3	642	0.042
4.	614	0.125
5	612	0.110
6	692	0.147
7.	597	0.105
8	596	0.165
9.	593	0.167
10.	595	—
11.	594	0.073
12	592	0.031
13	538	0.021
14	563	0.272
15.	564/1	0.052
16.	564/2	0.136
17.	564/3	0.146
18	565	—
19	561/1	0.073
20.	21/3, 4, 5, 6	0.470
21	35	0.281
22.	36	0.231
23.	64/1	0.015
24.	63	0.131
25	62	0.138
26	61/1	0.178
27.	60	0.146
28.	46/3	0.063
29.	109	0.324
30.	110	0.034

1	3	3
31.	106/2	0.119
32.	108	—
33.	116	0.324
34.	117	—
35.	118	0.384
36.	122	0.188
37.	121	0.272
38.	133	0.063
39.	130/1	0.073
40.	131	0.261
41.	140	0.314
42.	141	0.010
43.	159/2	0.252
44.	161/1	0.146
45.	171	0.194
46.	59	0.150
47.	563	0.010
48.	589	0.030
49.	603	0.175
50.	609	0.400
51.	610	0.020
52.	615	0.150
53.	643	0.110
54.	644	0.070
55.	704	0.039
56.	705	0.150
57	640	0.300
58.	627	0.100
	योग : कुलक्षेत्रफल	8.891

[सं० ओ-14016/182/85-जी. पी.]

S.O. 4398.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, (Department of Petroleum) S.O. 1495 dated 13-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6, of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village: Kuchlone Tehsil: Karera Distt.: Shivpuri (MP)

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1.	638	0.031
2.	639	0.857
3.	642	0.042
4.	614	0.125
5.	612	0.110
6.	602	0.147
7.	597	0.105
8.	596	0.105
9.	593	0.167
10.	595	—
11.	594	0.073
12.	592	0.031
13.	588	0.021
14.	562	0.272
15.	564/1	0.052
16.	564/2	0.136
17.	564/3	0.146
18.	565	—
19.	561/1	0.073
20.	21/3,4,5,6	0.470
21.	35	0.282
22.	36	0.231
23.	64/1	0.015
24.	63	0.131
25.	62	0.188
26.	61/1	0.178
27.	60	0.146
28.	46/3	0.063
29.	109	0.324
30.	110	0.084
31.	106/2	0.110
32.	108	—
33.	116	0.324
34.	117	—
35.	118	0.384
36.	122	0.188
37.	121	0.272
38.	133	0.063
39.	130/1	0.073
40.	131	0.261
41.	140	0.314
42.	141	0.010
43.	159/2	0.252
44.	161/1	0.146
45.	171	0.194
46.	59	0.150

1	2	3
47.	563	0.010
48.	589	0.030
49.	603	0.175
50.	609	0.400
51.	610	0.020
52.	615	0.150
53.	643	0.110
54.	644	0.070
55.	704	0.030
56.	705	0.150
57.	640	0.300
58.	627	0.100
	Total :—Area	8.891

[No. O—14016/182/85-GP]

का. आ. 4399 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 1494 तारीख 13-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : छीतिपुर तहसील : करेरा जिला : शिवपुरी राज्य : मध्य प्रदेश

अनुसूची

अनुक्रम०	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षे (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	379	0.200
2.	377/2	0.062
3.	378	0.357
4.	376	0.052
5.	875	0.105
6.	373	0.418
7.	372/2	0.130
8.	367	0.157
9.	369/2	—
10.	370/2	0.214
11.	365/1	0.157
12.	350/1	0.110
13.	350/2	0.080
14.	350/5	0.210
15.	350/6	0.190
16.	351	0.100
17.	352	0.150
18.	338	0 100
19.	318	0.118
20.	321/1	0.468
21.	277/2	0.468
22.	139/1	0.323
23.	140	0.105
24.	141	0.052
25.	147/1	0.055
26.	147/2	0.110
27.	147/3	0.105
28.	147/4	0.052
29.	145	0.021
30.	144/1	0.055
31.	144/2	0.052
32.	144/3	0.021
33.	105/935/6	0.468
34.	105/965/7	—
35.	105/965/7	0.084
36.	64	0.100
37.	88	0.050
38.	89/1	0.105
39.	89/2	0.105
40	90	0.073
41.	91	0.063
42.	99/1	0.052
43.	99/3	0.082
44.	92/1/2	0.157
45.	60/4	—
49.	93	0.021

1	2	3
47.	94	0.042
48.	57/1	0.060
49.	57/2	0.120
50.	57/3	—
51.	056	0.031
52.	53/1	0.063
53.	53/2	0.042
54.	53/3	0.052
55	53/4	0.052
56.	49/1	0.152
57.	49/2	0.152
	योग :कुल क्षेत्रफल	7.253

[सं. O-14016/181/85-ज पी

S.O. 4399.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy. (Deptt. of Petroleum) S.O. 1494 dated 13-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Preject

Village: Chitipur Tehsil: Karera Distt: Shivpuri (MP)

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1.	379	0.200
2.	377/2	0.062
3.	378	0.357
4.	376	0.052
5.	375	0.015
6.	373	0.418
7.	372/2	0.130
8.	367	0.157
9.	369/2	—
10.	370/2	0.214
11.	365/1	0.157
12.	350/1	0.110
13.	350/2	0.080
14.	350/5	0.210
15.	350/6	0.190
16.	351	0.100
17.	352	0.150
18.	338	0.100
19.	318	0.418
20.	321/1	0.468
21.	277/2	0.468
22.	139/1	0.323
23.	140	0.105
24.	141	0.052
25.	147/1	0.055
26.	147/2	0.110
27.	147/3	0.105
28.	147/4	0.052
29.	145	0.021
30.	144/1	0.055
31.	144/2	0.052
32.	144/3	0.021
33.	105/935/6	0.468
34.	105/965/7	—
35.	105/965/9	0.084
36.	64	0.100
37.	88	0.050
38.	89/1	0.105
39.	89/2	0.105
40.	90	0.073
41.	91	0.063
42.	99/1	0.025
43.	99/3	0.082
44.	92/1/2	0.157
45.	60/4	—
46.	93	0.021
47.	94	0.042
48.	57/1	0.060
49.	57/2	0.120
50.	57/3	—
51.	056	0.031
52.	53/1	0.063
53.	53/2	0.042
54.	53/3	0.052
55.	53/4	0.052
56.	49/1	0.152
57.	49/2	0.152
	Total: Area	7.253

[No. O—14016/181/85-GP]

का०आ० 4400.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 567 तारीख द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच.बी.जे. जे कट

ग्राम : जयसिंहपुरा तहसील : चाचौड़ा जिला : गुना राज्य : मध्य प्रदेश

अनुसूची

अनुक्रम	खसरा नं	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	26/3	0.146
2.	23	0.042
3.	27/1	0.116
4.	30	0.188
5.	31	0.355
6.	22	0.072
7.	32/1/1	0.325
8.	21	0.042
9.	20/1	0.052
10.	19/1	0.072
11.	15/1	0.062
12.	17/204	199
13.	16	0.188
14.	14/1/1	0.261
15.	14/2	0.413
16.	9	0.304
17.	13	0.147
18.	2	0.125
19.	7	0.188
20.	60	0.475
21.	62/1/1	0.370
22.	64/1	0.062
23.	63/1	0.271
24.	59/1/1	0.021
25	59/1/2	0.024
	योग कुल क्षेत्रफल	1.547

[सं. O-14016/14/85-जी पी]

S.O. 4400.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, (Department of Petroleum) S.O. 567 dated 9-2-85 under sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village Jaisingh pura Tehsil Chachoda Distt. Guna

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
1.	26/3	01146
2.	23	0.042
3.	27/1	0.116
4.	30	0.188
5.	31	0.355
6.	22	0.072
7.	32/1/1	0.325
8.	21	0.042
9.	20/1	0.052
10.	19/1	0.072
11.	15/1	0.062
12.	17/204	0.199
13.	16	0.188
14.	141/1	0.261

1	2	3
15.	14/2	0.443
16.	9	0.340
17.	13	0.147
18.	8	0.125
19.	7	0.188
20.	60	0.475
21.	62/1/1	0.370
22.	64/1	0.062
23.	63/1	0.271
24.	59/1/1	0.021
25.	59/1/2	0.221
	Total Area	4.547

[No. O-–14106/14/85–GP]

का. आ. 4401.—यत: पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 575 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजैक्ट

ग्राम: खेजरा ब्रहेरा तहसील: चाचोड़ा जिला: गुना राज्य (मध्यप्रदेश)

अनुसूची

अनुक्र.	खसरा नं	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	1	0.126
2.	18	0.061
3.	19	0.021
4	17	0.105
5.	4	0.460
6.	5	0.220
7.	6	0.355
8.	7	0.218
9.	8	0.500
10.	12	0.449
11.	14	0.105
12.	15	0.618
13.	16	0.324
14.	81/1	0.021
15.	82	0.240
16.	83	0.051
17.	84	0.051
18.	85/1	0.031
19.	85/2	0.051
20.	86	0.314
21.	87	0.385
22.	88	0.167
23.	97	0.167
24.	98	0.523
25.	99	0.081
26.	104	0.179
27.	105	0.333
28.	111	0.314
29.	128	0.240
30.	129	0.167
31.	127	0.523
32.	11	0.021
33.	100	0.067
	योग : कुल क्षेत्रफल	8.077

[सं. O-14016/22/83-ज. पी]

S.O. 4401.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 575 dated 9-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Khejrabhera Tehsil : Chachoda Disit. Guna

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectar
1	2	3
1.	1	0.126
2.	18	0.061
3.	19	0.021
4.	17	0.105
5.	4	0.469
6.	5	0.220
7.	6	0.335
8.	7	0.218
9.	8	0.500
10.	12	0.449
11.	14	0.105
12.	15	0.618
13.	16	0.324
14.	81/1	0.021
15.	82	0.240
16.	83	0.051
17.	84	0.051
18.	85/1	0.031
19.	85/2	0.051
20.	86	01314
21.	87	0.385
22.	88	0.467
23.	97	0.167
24.	98	0.523
25.	99	0.081
26.	104	0.479
27.	105	9.333
28.	111	0.314
29.	128	0.240
30.	129	0.167
31.	127	0.523
32.	11	0.021
33.	100	0.067
Total Area	—	8.077

[No. O-14016/22/85-GP]

का. आ. 4402—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का.आ.सं. 2320 तारीख 1-6-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : खड़ोय तहसील : पिछोर जिला : शिवपुरी राज्य : मध्य प्रदेश

अनुसूची

अनुक्रम	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	777	0.080
2.	778	0.010
3.	326	0.010
4.	826	0.220
5.	774	0.120
6.	773	0.100
7.	776	0.110
8.	325	0.160
9.	760	0.050
10.	781	0.130
11.	836	0.240
12.	775	0.120
13.	761	0.070
14.	764	0.060
15.	763	0.070
16.	805	0.080
17.	824	0.070
18.	867	0.020
19.	873	0.140
20.	772	0.090
21.	782	0.090
22.	794	0.060
23.	825	0.160
24.	851	0.010
25.	865	0.230
26.	693	0.020
27.	897	0.140
28.	765	0.140

1	2	3
29.	766	0.060
30.	767	0.120
31.	768	0.130
32.	803	0.160
33.	804	0.180
34.	868	0.030
35.	869	0.060
36.	870	0.080
37.	871	0.070
38.	872	0.080
39.	874	0.260
40.	780	0.060
41.	853	0.010
42.	770	0.120
43.	793	0.070
44.	795	0.060
45.	802	0.100
46.	828	0.080
47.	829	0.030
48.	852	0.050
49.	863	0.080
50.	754	0.050
51.	846	0.020
52.	847	0.040
53.	323	0.010
54.	324	0.180
55.	833	0.120
56.	848	0.280
57.	898	0.020
58.	745	0.020
59.	818	0.040
60.	838	0.020
61.	875	0.040
62.	919	0.020

योग : 5 कुल क्षेत्रफल 5.350

[सं. O-14016/336/85-जी०पी०]

S.O. 4402.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 2320 dated 1-6-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline:

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village: Khadoya Tehsil : Pichhore Distt. : Shivpuri

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectar
1	2	3
1.	777	0.080
2.	778	0.010
3.	326	0.010
4.	826	0.020
5.	774	0.120
6.	773	0.100
7.	776	0.110
8.	325	0.160
9.	760	0.050
10.	781	0.130
11.	836	0.240
12.	775	0.120
13.	761	0.070
14.	764	0.060
15.	763	0.070
16.	805	0.080
17.	824	0.070
18.	867	0.020
19.	873	0.140
20.	772	0.090
21.	782	0.090
22.	794	0.060
23.	825	0.160
24.	851	0.010
25.	865	0.230
26.	893	0.020
27.	897	0.140
28.	765	0.140
29.	766	0.060
30.	767	0.120
31.	768	0.130
32.	803	0.160
33.	804	0.180
34.	868	0.030
35.	869	0.060
36.	870	0.080
37.	871	0.070
38.	872	0.080

1	2	3
39.	874	0.620
40.	780	0.060
41.	853	0.010
42.	770	0.120
43.	793	0.070
44.	795	0.060
45.	802	0.100
46.	828	0.080
47.	829	0.030
48.	852	0.050
49.	863	0.080
50.	764	0.050
51.	846	0.020
52.	847	0.040
53.	323	0.010
54.	324	0.180
55.	833	0.120
56.	848	0.280
57.	898	0.020
58.	745	0.020
59.	818	0.040
60.	838	0.020
61.	875	0.040
62.	919	0.020
	Total Area	5.350

[No. O-14016/336/85—GP]

का. आ. 4403.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 591 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

769GI/85 6

एच. बी. जे. गैस पाईप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : निपान्यानुला तहसील : सारंगपुर जिला : राजगढ़ राज्य : मध्य प्रदेश

अनुसूची

अनुक्र.	सर्वे नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र। (हैक्टर में)
1	2	3
1.	829	0.040
2	841/5	0.120
3	705	0.030
4	828/1 मे	0.265
5.	804	0.320
6.	805 मे	0.200
7.	828/2	0.050
8.	806 मे	0.200
9	827	0.080
10.	819	0.270
11.	820	0.040
12	821	0.050
13.	815	0.070
14.	802,	0.040
15.	682 मे	0.100
16.	663	0.180
17	652	0.110
18.	654	0.230
19.	636	0.070
20.	662	0.160
21.	658एमएम	0.400
22.	659/1	0-090
23.	635	0.445
24.	628/1	0.270
25	622एम	0.350
26	623	0.045
27	624	0.270
28.	626/2/1	0.100
29.	818	0.060
30.	655	0.150
योग कुल क्षेत्रफल		4.805

[सं. O-14016/34/85-जी पी]

S.O. 4403.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 591 dated 9-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User is Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Nipanyatula Tehsil Sarangpur Distt. Rajgarh

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hecture
1.	829	0.040
2.	841/5	0.120
3.	705	0.030
4.	828/1 M.	0.265
5.	804	0.320
6.	805 M.	0.200
7.	828/2	0.050
8.	806 M.	0.200
9.	827	0.080
10.	819	0.270
11.	820	0.040
12.	821	0.050
13.	815	0.070
14.	802	0.040
15.	682 M.	0.100
16.	663	0.180
17.	652	0.110
18.	654	0.230
19.	636	0.070
20.	662	0.160
21.	658 MS	0.400
22.	659/1	0.090
23.	635	0.445
24.	628/1	0.270
25.	622-A	0.350
26.	623	0.045
27.	624	0.270
28.	626/2/1	0.100
29.	818	0.060
30.	655	0.150
	Total Area	4.805

[No. O-14016/34/85-GP]

का. आ. 4404.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2318 तारीख 1-6-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : कंडेसरा तहसील : पिछोर जिला : शिवपुरी राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

क्रमांक	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर में)
1	2	3
1	164	0.020
2	243	0 020
3	244	0.150
4	245	0.010
5	283	0.050
6	284	0.040
7.	286	0.030
8.	288	0.090
9	125	0.200
10.	128	0.240
11.	126	0.100
12	218	0.020
13	150	0.140
14.	151	0.080
15.	161	0.040
16.	262	0.120
17.	165	0.320
18.	270	0.150
19.	275	0.250
20.	276	0.140
21.	279	0.200
22.	291	0.300
23.	304	0.080
24.	305	0.100
25.	306	0.120
26	308	0.020
27.	217	0.380
28.	219	0.120
29.	295	0.340

1	2	3
30.	259	0.150
31.	258	0.040
32.	280	0.010
33.	282	0.200
34.	297	0.030
35.	298	0.180
36.	299	0.070
37.	301	0.180
38.	293	0.010
39.	267	0.250
40	269	0.400
41.	273	0.230
42.	261	0.100
43.	309	0.150
44.	127	0.120
45	166	0.390
46.	149	0.020
47.	265	0.100
48.	266	0.020
49.	1	0.020
50.	131	0.020
51.	216	0 050
52.	378	0.160
53	118	0.010
	योग : कुल क्षेत्रफल	6.220

[सं. O-14016/334/85-अ. प.]

S.O. 4404.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 2318 dated 1-6-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-sectoin (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all enumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Kandesara Tehsil Pichhore Distt. Shivpuri

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hector
1.	164	0.020
2.	243	0.020
3.	244	0.150
4.	245	0.010
5.	283	0.050
6.	284	0.040
7.	286	0.030
8.	288	0.090
9.	125	0.200
10.	128	0.240
11.	126	0.100
12.	218	0.020
13.	150	0.140
14.	151	0.080
15.	161	0.040
16.	262	0.120
17.	165	0.320
18.	270	0.150
19.	275	0.250
20.	276	0.140
21.	279	0.200
22.	291	0.300
23.	304	0.080
24.	305	0.100
25.	306	0.120
26.	308	0.020
27.	217	0.380
28.	219	0.120
29.	295	0.140
30.	259	0.150
31.	258	0.040
32.	280	0.010
33.	282	0.200
34.	297	0.030
35.	298	0.180
36.	299	0.070
37.	301	0.180
38.	293	0.010
39.	267	0.250
40.	269	0.040
41.	273	0.230
42.	261	0.100
43.	309	0.150
44.	127	0.120
45.	166	0.390
46.	149	0.020
47.	265	0.100
48.	266	0.020
49.	1	0.020
50.	131	0.020

1	2	3
51.	216	0.050
52.	378	0.160
53.	118	0.010
	Total Area	6.220

[No. O-14016/334/85-GP]

का. आ. 4405.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 867 तारीख 2-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच.बी.जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम : सिकोवा तहसील : दतिया जिला : दतिया राज्य : मध्य प्रदेश

अनुसूची

क्रम सं.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	92	0.186
2.	93	0.076
3.	96	0.153
4.	98	0.057
5.	146	0.085
6.	147	0.486
7.	148	0.348
8.	149	0.061
9.	150	0.272
10.	151	0.518
11.	161	0.300
12.	162/2	0.664
13.	164	0.330
14.	180	0.251
15.	181	0.332
16.	184	0.672
17.	185	0.073
18.	186	0.089
19.	187	0.278
20.	153	0.031
21.	163	0.031
22.	179	0.005
	योग . कुल क्षेत्रफल	5.298

[सं. O-14016/83/85-जी पी]

S.O. 4405.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 867 dated 2-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authorty has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Sikaucha Tehsil Datia Distt. Datia

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hecture
1.	92	0.186
2.	93	0.076
3.	96	0.153
4.	98	0.057
5.	146	0.085
6.	147	0.486
7.	148	0.348
8.	149	0.061
9.	150	0.272
10.	151	0.518
11.	161	0.300
12.	162/2	0.664
13.	164	0.330
14.	180	0.251
15.	181	0.332
16.	184	0.672

1	2	3
17.	185	0.073
18.	186	0.088
19.	187	0.278
20.	153	0.031
21.	163	0.031
22.	179	0.005
	Total Area	5.298

[No. O—14016/83/85-GP]

का. आ. 4406.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2317 तारीख 1-6-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : बनियाली तहसील : पिछोर जिला : शिवपुरी राज्य : मध्य प्रदेश

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर में)
1	2	3
1	319/392	0 080
2	173	0 360
3.	25	0.260
4.	240	0 330
5.	319	0 140
6.	5	0 250
7.	302	0 630
8.	238	0 670
9.	212	0.250
10.	318	0 270
11.	144	0 440
12	18	0 340
13.	10	0 410
14.	3	0 460
15.	99	0 250
16.	40	0.190
17.	107	0 150
18.	38	0.200
19.	145	0 230
20	177	0.120
21	303	0.510
22.	169	0 570
23.	312	0 290
24	313	0 200
25	23	0 310
26	174	0.620
27	12	0 520
28	32	0.150
29	41	0 250
30.	105	0 450
31.	95	0 550
32.	101	0.300
33	103	0.010
34	96	0.300
35	18	0.080
36.	102	0 010
37.	104	0.140
38	106	0.290
39.	143	0.360
40.	91	0.370
41.	170	0 560
42	243	0.020
43.	391	0.030
	योग : कुल क्षेत्रफल	12 920

[सं O-14016/333/85-जीपी]

S.O. 4406.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2317 dated 1-6-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands, shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Baniyani Tehsil: Pichhore Distt.: Shivpuri

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in hectare
1.	319/92	0.080
2.	172	0.360
3.	25	0.260
4.	240	0.330
5.	319	0.140
6.	5	0.250
7.	302	0.630
8.	238	0.670
9.	242	0.250
10.	318	0.270
11.	144	0.440
12.	18	0.340
13.	10	0.410
14.	3	0.460
15.	99	0.250
16.	40	0.190
17.	107	0.150
18.	38	0.200
19.	145	0.230
20.	177	0.120
21.	303	0.510
22.	169	0.570
23.	312	0.290
24.	313	0.200
25.	23	0.310
26.	174	0.620
27.	12	0.520
28.	32	0.150
29.	41	0.250
30.	105	0.450
31.	95	0.550
32.	101	0.300
33.	103	0.010
34.	96	0.300
35.	48	0.080
36.	102	20.010
37.	104	0.140
38.	106	0.290
39.	143	0.360
40.	91	0.370
41.	170	0.560
42.	243	0.020
43.	391	0.030
	Total Area	12.920

[No. O-14016/333/85-GP]

का. आ. 4407.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4407 तारीख 15-2-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम: खोनड़िया कालो तहसील: राजगढ़ जिला: राजगढ़ राज्य मध्य प्रदेश

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर में)
1	2	3
1.	50	0.100
2.	49	0.180
3.	48	0.025
4.	53/1	0.005
5.	47	0.039
6.	46/1	0.900
7.	46/1/1	0.200
8.	55	0.021
9.	56	0.005
10.	57	0.240
11.	70	0.005
12.	74	0.015
13.	58	0.063
14.	73	0.080
15.	75	0.130
16.	71	0.026
17.	72	0.124
18.	98	0.005
19.	101	0.303
20.	99	0.005
21.	100	0.127
22.	116/2	0.020
23.	103	0.210
24.	12/6	1.040

25.	109	0.015
26.	111	0.050
27.	12/4	0.162
28.	12/5	0.010
29.	112/2	0.020
30.	79	0.025
31	108	0.013
32	110	0.010
	कुल योग- - क्षेत्रफल	4.173

[सं. O-14016/372/84-जी पी]

S.O. 4407.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4407 dated 15-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Ghoghadiya Kalo Tehsil Rajgarh Distt. Rajgarh

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectares
1.	50	0.100
2.	49	0.180
3.	48	0.025
4.	53/1	0.005
5.	47	0.039
6.	46/1	0.900
7.	46/1/1	0.200
8.	55	0.021
9.	56	0.005
10.	57	0.240
11.	70	0.005
12.	74	0.015
13.	58	0.063
14.	73	0.080
15.	75	0.130
16.	71	0.026
17.	72	0.124
18.	98	0.005
19.	101	0.303
20.	99	0.005
21.	100	0.127
22.	116/2	0.020
23.	103	0.210
24.	12/6	1.040
25.	109	0.015
26.	111	0.050
27.	12/4	0.162
28.	12/5	0.010
29.	112/2	0.020
30.	79	0.025
31.	108	0.013
32.	110	0.010
	Total Area	4.173

[No. O-14016/372

का. आ. 4408.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2334 तारीख 1-6-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाईप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम बुधीनराजापुर तहसील पिछोर जिला—शिवपुरी राज्य (मध्यप्रदेश)

अनुक्रमांक	खसरा	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	33	0.231
2	24	0.188
3.	25	0.063
4.	32/1	0.736
5	78/2	0.149
6.	52/4	0.136
7.	56	0.369
8	72/2	1.415
9	73/1	0.649
10.	178	0.125
11.	188	0.052
12	189	0.063
13	190	0.052
14.	197	0.073
15.	198	0.125
16.	230	0.010
17.	231	0.063
18	232	0.074
19.	233	0.063
20.	234	0.073
21.	236	0.052
22.	237	0.052
23.	238	0.052
24	270	0.021
25.	271	0.081
26.	268	0.081
27.	283	0.105
28.	285	0.031
29	284	0.136
30	286	0.115
31.	287	0.021
32.	60	0.136
33	49—	0.063
34	46	0.063
35	282	0.010
36.	315	0.125
37.	334	0.010
38.	318	0.031
39.	22—	0.042
40	32/2	0.010
41.	46—	0.063
42.	49—	0.063
43.	74—	0.073
44.	81—	0.031
45	200	0.010
46.	204	0.021
47.	243	0.010
48.	256	0.010
49	257	0.010
50	259	0.010
51.	260	0.021
52.	261	0.010
53.	262	0.010
54.	263	0.031
55.	264	0.021
56.	265	0.072
57.	269	0.010
58.	277	0.031
59.	319	0.031
60	324	0.021
61.	339	0.052
62	342	0.021
63.	343	0.052
64.	61—	0.042
65.	235/740	0.125
66	235	0.042
67.	317	0.031
68.	288	0.147
69.	309	0.021
70.	310	0.052
71	311	0.157
72.	312	0.177
73	313	0.073
74.	335	0.197
75.	336	0.115
76.	337	0.081
77.	338	0.157
78.	238/741	0.042
79	334/743	0.251
	योग : कुलक्षेत्रफल	8.610

[सं. O-14016/350/85-जी पी]

S.O. 4408.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 2334 dated 1-6-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said repoort, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of thi declaration in the Gas Authority of India Ltd, free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Budhonrajapur Tehsil Pichhore Distt. Shivpuri

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectares
1	2	3
1.	23	0.231
2.	24	0.188
3.	25	0.063
4.	32/1	0.736
5.	78/2	0.449
6.	52/4	0.136
7.	56	0.369
8.	72/2	1.415
9.	73/1	0.649
10.	178	0.125
11.	188	0.052
12.	189	0.063
13.	190	0.052
14.	197	0.073
15.	198	0.125
16.	230	0.010
17.	231	0.063
18.	232	0.074
19.	233	0.063
20.	234	0.073
21.	236	0.052
22.	237	0.052
23.	238	0.052
24.	270	0.021
25.	271	0.081
26.	268	0.081
27.	283	0.105
28.	285	0.031
29.	284	0.136
30.	286	0.115
31.	287	0.021
32.	60	0.136
33.	49	0.063
34.	46	0.063
35.	282	0.010
36.	315	0.125
37.	334	0.010
38.	318	0.031
39.	22	0.042
40.	32/2	0.010
41.	46	0.063
42.	49	0.063
43.	74	0.073
44.	81	0.031
45.	200	0.010
46.	204	0.021
47.	243	0.010
48.	256	0.010
49.	257	0.010
50.	259	0.010
51.	260	0.021
52.	262	0.010
53.	263	0.031
54.	264	0.021
55.	265	0.072
56.	269	0.010
57.	277	0.031
58.	319	0.031
59.	324	0.021
60.	339	0.052
61.	342	0.021
62.	343	0.052
63.	61	0.042
64.	235/740	0.125
65.	235	0.052
66.	317	0.031
67.	288	0.147
68.	309	0.021
69.	310	0.052
70.	311	0.157
71.	312	0.177
72.	313	0.073
73.	335	0.197
74.	336	0.115
75.	337	0.081
76.	338	0.157
77.	238/74	0.042
78.	334/743	0.251
	Total Area	8.640

[No. O-14016/350/85-GP]

का. आ. 4409.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2030 तारीख 11-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में

विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम मनियर तहसील पिछोर जिला—शिवपुरी राज्य (मध्य प्रदेश)

क्रम सं.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	1	0.125
2.	30	0.178
3.	31	0.240
4.	32	0.042
5.	29	0.042
6.	28	0.272
7.	24	0.115
8.	25	0.303
9.	106	0.209
10.	104	0.230
11.	105	0.031
12.	109	0.084
13.	108	0.209
14.	122	0.010
15.	123	0.031
16.	124	0.010
17.	125	0.010
18.	128	0.084
19.	126	0.178
20.	127	0.052
21.	131	0.010
22.	132	0.052
23.	133	0.105
24.	141	0.031
25.	139	0.105
26.	140	0.010
27.	162	0.072
	योग : कुल क्षेत्रफल	2.840

[सं. O-14016/309/85-जीपी]

S.O. 4409.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 2030 dated 11-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declared that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPLINE PROJECT

Village : Maniyar, Tehsil : Pichhore, Distt Shivpuri

Sl. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectares
1.	1	0.125
2.	30	0.178
3.	31	0.240
4.	32	0.042
5.	29	0.042
6.	28	0.272
7.	24	0.115
8.	25	0.303
9.	106	0.204
10.	104	0.230
11.	105	0.031
12.	107	0.084
13.	103	0.209
14.	122	0.010
15.	123	0.031
16.	124	0.010
17.	125	0.010
18.	128	0.084
19.	126	0.178
20.	127	0.052
21.	131	0.010
22.	132	0.052
23.	133	0.105
24.	141	0.031
25.	139	0.105
26.	140	0.010
27.	162	0.072
	TOTAL AREA	2.840

[No. O-14016/309/85-GP]

का. आ. 4410.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3687 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट,

मौजा तुलसी खेड़ी तहसील चाचौड़ा जिला गुना राज्य (म.प्र.)

क्रम सं.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर में)
1.	388/4/2	0.209
2.	388/4/1	0.156
3.	390	0.259
4.	389	0.469
5.	391/1	0.021
6.	388/3	0.627
7.	395/1	0.020
8.	400	0.116
9.	399	1.333
10.	404/1	0.020
11.	294	0.209
12.	276/15	0.082
13.	293	0.732
14.	292	0.082
15.	283	0.115
16.	282	0.523
17.	281	0.026
18.	280	0.269
19.	252	0.569
20.	251	0.418
21.	253	1.045
22.	248	0.314
23.	247	0.052
24.	254	0.753
25.	245	0.021
26.	258	0.052
	कुल क्षेत्रफल	8.492

[सं. O-14016/135/84-जी पी]

S.O. 4410.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 3687 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Tulsikhedi Tehsil : Chachoda Distt. Guna (M.P.)

Sl. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1.	388/4/2	0.209
2.	388/4/1	0.156
3.	390	0.259
4.	389	0.469
5.	371/1	0.021
6.	388/3	0.627
7.	395/1	0.202
8.	400	0.116
9.	399	1.333
10.	404/1	0.020
11.	294	0.209
12	276/15	0.082
13.	293	0.732
14.	292	0.082
15.	283	0.115
16.	282	0.523
17.	281	0.026
18.	280	0.269
19.	252	0.569
20.	261	0.418
21.	253	1.045
22.	248	0.314
23.	247	0.052
24.	254	0.753
25.	258	0.052
26.	245	0.021
	Total Area	8.492

[No. O-14016/135/84-G

का. आ. 4411.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2048 तारीख 11-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम पहाड़ा कला तहसील पिछोर जिला—शिवपुरी राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर में)
1	2	3
1.	459	0.532
2.	465	0.125
3.	466	0.209
4.	467	0.261
5.	447	0.157
6.	448	0.011
7.	578	0.156
8.	579	0.324
9.	588	0.355
10.	590	0.146
11.	591	0.125
12.	592	0.064
13.	593	0.199
14.	632	0.387
15.	634	0.627
16.	633	0.063
17.	643	0.166
18.	644	0.240
19.	635/3	0.063
20.	572	0.010
21.	635/4	0.219
22.	642/11	0.282
23.	642/1	0.314
24.	642/2	0.105
25.	642/3	0.073
26.	642/4	0.115
27.	60	0.084
28.	635/5	0.042
29.	642/5	0.021
	योग : कुल क्षेत्रफल	5.475

[सं. O-14016/327/85-जीपी]

S.O. 4411.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 2048 dated 11-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village: Pahara Kala, Tehsil : Pichore, Distt. Shivpuri

SCHEDULE

Sl. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
1.	459	0.532
2.	465	0.125
3.	466	0.209
4.	467	0.261
5.	447	0.157
6.	448	0.011
7.	578	0.156
8.	579	0.324
9.	588	0.355
10.	590	0.146
11.	591	0.125
12.	592	0.064
13.	593	0.199
14.	632	0.387
15.	634	0.627

1	2	3
16.	633	0.063
17.	643	0.166
18.	644	0.240
19.	635/3	0.063
20.	572	0.010
21.	635/4	0.219
22.	642/11	0.282
23.	642/1	0.314
24.	642/2	0.105
25.	642/3	0.073
26.	642/4	0.115
27.	60	0.084
28.	635/5	0.042
29.	642/5	0.021
	TOTAL AREA	5.475

[No. O-14016/327/85-GP]

का. आ. 4412.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1545 तारीख 13-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. सें सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच० बी० जे० गैस लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम डाड तहसील करेरा जिला शिवपुरी राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स में)
1	2	3
1.	164	0.860
2.	162	0.840
3.	163	—
4.	157	0.420
5.	160	—
6.	159	0.020
7.	151	0.010
8.	152	0.120
9.	153	—
10.	144	0.060
11.	57/2	0.484
12.	59	—
13.	55	0.240
14.	53	0.180
15.	65	0.960
16.	64	0.150
17.	127	0.040
18.	124	0.720
19.	75/3 म.	0.220
20.	101	0.120
21.	94/2	0.500
22.	92	0.540
23.	97/1	0.940
24.	97/2मं.	—
25.	97/2मं.	0.500
26.	97/1145	0.060
27.	39	0.200
28.	40	0.030
29.	56	0.015
30.	74	0.080
31.	75/1	0.200
32.	75/2	0.250
33.	75/3मं.	0.003
34.	75/4	0.200
35.	75/5	0.015
36.	75/6	0.100
37.	75/7	0.050
38.	78/6	0.010
39.	158	0.136
40.	58	0.032
41.	95	0.080
42.	104	0.080
	योग :—कुल क्षेत्रफल	9.562

[सं. O-14016/212/85-जी. पी.]

S.O. 4412.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1545 dated 13-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report, to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village: Dhand, Tehsil: Karera, Distt.: Shivpuri

SCHEDULE

Sl. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1.	164	0.860
2.	162	0.640
3.	163	—
4.	157	0.420
5.	160	—
6.	159	0.020
7.	151	0.010
8.	152	0.120
9.	153	—
10.	144	0.060
11.	57/2	0.484
12.	59	—
13.	55	0.240
14.	53	0.180
15.	65	0.960
16.	64	0.150
17.	127	0.040
18.	124	0.720
19.	75/3 M.	0.220
20.	101	0.120
21.	94/2	0.500
22.	92	0.540
23.	77/1	0.940
24.	97/2 M.	—
25.	97/2 M.	0.500
26.	97/1145	0.060
27.	39	0.200
28.	40	0.030
29.	56	0.015
30.	74	0.080
31.	75/1	0.200
32.	75/2	0.250
33.	75/3 M.	0.003
34.	75/4	0.200
35.	75/5	0.015
36.	75/6	0.100
37.	75/7	0.050
38.	78/6	0.010
39.	158	0.136
40.	58	0.032
41.	95	0.080
42.	104	0.080
	TOTAL AREA	9.562

[No. O-14016/212/85-GP]

का. आ. 4413.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1304 तारीख 30-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इसे अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम अहमदपुर सहसंलग्न राघोगढ़ जिला-गुना राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षे० (हैक्टर्स में)
1.	42	0.115
2.	33/8	0.025
3.	33/4	0.146
4.	41	0.157
5.	40	0.084
6.	55	0.031
7	56/2	0.084
8.	56/1	0.178
9.	58/1	0.449
10.	59	0.418

11.	60	0.052
12.	17	0.219
13.	18	0.094
14.	30	0.052
15.	28	0 240
16.	27	0.293
17.	24	0.073
18.	19	0.021
19.	16	0.010
20.	20	0.073
21.	29/1	0.010
22.	31	0.010
23.	33/5	0.021
24.	50	0.021
25.	57	0 010
26.	61	0.010
27.	63/1	0.031
28.	44	0.324

योग :—कुल क्षेत्रफल 3.251

[सं. O-14016/142/85-ज प .]

S.O. 4413.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. No. 1304, dated 30-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village: Ahamadapur, Tehsil: Raghogarh, Distt. Guna

SCHEDULE

Sl. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hecture
1.	42	0.115
2.	33/8	0.025
3.	33/4	0.146
4.	41	0.157
5.	40	0.084
6.	55	0.031
7.	56/2	0.084
8.	56/1	0.178
9.	58/1	0.449
10.	59	0.418
11.	60	0.052
12.	17	0.219
13.	18	0.094
14.	30	0.052
15.	28	0.240
16.	27	0.293
17.	24	0.073
18.	19	0.021
19.	16	0.010
20.	20	0.073
21.	29/1	0.010
22.	31	0.010
23.	33/5	0.021
24.	50	0.021
25.	57	0.010
26.	61	0.010
27.	63/1	0.031
28.	44	0.324
	TOTAL AREA	3.251

[No. O-14016/142/85-GP]

का. आ. 4414.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2040 तारीख 11-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच.बी.जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम पगरा तहसील पिछोर जिला-शिवपुरी राज्य (मध्यप्रदेश)

अनुसूची

क्रम सं.	सर्वेक्षण सं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्समें)
1.	75	0.092
2.	233	0.021
3.	76	0.941
4.	71	0.502
5.	64	0.063
6.	63	0.084
7.	66	0.021
8.	57	0.021
9.	62	0.449
10.	185	0.021
11.	186	0.031
12.	187	0.021
13.	222	0.031
14.	227	0.105
15.	234	0.021
16.	228	0.084
17.	232	0.084
18.	230	0.031
19.	231	0.136
20.	242	0.084
21.	239	0.072
22.	243	0.021
23.	247	0.240
24.	246	0.355
25.	248	0.042
26.	270	0.063
27.	210	0.177
28.	209	0.219
29.	208	0.219
30.	206	0.261
31.	274	0.586
32.	273	0.125
33.	60	0.031
योग :—कुल क्षेत्रफल		5.254

[सं. O-14016/325/85-ज. प]

S.O. 4414.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 2046 dated 11-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notificaion hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village: Pagara, Tehsil: Pichore, Distt.: Shivpuri

SCHEDULE

Sl. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectar
1.	75	0.092
2.	233	0.021
3.	76	0.941
4.	71	0.502
5.	64	0.063
6.	63	0.084
7.	66	0.021
8.	57	0.021
9.	62	0.449
10.	185	0.021
11.	186	0.031
12.	187	0.021
13.	222	0.031
14.	227	0.105
15.	234	0.021
16.	228	0.084
17.	232	0.084
18.	230	0.031
19.	231	0.136
20.	242	0.084
21.	239	0.072
22.	243	0.021
23.	247	0.240
24.	246	0.355
25.	248	0.042
26.	270	0.063
27.	210	0.177
28.	209	0.219
29.	208	0.219
30.	206	0.261
31.	274	0.586
32.	273	0.125
33.	60	0.031
TOTAL AREA		5.254

[No. O-14016/325/85-GP]

का. आ. 4415.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधि-

नियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 1777 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	क्षेत्र किया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	इस्लामनगर	भवीपुर	325	1-16-0
				326	1-10-12
				327	0-19-4
				360	1-5-10
				359	1-1-0

[सं. O-14016/263/85—जी.पी.]

S.O. 4415.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Petroleum) S.O. 1777 dated 27-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands, shall instead of vesting in Central Government, vests on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Islampur Nag	Bhavi pur	325	1-16-0
				326	1-10-12
				327	0-19-4
				360	1-5-10
				359	1-1-0

[No. O-14016/263/85-GP]

का. आ. 4416.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 1735 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है। कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	इस्लामनगर	भगवन्त नगर	260	0–15–0
				262	0–7–0
				258	0–8–0
				259	0–1–0
				256	0–11–0
				257	0–6–0
				264	0–4–0
				272	0–15–10
				273	0–1–10
				278	0–2–5
				296	0–10–0
				297	0–9–0
				294	0–0–10
				295	1–4–0
				279	0–1–15
				283	0–16–0
				281	0–9–5
				282	0–8–5
				284	0–15–0
				332	0–13–0
				229	0–5–0
				233	0–1–10
				334	0–1–0
				328	0–1–0
				263	1–2–0
				265	0–0–10
				271	0–0–2

[सं. O–14016/380/85–जी.पी.]

S.O. 44196.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1755 dated 27-4-85 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Islam Nagar	Bhagvant Nagar	260	0–15–0
				262	0–7–0
				258	0–8–0
				259	0–1–0
				256	0–11–0
				257	0–6–0
				264	0–4–0
				272	0–15–10
				273	0–1–10
				278	0–2–5
				296	0–10–0
				297	0–9–0
				294	0–0–10
				295	1–4–0
				279	0–1–15
				283	0–16–0
				281	0–9–5
				282	0–5–8
				284	0–15–0
				332	0–13–0
				229	0–5–0
				233	0–1–10
				334	0–1–0
				328	0–1–0
				263	1–2–0
				265	0–0–10
				271	0–0–2

[No. O-14016/380/85-GP]

का. आ. 4417.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 1356 तारीख 23-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभ बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजैक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	आंवला	बलिया	कटका भरत	128	0-18-10
				127	0-2-16
				131	0-8-8
				132	0-7-10
				133	0-2-10
				124	0-0-12
				139	0-7-5
				137	0-9-12
				136	0-0-10
				135	0-0-5
				145	0-0-18
				146	0-5-0
				147	0-4-16
				148/1	0-2-16
				148/2	0-7-5
				129	0-1-4
				116	0-0-12
				143	0-0-12
				140	0-0-12

[सं. O-14016/149/85-जी.पी.]

S.O. 4417.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Petroleum) S.O. 1256 dated 23-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declares its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted reprot to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd., free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awlah	Billia	Kata Bharat	128	0-18-10
				127	0-2-16
				131	0-8-8
				132	0-7-10
				133	0-2-10
				124	0-0-12
				139	0-7-5
				137	0-9-12
				136	0-0-10
				135	0-0-5
				145	0-0-18
				146	0-5-0
				147	0-4-16
				148/1	0-2-16
				148/2	0-7-5
				129	0-1-4
				116	0-0-12
				143	0-0-12
				140	0-0-12

[No. O-14016/149/85-GP]

का. आ. 4418—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 4511 तारीख 22-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजैक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
इटावा	बिधूना	बिधूना	अगहरा	1	0–25
				20	0–18
				21	0–24
				16	0–17
				23	1–16
				82	0–73
				110	0–05
				116	1–30
				112	0–10
				115	1–23
				144	0–16
				143	0–12
				141	0–07
				142	0–25
				139	0–39
				140	0–06
				258	0–75
				260	0–05
				267	0–27
				264	0–50
				263	0–18
				266	0–33
				265	0–28
				283	0–07
				284	0–69
				281	0–33
				328	0–49
				329	0–22
				331	0–03
				330	0–09
				336	0–20
				466	0–12
				701	0–12
				540	0–07
				502	0–04
				541	0–05
				544	0–52
				545	0–20
				546	0–47
				676	0–52
				670	0–34
				680	0–66
				683	1–07
				684	0–10
				667	0–12
				633	1–16
				631	0–22
				617	1–20
				618	0–09
				622	0–05
				619	0–02
				620	0–04
				623	0–07
				624	0–04
				22	0–07
				261	0–03
				286	0–04
				500	0–13
				501	0–73
				285	0–01
				547	0–01
				621	0–53

[सं. O-14016/401/85-जी.पी.]

S.O. 4418.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4511 dated 22-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajra Barcilly Jagdishpur Pipeline Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	4	4	5	6
Etawa	Bidhwna	Bidhwna	Aghra	1	0–25
				20	0–18
				21	0–24

1	2	3	4	5	6
				16	0–17
				23	1–16
				82	0–73
				110	0–05
				116	1–30
				112	0–10
				115	1–23
				144	0–16
				143	0–12
				141	0–07
				142	0–25
				139	0–39
				140	0 06
				258	0–75
				260	0–08
				267	0–27
				264	0–50
				263	0–18
				266	0–33
				265	0–28
				283	0–07
				284	0–69
				281	0–33
				328	0–49
				329	0–22
				331	0–03
				330	0–09
				336	0–20
				466	0–12
				701	0–12
				540	0–07
				502	0–04
				541	0–05
				544	0–52
				545	0–20
				546	0–47
				676	0–52
				670	0–34
				680	0–66
				683	1–07
				684	0–10
				667	0–12
				633	1–16
				631	0–22
				617	1–20
				618	0–09
				622	0–05
				619	0–02
				620	0–04
				623	0–07
				624	0–04
				22	0–07
				261	0–03
				286	0–04
				500	0–13
				501	0–73
				285	0–01
				547	0–01
				621	0–53

[No. O-14016/401/85-GP]

का॰आ॰ 4419.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का. आ. 996 तारीख 9-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि॰ में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजैक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	दातागंज	सलेमपुर	लाहुडीरा	254	1–8–2
				257	0–0–18
				265	0–18–0
				264	0–6–0
				266	0–19–0
				267	0–6–0
				272	0–9–3
				268	0–1–0
				चकमार्ग	0–1–0

[सं. O–14016/122/85–जीपी]

S.O. 4419.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, (Department of Petroleum) S.O. 996 dated 9-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Dataganj	Salimpur	Loh-daura	254	1–8–2
				257	0–0–18
				265	0–18–0
				264	0–6–0
				266	0–19–0
				267	0–6–0
				272	0–9–3
				268	0–1–0
				Chak marg	0–1–0

[No.O-14016/122/85-GP]

का. आ. 4420 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. सं 1022 तारीख 9-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजैक्ट।

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	दातागंज	सलेमपुर	धनेली	69	0–8–10
				71	0–3–12
				70/1	0–1–5
				68	0–6–0
				67	1–17–0
				66	2–5–10
				65	0–5–0
				45	0–1–15
				47	0–0–10

[सं. O–14016/128/85–जी.पी.]

S.O. 4420.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1002 dated 9-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Dataganj	Salampur	Dhaneli	69	0–8–10
				71	0–3–12
				70/1	0–1–5
				68	0–6–0
				67	1–17–0
				66	2–5–10
				65	0–5–0
				45	0–1–15
				47	0–0–10

[No. O- 14016/128/85-GP]

का. आ. 4421 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं० 1749 ता० 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन लिए के एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन को इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजैक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	इस्लामनगर	सुन्दर नगर	96	1-1-12
				95	0-15-0
				94	0-4-15
				91	0-1-4
				78	0-19-4
				79	0-4-0
				83	0-12-0
				82	0-13-4
				69	0-1-16
				20	0-16-15
				30	0-1-16
				46	0-4-16
				45	0-10-16
				43	0-12-0
				42	0-12-0
				40/2	0-2-0
				40/1	0-6-0
1	2	3	4	5	6
				39	0-9-12
				176	0-3-12
				177	0-9-12
				178	0-10-15
				174	0-12-0
				171	0-10-16
				172	0-4-0
				170	0-1-4
				193	0-4-16
				194	0-18-12
				198	0-16-4
				199	0-18-0
				195	0-14-8
				173	0-0-10
				188	0-0-10
				छूटा है	0-1-0

[सं. O-14016/266/85-जी.पी]

S.O. 4421.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1749 dated 27-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Islam Nagar	Sunder Nagar	96	1-1-12
				95	0-15-0
				94	0-4-15
				91	0-1-4
				78	0-19-4
				79	0-4-0
				83	0-12-0
				82	0-31-4
				69	0-1-16

1	2	3	4	5	6
				20	0-16-15
				30	0-1-16
				46	0-4-16
				45	0-10-16
				43	0-12-0
				42	0-12-0
				40/2	0-2-0
				40/1	0-6-0
				39	0-9-12
				176	0-3-12
				177	0-9-12
				178	0-10-15
				174	0-12-0
				171	0-10-16
				172	0-4-0
				170	0-1-4
				193	0-4-16
				194	0-18-12
				198	0-16-4
				199	0-18-0
				195	0-14-8
				173	0-0-10
				188	0-0-10
				छूटा है	0-1-0

[No. O-14016/266/85-GP]

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1985

का. आ. 4422.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 का (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का.आ. सं. 1976 तारीख 9-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीश पुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायू	दातागंज	सलेम पुर	रसूलपुर	193	0-0-18

[सं. O-14016/97/85-जी०पी०]

New Delhi, the 12th September, 1985

S.O. 4422.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Petroleum) S.O. 1976 dated 9-3-85 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this not ification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Data-ganj	Salam-pur	Rusul-pur	193	0-0-18

[No. O-14016/97/85-GP]

का. आ. 4423.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना

का.आ.सं. 995, तारीख 9-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया एकड़
1	2	3	4	5	6
बदायूं	दातागंज	सलेमपुर	बरीसरोहा	488	0—13—0
				488/689/10	1-2
				488/689/30	6-5
				488/689/10	11—10
				488/689/50	8—15

[सं. O—14016/121/85—जी॰पी॰]

S.O. 4423.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 995 dated 9-3-85 under sub-secion (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Comoetent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot-No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Data-ganj	Salam-pur	Bari-Sohara	488	0–13–0
				488/689/10	1–2
				488/689/30	6–5
				488/689/40	11–10
				488/689/50	8–15

[No. O-14016/121/85-GP]

का. आ. 4424.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 992 तारीख 9-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	दातागंज	सलेमपुर	अमरौली	425	0—1—5
				424	1—2—2
				415	0—6—5
				416	0—7—16
				417	0—12—16
				411	0—12—0
				403	0—0—5
				410	0:9—7
				404	0—16—0
				407	0—3—5
				406	0—3—15
				405	0—2—10
				386	1—5—5
				383	0—1—4
				323	2—0—16
				325	0—17—3
				326	1—9—10
				377	1—4—4
				297	1—15—9
				309	0—1—5

[सं. O—14016/123/85-जी.पी]

S.O. 4424.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 997 dated 9-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Data-ganj	Salam-pur	Amrully	425	0-1-5
				424	1-2-2
				415	0-6-5
				416	0-7-16
				417	0-12-16
				411	0-12-0
				403	0-0-5
				410	0-9-7
				404	0-16-0
				407	0-3-5
				406	0-3-15
				405	0-2-10
				386	1-5-5
				383	0-1-4
				323	2-0-16
				325	0-17-3
				326	1-9-10
				327	1-4-4
				297	1-15-9
				309	0-1-5

[No. O-14016/123/85-GP]

का आ. 4425—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 999 तारीख 9-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा, बरेली, जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	दातागंज	सलेमपुर	सीर जैलाल	28	0–10–0
				3	1–1–16
				5	0–0–12
				6	1–15–0
				7	0–0–4
				2	0–7–14
				8	0–1–0
				1	0–5–10

[सं. O–14016/125/85 जी.पी.]

S.O. 4425.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Petroleum) S.O. 999 dated 9-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the scheduled appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project.

Distt.	Teh.	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Data-ganj	Salam-pur	Seor Jailal	28	0–10–0
				3	1–1–16
				5	0–0–12
				6	1–15–0
				7	0–0–4
				2	0–7–14
				8	1–0–0
				1	0–5–10

[No. O-14016/125/85 GP]

का. आ. 4426.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 1000 तारीख 9-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है .

और आगे उस धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं०	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	दातागंज	सलेमपुर	डियूनी	686	0–16–10
				687	0–14–10
				684	0–7–5
				683	0–11–10
				681	0–5–15
				682	0–19–17
				680	0–0–15
				679	0–16–4
				668	0–18–12
				450	0–4–0
				448	0–0–2
				744	
				667	0–0–2
				666	0–0–2
				314	0–0–15
				449	1–9–14
				313	1–0–8
				312	1–5–16
				309	1–5–4
				307	0–15–12
				305	1–3–8
				304	0–0–5

1	2	3	4	5	6
बदायूं	दाता-गंज	सलेम-पुर	दियूनी	303	0-15-12
				चाक-मार्ग	0-0-15
				460	0-13-10
				461	0-0-15
				459	0-13-5
				458	1-1-12
				457	0-3-0
				456	0-4-10
				455	1-8-15
				500	0-9-0
				499	0-3-10
				498	0-4-0
				689	0-0-2

[सं. O-14016/126/85-जी.पी.]

S.O. 4426.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 1000 dated 9-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Data-ganj	Solam-pur	Deuni	686	0-16-10
				687	0-14-10
				684	0-7-5
				683	0-11-10
				681	0-5-15
				682	0-19-17
				680	0-0-15
				679	0-16-4
				668	0-18-12
				450	0 4-0
				448/744	0-0-2
				667	0-0-2
				666	0-0 2
				314	0-0-15
				449	1-9-14
				313	1-0-8
				312	1-5-16
				309	1-5-4
				307	0-15-12
				305	1-3-8
				304	0-0-5
				303	0-15-12
				Chak-marg	0-0-15
				460	0-13-10
				461	0-0-15
				459	0-13-5
				458	1-1-12
				457	0-3-0
				456	0-4-10
				455	1-8-15
				500	0-9-0
				499	0-3-10
				498	0-4 0
				689	0-0-2

[No. O-14016/126/85—GP]

का. आ. 4427.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1001 तारीख 9-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे अत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	दातागंज	सलेमपुर	कनेई	389	0–2–10
				388	0–13–5
				387	0–8–10
				386	0–14–10
				385	0–17–0
				383	0–15–0
				380	0–11–10
				379	0–10–15
				376	0–17–0
				374	0–9–10
				375	0–0–15
				373	0–0–15
				366	0–9–0
				365	0–16–15
				362	0–15–0
				363	0–6–5
				360	0–5–15
				359	0–2–5
				315	0–2–10
				299	0–1–5
				310	0–4–0
				297	0–15–0
				296	0–0–10

[सं. O-14016/127/85-जी:पी.]

S.O. 4427.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1001 dated 9-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira - Bareilly—Jagdishpur Pipeline Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1.	2	3	4	5	6
Bodaun	Data-ganj	Solam-pur	Kanei	389	0–2–10
				388	0–13–5
				387	0–8–10
				386	0–14–10
				385	0–17–0
				383	0–15–0
				380	0–11–10
				379	0–10–15
				376	0–17–0
				374	0–9–10
				375	0–0–15
				373	0–0–15
				366	0–9–0
				365	0–16–15
				362	0–15–0
				363	0–6–5
				360	0–5–15
				359	0–2–5
				315	0–2–10
				299	0–1–5
				310	0–4–0
				297	0–15–0
				296	0–0–10

[No. O-14016/127/85—GP]

का. आ. 4428.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1003 तारीख 9-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में

उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	दाता-गंज	सलेम-पुर	कुमा	1168	2–4–2
				1169	1–8–4
				1172	0–19–16
				1171	0–13–0
				1158	0–2–14
				1148	0–10–6
				1150	0–8–0
				1149	1–19–0
				1151	0–8–0
				1100	0–15–0
				1097	0–1–0
				1099	0–0–2
				1013	0–0–4
				1014	0–8–0
				1015	0–0–3
				1016	0–5–0
				1004	0–7–18
				1003	0–1–10
				1017	0–6–10
				1098	0–2–2
				1002	0–16–0
				1000	0–0–12
				1023	1–2–16
				1029	0–2–10
				1024	1–1–9
				1026	0–9–7
				1027	0–1–10
				1053	0–10–0
				528	0–8–4
				529	1–7–0
				526	0–1–0
				524	0–1–5
				523	0–2–0
				522	0–4–10
				532	0–16–0
				533	0–13–5
				534	0–1–4
				537	2–4–16
				463	1–10–0
				464	1–6–8
				498	0–8–8
				495	0–8–8
				494	0–10–16
				486	0–0–8
				492	0–2–6
				491	0–7–12
				487	0–4–0
				489	0–9–0

[स. O–14016/129/85–जी. पी.]

S.O. 4428.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1003 dated 9-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira—Bareilly—Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badun	Data-ganj	Solam-pur	Kuma	1168	2–4–2
				1169	1–8–4
				1172	0–19–16
				1171	0–13–0
				1158	0–2–14
				1148	0–10 6
				1150	0 8–0
				1149	1–19–0
				1151	0–8–0
				1100	0–15–0
				1097	0 1–0
				1099	0–0 2

1	2	3	4	5	6
				1013	0-0-4
				1014	0-8-0
				1015	0-0-3
				1016	0-5-0
				1004	0-7-18
				1003	0-1-10
				1017	0-6-10
				1098	0-2-2
				1002	0-16-0
				1000	0-0-12
				1023	1-2-16
				1029	0-2-10
				1024	1-1-9
				1026	0-9-7
				1027	0-1-10
				1053	0-10-0
				528	0-8-4
				529	1-7-0
				526	0-1-0
				524	0-1-5
				523	0-2-0
				522	0-4-10
				532	0-16-0
				533	0-13-5
				534	0-1-4
				537	2-4-16
				463	1-10-0
				464	1-6-8
				498	0-8-8
				495	0-8-8
				494	0-10-16
				486	0-0-8
				492	0-2-6
				491	0-7-12
				487	0-4-0
				489	0-9-0

[No. O-14016/129/85-GP]

का. आ. 4429.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम मंत्रालय) की अधिसूचना का. आ. सं० 1004 तारीख 9-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट ।

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायु	दातागंज	सलेमपुर	खुकड़ी	910	0-15-0
				911	1-0-15
				908	0-0-8
				909	0-18-16
				878	0-5-10
				879	1-3-10
				883	1-17-10
				884	0-8-10
				525	0-19-4
				526	1-1-5
				541	0-18-5
				542	0-14-0
				543	0-0-13
				544	1-5-0
				548	0-0-15
				558	0-15-10
				553	0-11-11
				554	0-3-5
				555	0-15-5
				556	0-1-5
				832	0-7-0
				696	0-5-5
				695	0-5-0
				729	0-5-0
				694	0-11-7
				693	0-1-0
				573	0-10-0
				576	0-12-0
				577/1	0-1-10
				577/2	0-3-15
				578	0-6-10
				579	0-0-5
				586	0-8-10
				581	0-0-2
				585	0-8-10
				587	0-11-0

1	2	3	4	5	6
			खुर्खी (जारी)	589	0–5–0
				593	0–5–0
				592	0–5–16
				591	0–8–0
				590	0–5–0
				600	0–2–15
				601	0–2–5
				603	0–1–15
				609	0–12–0
				612	1–6–12
				613	0–18–15
				614	0–12–0
				615	0–5–10
				624	2–6–15
				633	0–3–0
				632	0–2–0
				627	0–0–15
				625	0–0–5
				623	0–0–12
				622	0–19–0
				871	0–1–5
				617	0–2–5

[सं. O–14016/ 130/85–जी.पी.]

S.O. 4429.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Deptt. of Petroleum) S.O. No. 563 dated 23-1-85 under sub-section (') of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended tothat notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira—Bareilly—Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Dataganj	Salempur	Khurkhi	910	0–15–0
				911	1–0–15
				908	0–0–8
			Khurkhi (Contd.)	909	0–18–16
				878	0–5–10
				879	1–3–10
				883	1–17–10
				884	0–8–10
				525	0–19–4
				526	1–1–5
				541	0–18–5
				542	0–14–0
				543	0–0–13
				544	1–5–0
				548	0–0–15
				558	0–15–10
				553	0–11–11
				554	0–3–5
				555	0–15–5
				556	0–1–5
				832	0–7–0
				696	0–5–5
				695	0–5–0
				729	0–5–0
				694	0–11–7
				693	0–1–0
				573	0–10–0
				576	0–12–0
				577/1	0–1–10
				577/2	0–3–15
				578	0–6–10
				579	0–0–5
				586	0–8–10
				581	0–0–2
				585	0–8–10
				587	0–11–0
				589	0–5–0
				593	0–5–0
				592	0–5–16
				591	0–8–0
				590	0–5–0
				600	0–2–15
				601	0–2–5
				603	0–1–15
				609	0–12–0
				612	1–6–12
				613	0–18–15
				614	0–12–0
				615	0–5–10
				624	2–6–15
				633	0–3–0
				632	0–2–0
				627	0–0–15
				625	0–0–5
				623	0–0–12
				622	0–19–0
				871	0–1–5
				617	0–2–5

[No.O–14016/130/85–G.P.]

का. आ. 4430.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 1653 तारीख 20-4-85 द्वारा, केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं०	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	सतासी	ससईया	402/1	1–2–14
				389/1	1–6–8
				388/1	1–7–12
				387/1	0–1–0
				387/2	0–0–3
				25	0–2–8
				17/1, 17/2, 17/3	0–15–0
				16/2	0–0–15
				15/1, 15/2	1–13–12
				14	1–11–12
				5	0–4–15
				44/1, 44/2	0–18–0
				45/1, 45/2	1–7–12
				66	1–7–8
				70/1	0–9–0
				83/1	0–15–12
				84	0–1–5
				82	0–11–10
बदायूं (जारी)			ससईया (जारी)	81	1–7–12
				80	0–3–10
				81/454	0–9–12

[सं. O–14016/213/85 जी०पी०]

S.O. 4430.—Whereas by notification of the Government of India in the Minister yof Energy (Deptt. of Petroleum) S.O. No. 1653 dated 20-4-1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 o fthe said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira–Bareilly–Jagdishpur Pipel ne Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bodaun	Bish-auli	Satshi	Siseyeya	402/1	1–2–14
				389/1	1–6–8
				388/1	1–7–12
				387/1	0–1–0
				387/2	0–0–3
				25	0–2–8
				17/1, 17/2, 17/3	0–15–0
				16/2	0–0–15
				15/1, 15/2	1–13–12
				14	1–11–12
				5	0–4–15
				44/1, 44/2	0–18–0
				45/1, 45/2	1–7–12
				66	1–7–8

1	2	3	4	5	6
Siseyeya (Contd.)				70/1	0-9-0
				83/1	0-15-12
				84	0-1-5
				82	0-11-10
				81	1-7-12
				80	0-3-10
				81/454	0-9-12

[No. O-14016/213/85-G.P.]

का० आ० 4431 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का०आ० सं० 1657 तारीख 20-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे इस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	बिसौली	कल्यानपुर	279	0-2-10
				278	0-14-0
				275	0-4-4
				273	1-8-4
				272	1-7-12
				274	0-3-0
				237	0-2-0
				6	0-4-0
				35	0-17-0
				37	0-3-0
				32	0-1-10
				33	0-18-0
				31	0-7-0
				30	0-7-10
				29	0-11-5
				17	0-1-8
				18	0-7-16
				20	0-4-16
				21	0-7-10
				22	0-4-15
				36	0-12-0

[सं. O-14016/217/85-जीपी]

S.O. 4431.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, (Department of Petroleum) S.O. 1657 dated 20-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bishauli	Bishauli	Kalyan-pur	279	0-2-10
				278	0-14-0
				275	0-4-4
				273	1-8-4
				272	1-7-12
				274	0-3-0
				237	0-2-0
				6	0-4-0
				35	0-17-0
				37	0-3-0
				32	0-1-10
				33	0-18-0

1	2	3	4	5	6
Kalyanpur (Contd.)				31	0-7-0
				30	0-7-10
				29	0-11-5
				17	0-1-8
				18	0-7-16
				20	0-4-16
				21	0-7-10
				22	0-4-15
				36	0-12-0

[No. O-14016/217/85-GP]

का. आ. 4432:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का.आ.सं. 1659 तारीख 20-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बंधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	सतासी	सिसौरी	109	0-1-15
				111	0-8-10
				113	0-12-0
				115	0-1-5
				84	0-1-0
				85	1-7-0
				86	0-2-8
				87	0-4-4
				119	0-1-15

1	2	3	4	5	6
			सिसौरी (जारी)	117	0-1-7
				78	0-4-16
				79	1-4-12
				83	0-1-0
				218	0-2-8
				220	0-7-4
				221	0-16-15
				222	0-0-12
				223	0-6-10
				247	0-10-16
				249	0-3-10
				250	0-13-16
				251	0-4-16
				252	0-2-0
				256	0-1-5
				239	0-1-0
				240	0-7-0
				241	0-1-0
				232	0-2-10
				233	0-2-10
				234	0-10-16
				236	0-6-0
				275	0-10-16
				276	0-12-0
				277	0-1-15
				305	0-2-8
				338	0-7-16
				351	1-1-0
				339	0-8-12
				340	0-2-6
				352	0-0-10
				353	0-3-10
				395	0-14-16
				396	0-18-0
				398	0-2-4
				399	0-12-12
				400	0-3-15

[सं. O-14016/219/85-जी.पी.]

S.O. 4432.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, (Department of Petroleum) S.O. 1659 dated 20-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-BareillyJa gdishpur Pipeline Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Satarhi	Sisouri	109	0-1-15
				111	0-8-10
				113	0-12-0
				115	0-1-5
				84	0-1-0
				85	1-7-0
				86	0-2-8
				87	0-4-4
				119	0-1-15
				117	0-1-7
				78	0-4-16
				79	1-4-12
				83	0-1-0
				218	0-2-0
				220	0-7-4
				221	0-16-15
				222	0-0-12
				223	0-6-10
				247	0-10-16
				249	0-3-10
				250	0-13-16
				251	0-4-16
				252	0-2-0
				256	0-1-5
				239	0-1-0
				240	0-7-0
				241	0-0-1
				232	0-2-10
				233	0-2-10
				234	0-10-16
				236	0-6-0
				275	0-10-16
				276	0-12-0
				277	0-1-15
				305	0-2-8
				338	0-7-16
				351	1-1-0
				339	0-8-12
				340	0-2-6
				352	0-0-10
				353	0-3-10
				395	0-14-16
				396	0-18-0
				398	0-2-4
				399	0-12-12
				400	0-3-15

[No. O-14016/219/85—GP]

का०आ० 4423:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 1863 तारीख 20-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट ।

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	बिसौली	पुरोहित खेड़ा	229	1-8-4
				228	0-5-8
				227	0-16-15
				226	0-6-15
				243	0-1-16
				245	0-9-0

288	1-4-15
291	0-0-5
292	0-5-10
334	0-0-5
333	0-12-10
336	0-1-0
335	0-0-5
337	0-5-10
338	0-1-0
350	0-7-15
349	0-4-10
353	0-2-10
354	0-4-15
356	0-7-10
357	0-3-0
358	0-4-0
516	0-1-15
361	0-13-0
359	0-0-5
514	0-9-0
515	0-3-5
366	0-0-5
512	0-12-12
513	0-4-10
522	0-4-5
530	0-13-4
523	0-0-2
529	0-16-4
535	0-13-10
533	0-3-10
534	0-3-10
548	0-12-15
504	0-0-2
547	0-2-0
549	0-7-15
550	0-6-0
500	0-2-4
488	0-11-10
487	1-4-10
484	0-6-0
485	0-12-0
483	0-0-5
532	0-0-16

[सं O-14016/ 223/85-जी. पी.]

S.O. 4433.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1663 dated 20-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira—Bareilly—Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Bisauli	Purohit Khera	229	1-8-4
				228	0-5-8
				227	0-16-15
				226	0-6-15
				243	0-1-16
				245	0-9-0
				288	1-4-15
				291	0-0-5
				292	0-5-10
				334	0-0-5
				333	0-12-10
				336	0-1-0
				335	0-0-5
				337	0-5-10
				338	0-1-0
				350	0-7-15
				349	0-4-10
				353	0-2-10
				354	0-4-15
				356	0-7-10
				357	0-3-0
				358	0-4-0
				516	0-1-15
				361	0-13-0
				359	0-0-5
				514	0-9-0
				515	0-3-5

1	2	3	4	5	6
				366	0-0-5
				512	0-12-12
				513	0-4-10
				522	0-4-5
				530	0-13-4
				523	0-0-2
				529	0-16-4
				535	0-13-10
				533	0-3-10
				534	0-3-10
				548	0-12-15
				504	0-0-2
				547	0-2-0
				549	0-7-15
				550	0-6-0
				500	0-2-4
				488	0-11-10
				487	1-4-10
				484	0-6-0
				485	0-12-0
				483	0-0-5
				532	0-0-16

[No. O-14016/223/85-GP]

का.आ. 4434.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1664 तारीख 20-4-1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजिरा—बरेली —जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट ।

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं०	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	बिसौली	खजुरिया	1	0-6-0
				3	0-3-0
				130	0-3-15
				133	0-0-5
				135	0-13-12
				134	0-8-0
				136	0-12-13
				139	0-1-0

[सं. O-14016/224/85-जी.पी.]

S.O. 4434.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1664 dated 20-4-85 under sub-section (1) of Section of 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira—Bareilly—Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bishuli	Bishuli	Khaju-riya	1	0-6-0
				3	0-3-0
				130	0-3-15
				133	0-0-5
				135	0-13-12
				134	0-8-0
				136	0-12-13
				139	0-1-0

[No. O-14016/224/85-GP]

का. आ. 4435 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1665 तारीख 20-4-1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट ।

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	सतासी	सडौली	99	0-4-16
				117	1-2-4
				108	0-1-16
				107	0-18-0
				106	0-13-4
				109	0-0-3
				110	0-1-10
				111	0-1-0
				112	0-18-0
				105	0-2-5
				144	0-2-0
				396	1-16-0
				395	0-0-10
				394	0-7-0
				370	0-3-17
				371	0-5-8
				372	0-0-10
				367	1-0-10
				374	0-3-6
				375	0-0-15
				376	0-15-12
				333	0-8-12
				332	0-15-0
				340	0-1-5
				330	0-1-15
				331	0-1-0
				332	0-12-0
				329	0-8-6
				344	0-10-0
				325	0-2-8
				322	0-10-4
				321	0-2-12
				320	1-5-4
				313	0-1-5
				314	0-1-15
				303	1-0-10
				288	0-4-4
				302	0-9-8
				289	0-0-5
				301	1-10-12
				296	0-3-12

[सं. O-14016-225/85-जीपी]

S.O. 4435.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1665 dated 20-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Satashi	Sodali	99	0-4-16
				117	1-2-4
				108	0-1-16
				107	0-18-0
				106	0-13-4
				109	0-0-3
				110	0-1-10
				111	0-1-0
				112	0-18-0
				105	0-2-5
				144	0-2-0
				396	1-16-0
				395	0-0-10
				394	0-7-0
				370	0-3-17
				371	0-5-8
				372	0-0-10
				367	1-0-10
				374	0-3-6
				375	0-0-15
				376	0-15-12
				333	0-8-12
				332	0-15-0
				340	0-1-5
				330	0-1-15
				331	0-1-0
				342	0-12-0
				329	0-8-8
				344	0-10-0
				325	0-2-8
				322	0-10-4
				321	0-2-12
				32;	1-5-4
				313	0-1-5
				314	0-1-15
				303	1-0-10
				288	0-4-4
				302	0-9-8
				289	0-0-5
				301	1-10-17
				296	0-3-12

[No. O-14016/225-85/GP]

का. आ. 4436.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1666 तारीख 20-4-1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट ।

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	बिसौली	बेहरा कोढ़ा	168	0-2-0
				169	0-10-16
				170	0-2-10
				171	0-3-0
				258	0-4-16
				260	1-2-4
				261	0-12-0
				262/1	1-7-12
				262/2	
				265	0-15-0
				266	0-7-0
				267	0-12-0
				268	0-10-16
				269	0-15-12
				270	0-0-6
				296	1-2-5
				297	0-10-4
				298	0-2-0
				299	0-10-10
				300	0-1-15
				305	0-13-5
				306	0-9-12

[सं. O-14016/226/85-जी. पी.]

S.O. 4436.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1666 dated 20-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipo Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Bisauli	Behta-kara	168	0-2-0
				169	0-10-16
				170	0-2-10
				171	0-3-0
				258	0-4-16
				260	1-2-0
				261	0-12-0
				262/1	1-7-12
				262/2	
				265	0-15-0
				266	0-7-0
				267	0-12-0
				268	0-10-16
				269	0-15-12
				270	0-0-6
				296	1-2-5
				297	0-10-4
				298	0-2-0
				299	0-10-10
				300	0-1-15
				305	0-13-5
				306	0-9-12

[No O-14016/226/85-G.P.]

का. आ. 4437.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1667 तारीख 20-4-1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट ।

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	बिसौली	शिमालपुर	2	0-5-0
				3	1-0-10
				4	0-1-5
				5	0-5-0

[सं. O-14016/227/85-जी. पी.]

S.O. 4437.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1667 dated 20-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acqtisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bishuli	Bishuli	Jamal-pur	2	0–5–0
				3	1–0–10
				4	0–1–5
				5	0–5–0

[No. O-14016/227/85-G.P.]

का. आ. 4458.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1668 तारीख 20-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	सतासी	अगोई	92	0-1-16
				102	0-13-4
				103	0-0-5
				101	1-2-10
				100	0-0-10
				97	0-12-8
				98	0-4-4
				113	0-11-2
				114	0-2-2
				84	0-4-4
				83	0-4-0
				82	0-0-10
				71	0-2-15
				72	0-7-10
				73	0-3-10
				69	0-10-10
				74	0-1-5
				68	0-8-10
				66	0-14-2
				60	0-10-16
				59	0-1[illegible]-5
				181	0-0-8
				188	0-0-5
				190	0-11-0
				189	0-10-0
				61	0-1-8
				57	0-2-0
				54	0-2-0
				216	0-19-16
				215	0-6-5
				212	0-15-0
				210	0-0-16
				210/675	0-7-0
				211	0-15-0
				205	1-5-16
				202	0-15-0
				298	0-3-3

1	2	3	4	5	6
				201	0-2-8
				299	0-9-10
				303	0-0-5
				304	0-8-8
				305	0-10-8
				308	0-13-0
				309	0-2-10
				312	0-4-4
				313	0-4-4
				314	0-3-15
				315	0-7-15
				316	0-2-10
				319	0-11-8
				320	0-4-0
				321	0-0-5
				322	0-3-0
				323	0-18-12
				324	0-3-0
				378	0-18-12
				382	0-4-4
				380	0-1-10
				379	0-1-4
				381	0-0-10
				419	0-10-4
				413	1-12-0
				417	0-3-0
				418	0-12-0
				436	1-1-10
				437	0-12-18
				439	0-4-0
				438	0-9-0
				457	0-19-0
				458	0-3-15
				455	0-4-16

[सं. O-14016/228/85-जी. पी.]/

S.O. 4438.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1668 dated 20-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (J) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bishouli	Satashi	Aegoi	92	0-1-16
				102	0-13-4
				103	0-0-5
				101	1-2-10
				100	0-0-10
				97	0-12-8
				98	0-4-4
				113	0-11-2
				114	0-2-2
				84	0-4-4
				83	0-4-0
				82	0-0-10
				71	0-2-15
				72	0-7-10
				73	0-3-10
				69	0-10-10
				74	0-1-5
				68	0-8-10
				66	0-14-2
				60	0-10-16
				59	0-14-5
				181	0-0-8
				188	0-0-5
				190	0-11-0
				189	0-10-0
				61	0-1-8
				57	0-2-0
				54	0-2-0
				216	0-19-16
				215	0-6-5
				212	0-15-0
				210	0-0-16
				210/675	0-7-0
				211	0-15-0
				205	1-5-16
				202	0-15-0
				298	0-3-3
				201	0-2-8
				299	0-9-10
				303	0-0-5

1	2	3	4	5	6
				304	0-8-8
				305	0-10-8
				308	0-13-0
				309	0-2-10
				312	0-4-4
				313	0-4-4
				314	0-3-15
				315	0-7-15
				316	0-2-10
				319	0-11-8
				320	0-4-0
				321	0-0-5
				322	0-3-0
				323	0-18-12
				324	0-3-0
				378	0-18-12
				382	0-4-4
				380	0-1-10
				379	0-1-4
				381	0-0-10
				419	1-10-4
				413	1-12-0
				417	0-3-0
				418	0-12-0
				436	1-1-10
				437	0-12-18
				439	0-4-0
				438	0-9-0
				457	0-19-0
				458	0-3-15
				455	0-4-16

[No. O-14016/228/85-G.P.]

का.आ. 4439.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पैट्रोलियम विभाग की अधिसूचना स. का. आ. 1669 तारीख 20-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	हसील	परगना	गांव	गाटा सं	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	बिसौली	गटगांव	373	0-1-4
				374	1-7-17
				560	0-10-16
				561	0-18-12
				562	0-14-10
				563	0-1-0
				555	0-8-8
				556	1-7-8
				554	0-1-0
				572	0-3-10
				551	0-2-0
				552	1-2-3
				553/1	0-10-10
				539	0-2-0
				540	0-13-7
				541	1-0-12
				536	0-3-17
				537	0-7-16
				538	0-16-3
				509	0-1-0
				510	0-0-16
				511	1-0-10
				508	0-2-0
				546	0-2-10
				394	0-0-5

[सं. O-14016/229/85-जीपी]

S.O. 4439.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1669 dated 20-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bidhu-na	Bisauli	Bisauli	Gadga-van	373	0-1-4
				374	1-7-17
				560	0-10-16
				561	0-18-12
				562	0-14-10
				563	0-4-0
				555	0-8-8
				556	1-7-8
				554	0-1-0
				572	0-3-10
				551	0-2-0
				552	1-2-3
				553/1	0-10-10
				539	0-2-0
				540	0-13-7
				541	1-0-12
				536	0-3-17
				537	0-7-16
				538	0-16-3
				509	0-1-0
				510	0-0-16
				511	1-0-10
				508	0-2-0
				546	0-2-10
				394	0-0-5

[No. O-14016/229/85 G.P.]

का. आ. 4440—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1670 तारीख 20-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट ।

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	बिसौली	बरखेड़ा	31	0-6-0
				32	0-4-0
				33	0-14-0
				35	0-6-0
				36	0-16-8
				37	0-4-15
				38	0-1-10
				49	0-5-10
				50	0-8-4
				51	0-6-15
				52	0-4-10
				53	0-3-5
				54	0-9-12
				55	0-3-10
				67	0-5-10
				68	0-10-0
				69	0-5-10
				70	0-8-10
				77	0-1-10
				78	0-3-4
				117	0-8-8
				47	0-1-10
				48	0-0-10
				71	0-1-5
				34	0-9-12

[सं. O-14016/230/85-जी. पी.]

S.O. 4440.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Petroleum) S.O. 1617 dated 20-4-85 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of the declaration in the Gas Authority of India Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Bisuli	Barkora	31	0-6-0
				32	0-4-0
				33	0-14-0
				35	0-6-0
				36	0-16-8
				37	0-4-15
				38	0-1-10
				49	0-5-10
				50	0-8-4
				51	0-6-15
				52	0-4-10
				53	0-3-5
				54	0-9-12
				55	0-3-10
				67	0-5-10
				68	0-10-0
				69	0-5-10
				70	0-8-10
				77	0-1-10
				78	0-3-4
				117	0-8-8
				47	0-1-10
				48	0-0-10
				71	0-1-5
				34	0-9-12

[No. O-14016/230/85-G.P.]

का० आ० 4441.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ०सं० 1671 तारीख 20-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दी है;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस—ता० में निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	बिसौली	बसई	31	0-3-3
				32	0-0-19
				33	0-0-18
				34	0-9-8
				36	2-8-0
				37	0-6-5
				53	0-10-5
				55	0-4-0
				56	0-0-5
				57	0-13-4
				58	0-14-10

1	2	3	4	5	6
				59	0-0-10
				61	0-2-5
				71	0-0-10
				72	0-17-15
				73	1-5-18
				79	0-10-10
				80	0-16-4
				81	0-0-5
				98	0-1-5
				101	0-10-4
				102/2	0-6-0
				102/1	0 11-8
				116	1-0-6
				117	0-16-4
				119/2	0-2-2
				120	0-3-12
				125	0-0-19
				127	1-1-0
				128	0-17-1
				129	0-1-16
				130	0-15-3
				131	1-0-14
				132	0-1-2
				133	0-2-2
				143	0-2-10
				193	0-1-12
				200	1-2-16
				201	1-6-11
				203	0-12-6
				225	1-7-8
				227	0-19-16
				228	0-0 16
				229	0-5-0

[सं. O-14016/231/85-जी. पी.]

S.O. 4441.—Whereas by notification of the Government India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 1671 dated 20-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquired the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
Badaun	Bisauli	Bisauli	Bashee	31	0-3-3
				32	0 0-19
				33	0-0-18
				34	0-9-8
				36	2 8-0
				37	0-6-5
				53	0-10-5
				55	0-4-0
				56	0-0-5
				57	0-13-4
				58	0-14-10
				59	0-0-10
				61	0-2-5
				71	0-0-10
				72	0-17-15
				73	1-5-18
				79	0-10-10
				80	0-16-4
				81	0-0-5
				98	0-0-5
				102	0-10-4
				102/2	0-6-0
				102/1	0-11-8
				116	0-1-6
				17	0-16-4
				119/2	0-2-2
				120	0-3-12
				125	0-0-19
				127	1-1-0
				128	0-17-1
				129	0-1-16
				130	0-15-3
				131	1 0-14
				132	0-1-2
				133	0-2-2
				143	0-2-10
				193	0-1-12
				200	1-2-16
				201	1-6-11
				203	0-12-6
				225	1-7-8
				227	0-19-16
				228	0-0-16
				229	0-5-0

[No. O-14016/231/85-G.P.]

का० आ० 4442.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० सं० 1788 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5	6
					बि.बी.वि
हरदोई	बिलग्राम	कटियारी	दहेलिया	1848	0–1–15
				1849	0–12–6
				1856	0–1–8
				1857	0–13–10
				1858	0–0–10
				1859	0–14–10
				1862	0–13–10
				1863	0–1–0
				1865	0–2–10
				1877	0–11–0
				1878	0–15–0
				1882	0–19–10
				1884	0–9–0
				1885	0–10–10
				1887	1–10–0
				1902	0–0–15
				1950	0–0–4
				1951	0–0–5
				2046	0–2–0
				2047	0–2–10
				2048	0–16–10
				2050	0–13–0
				2051	0–0–10
				3047	0–4–0
				3095	0–9–0
				3101	0–3–10
				3102	0–9–0
				3103	0–6–10
				3104	0–0–1
				3108	0–0–10
				3109	0–4–0
				3110	0–3–0
				3112	0–3–0
				3113	0–4–0
				3114	0–5–10
				3115	1–5–0
				3060	0–0–10
				3251	0–2–8
				3260	0–1–0
				3261	0–7–10
				3263	0–9–10
				3266	0–11–0
				3267	0–1–0
				3268	0–13–0
				3269	0–6–10
				3270	0–11–0
				3271	0–4–0
				3272	0–9–10
				3099	0–0–5
				3273	0–12–0
				3274	0–1–10
				3275	0–5–10
				3276	0–2–0
				3277	0–0–5
				3319	0–0–19
				3320	0–4–0

1	2	3	4	5	6
			दहेलिया	3321	0–8–10
				3322	0–1–0
				3323	0–3–10
				3324	0–3–10
				3325	0–1–10
				3326	0–6–0
				3328	0–7–0
				3329	0–3–10
				3331	0–12–0
				3338	0–3–0
				3339	0–7–0
				3330	0–8–0
				3341	0–1–0
				3359	0–5–0
				3360	0–10–10
				3361	0–3–0
				3365	0–0–10
				3366	0–2–0
				3415	0–4–10
				3613	0–17–0
				3733	1–1–0
				3737	2–18–0
				3747	3–8–0
				3769	3–12–0
				3771	0–16–0
				3799	1–19–10
				3800	0–11–10
				3802	0–13–0
				3798	1–7–0
				3819	6–0–0
				3820	2–4–0

[सं. O–14016/234/85–जीपी]

S.O. 4442.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1788 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Bilgram	Katiyari	Dahelia	1848	0–1–15
				1849	0–12–6
				1856	0–1–8
				1857	0–13–10
				1858	0–0–10
				1859	0–14–10
				1862	0–13–10
				1863	0–1–0
				1865	0–2–10
				1877	0–11–0
				1878	0–15–0
				1882	0–19–10
				1884	0–9–0
				1885	0–10–10
				1887	1–10–0
				1902	0–0–15
				1950	0–0–4
				1951	0–0–5
				2046	0–2–0
				2047	0–2–10
				2048	0–16–10
				2050	0–13–0
				2051	0–0–10
				3047	0–4–0
				3095	0–9–0
				3101	0–3–10
				3102	0–9–0
				3103	0–6–10
				3104	0–0–1
				3108	0–0–10
				3109	0–4–0
				3110	0–3–0
				3112	0–3–0
				3113	0–4–0
				3114	0–5–10
				3115	1–5–0
				3060	0–0–10
				3251	0–2–0
				3260	0–1–0
				3261	0–7–10
				3263	0–9–10
				3266	0–11–0
				3267	0–1–0
				3268	0–13–0

1	2	3	4	5	6
			Dahelia	3269	0-6-10
			(Contd.)	3270	0-11-0
				3271	0-4-0
				3272	0-9-10
				3099	0-0-5
				3273	0-12-0
				3274	0-1-10
				3275	0-5-10
				3276	0-2-0
				3277	0-0-5
				3319	0-0-9
				3320	0-4-0
				3321	0-8-10
				3322	0-1-0
				3323	0-3-10
				3324	0-3-10
				3325	0-1-10
				3326	0-6-0
				3328	0-7-0
				3329	0-3-10
				3331	0-12-0
				3338	0-3-0
				3339	0-7-0
				3340	0-8-0
				3341	0-1-0
				3359	0-5-0
				3360	0-10-10
				3361	0-3-0
				3365	0-0-10
				3366	0-2-0
				3415	0-4-10
				3613	0-17-0
				3733	1-1-0
				3737	2-18-0
				3747	3-8-0
				3769	3-12-0
				3771	0-16-0
				3799	1-19-10
				3800	0-11-10
				3802	0-13-0
				3798	1-7-0
				3819	6-0-0
				3820	2-4-0

[No. O-14016/234/85-G.P.]

का०आ० 4443.— यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ०सं० 1789 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5	6
हरदोई	शाहाबाद	पाली	मरकड़ा	18	0–2–0
				19	0–0–5
				20	0–14–05
				21	0–12–15
				22	0–12–15
				23	0–0–5
				108	0–12–0
				109	0–16–10
				110	0–10–10
				111	0–5–0
				112	1–17–10
				113	0–3–0
				115	0–1–15
				116	0–7–0
				120	0–0–10
				140	0–6–0
				141	0–4–15
				341	0–12–10

1	2	3	4	5	6
			मरकाड़ा—जारी	342	0–0–5
				345	0–12–10
				356	0–1–10
				357	0–2–10
				358	0–4–0
				359	0–2–0
				360	0–5–0
				421	0–9–5
				466	0–0–5
				475	0–12–10
				476	0–18–10
				478	0–4–10
				479	0–19–10
				487	0–3–5
				489	0–4–0
				490	0–14–10
				491	0–1–10
				492	1–6–5
				493	0–7–5
				480	0–1–10
				118	0–1–5

[सं. O–14016/235/85–जीपी]

S.O. 4443.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1789 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipeline Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Shah-bad	Pali	Markara	18	0–2–0
				19	0–0–5
				20	0–14–5
				21	0–12–15
				22	0–12–15
				23	0–0–5
				108	0–12–0
				109	0–16–10
				110	0–10–10
				111	0–5–0
				112	1–17–10
				113	0–3–0
				115	0–1–15
				116	0–7–0
				120	0–0–10
				140	0–6–0
				141	0–4–15
				341	0–12–10
				342	0–0–5
				345	0–12–10
				356	0–1–10
				357	0–2–10
				358	0–4–0
				359	0–2–0
				360	0–5–0
				421	0–9–5
				466	0–0–5
				475	0–12–10
				476	0–18–10
				478	0–4–10
				479	0–19–10
				487	0–3–5
				489	0–4–0
				490	0–14–10
				491	0–1–10
				492	1–6–5
				493	0–7–5
				480	0–1–10
				118	0–1–5

[No. O–14016/235/85—GP]

का.आ. 4444.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ सं. 1790 तारीख 16–4–85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित रकबा बी. वि.वि.
1	2	3	4	5	6
हरदोई	बिलग्राम	कटियारी	बरामऊ सीसाला	34	0–1–0
				35	0–13–5
				36	0–13–0
				42	0–13–5
				37	0–15–0
				368	0–2–0
				265	0–3–0
				269	0–14–0
				284	0–16–0
				262	0–6–0
				263	0–6–0
				264	0–4–0
				290	0–12–0
				291	0–14–10
				317	0–16–0
				321	0–4–0
				322	0–2–0
				316	0–3–10
				318	0–18–0
				319	0–8–10
				294	0–3–10
				310	0–4–0
				311	0–12–10
				312	0–3–10
				309	0–6–0
				369	0–4–15
				326	0–1–0
				280	0–2–0
				285	0–1–0
				281	0–1–0

[सं. O–14016/236/85–जी.पी.]

S.O. 4444.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1790 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Bilgram	Katiyari	Bard-mau Sisala	34	0-1-0
				35	0-13-5
				36	0-13-0
				42	0-13-5
				37	0-15-0
				268	0-2-0
				265	0-3-0
				269	0-14-0
				284	0-16-0
				262	0-6-0
				263	0-6-0
				264	0-4-0
				290	0-12-0
				291	0-14-10

1	2	3	4	5	6
				317	0-16-0
				321	0-4-0
				322	0-2-0
				316	0-3-10
				318	0-18-0
				319	0-8-10
				294	0-3-10
				310	0-4-0
				311	0-12-10
				312	0-3-10
				309	0-6-0
				369	0-4-15
				326	0-1-0
				270	0-2-0
				285	0-1-0
				281	0-1-0

[No.O -14016/236/85—GP]

का. आ. 4445 :—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1794 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर गैसपाईप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकवा बी.बि.बि.
1	2	3	4	5	6
हरदोई	शाहाबाद	पछोहा	चांदपुर	78	0-0-5
				79	0-19-0
				80	0-6-0
				81	0-7-0
				82	0-8-0
				90	1-16-0
				131	0-2-10
				133	0-0-5
				134	0-1-5
				135	0-1-30
				151	0-1-0
				161	0-1-10
				162	0-17-0
				163	0-1-10
				164	0-5-10
				165	0-0-15
				175	0-17-0
				176	0-3-0
				177	0-7-0
				178	0-14-0
				179	0-12-15
				180	0-12-0
				181	0-0-10
				182	0-1-10
				183	0-17-10
				188	0-1-10
				189	0-9-0
				190	0-14-10
				191	0-3-0
				197	0-1-10
				198	0-0-15
				215	0-2-10
				201	0-8-10
				435	0-0-5
				436	0-12-0
				437	0-7-0
				438	07-0
				439	0-3-10
				441	0-9-5
				443	0-6-0
				444	0-10-0
				445	0-12-0
				446	0-I 2-10
				450	0-3-10
				465	0-3-0

[सं. O-14016/240/85-जी.पी.]

S.O. 4445.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1794 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Vill.	Plot No.	Area Acquired B.V.V.
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Shaha-bad	Pach-hoha	Chand-pur	78	0-0-5
				79	0-19-0
				80	0-6-0
				81	0-7-0
				82	0-8-0
				90	1-16-0
				131	0-2-10
				133	0-0-5
				134	0-1-5
				135	0-1-10
				151	0-1-0
				161	0-1-10
				162	0-17-0
				163	0-1-10
				164	0-5-10
				165	0-0-15
				175	0-17-0
				176	0-3-0
				177	0-7-0
				178	0-14-0
				179	0-12-15
				180	0-12-0
				181	0-0-10
				182	0-1-10
				183	0-17-10
				188	0-1-10
				189	0-9-0
				190	0-14-10
				191	0-3-0
				197	0-1-10
				198	0-0-15
				215	0-2-10
				201	0-8-10
				435	0-0-5
				436	0-12-0
				437	0-7-0
				438	0-7-0
				439	0-3-10
				441	0-9-5
				443	0-6-0
				444	0-10-0
				445	0-12-0
				446	0-12-10
				450	0-3-10
				465	0-3-0

[No. O-14016/240/85—GP]

का० आ० 4446.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ०सं० 1757 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित रकबा बी.बी.बी.
1	2	3	4	5	6
हरदोई	शाहबाद	पछोहा	मुर्तजा-नगर	72	0-5-0
				75	0-7-10
				73	0-13-10
				76	0-10-10
				77	0-8-0
				78	0-5-0
				83	0-1-10
				104	0-18-0
				105	0-10-10
				107	0-7-0
				114	1-4-0
				116	1-10-0
				125	1-8-0
				126/1	0-5-10
				205	0-5-0
				375	0-3-0
				376	0-3-0
				377	0-9-0
				378	0-0-5
				382	2-5-0
				397	0-10-0
				398	0-6-0
				399	1-2-15

[सं. ओ-14016/243/85-जीपी]

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired in acres B. B. B.
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Shah-bad	Pach-hoha	Murtza-nagar	72	0-5-0
				75	0-7-10
				73	0-13-10
				76	0-10-10
				77	0-8-0
				78	0-7-5
				83	0-1-10
				104	0-18-0
				105	0-10-10
				107	0-7-0
				114	1-4-0
				116	1-10-0
				125	1-8-0
				126/1	0-5-10
				205	0-5-0
				375	0-3-0
				376	0-3-0
				377	0-9-0
				378	0-0-5
				382	2-5-0
				397	0-10-0
				398	0-6-0
				399	1-2-15

[No. O-14016/243/85-GP]

S.O. 4446.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Deptt. of Petroleum) S.O. 1757 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from all encumbrances.

का. आ. 4447 :— यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 1767 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा वी.वी.वि.
1	2	3	4	5	6
हरदोई	शाहबाद	पाली	गाजियापुर	21	0-6-0
				22	0-0-10
				31	0-0-10
				32	0-10-0
				33	0-3-0
				34	0-18-0

[सं. ओ-14016/253/85-जी.पी.]

S.O. 4447.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Deptt. of Petroleum) S.O. 4767 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals, Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in B.B.B.
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Shaha-bad	Pali	Gajia-pur	21	0-6-0
				22	0-0-10
				31	0-0-10
				32	0-10-0
				33	0-3-0
				34	0-18-0

[No. O-14016/253/85—GP]

का.आ. 4448.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का.आ. सं. 1768 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा वी.वि.वि.
1	2	3	4	5	6
हरदोई	शाहाबाद	पछोड़ा	पैतपुर	145	0-9-15
				146	0-2-10
				143	0-0-15
				144	0-13-5
				142	0-7-5
				115	0-0-5
				139	0-1-5

1	2	3	4	5	6
				140	0-13-5
				138	0-10-15
				136	0-1-5
				137	0-11-0
				158	0-0-10
				135	0-14-10
				162	0-16-0
				163	0-0-10
				164	0-9-0
				87	0-4-0
				165	0-1-10
				166	0-12-0
				167	0-1-0
				168	0-3-0
				169	0-3-10
				74	0-3-10
				73	0-10-0
				72	0-1-10
				62	1-1-0
				63	0-7-10
				58	0-14-10
				636	0-0-10
				637	1-8-0
				639	0-14-5
				640	0-6-10
				644	0-2-0
				645	0-3-0
				646	0-4-10
				647	0-7-15
				648	0-7-15
				649	0-16-0

[सं. ओ-14016/254/85-जीपी]

S.O. 4448.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1768 dated 16th April, 1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira—Bareilly—Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired B.B.B.
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Shahabad	Pachhoha	Pantpur	145	0-9-15
				146	0-2-10
				143	0-0-15
				144	0-13-5
				142	0-7-5
				115	0-0-5
				139	0-1-5
				140	0-13-5
				138	0-10-15
				136	0-1-5
				137	0-11-0
				158	0-0-10
				135	0-14-10
				162	0-16-0
				163	0-0-10
				164	0-9-0
				87	0-4-0
				165	0-1-10
				166	0-12-0
				167	0-1-0
				168	0-3-0
				169	0-3-10
				74	0-3-10
				73	0-10-0
				72	0-1-10
				62	1-1-0
				63	0-7-10
				58	0-14-10
				636	0-0-10
				637	1-8-0
				639	0-14-5
				640	0-6-10
				644	0-2-0
				645	0-3-0
				646	0-4-10
				647	0-7-15
				648	0-7-15
				649	0-16-0

[No. O-14016/254/85—GP]

का. आ. 4449—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1769 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा बी. वि. वि.
1	2	3	4	5	6
हरदोई	बिलग्राम	कटियारी	सुरजपुर	207	0-9-0
			दुर्जना	260	0-7-15
			सीसाला	210	0-6-7
				212	0-4-0
				214	0-0-15
				215	0-7-0
				258	0-7-0
				259	0-1-0
				211	0-0-10
				213	1-3-6
				216	0-9-6
				261	0-6-0
				267	0-3-0
				217	0-11-8
				218	0-12-0
				262	0-1-10
				264	0-4-10
				268	0-1-0
				269	0-10-0

[सं. ओ-14016/255/85-जीपी.]

S.O. 4449.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1769 dated 16-4-1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in B.B.B.
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Bilgram	Katiyari	Surjupur	207	0-9-0
			Durjana	260	0-7-15
			Sisala	210	0-6-7
				212	0-4-0
				214	0-0-15
				215	0-7-0
				258	0-7-0
				259	0-1-0
				211	0-0-10
				213	1-3-6
				216	0-9-6
				261	0-6-0
				267	0-3-0
				217	0-11-8
				218	0-12-0
				262	0-1-10
				264	0-4-10
				268	0-1-0
				269	0-10-0

[No. O-14016/255/85-GP]

का०आ० 4450.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० सं० 1770 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाईन को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा बी.बि.बि.
1	2	3	4	5	6
हरदोई	बिलग्राम	कटियारी	मोहनपुर	139	0-0-15
			सीशाला	144	0-4-16
				439	1-2-10
				446	0-6-18
				444	0-14-10
				533	0-4-0
				536	0-10-0
				441	0-0-10
				442	1-10-15
				525	0-3-0
				526	1-0-0
				529	0-1-0
				532	0-11-10
				534	0-5-10
				542	0-1-10
				524	0-12-0
				696	0-7-0
				695	0-15-0
				612	0-1-6
				700	0-15-0
				70एलएम	0-6-17
				694	0-11-0
				70एलएम	0-6-16
				702	0-11-0
				697	0-1-0
				613	0-4-15
				614	0-8-15
				615	0-15-12

[सं. O-14016/256/85-जी.पी.]

S.O. 4450.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1770 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipe Line Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in B.B.B.
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Bilgram	Kati-yari	Mo-hanpur sisala	139	0-0-15
				144	0-4-16
				439	1-2-10
				446	0-6-18
				444	0-14-10
				533	0-4-0
				536	0-10-0
				441	0-0-10
				442	1-10-15

	5	6
	525	0-3-0
	526	1-0-0
	529	0-1-0
	532	0-11-10
	534	0-5-10
	542	0-1-10
	524	0-12-0
	696	0-7-0
	695	0-15-0
	612	0-1-6
	700	0-15-0
	701m.	0-6-17
	694	0-11-0
	701m.	0-6-16
	702	0-11-0
	697	0-1-0
	613	0-4-15
	614	0-8-15
	615	0-15-12

[No. O-14016/256/85-G.P.]

का०आ० 4451:—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० सं० 1773 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईन को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायू	बिसौली	इस्लामनगर	बंजारीं	351	0-12-0
				352	0-11-0
				382	0-1-15
				379	0-4-10
				378	0-18-0
				371	0-1-10
				372	0-13-5
				373	0-8-10
				374	0-1-0
				383	0-6-5
				384	0-2-5
				263	0-4-10
				264	0-18-5
				265	0-4-15
				271	0-13-10
				272	0-0-5
				250	0-18-0
				249	0-16-15
				274	0-5-5
				246	0-3-0
				208	0-10-10
				209	0-12-10
				205	1-0-10
				202	0-13-10
				203	0-5-10
				204	0-5-10
				207	0-0-5

[सं. O-14016/259/85-जी.पी.]

S.O. 4451.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum (Department of Petroleum) S.O. 1773 dated 27-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Islam Nagar	Vazangi	351	0-12-0
				352	0-11-0
				382	0-1-15
				379	0-4-10
				378	0-18-0
				371	0-1-10
				372	0-13-5
				373	0-8-10
				374	0-1-0
				383	0-6-5
				384	0-2-5
				263	0-4-10
				264	0-18-5
				265	0-4-15
				271	0-13-10
				272	0-0-5
				250	0-18-0
				249	0-16-15
				274	0-5-5
				246	0-3-0
				208	1-10-10
				209	0-12-0
				205	1-0-10
				202	0-13-10
				203	0-5-10
				204	0-5-10
				207	0-0-5

[No. O-14016/259/85-G.P.]

फा०आ० 4452:—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना फा०आ० सं० 1774 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईन को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	इस्लाम-नगर	रूपायन पट्टी	365	0-5-0
		नगर		367	0-1-0
			पट्टी पृथ्वीसिंह	364	1-6-10
				69	0-0-13
				370	1-2-15
				76	0-1-6
				79	0-13-6
				280	0-0-3
				281	1-14-01
				85	0-13-15
				286	0-2-5
				262	0-3-10
				261	0-9-1
				259	0-10-6
				250	0-5-11
				251	0-2-0
				252	0-7-10
				236	1-6-10
				237	0-4-2
				238	0-0-5
				238	0-1-15
				263	0-0-15

[सं.-14016/260/35-जी पी]

S.O. 4452.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1774 dated 27-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of powers conferred by sub-section (4) of that section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipeline Project.

Distt	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bishuli	Islam Nagar	Rupain Patti Prithi Singh	365	0-5-0
				367	0-1-0
				364	1-16-10
				369	0-0-13
				370	1-2-15
				276	0-1-16
				279	0-13-6
				280	0-0-13
				281	1-14-10
				285	0-13-14
				286	0-2-5
				262	0-3-10
				261	0-9-1
				259	0-10-6
				250	0-5-11
				251	0-2-0
				252	0-7-10
				236	1-6-10
				237	0-4-2
				238	0-0-5
				238	0-1-15
				263	0-0-15

[No. O-14016/260/85-G.P.]

का०आ० 4453.—यत: पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० सं० 1776 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	इस्लामनगर	कहनपुर	670	1-9-8
				766	0-3-16
				773/1	0-0-15
				773/2	0-6-0
				774	0-10-10
				775	0-16-7
				777	0-7-10
				766	1-3-2
				740	0-5-12
				749	1-13-16

1	2	3	4	5	6
				747	0-12-2
				746	0-0-10
				741	0-19-8
				742	0-0-15
				738	0-7-16
				743	1-17-0
				733	0-0-10
				736	0-16-7
				727	2-13-0
				728	0-0-7

[सं. O-14016/262/85-जी.पी.]

S.O. 4453.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1776 dated 27-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Govrenment declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bodaun	Bisauli	Islam Nagar	Karanpur	670	1-9-8
				766	0-3-16
				773/1	0-0-15
				773/2	0-6-0
				774	0-10-10
				775	0-16-7
				777	0-7-10
				766	1-3-2
				748	0-5-12
				749	1-13-16
				747	0-12-2
				746	0-0-10
				741	0-19-8
				742	0-0-15
				738	0-7-16
				743	1-17-0
				733	0-0-10
				736	0-16-7
				727	2-13-0
				728	0-0-7

[No. O-14016/262/85-GP.]

भा० आ० 4454.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० 1748 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट ।

जिला	तहसील	परगना	गांव	प्लाट संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायू	बिसौली	इस्लामनगर	भईकलां	153	1–0–8
				154	0–12–0
				155	0–7–4
				151	0–1–16
				9	0–4–16
				8	1–0–8
				11	0–10–16
				12	0–14–8
				10	0–4–16
				16	0–19–16
				5	0–2–8

[सं. O-14016/265/85-जी.पी]

S.O. 4454.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1748 dated 27-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira–Bareilly–Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acqaired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Islam Nagar	Maika-lam	153	1–0–8
				154	0–12–0
				155	0–7–4
				151	0–1–16
				9	0–4–16
				8	1–0–8
				11	0–10–16
				12	0–14–8
				10	0–4–16
				16	0–19–16
				5	0–2–8

[No. O-14016/265/85-GP]

का० आ० 4455—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 1750 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर, पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	इस्लाम नगर	रसूल-पुरसंजा	386	0–8–10
				388	0–9–12
				389	0–7–0
				391	0–6–0
				393	0–5–5
				392	0–7–4
				395	0–9–0
				397	0–5–5
				396	0–0–15
				385	0–0–2

[सं. ओ.–14016/267/85–जी. पी.]

S.O. 4455.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1750 dated 29-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Centrar Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira–Barielly–Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisoli	Islam Nagar	Rasul-pur Suvanga	386	0–8–10
				388	0–9–12
				389	0–7–0
				391	0–6–0
				393	0–5–5
				392	0–7–4
				395	0–9–0
				397	0–5–5
				396	0–0–15
				385	0–0–2

[No. O-14016/267/85-GP]

का० आ० 4456.—यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 1751 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	इस्लाम नगर	सादात-पुर नाचनी	20	0–10–0
				37	0–6–15
				38	0–13–4

1	2	3	4	5	6
				39	0–16–16
				40	0–16–10
				16	0–1–4
				8	0–9–12
				7	1–3–8
				58	0–1–5
				59	0–3–10
				60	0–1–16
				63	0–14–8
				62	0–4–10

[सं. ओ.–14016/268/85-जी. पी.]

S.O. 4456.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1751 dated 27-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira–Bareilly–Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Islam Nagar	Sadatpur Nachni	20	0–10–0
				37	0–6–15
				38	0–13–4
				39	0–16–16
				40	0–16–10
				16	0–1–4
				8	0–9–12
				7	1–3–8
				58	0–1–5
				59	0–3–10
				60	0–1–16
				63	0–14–8
				62	0–4–10

[No. O-14016/268/85-GP]

का० आ० 4457.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 1753 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजीरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	इस्लाम नगर	लशकर पुर	746	1–16–0
				724	1–5–0
			ओरिया मार्ग	747	0–1–4
					0–1–15

[सं. ओ.–14016/270/85–जी. पी.]

S.O. 4457.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1753 dated 27-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira–Bareilly–Jagdishpur Pipe line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Islam Nagar	Lasker-pur	746	1–16–0
				724	1–5–0
			Oriya	747	0–1–4
				Marg	0–1–15

[No. O-14016/270/85-GP]

का. आ. 4458---यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 1755 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	औसत रकबा
1	2	3	4	5	6
हरदोई	बिलग्राम	कटियारी	बारी	37	0600
				38	0500
				40	0600
				41	1200
				42	0400
				43	0025
				44	1200
				48	3600
				352	0505
				353	1250
				354	0885
				355	0125
				356	0100
				357	0635
				358	1700
				359	0760
				324	0658
				326	1000
				327	0380
				330	0500
				331	0700
				332	0900
				335	0125
				336	0630
				309	1140
				337	1200
				338	0200
				339	1140
				376/2	0050
				563	0550
				564	0850
				566	0200
				551	0050
				554	1100
				555	1345
				559	1150
				560	0800
				579	0900
				580	0950
				581	1200

1	2	3	4	5	6
				582	0800
				583	0630
				328	0100
				340	0050
				341	0050
				342	0100
				565	0850

[सं. ओ.—14016/272/85-जी. पी.]

S.O. 4458.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Deptt. of Petroleum) S.O. 1755 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Cenral Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipe Line Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired Hakt.
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Bilgram	Katiyari	Bari	37	0600
				38	0500
				40	0600
				41	1200
				42	0400
				43	0025
				44	1200
				48	3600
				352	0505
				353	1250
				354	0885
				355	0125
				356	0100
				357	063 5
				358	1700
				359	0760
				324	0650
				326	1000
				327	0380
				330	0500
				331	0700
				332	0900
				335	0125
				336	0630
				309	1140
				337	1200
				338	0200
				339	1140
				376/2	0050
				563	0550
				564	0850
				566	0200
				551	0050
				554	1100
				555	1345
				559	1150
				560	0800
				579	09 00
				580	0950
				581	1200
				582	0800
				583	0630
				328	0100
				340	0050
				341	9050
				342	0100
				565	0850

[No. O-14016/272/85-GP]

का.आ. 4459 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 1731 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा

(1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
हरदोई	शाहबाद	पाली	मुड़ेर	58	0–0–10
				59	0–3–
				62	0.12–0
				63	1–10–0
				64	0–0–10
				65	0–1–10
				66	0–7–10
				68	0–8–10
				69	0–15–10
				85	0–6–0
				87	0–6–0
				88	0–5–0
				90	0–15–10
				91	0–5–0
				92	0–12–0
				100	1–5–10
				101	0–18–0
				135	0–3–0
				152	1–11–0
				153	0–4–10
				158	0–1–0
				159	1–7–0
				160	0–0–5
				162	0–12–0
				163	0–6–0
				164	0–5–0
				165	0–3–10
				168	0–3–10
				169	0–6–0
				84	0–1–0
				171	0–3–10
				213	1–6–5
				566	0–8–0
				567	0–8–0
				583	0–6–0
				584	0–6–0
				578	0–6–0
				585	0–12–0
				586	0–7–0
				587	0–6–0
				588	0–2–10
				589	0–1–0
				615	0–18–0
				616	0–2–10
				617	0–12–0
				618	0–5–0
				619	0–7–0
				620	0–12–0
				627	0–0–10
				855	0–0–15
				924	0–7–0
				977	0–5–0
				1432	0–3–0
				1433	0–5–0
				1434	0–2–0
				1435	0–4–0
				1437	0–2–10
				1439	1–4–0
				1445	1–1–0
				1446	0–0–5
				1474	0–2–10
				1476	0–12–10
				1477	0–7–10
				1478	0–10–10
				1479	0–15–0
				1480	0–3–10
				1491	0–0–5
				1499	0–11–0
				1500	0–9–0
				1501	0–7–0
				1490	0–2–10
				1503	0–9–0
				1504	0–5–0
				1505	0–2–0
				1506	0–5–0
				1508	0–7–0

1	2	3	4	5	6
				1509	0–18–0
				1519	0–2–0
				1532	0–3–0
				1533	0–6–0
				1534	0–12–0
				1540	1–5–0
				1431	0–0–5

[सं. ओ.—14016/276/85-जी. पी.]

S.O. 4459.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Petroleum) S.O. 1731 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notificfiation;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specifled in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira–Barielly–Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pragana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Shaha-bad	Poli	Mundar	58	0–0–10
				59	0–3–0
				62	0–12–0
				63	1–10–0
				64	0–0–10
				65	0–1–10
				66	0–7–10
				68	0–8–10
				69	0–15–10
				85	0–6–0
				87	0–6–0
				88	0–5–0
				90	0–15–10
				91	0–5–0
				92	0–12–0
				100	1–5–1
				101	0–18–0
				135	0–3–0
				152	1–11–0
				153	0–4–10
				158	0–1–03
				159	1–7–0
				160	0–0–5
				162	0–12–0
				163	0–6–0
				164	0–5–0
				165	0–3–10
				168	0–3–10
				169	0–6–9
				84	0–1–0
				171	0–3–10
				213	1–6–5
				566	0–8–0
				567	0–8–0
				585	0–6–0
				584	0–6–0
				578	0–6–0
				585	0–12–0
				586	0–7–0
				587	0–6–0
				588	0–2–10
				589	0–1–0
				615	0–18–0
				616	0–2–10
				617	0–12–0
				618	0–5–0
				619	0–7–0
				620	0–12–0
				627	0–0–10
				855	0–0–15
				924	0–7–0
				977	0–5–0
				1432	0–3–0
				1433	0–5–0
				1434	0–2–0
				1435	0–4–0
				1437	0–2–10
				1439	1–4–0
				1445	1–1–0
				1146	0–0–5
				1474	0–2–10
				1476	0–12–10
				1477	0–7–10
				1478	0–10–10
				1479	0–15–0
				1480	0–3–10
				1491	0–0–5
				1499	0–11–0
				1500	0–9–0
				1501	0–7–0
				1490	0–2–10

1	2	3	4	5	6
				1503	0–9–0
				1504	0–5–0
				1505	0–2–0
				1506	0–5–0
				1508	0–7–0
				1509	0–18–0
				1519	0–2–0
				1532	0–3–0
				1533	0–6–0
				1534	0–12–0
				1540	1–5–0
				1431	0–0–5

[No. O-14016/276/85-GP]

का. आ. 4460--यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 1733 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	इस्लाम नगर	शिव-नगर उर्फ चिड़िया खेड़ा	178	0–0–10
				179	1–4–0

1	2	3	4	5	6
				180	0–7–10
				185	0–6–0
				253	0–1–10
				336	0–3–5
				335	1–4–0
				254	0–2–15
				334	0–15–15
				330	0–1–10
				332	0–13–0
				331	0–12–0
				326	0–4–12
				325	0–9–12
				323	0–8–12
				321	0–2–10
				324	0–0–5

[सं. ओ०–14016/278/85-जी. पी.]

S.O. 4460.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1733 dated 27-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notificfiation;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisvuli	Islam Nagar	Shiv Nagar urf Chiria Khera	178	0–0–10
				179	1–4–0
				180	0–7–10
				185	0–6–0
				253	0–1–10

1	2	3	4	5	6
				336	0-3-5
				335	1-4-0
				254	0-2-15
				334	0-15-15
				330	0-1-10
				332	0-13-0
				331	0-12-0
				326	0-4-12
				325	0-9-12
				323	0-8-12
				321	0-2-10
				324	0-0-5

[No. O-14016/278/85-GP]

का. आ. 4461.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1737 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	इस्लाम नगर	राम-नगर	207	0-4-16
				208	1-7-0
			सैदपुर	210	0-8-10
				209	0-9-12
				222	1-6-8
				223	0-6-10
				224/1	0-1-5
				224/2	0-8-7
				246	0-0-5
				245	0-12-0
				243	0-1-4
				242	1-11-4
				241	0-1-10
				240	0-16-16
				262	0-10-0
				239	0-11-8
				263	0-1-4
				266	0-9-12
				267	1-4-10
				268	0-1-4
				270	0-1-4
				269	1-4-0
				279	0-15-12
				278	0-2-2
				282	0-0-16
				281	0-2-0
				283	0-6-8
				284	0-1-0
				285	0-12-0
				286	0-14-8
				133	0-2-0
				211 ए	0-0-5

[सं. ओ.-14016/282/85-जी. पी.]

S.O. 4461.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 1737 dated 27-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Islam Nagar	Ram-Nagar	207	0-4-16
			Saidpur	208	1-7-0
				210	0-8-10
				209	0-9-12
				222	1-6-8
				223	0-6-10
				224/1	0-1-5
				224/2	0-8-7
				246	0-0-5
				245	0-12-0
				243	0-1-4
				242	1-11-4
				241	0-1-10
				240	0-16-16
				262	0-10-0
				239	0-11-8
				263	0-1-4
				266	0-9-12
				267	1-4-10
				268	0-1-4
				270	0-1-4
				269	1-4-0
				279	0-15-12
				278	0-2-2
				282	0-0-16
				281	0-2-0
				283	0-6-8
				284	0-1-0
				285	0-12-0
				286	0-14-8
				133	0-2-0
				211A	0-0-5

[No. O-14016/282/85-G.P.]

का.आ. 4462.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1784 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	इस्लाम नगर	अचल पुर	355	0-4-0

[सं. ओ.-14016/284/85-जी. पी.]

S.O. 4462.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 1784 dated 27-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Islam Nagar	Achal pur	355	0-4-0

[No. O-14016/284/85-G.P.]

का०आ० 4463.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० 1740 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी हैं ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	इस्लाम नगर	रायपुर	11	0—14—10
				12	0—2—15
				13	0—16—4
				39	0—9—0
				40	0—4—4
				41	0—13—16
				48	1—7—0
				10	0—8—3
				52	0—3—15
				50	1—8—16
				51	0—15—6
				77	0—16—13
				73	0—0—5
				75	0—1—19
				74	0—4—4
				72	0—1—0
				62	1—11—0
				65	0—6—0
				126	0—2—10
				130	1—11—0
				131	0—18—0
				132	0—1—0
				76	1—5—10
				123	0—3—0
				9	0—4—0
				64	0—0—5
				78	0—2—0
				86	0—1—0
				46	0—0—10
				47	2—3—0
				42	0—1—10

[स. अ.—14016/285/85—जी. पी.]

S.O. 4463.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 1740 dated 27-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe line Project

Distt	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badoun	Bisali	Islam Nagar	Raipur	11	0-14-10
				12	0-2-15
				13	0-16-4
				39	0-9-0
				40	0-4-4
				41	0-13-16
				48	1-7-0
				10	0-8-3
				52	0-3-15
				50	1-8-16
				51	0-15-6
				77	0-16-13
				73	0-0-5
				75	0-1-19
				74	0-4-4
				72	0-1-0
				62	1-11-0
				65	0-6-0
				126	0-2-10
				130	1-11-0
				131	0-18-0
				132	0-1-0
				76	1-5-10
				123	0-3-0
				9	0-4-0
				64	0-0-5
				78	0-2-0
				86	0-1-0
				46	0-0-10
				47	2-3-0
				42	0-1-10

[No. O-14016/285/85-G.P.]

का० आ० 4464.—यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 1742 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है। कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा में प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	आंवला	आंवला	राजपुर खुर्द	1	0-4-0
				2	0-1-5
				4	0-0-5

[सं. ओ-14016/287/85-जी. पी.]

S.O. 4464.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 1742 dated 27-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jadishpur Pipe line Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Awala	Rajpur Khurd	1	0-4-0
				2	0-1-5
				4	0-

[No. O-14016/287/85-G.P.]

का० आ० 4465.—यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 1744 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	आंवला	आंवला	दरका	574	0-4-16
				573	0-1-4
				572	1-5-0
				578	0-0-12
				570	0-8-16
				484	0-3-0
				485	0-15-10
				486	0-6-12
				483	0-4-0
				482	0-7-7
				481	0-18-0
				474	0-11-4
				475	0-4-10
				476	0-9-12
				468	1-4-2
				467	0-6-15
				466	0-2-10
				456	0-2-10
				509	0-2-2
				112	1-2-16
				513	0-0-10
				511	0-0-15
				316	0-2-0
				317	0-13-10
				314	0-1-10
				319	0-0-12
				330	0-4-0
				329	0-9-3
				338	0-2-10
				331	0-0-2
				325	0-4-0
				323	0-0-10
				322	0-2-10
				333	0-2-8
				163	0-1-6
				162	0-5-0
				164	0-7-0

1	2	3	4	5	6
				157	0–11–0
				169	0–2–0
				156	0–3–0
				170	0–1–12
				324	0–0–10
				171	0–18–0
				172	0–1–0
				198	0–1–10
				106	1–1–12
				105	0–13–4
				104	0–8–0
				102	0–1–10
				103	0–3–10
				79	0–2–8
				52	0–17–0
				63	0–9–10
				55	0–0–15
				56	0–1–10
				58	0–4–5
				57	0–1–5
				59	0–5–0
				60	0–2–10
				61	0–0–2
				73	0–4–16
				155	0–0–10

[सं. O/14016/288/85–जी.पी.]

S.O. 4465.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 1744 dated 27-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Awala	Darka	574	0–4–16
				573	0–1–4
				572	1–5–0
				578	0–0–12
				570	0–8–16
				484	0–3–0
				485	0–15–10
				486	0–6–12
				483	0–4–0
				482	0–7–7
				481	0–18–0
				474	0–11–4
				475	0–4–10
				476	0–9–12
				468	1–4–2
				467	0–6–15
				466	0–2–10
				456	0–2–10
				509	0–2–2
				112	1–2–16
				513	0–0–10
				511	0–0–15
				316	0–2–0
				317	0–13–10
				314	0–1–10
				319	0–0–12
				330	0–4–0
				329	0–9–3
				338	0–2–10
				331	0–0–2
				325	0–4–0
				323	0–0–10
				322	0–2–10
				333	0–2–8
				163	0–1–6
				162	0–5–0
				164	0–7–0
				157	0–11–0
				169	0–2–0
				156	0–3–0
				170	0–1–12
				324	0–0–10
				171	0–18–0
				172	0–1–0
				198	0–1–10
				106	1–1–12
				105	0–13–4
				104	0–8–0

1	2	3	4	5	6
				102	0–1–10
				103	0–3–10
				79	0–2–8
				52	0–17–0
				63	0–9–10
				55	0–0–15
				56	0–1–10
				58	0–4–5
				57	0–1–5
				59	0–5–0
				60	0–2–10
				61	0–0–2
				73	0–4–16
				155	0–0–10

[No. O-14016/288/85–G.P.]

का० आ० 4466.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 40) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 2328 तारीख 18-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5	6
हरदोई	शाहबाद	पछोहा	नगलापट्टु		बी.वि.वि.
				153	0–11–0
				154	0–7–0
				527	0–2–0
				528	0–5–0
				529	0–3–10
				530	0–0–10
				531	0–12–0
				532	0–2–10
				553	0–0–10
				554	1–17–10
				557	0–3–0
				558	0–6–10
				559	0–15–10
				565	0–0–10
				572	0–12–0
				573	0–1–0
				575	0–2–10
				576	0–6–0
				577	0–2–0
				584	1–4–0
				585	0–1–0
				586	0–1–10
				496	0–10–0
				391	1–16–0
				392	0–1–10
				393	1–4–0
				394	0–8–0
				397	0–1–0
				398	0–1–10
				396	0–1–0
				401	0–1–10
				402	0–10–0
				403	0–16–0
				412	0–2–10
				413	0–8–10
				414	0–5–0
				415	0–2–10
				416	0–6–0
				417	0–5–0
				452	0–7–0
				453	0–8–10

1	2	3	4	5	6
				454	0–8–10
				456	0–7–0
				457	0–5–0
				460	0–5–0
				458	0–1–0

[सं. 14016/344/85–जी.पी.]

S.O. 4466.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroeum S.O. 2328 dated 18-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Shahabad	Pachhoha	Naglapatty	153	0–11–0
				154	0–7–0
				527	0–2–0
				528	0–5–0
				529	0–3–10
				530	0–0–10
				531	0–12–0
				532	0–2–10
				553	0–0–10
				554	1–17–10
				557	0–3–0
				558	0–6–10
				559	0–15–10
				565	0–0–10
				572	0–12–0
				573	0–1–0
				575	0–2–10
				576	0–6–0
				577	0–2–0
				584	1–4–0
				585	0–1–0
				586	0–1–10
				496	0–10–0
				391	1–16–0
				392	0–1–10
				393	1–4–0
				394	0–8–0
				397	0–1–0
				398	0–1–10
				396	0–1–0
				401	0–1–10
				402	0–10–0
				403	0–16–0
				412	0–2–10
				413	0–8–10
				414	0–5–0
				415	0–2–10
				416	0–6–0
				417	0–5–0
				452	0–7–0
				453	0–8–10
				454	0–8–10
				456	0–7–0
				457	0–5–0
				460	0–5–0
				458	0–1–0

[No. O-14016/344/85-G.P.]

का०आ० 4467.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० 2591 तारीख 30-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 का उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त नियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय

सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीश पुर गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

जिला : तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
शाहजहांपुर सदर	कान्ट	अख्तयारपुर बघौरा			
			2		06
			3.		06
			4.		49
			18.		08
			19.		10
			21.		27
			966/22.		43
			30.		68
			36.		64
			37.		08
			38.		75
			42.		08
			17.		75
			29.		05

[सं. O-14016/353/85-जीपी]

S.O. 4467.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2591, dated 30-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended in that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

H. B. J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Shah-jhan Pur	Sadar	Kant	Akhtyar Pur Bag-houra	2	06
				3	06
				4	49
				18	08
				19	10
				21	27
				966/22	43
				30	68
				36	64
				37	08
				38	75
				42	08
				17	75
				29	05

[No. O-14016/35/85-G.P.]

का० आ० 4468.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 2586 तारीख 30-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने की अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम के द्वारा 6 की उपधारा (17 के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार

में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकारण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रशासन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजैक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित रकबा एकड़ में
1	2	3	4	5	6
शाहजहांपुर	सदर	जमौर	खमारिया	98	21
				99	06
				100	22
				101	58
				103	15
				124	34
				125	70
				126	07
				167	55
				182	34
				183	06
				187	17
				188	15
				189	14
				190	52
				191	01
				208	03
				216	14
				217	25
				219	03
				223	18
				224	06
				226	21
				229	42
				230	03
				231	56
				225	16
				118	66
				232	24
				233	20
				234	02
				121	01
				122	03
				228	02

[सं. O–14016/360/85–जी.पी.]

S.O. 4468.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2586 dated 30-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Shahjahan pur	Sadar	Jamaur	Khama-riya	98	21
				99	06
				100	22
				101	58
				103	15
				124	34
				125	70
				126	07
				167	55
				182	34
				183	06
				187	17
				188	15
				189	14
				190	52
				191	01
				208	03
				216	14
				217	25
				219	03
				223	18
				224	06
				226	21
				229	42
				230	03
				231	56
				225	16
				118	66
				232	24
				233	20
				234	02
				121	01
				122	03
				228	02

[No. O-14016/360/85-G.P.]

का० आ० 4469 4.—यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 2583 तारीख 30-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर गैस पाईप लाइन प्रोजैक्ट

जिला	तहसील परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित रकबा बी. वि. वि.
1	2 3	4	5	6
हरदोई	शाहाबाद पदछोहा	भरखनी	1803	1–15–0
			1802	0–13–10
			1797	0–13–0
			1796	1–10–0
			761	0–7–10
			762	0–15–0
			763	0–15–0
			768	0–9–10
			769	0–6–0
			770	0–11–10
			772	0–10–10
			773	1–3–0
			784	0–17–0
			783	0–0–10
			697	0–5–0
			787	0–0–15
			789	0–0–10
			788	0–13–0
			790	0–15–0
			791	0–10–10
			793	0–1–0
			691	0–18–0
			692	0–0–10
			795	0–0–10
			796	2–2–0
			1745	0–13–0
			1744	0–17–10
			1743	0–9–0
			800	0–6–0
			1742	0–0–5
			814	0–9–0
			815	0–5–0
			816	0–12–0
			1810	0–1–10
			949	0–0–5
			909	0–0–10
			817	0–1–10
			813	0–0–10
			837	1–7–10
			836	0–12–0
			835	0–4–0
			839	0–6–0
			833	0–0–8
			865	2–7–10
			864	0–7–10
			867	0–6–0
			868	0–0–10
			881	0–7–0
			882	0–17–0
			916	0–8–10
			893	0–9–10
			894	1–1–0
			895	0–0–2
			811	0–9–0
			896	0–10–0
			906	0–0–10
			907	0–4–15
			905	0–19–5
			904	0–12–0

1	2	3	4	5	6
				900	0–0–5
				901	0–2–0
				902	0–10–0
				897	0–3–0
				704	0–3–10
				705	0–0–5
				1805	0–0–5

[सं. O–14016/362/85–जी.पी.]

S.O. 4469.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2583 dated 30-7-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipeline Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Shahbad	Pachhoha	Bharkhani	1803	1–15–0
				1802	0–13–10
				1797	0–13–0
				1796	1–10–0
				761	0–7–10
				762	0–15–0
				763	0–15–0
				768	0–9–10
				769	0–6–0
				770	0–11–10
				772	0–10–10
				773	1–3–0
				784	0–17–0
				783	0–0–10
			Bharkhani (Contd.)	697	0–5–0
				787	0–0–15
				789	0–0–10
				788	0–13–0
				790	0–15–0
				791	0–10–10
				793	0–1–0
				691	0–18–0
				692	0–0–10
				795	0–0–10
				796	2–2–0
				1745	0–13–0
				1744	0–17–10
				1743	0–9–0
				800	0–6–0
				1742	0–0–5
				814	0–9–0
				815	0–5–0
				816	0–12–0
				1810	0–1–10
				949	0–0–5
				909	0–0–10
				817	0–1–10
				813	0–0–10
				837	1–7–10
				836	0–12–0
				835	0–4–0
				839	0–6–0
				833	0–0–8
				865	2–7–10
				864	0–7–10
				867	0–6–0
				868	0–0–10
				881	0–7–0
				882	0–17–0
				916	0–8–10
				893	0–9–10
				894	1–1–0
				885	0–0–2
				911	0–9–0
				896	0–10–0
				906	0–0–10
				907	0–4–15
				905	0–19–5
				904	0–12–0
				900	0–0–5
				901	0–2–0
				902	0–19–5
				897	0–3–0
				704	0–3–10
				705	0–0–5
				1805	0–0–5

[No. O-14016/362/85-G.P.]

का० आ० 4470.—यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 2581 तारीख 30-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर गैस पाईप लाइन प्रोजैक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित रकबा बी.वि.वि.
1	2	3	4	5	6
हरदोई	शाहबाद	पछोहा	सकरौली	239	1–0–0
				241	0–4–10
				242	0–11–0
				243	0–6–0
				244	0–0–3
				247	0–1–10
				248	0–12–10
				260	0–12–10
				261	0–0–2
				277	0–3–5
				278	0–14–10
1	2	3	4	5	6
			सकरौली (जारी)	279	0–10–10
				280	0–5–10
				281	0–0–5
				297	0–0–5
				298	0–8–0
				299	0–4–0
				302	0–0–5
				303	0–14–10
				304	0–4–0
				305	0–1–10
				307	0–3–10
				202	0–3–0
				201	0–6–0
				200	0–2–0
				199	0–7–5
				198	0–5–10
				177	0–8–15
				176	0–0–3
				181	0–2–10
				182	0–0–4
				179	0–3–0
				178	0–3–10
				174	0–6–0
				173	0–7–0
				169	0–8–10
				170	0–6–0
				411	0–0–3
				410	0–10–0
				409	0–3–0
				408	0–9–10
				407	0–0–10
				406	0–12–0
				405	0–2–15
				436	0–5–0
				467	0–6–0
				468	0–15–10
				469	0–9–0
				470	0–4–0

[सं. O–14016/364/85–जी. पी.]

S.O. 4470.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2581 dated 30-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline:

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipeline Project

Distt.	Teksil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acquired B.V.V.
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Shahabad	Pachhoha	Sakrauli	239	1-0-0
				241	0-4-10
				242	0-11-0
				243	0-6-0
				244	0-0-3
				247	0-1-10
				248	0-12-10
				260	0-12-10
				261	0-0-2
				277	0-3-5
				278	0-14-10
				279	0-10-10
				280	0-5-10
				281	0-0-5
				297	0-0-5
				298	0-8-0
				299	0-4-0
				302	0-14-10
				303	0-14-10
				304	0-4-0
				305	0-1-10
				307	0-3-10
				202	0-3-0
				201	0-6-0
				200	0-2-0
				199	0-7-5
				198	0-5-10
				177	0-8-15
				176	0-0-3
				181	0-2-10
				182	0-0-4
				179	0-3-0
				178	0-3-10
				174	0-6-0
1	2	3	4	5	6
Sahrauli (contd.)				173	0-7-0
				169	0-0-0
				170	0-6-0
				411	0-0-3
				410	0-10-0
				409	0-3-0
				408	0-9-10
				407	0-0-10
				406	0-12-0
				405	0-2-15
				436	0-5-0
				467	0-6-0
				468	0-15-10
				469	0-9-0
				470	0 4-0

[No. O-14016/364/85-G.P.]

का० आ० 4471—यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 2580 तारीख 30-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर गैस पाईप लाइन प्रोजैक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित रकबा बी.वि.वि.
1	2	3	4	5	6
हरदोई	बिलग्राम	कटियारी	गौरिया गऊ सीशाला	353	1–3–0
				351	0–4–0
				352	0–14–0
				354	0–15–0
				369	0–13–4
				370	0–7–4
				371	0–5–8
				373	0–6–0
				380	0–5–0
				398	0–1–13
				403	0–4–16
				382	0–5–8
				383	0–5–8
				397	0–3–0
				399	0–1–13
				610	0–15–0
				401	0–3–0
				402	0–4–4
				561	0–18–0
				404	0–10–16
				405	0–11–17
				406	0–5–8
				407	0–6–5
				425	0–8–15
				428	0–8–8
				435	0–10–0
				436	0–7–7
				437	0–6–0
				438	0–3–7
				542	0–9–0
				562	0–13–0
				547	0–14–17
				548	0–10–0
				550	0–13–0
				558	0–3–10
				557	0–13–0
				566मि.	1–7–0
				568	0–5–0
				608	0–2–0
				570	0–4–16
				571	0–2–14
				572	0–1–10
			गौरिया गऊ सीशाला (जारी)	573	0–2–0
				597	0–6–12
				605	0–0–10
				616	0–15–0
				606	0–13–0
				611	0–6–0
				615	0–3–10
				600	0–1–6
				901	0–0–5
				902	0–5–0
				903	0–13–0
				904	0–10–0
				905	0–17–0
				921	0–8–0
				915	0–10–0
				899	0–12–0
				914	0–15–0
				897	0–6–0
				910	0–18–0
				912	0–12–10
				911	0–15–0
				916	0–3–0
				913	0–4–10
				906	0–7–0
				907	0–4–0
				295	0–5–0
				563	0–2–0
				909	0–2–0

[सं. O–14016/365/85–जी.पी.]

S.O. 4471.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2580 dated 30-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of

this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira—Bareilly Jagdishpur Pipeline Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acquired
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Bilgram	Katiyari	Gouria Mau Sisala	353	3–1–0
				351	0–4–0
				352	0–14–0
				354	0–15–0
				369	0–13–4
				370	0–7–4
				371	0–5–8
				373	0–6–0
				380	0–5–0
				398	0–1–13
				403	0–4–16
				382	0–5–8
				383	0–5–8
				397	0–3–0
				399	0–1–13
				610	0–15–0
				401	0–3–0
				402	0–4–4
				561	0–18–0
				404	0–10–16
				405	0–11–17
				406	0–5–8
				407	0–6–5
				425	0–8–15
				428	0–8–8
				435	0–10–0
				436	0–7–7
				437	0–6–0
				438	0–3–7
				542	0–9–0
				562	0–13–0
				547	0–14–17
				548	0–10–0
				550	0–13–0
				558	0–3–10
				557	0–13–0
				566	1–7–0
				568	0–5–0
				608	0–2–0
				570	0–4–16
				571	0–2–14
				572	0–1–10
				673	5–2–0
				597	0–6–12
				608	0–0–10
				616	0–15–0
				606	0–13–0
				611	0–6–0
			Gauria Mau Sisala	615	0–3–10
				600	0–1–6
				901	0–0–5
				902	0–5–0
				903	0–13–0
				904	0–10–0
				905	0–17–0
				921	0–8–0
				915	0–10–0
				899	0–12–0
				914	0–15–0
				897	0–6–0
				910	0–18–0
				912	0–12–10
				911	0–15–0
				916	0–3–0
				913	0–4–10
				906	0–7–0
				90ख	0–4–0
				275	0–5–0
				563	0–2–0
				909	0–2–0

[No. O-14016/365/85-G.P.]

का. आ. 4472.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 3444 तारीख 29-6-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार

में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा, बरेली, जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजैक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	(गाटा सं०) प्लाट नं०	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	बिसौली	राबेट	1	0-06-15
			गोविन्द	2	0-01-00
			पुर	3	0-00-10
				4	0-00-10
			योग	4	0-08-15
					बीघा या (0.1107) है०

[सं० ओ-14016/367/85-जी०पी०]

S.O. 4472.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Deptt. of Petroleum) S.O. 3944 dated 29-6-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bodau	Bisauli	Bisali	Robet Govind	1	0-06-15
			Pur	2	0-01-00
				3	0-00-10
				4	0-00-10
			Total	4	0-08-15
					बीघा या (0.1107) है०

[No. O-14016/367/85-G.P.]

का० आ० 4473.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 4043 तारीख 29-6-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा, बरेली, जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजैक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	आंवला	आंवला	दराव	480	0-2-8
			नगर	481	0-15-0
				466	2-2-0
				465	0-13-5
				467	0-0-15
				468	0-0-15
				474	0-5-0
				473	0-6-0
				472	0-6-0

1	2	3	4	5	6
				471	0-12-0
				469	1-6-8
				462	0-1-10
				431	0-5-10
				426	0-6-0
				425	1-3-3
				458	0-0-10
				434	0-1-0
				433	0-1-0
				457	0-4-18
				435	1-14-10
				416	0-1-16
				279	0-1-10
				415	0-1-10
				280	1-4-10
				290	0-3-10
				289	0-1-8
				288	0-2-15
				287	0-2-8
				286	0-1-4
				283	0-1-40
				284	0-0-8
				252	0-1-16
				268	0-1-4
				254	0-11-12
				42	0-0-14
				41	0-17-10
				40	0-13-0
				39	1-7-5
				38	0-15-5
				50	0-12-5
				51	0-15-0
				52	0-1-5
				54	2-8-0
				58	0-3-10
				65	0-5-0
				37	0-11-8
				55	1-7-0
				59	2-5-0
				60	0-11-10
				61	0-0-2
				53	0-0-5

[सं० ओ-14016/369/85-जी०पी०]

S.O. 4473.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Deptt. of Petroleum) S.O. 4043 dated 29-6-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline:

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Awala	Daraw-Nagar	480	0-2-8
				481	0-15-0
				466	2-2-0
				465	0-13-5
				467	0-0-15
				468	0-0-15
				474	0-5-0
				473	0-6-0
				472	0-6-0
				471	0-12-0
				469	1-6-8
				462	0-1-10
				431	0-5-10
				426	0-6-0
				425	1-3-3-
				458	0-0-10
				434	0-1-0
				433	0-1-0
				457	0-4-18
				435	0-14-10
				416	0-1-16
				279	0-1-10
				415	0-1-10
				280	1-4-10
				290	0-3-10
				289	0-1-8
				288	0-2-15
				287	0-2-8
				286	0-1-4
				283	0-14-10
				284	0-0-8
				252	0-1-16

1	2	3	4	5	6
				268	0-1-4
				254	0-11-12
				42	0-0-14
				41	0-17-10
				40	0-13-0
				39	1-7-5
				38	0-15-5
				50	0-12-0
				51	0-15-0
				52	0-1-5
				54	2-8-0
				58	0-3-10
				65	0-5-0
				37	0-11-8
				55	1-7-0
				59	2-5-0
				60	0-11-10
				61	0-0-2
				53	0-0-5

[No. O-14016/369/85-G.P]

का० आ० 4474—यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 3040 तारीख 29-6-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और, यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और, आगे, यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप के घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली,—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजैक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
बदायूं	बिसौली	बिसौली	निजारा	374	1-4-0
				372	0-0-5
				373	0-10-16
				375	0-1-0
				393	0-8-8
				392	0-3-0
				394	0-4-0
				404	0-8-10
				403	0-3-0
				405	0-6-0
				402	0-6-0
				315	0-3-10
				312	0-3-10
				311	0-11-8
				316	0-0-5
				307	0-5-0
				308	0-10-10
				284	0-1-10
				281	1-18-0
				282	0-1-15
				280	0-3-0
				272	0-18-0
				273	0-0-5
				269	0-14-8
				270	0-3-0
				270/537	0-2-10
				54	0-6-12
				56	0-13-0
				58	0-1-0
				60	0-12-12
				61	0-3-0
				190	0-0-15
				200	0-1-5
				201	0-10-0
				202	0-7-4
				62	1-2-16
				64	0-12-10
				65	1-5-4
				85	0-0-5
				87	0-3-0
				182	0-0-5
				181	0-10-16
				180	0-7-15
				109/535	0-0-5
				109	0-3-0
				179	0-5-0
				127	0-0-5
				123	0-1-0

1	2	3	4	5	6
				122	0–3–0
				120	0–0–15
				119	2–10–15
				111	0–0–5
				112	0–0–5
				116	0–0–5
					5.0322 हैक्टेयर

[सं० ओ-14016/371/85-जीपी]

S.O. 4474.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3040 dated 29-6-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Bisauli	Nizra	374	1–4–0
				372	0–0–5
				373	0–10–16
				375	0–1–0
				393	0–8–8
				392	0–3–0
				394	0–4–0
				404	0–8–10
				403	0–3–0
				405	0–6–0
				402	0–6–0
				315	0—310
				312	0–3–10
				311	0–11–8
				316	0–0–5
				307	0–5–0
				308	0–10–10
				284	0–1–10
				281	1–18–0
				282	0–1–15
				280	0–3–0
				272	0–18–0
				273	0–0–5
				269	0–14–8
				270	0–3–0
				270/537	0–2–10
				54	0–6–12
				56	0–13–0
				57	0–4–0
				58	0–1–0
				60	0–12–12
				61	0–3–0
				199	0–0–15
				200	0–1–5
				201	0–10–0
				202	0–7–4
				62	1–2–16
				64	0–12–10
				65	1–5–4
				85	0–0–5
				87	0–3–0
				182	0–0–5
				181	0–10–16
				180	0–7–15
				109/535	0–0–5
				109	0–3–0
				179	0–5–0
				127	0–0–5
				123	0–1–0
				122	0–3–0
				120	0–0–15
				119	2–10–15
				111	0–0–5
				112	0–0–5
				116	0—0–5
					5.0322 Hactor

[No. O-14016/371/85-G.P].

का०आ० 4475.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० 3037 तारीख 29-6-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाईप लाइन प्रोजैक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायू	दाता गंज	सलेमपुर	सरहा	1	0-01-00
			पोक्टा	18	01-02-10
				17	0-00-02
				15	0-05-17
				16	0-15-00
				14	0-10-05
				4	0-12-15
				12	0-01-00
				6	1-10-10
				5	0-00-05
				8	0-01-00
				7	0-12-15
				172	0-00-18
				162	0-04-13
				167	0-10-04
				166	1-01-00
				165	0-01-00
				156	0-03-10
				157	0-00-05 छूटा था
				150	0-01-16
				151	0-02-10
				153	0-04-10
				210	0-01-10
				211	0-13-15
				152	0-06-00 छूटा था
				212	0-10-04
				213	0-03-10
				219	0-18-14
				220	0-16-16
				221	0-14-10
				222	0-00-05
				223	0-19-00
				333	0-01-16
				301	1-03-00
				300	0-6-00
				302	0-05-10
				303	0-09-00
				304	0-11-15
				305	0-12-00
				306	0-13-06
				313	0-03-15
				307	0-10-16
				308	0-04-10
			सम्पूर्ण योग	43	18-08-17 बीघा या 4.6596 है०

[सं० ओ-14016/372/85-जी०पी०]

S.O. 4475.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3031 dated 29-6-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-Section (I) of Section 6 of the said Act submitted report to Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEUDLE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipeline Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Dataganj	Salaim-pur	Sarha Pokta	1	0-01-00
				18	01-02-10
				17	0-00-02
				15	0-05-17
				16	0-15-00
				14	0-10-05
				4	0-12-15
				12	0-01-00
				6	1-10-10
				5	0-00-05
				8	0-01-00
				7	0-12-15
				172	0-00-18
				162	0-04-13
				167	0-10-04
				166	1-01-00
				165	0-01-00
				156	0-03-10 छूटा था
				157	0-00-05
				150	0-01-16
				151	0-02-10
				153	0-04-10
				210	0-01-10
				211	0-13-15 छूटा था
				152	0-06-00
				212	0-10-04
				213	0-03-10
				219	0-18-14
				220	0-16-16
				221	0-14-10
				222	0-00-05
				223	0-19-00
				333	0-01-16
				301	1-03-00
				300	0-06-00
				302	0-05-10
				303	0-09-00
				304	0-11-15
				305	0-12-00
				306	0-13-06
				313	0-03-15
				307	0-10-16
				308	0-04-10
			Total	43	18-08-17 Bigha or 4.6596-Hec.

[No. O-14016/372/85-G.P.]

का.आ. 4476.— यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3045 तारीख 29-6-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है। कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुरा पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	दातागंज	सलेमपुर	सेरहा खाम	25	0-05-05
				23	0-01-00
				20	0-01-00
				24	1-06-00
				26	0-01-00 छूटा था
				27	0-05-00
				97	0-02-08
				12	0-09-01
				102	0-06-15
				100	0-00-02
				101	0-10-15
				99	0-01-15
				98	0-07-05

1	2	3	4	5	6
				105	1-00-00
				106	0-15-15
				183	1-15-08
				180	0-18-00
				216	0-09-12
				215	0-17-02
				214	0-05-05
				213	0-15-00
				184	0-00-05
				85/2	0-01-04
				237	1-06-00
				239	0-06-12
				293/1	0-14-00
				323	0-06-00
				319	2-00-05
				321	0-01-05
				320	0-15-00
				317	1-00-05
				316	0-06-10
				370	0-15-15
				387	0-04-16
				386	0-15-06
				385	1-01-00
				384	0-13-00
				383	0-07-10
				392	0-00-07
				404	0-18-10
				334	0-04-00
				335	0-00-02
				391	0-00-02
				389	0-14-00
				324	0-10-10
				322	0-10-04
सम्पूर्ण योग				46 21-14-16 बीघा या 5.5002 है०	

[सं० ओ०-14016/375/85-जी पी]

S.O. 4476.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 3045 dated 29-6-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipeline Project.

Distt.	Tehsil	Village	Pargana	Plot No	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Dataganj	Salam-pur	Serha Kham	25	0-05-05
				23	0-01-00
				20	0-01-00
				24	1-06-00
				26	0-01-00
					छूटा था
				27	0-05-00
				97	0-02-08
				12	0-08-01
				102	0-06-15
				100	0-00-02
				101	0-10-15
				99	0-01-15
				98	0-07-05
				105	1-00-00
				106	0-15-15
				183	1-15-08
				180	0-18-00
				216	0-09-12
				215	0-17-02
				214	0-05-05
				213	0-15-00
				184	0-00-05
				85/2	0-01-04
				237	1-06-00
				239	0-06-12
				293/1	0-14-00
				323	0-06-00
				319	0-00-05
				321	0-01-05
				320	0-15-00
				317	1-00-05
				316	0-06-10
				370	0-15-15
				387	0-04-16
				386	0-15-06
				385	1-01-00
				384	0-13-00
				383	0-07-10
				392	0-00-07

	404	0–18–10
	334	0–04–00
	335	0–00–02
	391	0–00–02
	389	0–14–00
	324	0–10–10
	322	0–10–84
Total	46	21–14–16 Bigha or Hec. 5.5002

[No. O-14016/375/85-G.P.]

का०आ० 4477-यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्‌पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : बड़ोदरा तालुका : करजण

गांव	सर्वे नं०	हैक्टेयर	आर०	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
सानडोल	कोटर	0	12	00
	262	0	08	40
	264	0	73	80

1	2	3		5
	263	0	04	80
	271	0	06	00
	273	0	40	80
	274	0	07	20
	277/1	0	44	40
	280	0	22	40
	281	0	11	20
	283	0	15	60
	284/2	0	46	80
	284/3	0	00	30
	285	0	29	60
	319	0	39	60
	318	0	32	40
	320	0	61	20
	324	0	13	20
	323	0	12	00
	326	0	07	20
	329	0	18	00
	332	0	00	30
	331	0	03	60
	330	0	14	40

[सं० ओ-14016/489/85-जी०पी०]

S.O. 4477.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly-Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the scheduled annexed hereto;

Now. therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Sagdol	Kotar	0	12	00
	262	0	08	40
	264	0	73	80
	263	0	04	80
	271	0	06	00
	273	0	40	80
	274	0	07	20
	277/1	0	44	40
	280	0	22	40
	281	0	11	20
	283	0	15	60
	284/2	0	46	80
	284/3	0	00	30
	285	0	39	60
	319	0	39	60
	318	0	32	40
	320	0	61	20
	324	0	13	20
	323	0	12	00
	326	0	07	20
	329	0	18	00
	332	0	00	30
	331	0	03	60
	330	0	14	40

[No. O-14016/489/85-G.P.]

का०आ० 4478—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 56) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाईन बिछाने के लिये

राज्य—गुजरात जिला—वडोदरा तालुका—करजन

गांव	सर्वे नं०	हैक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
भालोद	11	0	37	50
	13	0	13	50
	14	0	10	20
	113	0	01	40
	23	0	43	50
	26	0	01	20
	27/1	0	34	50
	27/2	0	12	00
	27	0	02	10
	27/3	0	18	00
	106	0	18	00
	37	0	24	00
	36	0	49	20
	40	0	06	00
	41	0	73	20
	46	0	04	50
	45	0	27	60
	58	0	32	40
	57	0	41	80
	60	0	01	20
	कार्ट ट्रेक	0	08	40

[सं० ओ०-14016/490/85-जी०पी०]

S.O. 4478.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly-Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the scheduled annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the

Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Malod	11	0	37	50
	13	0	13	50
	14	0	10	20
	113	0	01	40
	23	0	43	50
	26	0	01	20
	27/1	0	34	50
	27/2	0	12	00
	27	0	02	10
	27/3	0	18	00
	106	0	18	00
	37	0	24	00
	36	0	49	20
	40	0	05	00
	41	0	73	20
	46	0	04	50
	45	0	27	60
	58	0	32	40
	57	0	41	80
	60	0	01	20
	Cart track	0	08	40

[No. O-14016/490/85-GP]

का०आ० 4479.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 56) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाईन बिछाने के लिये

राज्य—गुजरात जिला—भरुच तालुका—अंकलेश्वर

गांव	ब्लाक नं०	हैक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
पीपरोद	105	0	26	40
	97	0	43	20
	106	0	51	52
	110	0	20	48
	111	0	00	50
	107	0	00	30
	108	0	55	68
	109	0	11	52

[सं० ओ-14016/491/85-जी०पी०]

S.O. 4479.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly-Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the scheduled annexed hereto,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Anleshwar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Piprod	105	0	26	40
	97	0	43	20
	106	0	51	52
	110	0	20	48
	111	0	00	50
	107	0	00	30
	108	0	55	68
	109	0	11	52

[No. O-14016/491/85-GP]

का. आ. 4480.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिये।

राज्य—गुजरात जिला—भरुच तालुका—झगडीया

गाव	सर्वे नं.	हेक्टर	ए आर ई	सेंटीआर
1	2	3	4	5
कपलसडी	124	0	25	50
	123	0	24	00
	119	0	22	50
	120	0	09	00
	107	0	15	00
	कार्ट ट्रेक	0	03	00
	135	0	36	50
	136	0	67	50
	139	0	82	50
	99	0	21	00
	100	0	16	50
	59	0	30	00
	68	0	11	25

[सं. O-14016/492/85-जी पी]

S.O. 4480.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly-Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the scheduled annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Zaghadiya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Kapalsadi	124	0	25	50
	123	0	24	00
	119	0	22	50
	120	0	09	00
	107	0	15	00
	Cart track	0	03	00
	135	0	36	50
	136	0	67	50
	139	0	82	50
	99	0	21	00
	100	0	16	50
	69	0	30	00
	68	0	11	25

[No. O-14016/492/85-G.P.]

का. आ. 4481:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा—बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल, प्रभाग मकरपुरा रोड़, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—बड़ोदरा तालुका—करजा

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेअर	एआर	सेंटीआर
मोटा कोयल	188	0	51	30
	117	0	17	10
	120	0	28	80
	121	0	10	50
	122	0	21	00
	123	0	18	50
	115	0	10	00
	कार्ट ट्रेक	0	03	60
	192	0	13	20
	190	0	03	30
	191	0	11	25
	कार्ट ट्रेक	0	06	00
	206	0	20	40
	207	0	12	00
	275	0	24	00
	280	0	48	00
	279	0	14	40
	278	0	25	12

[सं. O-14016/4938/5-जीपी]

S.O. 4481.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Barellly-Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the scheduled annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Moti Koral	118	0	51	30
	117	0	17	10
	120	0	28	80
	121	0	10	50
	122	0	21	00
	123	0	18	50
	115	0	10	00
	Cart track	0	03	60
	192	0	13	20
	190	0	03	30
	191	0	11	25
	Cart track	0	06	00
	206	0	20	40
	207	0	12	00
	275	0	24	00
	280	0	48	00
	279	0	14	40
	278	0	25	12

[No. O-14016/493/85-G.P.]

का. आ. 4482—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा—बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य—गुजरात जिला—भरुच तालुका—झगड़ीया

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आरे	सेंटीयर
1	2	3	4	5
वाघपुरा	275	0	36	00
	274	0	35	05
	278	0	25	45
	279	0	16	80
	280	0	38	40
	281	0	09	60
	252	0	21	60
	251	0	24	00
	309	0	14	40
	310	0	20	40
	312	0	05	76
	311	0	13	20
	303	0	48	00
	302	0	30	00
	301	0	08	40
	6	0	20	40
	12	0	18	00
	कार्ट ट्रैक	0	01	80
	36	0	32	00
	32	0	01	60
	35	0	16	80
	34	0	31	20

[सं. O-14016/494/85-जीपी]

S.O. 4482.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly-Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the scheduled annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Zaghadiya

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Vaghpura	275	0	36	00
	274	0	35	05
	278	0	25	45
	279	0	16	80
	280	0	38	40
	281	0	09	60
	252	0	21	60
	251	0	24	00
	309	0	14	40
	310	0	20	40
	312	0	05	76
	311	0	13	20
	303	0	48	00
	302	0	30	00
	301	0	08	40
	6	0	20	40
	12	0	18	00
	Cart track	0	0.	80
	36	0	32	00
	32	0	01	60
	35	0	16	80
	34	0	31	20

[No. O-14016/494/85-G.P.]

का. आ. 4483:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुर रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य—गुजरात जिला—भरुच तालुका—झगडीया

गांव	सर्वे नं0	हेक्टयर	आरे0	सेंचीय र
1	2	3	4	5
वंयेवाल	कौंटार	0	15	00
	153	0	54	00
	134	0	28	50
	151	0	25	50
	150	0	30	00
	149	0	22	50
	148	0	02	00
	147	0	52	00
	144	0	19	50
	145	0	43	50
	गामताल	0	27	75
	184	0	00	50
	7	0	09	75
	6	0	02	50
	5	0	20	50
	3	0	00	75
	2	0	02	50
	कार्ट ट्रैक	0	06	00
	1	0	02	50
	204	0	57	00
	203	0	22	00
	23	0	09	75

[सं. O-14016/495/85-जीपी]

S.O. 4483.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly-Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the scheduled annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Zaghadiya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Vantheval	Kotar	0	15	00
	153	0	54	00
	134	0	28	50
	151	0	25	50
	150	0	30	00
	149	0	22	50
	148	0	02	00
	147	0	52	00
	144	0	19	50
	145	0	43	50
	Gamtal	0	27	75
	184	0	00	50
	7	0	09	75
	6	0	02	50
	5	0	20	50
	3	0	00	75
	2	0	02	50
	Cart track	0	06	00
	1	0	02	50
	204	0	57	00
	203	0	22	00
	23	0	09	75

[No. O-14016/495/85-G.P.]

का. आ. 4484.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य—गुजरात जिला—भरुच तालुका —झगड़ीया

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
1	2	3	4	5
सुल्तानपुर	364	0	22	50
	363/ए	0	39	00
	365	0	00	50
	361	0	14	50
	कार्ट ट्रेक	0	06	00
	398	0	14	62
	397	0	00	30
	399	0	28	50
	400	0	24	00
	407	0	32	00
	408	0	03	00
	406	0	34	00
	405	0	15	00
	कार्ट ट्रेक	0	07	50
	421	0	04	50
	513	0	20	25
	512	0	06	75
	511	0	27	75
	510	0	37	00
	514	0	08	00
	508	0	39	00
	Kotar	0	13	50
	505	0	25	50
	498	0	25	50
	499	0	18	00
	504	0	01	00
	500	0	30	00
	472	1	06	50
	478	0	06	00

[सं. O-14016/496/85-जी.पी.]

S.O. 4484.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly-Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the scheduled annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Zaghadiya

Village	Survey No.	Hecate	Are	Centiar
1	2	3	4	5
Sultanpur	364	0	22	50
	363/A	0	39	00
	365	0	00	50
	361	0	14	50
	Cart track	0	06	00
	398	0	14	62
	397	0	00	30
	399	0	28	50
	400	0	24	00
	407	0	32	00
	408	0	03	00
	406	0	34	00
	405	0	15	00
	Cart track	0	07	50
	421	0	04	50

1	2	3	4	5
Sultanpur (contd.)	513	0	20	25
	512	0	06	75
	511	0	27	75
	510	0	37	00
	514	0	08	00
	508	0	39	00
	Kotar	0	13	50
	505	0	25	50
	498	0	25	50
	499	0	18	00
	504	0	01	00
	500	0	30	00
	472	1	06	50
	478	0	06	00

[No. O-14016/496/85-G.P.]

का. आ. 4465.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः, अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—वड़ोदरा तालुका—करजन

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आरे	सेंटियर
1		3	4	5
पुरा	367	0	09	60
	कार्टट्रेक	0	03	60
	365	0	04	50
पुरा (जारी)	366	0	10	80
	368	0	10	80
	369	0	15	00
	362	0	12	60
	372	0	01	00
	373	0	23	00
	356	0	03	00
	355	0	10	80
	353	0	12	00
	352	0	06	00
	351	0	14	80
	350	0	06	00
	349	0	04	80
	348	0	05	10
	344	0	02	70
	343	0	12	00
	337	0	00	48
	336	0	02	22
	293	5	18	00
	291	0	05	05
	290	0	03	00

[सं. O-14016/497/85-जी० पी०]

S.O. 4485.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly-Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Pura	367	0	09	60
	Cart track	0	03	60
	365	0	04	50
	366	0	10	80
	368	0	10	80
	369	0	15	00
	362	0	12	60
	372	0	01	00
	373	0	23	00
	356	0	03	00
	355	0	10	80
	353	0	12	00
	352	0	06	00
	351	0	04	80
	350	0	06	00
	349	0	04	80
	348	0	05	10
	344	0	02	70
	343	0	12	00
	337	0	00	48
	336	0	02	22
	293	0	18	00
	291	0	05	05
	290	0	03	00

[No. O-14016/497/85-G.P.]

का. आ. 4486.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—वडोदरा तालुका—करजन

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आरे	सेंटीयर
बेमार	312	0	07	50
	311	0	33	60
	305	0	01	68
	306	0	34	80
	307	0	30	00
	294	0	33	00
	287	0	54	00
	282	0	04	40
	286	0	29	20
	कार्ट ट्रेक	0	02	40
	256	0	13	50
	263	0	42	00
	264	0	12	80
	241	0	12	80
	242	0	30	80
	243	0	36	00
	244	0	18	00
	229	0	34	80
	230	0	01	00
	228	0	09	60
	215	0	01	50
	216	0	31	80
	212	0	46	08
	213	0	01	92
	203	0	10	80
	204	0	27	36
	202	0	06	00
	201	0	13	60
	200	0	18	00
	197	0	48	00
	199	0	18	20
	198	0	14	08
	Kans	0	19	20
	138	0	21	20
	139	0	10	24
	Kans	0	12	80
	137	0	18	00

[सं. O-14016/4985/8-जी पी]

S.O. 4486.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan

Village	Block No.	Hectare	Are	Centriare
Vemar	312	0	07	50
	311	0	33	60
	305	0	01	68
	306	0	34	80
	307	0	30	00
	294	0	33	00
	287	0	54	00
	282	0	04	40
	286	0	29	20
	Cart track	0	02	40
	256	0	13	50
	263	0	42	00
	264	0	12	80
	241	0	12	80
	242	0	30	80
	243	0	36	00
	244	0	18	00
	229	0	34	80
	230	0	01	00
	228	0	09	60
	215	0	01	50
	216	0	31	80
	212	0	46	08
	213	0	01	92
	203	0	10	80
	204	0	27	36
	202	0	06	00
	201	0	13	60
	200	0	18	00
	197	0	48	00
	199	0	18	20
	198	0	14	08
(Contd.)	Kans	0	19	20
	138	0	21	20
	139	0	10	24
	Kans	0	12	80
	137	0	18	00

[No. O-14016/498/85-G.P.]

का.आ. 4487.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य: गुजरात जिला:—भरूच तालुका:—झगड़ीया

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
अविधा	1013	0	15	00
	1014	0	10	25
	1091	0	15	00
	1092	0	08	05

1	2	3	4	5
अविधा (जारी)	1093	0	18	00
	1096	0	48	00
	1097	0	18	00
	1098	0	15	00
	1099	0	04	10
	1100	0	10	00
	कार्ट ट्रैक	0	02	40
	1115	0	35	10
	1116	0	19	50
	1120	0	16	50
	1121	0	15	00
	1122	0	22	50
	1132	0	18	06
	1131	0	25	10
	1129	0	01	00
	1150	0	21	00
	1151	0	04	80
	1149	0	04	80
	1152	0	15	00
	कोटार	0	08	40
	158	0	24	60
	152	0	48	00
	153+154+155	0	03	00
	151	0	07	50
	150	0	09	00
	175	0	09	00
	184	0	21	00
	182	0	05	00
	183/ग	0	09	35
	181	0	16	50
	कार्ट ट्रैक	0	05	10
	233	0	33	00
	66	0	00	75
	65	0	12	60
	64	0	39	60
	63	0	02	10
	61	0	45	00
	356	0	01	20
	60	0	01	20
	कार्ट ट्रैक	0	01	00
	366	0	18	00
	365	0	19	50
	364	0	08	05
	377	0	08	00
अविधा (जारी)	378	0	25	50
	379	0	21	00
	381	0	19	50
	382	0	01	92
	383	0	39	00
	393	0	00	20
	389	0	30	00

[सं. O-14016/499/85-जी.पी]

S.O. 4487.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Zaghadiya

Village	Survey No	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Avidha	1013	0	15	00
	1014	0	10	25
	1091	0	15	00
	1092	0	08	05
	1093	0	18	00
	1096	0	48	00
	1097	0	18	00
	1098	0	15	00
	1099	0	04	10
	1100	0	10	00
	Cart track	0	02	40
	1115	0	35	10
	1116	0	19	50
	1120	0	16	50
	1121	0	15	00
	1122	0	22	50
	1132	0	18	00

1	2	3	4	5
	1131	0	25	10
	1129	0	01	00
	1150	0	21	00
	1151	0	04	80
	1149	0	04	80
	1152	0	15	00
	Kotar	0	08	40
	158	0	24	60
	152	0	48	00
	153—154—155	0	03	00
	151	0	07	50
	150	0	09	00
	175	0	09	00
	184	0	21	00
	182	0	05	00
	183/A	0	09	35
	181	0	16	50
	Cart track	0	05	10
	233	0	33	00
	66	0	00	75
	65	0	12	60
	64	0	39	60
	63	0	02	40
	61	0	45	00
	356	0	01	20
	60	0	01	20
	Cart track	0	01	00
	366	0	18	00
	365	0	19	50
	364	0	08	05
	379	0	08	00
	378	0	25	50
	377	0	21	00
	381	0	19	50
	382	0	01	92
	383	0	39	00
	392	0	00	20
	389	0	30	00

[No. O-14016/499/85-G.P.]

का. आ. 4488.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : झगड़िया

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
जारसद	100	0	12	00
	99	0	48	00
	97	0	37	50
	124	0	40	50
	125	0	10	00
	41	0	21	50
	128	0	33	00
	130	0	39	00
	131	0	10	50
	132	0	15	60
	133	0	08	75
	कोटार	0	07	50
	182	0	11	10
	185	0	11	00
	186	0	34	80
	190	0	30	00
	191	0	00	50
	188	0	03	75
	कोटार	0	18	00
	234	0	14	45
	237	0	14	45
	235	0	10	50
	230	0	06	00
	229	0	38	10
	228	0	03	90

1	2	3	4	5
	224	0	13	50
	222	0	22	50
	216	0	27	00
	215	0	01	00
	217	0	00	50

[सं० O-14016/500/85-जी०पी०]

S.O. 4488.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly-Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the scheduled annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch Taluka: Zaghadiya

Village	Survey No.	Hectare	Are.	Contiare
1	2	3	4	5
Jarsad	100	0	12	00
	99	0	48	00
	97	0	37	50
	124	0	40	50
	125	0	10	00
	41	0	21	50
	128	0	33	00
	130	0	39	00
	131	0	10	50
	132	0	15	60
	133	0	08	75
	Kotar	0	07	50
	182	0	11	10
	185	0	11	00
	186	0	34	80
	190	0	30	00
	191	0	00	50
	188	0	03	75
	Kotar	0	18	00
	234	0	14	45
	237	0	14	45
	235	0	10	50
	230	0	06	00
	229	0	38	10
	228	0	03	90
	224	0	13	50
	222	0	22	50
	216	0	27	00
	215	0	01	00
	217	0	00	50

[No. O-14016/500/85-G.P.]

का.आ. 4489.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत;

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : अंकलेश्वर

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
उवादर	250	0	40	80
	177	0	48	00
	175	0	40	80
	173	1	12	80

1	2	3	4	5
	कोटार	0	21	60
	158	0	16	80
	161	0	07	20
	160	0	08	40
	162	0	24	00
	163	0	16	80
	167	0	48	00
	131	0	48	00
	130	0	26	40
	129	0	24	00
	31	0	40	80
	32	0	14	40
	33	0	12	00
	34	0	88	80
	35	0	33	60
	127	0	03	00
	45	0	12	00
	86	0	45	60
	कोटार	0	04	80
	85	0	39	60
	79	0	09	60
	88	0	26	40

[सं. O-14016/501/85-जी.पी.]

S.O. 4489.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly-Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the scheduled annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State:Gujarat District : BharuchTaluka : Ankleshwar

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	4	4	5
Uvader	250	0	40	80
	177	0	48	00
	175	0	40	80
	173	1	12	80
	Kotar	0	21	60
	158	0	16	80
	161	0	07	20
	160	0	08	40
	162	0	24	00
	163	0	16	80
	167	0	48	00
	131	0	48	00
	130	0	26	40
	129	0	24	00
	31	0	40	80
	32	0	14	40
	33	0	12	00
	34	0	88	80
	35	0	33	60
	127	0	03	00
	45	0	12	00
	86	0	45	60
	Kotar	0	04	80
	85	0	37	60
	79	0	09	60
	88	0	26	40

[No. O-14016/501/85-G.P.]

का. आ. 4490 —यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा—बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : वालीया

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
कोंध	1189	0	15	00
	1190	0	44	25
	1193	0	12	15
	1194	0	12	15
	1195	0	36	00
	1196	0	48	68
	1197	0	02	12
	1222	0	52	50
	1221	0	15	00
	1220	0	22	50
	1241	0	06	00
	1242	0	07	50
	1218	0	82	50
	1246	0	12	00
	1147	0	33	00
	114	0	23	50
	110	0	02	50
	109	0	01	25
	108	0	21	00
	107	0	36	50
	96	0	00	25
	99	0	01	50
	100	0	30	00
	89	0	45	00
	90	0	13	50
	कार्टट्रेक	0	07	50
	222	0	15	00
	224	0	43	63
	69	0	08	87
	225	0	67	50
	218	0	43	50
	216	0	19	50
	कोटार	0	15	00
	230	0	05	62
	228	0	58	88
	253	0	16	50
	254	0	04	50
	252	0	18	00
	231	0	37	50
	251	0	00	50
	232	0	03	70
	248	0	53	25
	247	0	10	50
	242	0	30	00
	241	0	13	50
	238	0	22	50
	237	0	25	50
	239	0	10	50

[सं. ओ.-14016/502/85-जी. पी.]

S.O. 4490.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly-Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the scheduled annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira– Bareilly–Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch Taluk : Valiya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centriare
1	2	3	4	5
Kondh	1189	0	15	00
	1190	0	44	25
	1193	0	12	15
	1194	0	12	15
	1195	0	36	00
	1196	0	48	68
	1197	0	02	12
	1222	0	52	50
	1221	0	15	00
	1220	0	22	50
	1241	0	06	00
	1242	0	07	50
	1218	0	82	50
	1246	0	12	00
	1147	0	33	00
	114	0	23	50
	110	0	02	50
	109	0	01	25
	108	0	21	00
	107	0	36	50
	96	0	00	25
	99	0	01	50
	100	0	30	00
	89	0	45	00
	90	0	13	50
	Cart tract	0	07	50
	222	0	15	00
	224	0	43	63
	69	0	08	87
	225	0	67	50
	218	0	43	50
	216	0	17	50
	Kotar	0	15	00
	230	0	05	62
	228	0	58	88
	253	0	16	50
	254	0	04	50
	252	0	18	00
	231	0	37	50
	251	0	00	50
	232	0	03	70
	248	0	53	25
	247	0	10	50
	242	0	30	00
	241	0	13	50
	238	0	22	50
	237	0	25	50
	237	0	10	50

[No. O-14016/550/85-G P]

का. आ. 4491.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा–बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी पाइपों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदरा—9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : झगड़िया

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
भालोद	661	0	22	50
	660	0	00	30
	663	0	21	00
	664	0	27	00
	कार्टट्रेक	0	03	00
	743	0	26	50
	742	0	00	50
	746	0	12	00
	747	0	13	50
	741	0	58	50
	740	0	45	50
	739	0	01	00
	कार्टट्रेक	0	56	25

1	2	3	4	5
	720	0	10	50
	719	0	16	50
	718	0	15	75
	717	0	12	00
	707	0	01	50
	706	0	34	50
	924	0	40	50
	कार्टट्रेक	0	04	50
	919	0	29	25
	929	0	03	75
	918	0	60	00
	कार्टट्रेक	0	01	80
	13	0	22	50
	12	0	22	50
	30	0	02	62
	31	0	27	00
	29	0	13	50
	कार्टट्रेक	0	09	00
	168/2	0	13	50
	167	0	08	00
	943	0	24	00
	कार्टट्रेक	0	03	00
	36	0	24	00
	38	0	03	00
	39	0	04	50

[No. O–14016/503/85–G. P.]

S.O. 4491.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly-Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Zaghadiya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Bhalod	661	0	22	50
	660	0	00	30
	663	0	21	00
	664	0	27	00
	Cart track	0	03	00
	743	0	26	50
	742	0	00	50
	746	0	12	00
	747	0	13	50
	741	0	58	50
	740	0	45	50
	739	0	01	00
	Cart track	0	56	25
	720	0	10	50
	719	0	16	50
	718	0	15	75
	717	0	12	00
	707	0	01	50
	706	0	34	50
	924	0	40	50
	Cart track	0	04	50
	919	0	29	25
	929	0	03	75
	918	0	60	00
	Cart track	0	01	80
	13	0	22	50
	12	0	22	50
	30	0	02	62
	31	0	27	00
	29	0	13	50
	Cart track	0	09	00
	168/2	0	13	50
	167	0	08	00
	943	0	24	00
	Cart track	0	03	00
	36	0	24	00
	38	0	03	00
	39	0	04	50

[No. O–14016/503/85–G. P.]

का. आ. 4492—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य हजीरा—बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, वडोदरा—9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : झगडीया

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
रुन्ड	कार्टट्रेक	0	04	50
	422	0	24	00
	423	0	00	50
	431	0	16	50
	432	0	10	50
	433	0	06	00
	434	0	01	00
	440	0	30	00
	435	0	12	00
	437	0	04	40
	438	0	13	50
	455	0	18	00
	454	0	07	00
	453	0	07	00
	452	0	18	00
	451	0	18	00

[सं. O.-14016/504/85-जी. पी.]

S.O. 4492.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly-Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Zaghadiya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Rundh	Cart track	0	04	50
	422	0	24	00
	423	0	00	50
	431	0	16	50
	432	0	10	50
	433	0	06	00
	434	0	01	00
	440	0	30	00
	435	0	12	00
	437	0	04	40
	438	0	13	50
	455	0	18	00
	454	0	07	00
	453	0	07	00
	452	0	18	00
	451	0	18	00

[No. O-14016/504/85-G.P.]

का. आ. 4493:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा—बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल

प्रभाग, मकरपुरा रोड़, वडोदरा—9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य : गुजरात जिला : वडोदरा तालुका : करजण

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर ई	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
कहोणा	248	0	18	00
	249	0	42	00
	250	0	21	60
	253	0	17	20
	252	0	17	54
	254	0	21	80
	255	0	36	00
	256	0	11	10
	257	0	13	20
	260	0	31	20
	258	0	01	20
	259	0	04	20
	263	0	21	92
	264	0	01	60
	265	0	00	64
	266	0	02	24
	267	0	03	20
	268	0	24	40
	कार्टट्रेक	0	08	40
	58	0	66	00
	कार्टट्रेक	0	03	60

[सं. O-14016/505/85-जी. पी.]

S.O 4493.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly- Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Kahona	248	0	18	00
	249	0	42	00
	250	0	21	60
	253	0	17	20
	252	0	17	54
	254	0	21	80
	255	0	36	00
	256	0	11	40
	257	0	13	20
	260	0	31	20
	258	0	04	20
	259	0	04	20
	263	0	21	92
	264	0	01	60
	265	0	00	64
	266	0	02	24
	267	0	03	20
	268	0	24	40
	Cart track	0	08	40
	58	0	66	00
	Cart track	0	03	60

[No. O-14016/505/85-G.P.]

का. आ. 4494—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा—बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बड़ोदरा—9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिये।

राज्य : गुजरात जिला : पंचमहाल तालुका : लीमखेड़ा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
घुटीया	29	0	11	00
	38/पी	0	04	50

[सं० O-14016/506/85-जी. पी.]

S.O. 4494.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira—Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira Bareilly Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal

Fauka : Limkheda

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Ghutiya	27	0	11	00
	38/P	0	04	50

[No. O-14016/506/85-GP]

का. आ. 4495.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य :—गुजरात जिला :—मच महल तालुका :—दाहोद

गांव	सर्वेक्षण नं.	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
कठला	45	0	02	90
	211	0	10	84
	212	0	15	69

[सं O-14016/507/85-जी.पी.]

S.O. 4495.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly-Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Rignt of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal

Taluka : Dahod

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Kathala	45	0	02	90
	211	0	10	84
	212	0	15	6

[No. O-14016/507/85-GP]

का.आ. 4496.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है। लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसा लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिये ।

राज्य :—गुजरात जिला :—भरूच तालुका :—अंकलेश्वर

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
करारवेल	305	0	19	20
	15	0	16	64
	306	0	14	40
	302	0	00	30
	301	0	63	80
	307	0	40	80
	294	0	00	80
	292	0	40	80
	293	0	24	00

[सं. O-14016/508/85-जी.पी.]

S.O. 4496.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch

Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Kararvel	305	0	19	20
	15	0	16	64
	306	0	14	40
	302	0	00	30
	301	0	64	80
	307	0	40	80
	294	0	00	80
	292	0	40	80
	293	0	24	00

[No. O-14016/508/85-GP]

का.आ. 4497.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य— गुजरात जिला—वडोदरा तालुका—करजण

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
आलमपुर	150	0	24	00
	149	0	02	00
	148	0	22	20
	146	0	20	40
	145	0	14	40
	142	0	26	20
	141	0	00	47
	163	0	14	20
	140	0	06	12
	139	0	00	64
	162	0	04	50
	165	0	09	00

[सं. O-14016/509/85-जी.पी.]

S.O. 4497.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan

Village	Block No.	Hec-tare	Area	Con-tiare
Alampur	150	0	24	00
	149	0	02	00
	148	0	22	20
	146	0	20	40
	145	0	14	40
	142	0	26	20
	141	0	00	47
	163	0	14	20
	140	0	06	12
	139	0	00	64
	162	0	04	50
	165	0	09	00

[No. O-14016/509/85-GP]

का. आ. 4498.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिये

राज्य—गुजरात, जिला—वडोदरा तालूका—करजण

गांव	सर्वे नं.	हेक्टयर	एआरई	सेन्टीअर
लीलोद	कार्ट ट्रेक	0	08	40
	92	0	10	80
	93	0	16	20
	94	0	14	40
	86	0	38	40
	86/1	0	31	20
	86/2	0	00	20
	कार्ट ट्रेक	0	04	80

[सं. O-14016/510/85-जी.पी.]

S.O. 4498.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Rignt of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Lilod	Cart track	0	08	40
	92	0	10	80
	93	0	16	20
	94	0	14	40
	86	0	38	40
	86/1	0	31	20
	86/2	0	00	30
	Cart track	0	04	80

[No. O-14016/510/85-GP]

का. आ. 4499.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिये

राज्य—गुजरात जिला—भरूच तालुका—अंकलेश्वर

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेअर	एआरई	सेन्टीअर
जोलवी	517	0	40	80
	520	0	21	60
	518	0	11	52
	519	0	50	40
	528	0	24	00
	535	0	33	60
	567	0	19	20
	573	0	15	36
	574	0	69	60
	575	0	52	80

[सं. O-14016/511/85-जीपी]

S.O. 4499.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat Dist : Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Jitali	517	0	40	80
	520	0	21	60
	518	0	11	52
	519	0	50	40
	528	0	24	00
	565	0	33	60
	567	0	19	20
	573	0	15	36
	574	0	69	60
	575	0	52	80

[No. O-14016/511/85-G.P.]

का.आ. 4500.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा—बरेली—जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिये

राज्य—गुजरात जिला—भरूच तालुका—अंकलेश्वर

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेअर	एआरई	सेन्टीआर
1	2	3	4	5
फुलवाडी	117	0	19	50
	कार्ट ट्रेक	0	03	00
	109	0	16	50
	111	0	20	25
	107	0	04	50
	105	0	50	00
	104	0	00	50
	106	0	00	50
	58	0	07	50
	59	0	37	50
	60	0	07	00
	61	0	39	00
	62	0	34	50
	64	0	27	00
	65	0	18	00
	69	0	00	50
	68	0	18	00
	67	0	03	00
	कार्ट ट्रेक	0	03	00
	365	0	21	80
	370	0	08	70
	369	0	28	00
	368	0	09	00
	552	0	39	00
	545	0	37	50
	554	0	33	00
	539	0	33	00
	540	0	28	50

1	2	3	4	5
	534	0	28	50
	535	0	09	00
	532	0	21	00
	509	0	31	50
	497	0	29	50
	513	0	05	25
	514	0	22	50
	496	0	22	50
	495	0	24	00
	कार्ट ट्रेक	5	03	00
	491	0	51	00
	490	0	01	00
	492	0	07	50
	कार्ट ट्रेक	0	03	00
	454/पी	0	48	00
	456	0	30	00
	कोटार	0	39	00

[सं० O-14016/512/85-जी० पी०]

S.O. 4500.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat Dist. : Bharuch Taluka : Jaghadiya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Fulwadi	117	0	19	50
	Cart track	0	03	00
	109	0	16	50
	111	0	20	25
	107	0	04	50
	105	0	50	00
	104	0	00	50
	106	0	00	50
	58	0	07	50
	59	0	37	50
	60	0	07	00
	61	0	39	00
	62	0	34	50
	64	0	27	00
	65	0	18	00
	69	0	00	50
	68	0	18	00
	67	0	30	00
	Cart track	0	03	00
	365	0	21	80
	370	0	08	70
	369	0	28	00
	368	0	09	00
	552	0	39	00
	545	0	37	50
	554	0	33	00
	539	0	33	00
	540	0	28	50
	534	0	28	50
	535	0	09	00
	532	0	21	00
	509	0	31	50
	497	0	29	50
	513	0	05	25
	514	0	22	50
	496	0	22	50
	495	0	24	00
	Cart track	0	03	00
	491	0	51	00
	490	0	01	00
	492	0	07	50
	Cart track	0	03	00
	454/P	0	48	00
	456	0	30	00
	Kotar	0	39	00

[No. O-14016/512/85-G.P.]

का.आ. 4501.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारत गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए तद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय

सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : बड़ोदरा तालुका : करजण

गांव	सर्वे नं.	हैक्टेयर	एआर ई	सेन्टियर
फतेपुर	191	0	94	80
	192/1	0	30	00
	कार्ट ट्रैक	0	06	00
	167	0	93	60
	169/1	0	12	48
	169/2	0	16	64
	137	0	60	00
	135	0	09	00
	130	0	12	92
	128	0	18	00
	123	0	05	40
	127	0	45	60
	124	0	31	20
	कार्ट ट्रैक	0	08	40
	73	0	32	40
	74	0	19	20
	75	0	44	40
	कार्ट ट्रैक	0	10	80
	49	0	92	40
	50	0	51	60
	कार्ट ट्रैक	0	04	80

[सं O-14016/513/85-जी पी]

S.O. 4501.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

768 GI/85—21

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Fatepur	191	0	94	80
	192/1	0	30	00
	Cart track	0	06	00
	167	0	93	60
	169/1	0	12	48
	169/2	0	16	64
	137	0	60	00
	135	0	09	00
	130	0	12	92
	128	0	18	00
	123	0	05	40
	127	0	45	60
	124	0	31	20
	Cart track	0	08	40
	73	0	32	40
	74	0	19	20
	75	0	44	40
	Cart track	0	10	80
	49	0	92	40
	50	0	51	60
	Cart track	0	04	80

[No. O-14016/513/85-GP]

का. आ. 4502.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा—बरेली से जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : सूरत तालुका : मांगरोल

गांव	ब्लाक नं.	हैक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
बोरीद्रा	173	0	07	20
	174	0	20	40
	175	0	44	40
	185	0	84	60
	179	0	05	40
	192	0	54	00
	183	0	05	40
	कार्ट ट्रैक	0	04	80
	192	0	26	40
	191	0	42	00
	194	0	66	00
	195	0	18	00
	197	0	30	00
	198	0	21	00
	196	0	30	00

[सं. O-14016/514/85-जी. पी]

S.O. 4502.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Surat

Taluka : Mangrol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Baroda	173	0	07	20
	174	0	20	40
	175	0	44	40
	185	0	84	60
	179	0	05	40
	192	0	54	00
	183	0	05	40
	Cart track	0	04	80
	192	0	26	40
	191	0	42	00
	194	0	66	00
	195	0	18	00
	197	0	30	00
	198	0	21	00
	196	0	30	00

[No. O-14016/514 85-GP]

का. आ. 4053—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा—बरेली से जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : वडोदरा तालुका : करजण

गांव	ब्लाक नं.	हैक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
बकापुर	106	0	28	80
	कार्ट ट्रैक	0	04	80
	71	0	63	60
	70	0	59	20
	75	0	01	60
	68	0	21	60
	67	0	13	20
	66	0	13	20

[सं. O-14016/515/85-जी. पी]

S.O. 4503.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Bakapur	106	0	28	80
	Cart track	0	04	80
	71	0	63	60
	70	0	59	20
	75	0	01	60
	68	0	21	60
	67	0	13	20
	66	0	13	20

[No. O-14016/515/85-GP]

का.आ. 4504.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा—बरेली से जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : बड़ोदरा तालुका : करजण

गांव	ब्लॉक नं.	हैक्टेयर	ए आर ई	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
सीमली	153	0	34	80
	152	0	09	60
	154	0	24	00
	147	0	00	80
	21	0	04	40
	22	0	19	20
	24	0	24	00
	25	0	32	40
	30	0	03	20
	27	0	24	40
	29	0	28	80
	33	0	30	00
	34	0	03	7
	कार्ट ट्रैक	0	02	40
	126	0	30	00
	कार्ट ट्रैक	0	04	80
	94	0	19	20
	95	0	11	30
	84	0	30	00
	92	0	24	00
	कार्ट ट्रैक	0	03	60
	47	0	26	40
	48	0	28	80
	49	0	12	00
	50	0	14	40
	52	0	08	80
	749	0	45	60
	756	0	26	80
	5	0	08	00
	141	0	31	12
	76	0	10	88
	207	0	09	00
	276	0	10	20
	320	0	18	60
	408	0	27	60
	कार्ट ट्रैक	0	06	00
	687	0	37	20
	719	0	33	60
	718	0	27	00
	723	0	19	80
	712	0	06	60

[सं. O-14016/516/85-जी पी]

S.O. 4504.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira--Bareilly--Jagdishpur

State : Gujarat--District : Vadodara Taluka : Karjan

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Simali	153	0	34	80
	152	0	09	60
	154	0	24	00
	147	0	00	80
	21	0	04	40
	22	0	19	20
	24	0	24	00
	25	0	32	40
	30	0	03	20
	27	0	24	40
	29	0	28	80
	33	0	30	00
	34	0	03	72
	Cart track	0	02	40
	136	0	30	00
	Cart track	0	04	80
	94	0	19	20
	95	0	11	30
	84	0	30	00
	92	0	24	00
	Cart track	0	03	60
	47	0	26	40
	48	0	28	80
	49	0	12	00
	50	0	14	40
	52	0	08	80
	749	0	45	60
	756	0	26	80
	5	0	08	00
	141	0	31	12
	76	0	10	88
	206	0	09	00
	276	0	10	20
	320	0	18	60
	408	0	27	60
	Cart track	0	06	00
	687	0	37	20
	719	0	33	60
	718	0	27	00
	723	0	19	80
	712	0	06	60

[No. O-14016/516/85-GP]

का.आ. 4505—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्-द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिये ।

राज्य : -गुजरात : जिला : -बरोडा तालुका : करजण

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेअर	एआरई	सेन्टीअर
कोठाय	50	0	14	00
	55	0	04	80

[सं. O-14016/517/85-जी.पी.]

S.O. 4505.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Baroda Taluka : Karjan

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Kothav	50	0	14	00
	55	0	04	80

[No. O-14016/517/85-G.P.]

का. आ. 4506—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिजे पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिये ।

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : झगडीया

गांव	ब्लौक नं०	हैक्टेयर	एआरआई	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
कराड	389	0	39	00
	388	0	61	50
	387	0	37	50
	366/पी	0	04	20
	कार्ट ट्रेक	0	30	00
	382	0	20	40
	381	0	20	40
	374	0	18	60
	कार्ट ट्रेक	0	06	00
	375	0	18	00
	372	0	21	00
	371	0	07	50
	31	0	14	50
	36	0	05	00
	35	0	26	20
	42	0	26	10
	कोटर	0	07	50
	277	0	15	00
	276	0	21	90
	275	0	12	60
	273	0	12	60
	274	0	09	60
	कोटर	0	04	50
	58	0	24	00
	57	0	05	60
	60	0	00	62
	61	0	74	35
	62	0	02	75
	71	0	16	50
	72	0	12	00
	73	0	09	00
	74	0	07	50
	कोटर	0	20	00
	193	0	22	50
	174	0	02	75

1	2	3	4	5
	192	0	11	30
	191	0	15	00
	175	0	33	00
	168	0	36	00
	178	0	27	00
	177/ए	0	07	50
	406	0	32	10
	158/बी	0	02	00
	159	0	28	50
	405	0	01	00
	160	0	13	50
	161	0	31	50
	162	0	05	40
	कार्ट ट्रेक	0	03	60
	146	0	24	00
	145	0	27	00

[सं. O-14016/518/85-जी०पी०]

S.O. 4506.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Zaghadia

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Karad	389	0	39	00
	388	0	61	50
	387	0	37	50
	366/P	0	04	20
	Cart track	0	30	00
	382	0	20	40
	381	0	20	40
	374	0	18	60
	Cart track	0	06	00
	375	0	18	00
	372	0	21	00
	371	0	07	50
	31	0	14	50
	36	0	05	00
	35		26	20
	42	0	26	10
	Kotar	0	7	50
	277	0	15	00
	276	0	21	90
	275	0	12	60
	273	0	12	60
	274	0	09	60
	Kotar	0	04	50
	58	0	24	00
	57	0	05	60
	60	0	00	62
	61	0	74	35
	62	0	02	75
	71	0	16	50
	72	0	12	00
	73	0	09	00
	74	0	07	50
	Kotar	0	20	00
	193	0	22	50
	174	0	02	75
	192	0	11	30
	191	0	15	00
	175	0	33	00
	168	0	36	00
	178	0	27	00
	177/A	0	07	50
	406	0	32	10
	158/B	0	02	00
	159	0	28	50
	405	0	01	00
	160	0	13	50
	161	0	31	50
	162	0	05	40
	Cart track	0	03	60
	146	0	24	00
	145	0	27	00

[No. O-14016/518/85-G.P.]

का. आ. 4507.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्पाबद्ध घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिये।

राज्य—गुजरात जिला—वडोदरा तालुक—करजण

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	आरे	सेंटीआर
1	2	3	4	5
	कोटार	0	09	60
देरोली	149	0	15	90
	141/5	0	05	40
	148/1	0	13	60
	148/2	0	06	60
	141/9	0	20	80
	147	0	03	60
	141/2	0	05	00
	141/7	0	38	80
	141/3	0	42	80
	140	0	50	00
	156	0	04	40
	157	0	01	60
	159/1	0	03	52
	159/2	0	03	20
	159/3	0	01	44
	150	0	27	00
	152	0	22	32
	153	0	23	28
	154/1	0	08	88
	175	0	34	80
	176	0	34	00
	174	0	02	40
	कार्ट ट्रैक	0	03	60

[सं० O-14016/519/85-जीपी]

S.O. 4507.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodar Taluka : Karjan

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Deroli	Kotar	0	09	60
	149	0	15	90
	141/5	0	05	40
	148/1	0	13	60
	148/2	0	06	60
	141/9	0	20	80
	147	0	03	60
	141/2	0	05	00
	141/7	0	38	80
	141/3	0	42	80
	140	0	50	00
	156	0	04	40
	157	0	01	60
	159/1	0	03	52
	159/2	0	03	20
	159/3	0	01	44
	150	0	27	00
	152	0	22	32

1	2	3	4	5
	153	0	23	28
	154/1	0	08	88
	175	0	34	80
	176	0	34	00
	174	0	02	40
	Cart Track	00	03	60

[No. O-14016/519/85-G.P.]

का. आ. 4508.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा—बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेटोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 की 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बडोदरा को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य—गुजरात जिला—बड़ोदरा तालुका—करजण

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	आरे	सेंटीआर
1	2	3	4	5
मेथी	कार्ट ट्रेफ	0	16	80
	164	0	17	92
	165	0	17	80
	166	0	07	20
	170	0	24	00
	171	0	05	28
	229	0	30	00
	फन्स	0	10	80
	231	0	54	00
	236	0	00	85
	237	0	32	40
	238	0	04	48
	239	0	37	60
	225	0	02	40
	264	0	07	20
	265	0	41	40
	266	0	05	76
	272	0	09	00
	271	0	16	80
	273	0	30	00
	294	0	18	75
	293	0	44	27
	292	0	04	48
	311	0	30	80
	312	0	05	20
	कार्ट ट्रेक	0	02	40
	328	0	14	00
	329	0	00	40
	327	0	49	20
	कार्ट ट्रेक	0	08	40
	343	0	40	72
	361	0	02	88
	344	0	00	80
	355	0	46	08
	359	0	01	92
	358	0	14	00
	369/ए	0	12	00
	375	0	08	40
	374	0	07	50
	373	0	07	00
	372	0	01	40
	371	0	07	20
	370	0	16	80
	387	0	05	60
	386	0	37	20
	385	0	11	20
	कार्ट ट्रेक	0	04	80
	385/पी	0	06	60

[सं० O-14016/520/85-जी पी]

S.O. 4508.—Whreas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

Schedule

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Baroda Taluka : Karjan

Village	Block No.	Hectare	Area	Centiare
1	2	3	4	5
Methi	Cart track	0	16	80
	164	0	17	92
	165	0	30	80
	166	0	07	20
	170	0	24	00
	171	0	05	28
	229	0	30	00
	Kans	0	10	80
	231	0	54	00
	236	0	00	85
	237	0	32	40
	238	0	04	48
	239	0	37	60
	225	0	02	40
	264	0	07	20
	265	0	41	40
	266	0	05	76
	272	0	09	00
	271	0	16	80
	273	0	20	00
	294	0	18	75
	293	0	44	27
	292	0	04	48
	311	0	30	80
	312	0	05	20
	Cart track	0	02	40
	328	0	14	00
	329	0	00	40
	327	0	49	20
	Cart track	0	08	40
	343	0	40	72
	361	0	02	88
	344	0	00	80
	355	0	46	08
	359	0	01	92
	358	0	14	00
	369/A	0	12	00
	375	0	08	40
	374	0	07	50
	373	0	07	00
	372	0	01	40
	371	0	07	20
	370	0	16	80
	387	0	05	60
	386	0	37	20
	385	0	11	20
	Cart track	0	04	80
	385/P	0	06	60

[No. O-14016/520/85-G.P.]

का. आ. 4509.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य—गुजरात जिला—भरुच तालुका—अंकलेश्वर

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेंटीयर
भादी	219	0	48	00
	201	0	48	00

[सं. O-14016/521/85-जी पी]

S.O. 4509.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

Schedule

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch

Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hec-tare	Area	Cen-tiare
Bhadi	219	0	48	00
	201	0	48	00

[No. O-14016/521/85-G.P.]

का. आ. 4510.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को उस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य—गुजरात जिला—वडोदरा तालुका—कारजन

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेंटीयर
हीरजीपुर	84	0	28	80
	89	0	34	20
	26	0	25	04
	22	0	10	00
	25/2	0	18	00
	24/2	0	15	60
	128/1	0	24	00

[सं. O-140146/522/85-जीपी]

S.O. 4510.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, 390 009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

Schedule

Pipeline from Hajira - Bareilly Jagdishpur
State : Gujarat District : Vadodara Taluka: Karjan

Village	Survey No.	Hectare	Area	Centiare
Hi jipur	84	0	28	80
	89	0	34	20
	26	0	25	04
	22	0	10	00
	25/2	0	18	00
	24/2	0	15	60
	128/1	0	24	00

[No. O-14016/522/85-.G.P.]

का. आ. 4511.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होत है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्‌पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग क अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भुमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्‌द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर

राज्य—गुजरात जिला—भरुच तालुका—झगड़ीया

गाव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेंटीयर
1	2	3	4	5
दंदड़ा	258	0	15	00
	Kotar	0	03	00
	186	0	69	50
	185	0	05	50
	कार्ट ट्रेक	0	04	50
	188/ग	0	00	50
	187	0	30	00
	कार्ट ट्रेक	0	03	00
	179	0	16	50
	178	0	22	50
	180	0	09	00
	177	0	28	50
	176	0	46	50
	174	0	78	00
	173	0	07	50
	170	0	33	00
	171	0	00	50
	164	0	60	00
	कार्ट ट्रेक	0	06	00
	155	0	00	50
	138	0	36	00
	137	0	37	50
	136	0	18	00
	139/बी	0	19	50
	131/बी	0	06	00
	131/ग	0	90	00
	126	0	48	00

[सं. O-14016/523/85-जीपी]

एम. एस. श्रीनिवासन, उप सचिव

S.O. 4511.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, 390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

Schedule

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch
Taluka : Baghadiyai

Village	Survey No.	Hectare	Area	Centiare
1	2	3	4	5
Dadheda	258	0	15	00
	Kotar	0	03	00
	186	0	69	50
	185	0	05	50
	Cart track	0	04	50
	188/A	0	00	50
	187	0	30	00
	Cart track	0	03	00
	179	0	16	50
	178	0	22	50
	180	0	09	00
	177	0	28	50
	176	0	46	50
	174	0	78	00
	173	0	07	50
	170	0	33	00
	171	0	00	50
	164	0	60	00
	Cart track	0	06	00
	155	0	00	50
	138	0	36	00
	137	0	37	50
	136	0	18	00
	139/B	0	19	50
	131/B	0	06	00
	131/A	0	90	00
	126	0	48	00

[No. O-14016/523/85-G.P.]

M. S. SRINIVASAN, Dy. Secy.

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1985

का.आ. 4512.—राजनयिक एवं कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41 वां) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुपालन में केन्द्र सरकार, इसके द्वारा बहरैन स्थित भारत के राजदूतावास में सहायक श्री राम रक्खा शर्मा को 6-8-85 से कौंसल एजेन्ट के कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[संख्या टी 4330/1/85]

के० जे० एस० सोधी, अवर सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 26th August, 1985

S.O.4512.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise Shri Ram Rakha Sharma, Assistant in the Embassy of India, Bahrain to perform the duties of Consular Agent with effect from 6th August, 1985.

[No. T. 4330/1/85]

K. J. S. SODHI, Under Secy.

इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1985

का.आ. 4513.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के भूतपूर्व ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग की अधिसूचना सं० का.आ. 3557 तारीख 22 सितम्बर, 1982 द्वारा जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 9 अक्तूबर, 1982 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 513.962 हैक्टर (लगभग) या 1270.00 एकड़ (लगभग) भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के इस्पात खान और कोयला मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 881 तारीख 15 फरवरी, 1985 द्वारा 9 अक्तूबर, 1984 से आरंभ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट किया था जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि का या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दे सकती है,

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला अभिप्राप्य है ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है :—

(क) इससे उपाबद्ध अनुसूची "क" में वर्णित भूमि जिसका माप 81.687 हैक्टर (लगभग) या 201.85 एकड़ (लगभग) है;

(ख) इससे उपाबद्ध "ख" में वर्णित भूमि जो 413.634 हैक्टर (लगभग) या 1022.09 एकड़ (लगभग) है, में खनिजों के खनन, उत्खनन, शेधन खोदने और खोजने और उन्हें प्राप्त करने, खुदाई करने और ले जाने के अधिकार ।

टिप्पण : 1. इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं० सं.-1-(ई)/iii/मा आर 276-284 तारीख 11 फरवरी, 1984 का निरीक्षण कलक्टर, शहडोल (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1 काउंसिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता के कार्यालय में या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (राजस्व अनुभाग) कोयला एस्टेट, सिविल लाइंस, नागपुर-440001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

टिप्पण : 2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबन्धों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिनमें निम्नलिखित उपबंध है :

अर्जन के प्रति आक्षेप :

"8(1) किसी ऐसी भूमि में, जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, अधिसूचना जारी किए

जाने के तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आक्षेप कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के अधीनगत किसी व्यक्ति की ओर से यह कहना आक्षेप नहीं माना जाएगा कि वह स्वयं उस भूमि में कोयला उत्पादन के लिए खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं की जानी चाहिए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई है, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आक्षेपों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्रवाई के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उस व्यक्ति को भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों को इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिया जाता है ।"

टिप्पण : 3 केन्द्रीय सरकार ने, कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है ।

अनुसूची "क"

बिजुरी विस्तारण ब्लाक

सागरा खंड कोयला क्षेत्र

जिला शहडोल (मध्य प्रदेश)

सभी अधिकार

क्रम सं.	ग्राम	पटवारी सर्किल सं	व्यवस्थापन सं	तहसील और जिला	क्षेत्र एकड़ में	टिप्पणियां
1	लोहसारा	21	929	कोतमा और शहडोल	201.85	भाग

कुल क्षेत्र : 201.85 एकड़ (लगभग)

या 81.687 हैक्टर

(लगभग)

ग्राम लोहसारा में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं.

5 भाग, 6 से 8, 9 भाग, 10 से 22, 23 भाग, 24, 25 भाग, 26 भाग, 27 भाग, 28 भाग, 46 भाग, 47 भाग, 48 से 65, 66 भाग 67 भाग 68 भाग, 70 भाग, 77 भाग, 78 भाग, 79 भाग, 80 भाग, 81 भाग, 82 से 85, 86 भाग, 312 भाग, 313 भाग 314 से 326, 327 भाग, 615 भाग, 621 भाग, 622 भाग, 624 भाग, 627 भाग, 628 से 631, 632 भाग, 633 से 641 642 भाग, 643, 644, 645 भाग, 646 से 685, 686 भाग, 687 भाग, 688 से 704, 705 भाग, 706 से 739, 740 भाग, 792 भाग, 793 भाग, 794 भाग, 797 भाग, 821 भाग, 822 भाग, 823 से 837, 838 भाग, 841 भाग, 842 से 845 842 भाग, 847, 848 भाग, 849 भाग, 850 भाग, 851 से 859, 860 भाग, 861 से 874, 875 भाग, 876 से 882, 883 भाग, 884 भाग, 885, 886, 887 भाग, 888, 889 भाग, 891 भाग, 892, 893 भाग, 894, 895, 896 भाग, 897 भाग, 900 भाग, 901 भाग, 927 भाग, 928 से 956, 957 भाग, 958, 959 भाग 960 भाग, 962 भाग, 963 964, 965 भाग, 966 भाग, 967 भाग, 969 भाग, 970 भाग, 971 भाग, 973 भाग, 974 भाग, 975 भाग, 976 भाग, 987 भाग, 988 भाग, 989 भाग, 990 से 994, 995 भाग, 996 से 1017, 1018 भाग, 1019 भाग, 1023 भाग, 1024 भाग, 1025 भाग, 1026 भाग, 1027 भाग, 1030 भाग, 1048 भाग, 1083, 1086, 1096, 1097, 1099 और 1100 भाग ।

सीमा वर्णन :

क–ख रेखा बिन्दु "क" से आरम्भ होती है और सोमना और लोहसारा ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है ।

ख–ग रेखा, लोहसारा ग्राम के प्लाट सं० 710, 792, 705, 793, 794, 707 में से होकर जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है ।

ग–घ रेखा लोहसारा ग्राम के प्लाट सं० 687, 686, 822, 821, 838, 841 846, 848, 849 850, 860, 861, 957, 959, 960, 962, 965, 966, 967, 969, 970, 971 995, 973, 974, 989, 975, 976 में से होकर जाती है और प्लाट सं० 1099 में बिन्दु "घ" पर मिलती है ।

घ–ङ रेखा, लोहसारा ग्राम के प्लाट सं० 1098, 987, 988 में से होकर जाती है और लोहसारा और कोरजा ग्रामों की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु "ङ" पर मिलती है ।

ङ–च रेखा, लोहसारा और कोरजा ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "च" पर मिलती है ।

च–छ रेखा, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन अर्जित क्षेत्र की दक्षिणी सीमा के साथ साथ जाती है देखिए अधिसूचना का. आ. सं० 2978 तारीख 17 दिसम्बर, 1962 और लोहसारा ग्राम के प्लाट सं. 988 में बिन्दु "छ" पर मिलती है ।

छ–ज–झ रेखा, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन अर्जित क्षेत्र की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ लोहसारा ग्राम में से होकर जाती है देखिए अधिसूचना का.आ. सं० 2978 तारीख 17 दिसम्बर, 1962 और बिन्दु "क" पर मिलती है ।

झ–क रेखा, लोहसारा ग्राम के प्लाट सं० 28, 23, 5, 9, में से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

अनुसूची "ख"

बिजुरी विस्तारण ब्लाक

सोहागपुर कोयला क्षेत्र

जिला शहडोल (मध्य प्रदेश)

खनन अधिकार

क्र. सं. ग्राम	पटवारी सर्किल सं.	बंदोबस्त सं.	तहसील और जिला	क्षेत्र एकड़ में	टिप्पणियां
1. कोरजा	20	126	कोतमा और शहडोल	110.00	भाग
2. पडरीपानी	20	584	यथोक्त	65.72	भाग
3. बिजुरी	20	734	यथोक्त	357.75	भाग
4. दलदल	20	428	यथोक्त	486.52	भाग
5. मटुवारी उपनाम मटुवारी खुर्द	20	845	यथोक्त	2.10	भाग

कुल क्षेत्र 1022.09 एकड़

(लगभग)

या 413.634 हैक्टर (लगभग)

ग्राम कोरजा में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं.

63 भाग, 64 भाग, 65 भाग, 66 से 77, 78 भाग, 79 भाग, 80 भाग, 103 भाग, 105 भाग, 106, 107 भाग, 108 भाग और 253 भाग।

ग्राम पडरीपानी में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं. :

1/2, 2/2, 3/1, 4 से 10, 11 भाग, 12 से 33, 34 भाग, 41 भाग, भाग, 42 भाग, 43 से 55, 56 भाग, 57 भाग, 58, 59 भाग, 60 भाग 75 भाग, 77 भाग, 78 से 83, 84/1 भाग, 85 से 88, 89 भाग, 90 भाग, 96 भाग, 117 भाग, 118 भाग, 119 भाग, 120 भाग, 121 से 129, 130 भाग, 131 भाग, 133 भाग, 178, 179 और 183।

ग्राम बिजुरी में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं.

142 भाग, 143 भाग, 145/1, 145/2, 904, 899, 146 भाग, 147 से 152, 153 भाग, 155 भाग, 156 भाग, 180 भाग, 184/1 185 से 189, 190 भाग, 191/1, 192/1, 193 से 200, 201 भाग, 202 भाग, 204 भाग, 205 से 294, 295/1 296/1, 298 से 346, 347 भाग, 348, 380 भाग, 381/1, 385/1, 386/1, 387 से 397, 398/1, 399/1, 400 से 436, 437/1, 438/1, 439 भाग, 440, 441 भाग, 442 भाग, 477 भाग, 531/1, 532 भाग, 533/1, 534, 535 भाग, 536 भाग, 538 भाग, 539/1, 539/3 540/1, 541 से 541, 545 भाग, 546 से 618, 619/1, 620/1, 621 से 657, 658/1, 661 से 880, 881 भाग, 886 से 989 और 901,

ग्राम दलदल में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं.

3 भाग, 4, 5 भाग, 6, 7 भाग, 8 से 89, 90 भाग, 91, 92 भाग 93, 94, 95 भाग, 96 भाग, 109 भाग, 110 भाग, 190 भाग, 213 भाग, 223 भाग, 235 भाग, 236 भाग, 237, 238 भाग, 239 भाग 240 भाग, 241 से 243 और 244 भाग।

ग्राम मटुवारी उपनाम मटुवारी खुर्द में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं.

659/8 भाग

सीमा वर्णन :

क—च रेखा, कोरजा ग्राम के प्लाट सं० 63, 64, 65, 80, 79 78, 103, 105, 107, 108, में से होकर जाती है और बिन्दु "च" मिलती है।

च-छ रेखा, कोरजा ग्राम के प्लाट सं० 108, 253 में से होकर जाती है फिर पडरीपानी ग्राम के प्लाट सं० 84/1, 89, 90, 96, 77, 60, 59, 57, 56, 42, 41, में से होकर जाती है और प्लाट सं० 11 में बिन्दु "छ" पर मिलती है।

छ-ज रेखा, प्लाट सं. 32 की दक्षिण सीमा के साथ-साथ पडरीपानी ग्राम के प्लाट सं० 11 में से होकर जाती है, फिर प्लाट सं. 34, 118, 117, 119, 120, 131, 130, 133 में से होकर जाती है, फिर बिजुरी ग्राम के प्लाट सं. 881 में से होकर जाती है और फिर दलदल ग्राम के प्लाट सं० 110, 190, 109, 90, 213, 92, 95, 96 में से होकर जाती है, रेल लाइन पार करती है और प्लाट सं. 236, 235, 238, 239, 240, 244 से होकर जाती है और बिन्दु "ज" पर मिलती है।

ज—झ रेखा, दलदल ग्राम के प्लाट सं. 244 में से होकर जाती है और बिन्दु "झ" पर मिलती है।

झ—ञ रेखा, दलदल ग्राम के प्लाट सं. 244, 7, 3, 5 में से होकर जाती है और फिर बिजुरी ग्राम के प्लाट सं० 204, 201 में से जाती है और बिन्दु "ञ" पर मिलती है।

ञ-ट रेखा, बिजुरी ग्राम के प्लाट सं. 202 में होकर जाती है फिर मटुवारी ग्राम से होकर जाती है और प्लाट सं. 659/8 में बिन्दु "ट" पर मिलती है।

ट-ठ-ड रेखा, मटुवारी ग्राम के प्लाट सं. 659/8 में से होकर जाती है और बिन्दु "ड" पर मिलती है।

ड-ढ-ण-त-थ रेखा, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन अर्जित क्षेत्र की पूर्वी सीमा के साथ-साथ मटुवारी, बिजुरी और पडरीपानी ग्रामों में जाती है देखिए अधिसूचना का.आ. सं. 2978 तारीख 17 सितम्बर, 1962 और पडरीपानी ग्राम में बिन्दु "थ" पर मिलती है।

थ-द-क रेखा, लोहसारा और कोरजा ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ साथ जाती है और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[सं. 43015/17/85-सी.ए.]

डा. सी. एच. श्री निवासन, निदेशक

MINISTRY OF STEEL, MINES AND COAL

(Department of Coal)

New Delhi, the 9th September, 1985

S.O. 4513.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Energy, Department of Coal S.O. 3557 dated the 22nd September, 1982 under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) and published in the Gazette of India in Part-II, Section 3, sub-section (ii) dated the 9th October, 1982, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 513.962 hectares (approximately) or 1270.00 acres (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of Coal) No. S.O. 884 dated 15th February, 1985 under sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Governmet specified a further period of one year commencing from the 9th October 1984 as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said land;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire :

(a) the lands measuring 81.687 hectares (approximately) or 201.85 acres (approximately) described in Schedule 'A' appended hereto;

(b) the rights to mine, quarry, bore, dig, and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 413.634 hectares (approximately) or 1022.09 acres (approximately) described in Schedule 'B' appended hereto.

Note-1: the plan bearing No. C-1(E)/III/CR/276-284 dated 11th February, 1984 of the area covered by this notification may be inspection in the Office of the Collector, Shahdol (Madhya Pradesh) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the Western Coalfields Limited (Revenue Section), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001 (Maharashtra).

Note-2: Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the aforesaid Act which provide as follows :

Objection to Aquisition : 8(1)—Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation:—It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the Competent Authority in writing and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, *after hearing all such objections and after making such* further enquiry, if any, as he thinks necessary, either makes a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land or make *different* reports *in respect of different parcels* of such land or of rights in or over such land to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceeding held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act."

Note 3:—The Coal Controller 1, Council House Street Calcutta has been appointed by the Central Government as the Competent Authority under the Act.

SCHEDULE 'A'

BIJURI EXTENSION BLOCK
JHAGRAKHAND COALFIELD
DISTRICT SHAHDOL (MADHYA PRADESH)

ALL RIGHTS

Sr. No.	Village	Patwari circle number	Settlement number	Tehsil & District	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lohsara	21	929	Kotma & Shahdol (कोतमा व शहडोल)	201.85	Part
				Total Area :	201.85 acres (approximately)	
				or	81.687 hectares (approximately)	

Plot numbers to be acquired in village Lohsara :

5 Part, 6 to 8, 9 Part 10 to 22, 23 Part 24 25, Part 26, Part, 27 Part, 28 Part, 46 Part, 47 Part 48 to 65, 66 Part, 67 Part, 68 Part, 70 Part, 77 Part, 78 part 79 Part, 80 Part, 81 Part, 82 to 85, 86 Part, 312 Part, 313 Part, 314 to 326 327 Part, 615 Part, 621 Part, 622 Part, 624 Part, 627 Part, 628 to 631, 632 Part, 633 to 641, 642 Part, 643, 644, 645 Part, 646 to 685, 686 Part, 687 Part, 688 to 704, 705 Part, 706 to 739, 740 Part, 792 Part, 793 Part, 794 Part, 797 Part, 821, 822 Part, 823 to 837, 838 Part, 841 Part, 842 to 845, 846 Part, 847, 848 Part, 849 Part, 850 Part, 851 to 859, 860 Part, 861 to 874, 875 Part, 876 to 882, 883 Part, 884 Part, 885, 886 887 Part, 888, 889 Part, 891 Part, 892, 893 Part 894 895, 896 Part, 897 Part, 900 Part, 901 Part, 927 Part 928 to 956, 957 Part, 958, 959 Part, 960 Part, 962 Part, 963, 964, 965 Part, 966 Part, 967 Part, 969 Part, 970 Part, 971 Part, 973 Part, 974 Part, 975 Part, 976 Part, 987 Part, 988 Part, 989 Part, 990 to 994, 995 Part, 996 to 1017, 1018 Part, 1019 Part, 1023 Part, 1024 Part, 1025

Part, 1026. Part, 1027 Part, 1030 Part, 1048 Part, 1083, 1086, 1096, 1097, 1099 and 1100 Part

Boundary description :

A—B : Line starts from point 'A' and passes along the common boundary of villages Somna and Lohsara and meets at point 'B'.

B—C : Line proceeds through village Lohsara in plot numbers 740, 792, 705, 793, 794, 797 and meets at point 'C'.

C—D : Line passes through village Lohsara in plot numbers 687, 686, 822, 821, 838, 841, 846, 848, 849, 850, 860, 861, 957, 959, 960, 962, 965, 966, 967, 969, 970, 971, 995, 973, 974, 989, 975, 976 and meets in plot number 1099 at point 'D'.

D—E : Line passes through village Lohsara in plot numbers 1099, 987, 988 and meets at the common boundary of villages Lohsara and Korja at point 'E'.

E—R : Line passes along the common village boundary of Lohsara and Korja and meets at point 'R'.

R—S : Line passes along the southern boundary of the area acquired under Section 9(1) of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act 1957 vide notification S.O. No. 2978 dated 17th September 1962 and meets in plot No. 988 of village Lohsara at point 'S'.

S–T–U : Line passes through village Lohsara along the western boundary of the area acquired under Section 9(1) of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 vide notification S. N. No. 2978 dated 17th September 1962 and meets at point 'U.'

U—A : Line passes through village Lohsara in plot number 28, 23, 5, 9 and meets at the starting point 'A'.

SCHEDULE 'B'

BIJURI EXTENSION BLOCK

JHAGRAKHAND COALFIELD

DISTRICT SHAHDOL (MADHYA PRADESH)

MINING RIGHTS

Sr. No.	Village	Patwari circle number	Settlement number	Tahsil & District	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Korja (कोरजा)	20	126	Kotma & Shahdol (कोतमा व शहडोल)	111.00	Part
2.	Padripani (पाड़रीपानी)	20	584	Kotma & Shahdol	65.72	Part
3.	Bijuri (बिजुरी)	20	734	Kotma & Shahdol	357.75	Part
4.	Daldal (दलदल)	20	428	Kotma & Shahdol	486.52	Part
5.	Mahuwari Alias Mahuwar Khurd (महुवारी उपनाम महुवर खुर्द)	20	645	Kotma & Shahdol	2.10	Part

Total Area: 1022.09 acres (approximately)
or
413.634 hectares (approximately)

Plot numbers to be acquired in village Korja :

63 Part, 64 Part, 65 Part, 66 to 77, 78 Part, 79 Part, 80 Part, 102 Part, 105 Part, 106, 107 Part, 108 Part and 253 Part.

Plot numbers to be acquired in village Padripani :

1/2, 2/2, 3/1, 4 to 10, 11 Part, 12 to 33, 34 Part, 41 Part, 42 Part, 43 to 55, 56 Part, 57 Part, 58, 59 Part, 60 Part, 75 Part, 77 Part, 78 to 83, 84/1, Part, 85 to 88, 89 Part, 90 Part, 96 Part, 117 Part, 118 Part, 119 Part, 120 Part, 121 to 129, 130 Part, 131 Part, 133 Part, 178, 179 and 183.

Plot numbers to be acquired in village Bijuri :

142 Part, 143 Part, 145/1, 145/2, 904, 899, 146 Part, 147 to 152, 153 Part, 155 Part, 156 Part, 180 Part, 184/1, 185 to 189, 190 Part, 191/1, 192/1, 193 to 200, 201 Part, 202 Part, 204 Part, 205 to 294, 295/1, 296/1 298 to 346, 347 Part, 348, 380 Part, 381 1, 385/1, 386/1, 387 to 397, 398/1, 399/1, 400 to 436, 437/1, 438 1, 439 Part, 440, 441 Part, 442 Part, 447 Part, 531/1, 532 Part, 533/1, 534, 535 Part, 536 Part, 538 Part, 539/1, 539/3, 540/1, 541 to 544, 545 Part, 546 to 618, 619/1, 620/1, 621 to 657, 658/1, 661 to 880, 881, Part, 886 to 898 and 901.

Plot numbers to be acquired in village Daldal :

3 Part, 4, 5 Part, 6, 7 Part, 8 to 89, 90 Part, 91, 92 Part, 93, 94, 95 Part, 96 Part, 109 Part, 110 Part, 190 Part, 213 Part, 223 Part, 235 Part, 236 Part, 237, 238 Part, 239 Part, 240 Part, 241 to 243 and 244 Part.

Plot numbers to be acquired in village Mahuwari alias Mahuwar Khurd :

659/8 Part.

Boundary description :

E—F : Line passes through village Korja in plot numbers 63, 64, 65, 80, 79, 78, 103, 105, 107, 108 and meets at point 'F'.

F—G : Line passes through village Korja in plot numbers 108, 253, then proceeds through village Padripani in plot numbers 84/1, 89, 90, 96, 97, 77, 75, 60, 59, 57, 56, 42, 41 and meets inplot number 11 at point 'G'.

G—H : Line proceeds through village Padripani in plot number 11 along the suthern boundary of plot number 32, then through plot numbers 34, 118, 117, 119, 120,

131, 130, 133 then proceeds through village Bijuri in plot number 881 and then proceeds through village Daldal in plot numbers 110, 190, 109, 90, 213, 92, 95, 96, crosses railway line, 236, 235, 238, 239, 240, 244 and meets at point 'H'.

H—I : Line passes through village Daldal in plot number 244 and meets at point 'I'.

I—J : Line passes through village Daldal in plot numbers 244, 7, 3, 5, then proceeds through village Bijuri in plot numbers 204, 201 and meets at point 'J'.

J—K : Line passes through village Bijuri in plot number 202, then proceeds through village Mahuwari and meets in plot number 659//8 at point 'K'.

K—L—M : Line passes through village Mahuwari in plot number 659/8 and meets at point 'M'.

M—N—O—P—Q Line passes in villages Mahuwari, Bijuri and Padripani along the eastern boundary of the area acquired under section 9(1) of the Coal Boaring Areas (Acquisition and Dovelopment) Act 1957 vide notification S.O. No. 2978 dated 17 September, 1962 and meets in village Padrinpani at point 'Q'.

Q—R—E : Line passes along the common boundary of villages Lohsara and Korja and meets at the starting point 'E'.

[No. 43015/17/85-CA]
T. C. A. SRINIVASAN, Director.

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 21 जून, 1985

का. आ. 4514.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955, के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम/एल-0370639, जिसके ब्योरे नीचे अनुसूची में दिये गये हैं, 85-02-01 से लाइसेंसधारी की प्रार्थना पर रद्द कर दिया गया है, और वापस ले लिया माना जाए।

अनुसूची

क्र. सं.	लाइसेंस संख्या और दिनांक	लाइसेंस धारी का नाम और पता	रद्द लाइसेंस अधीन वस्तु/प्रक्रिया	सम्बद्ध भारतीय मानक
1	2	3	4	5
1.	सी एम/एल-0370639 1974-02-06	मैसर्ज बंगलोर वायर रोड मिल, (ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन आफ इंडिया प्रा. लि., की इकाई) महादेवपुर डाकघर वाइटफील्ड रोड, बंगलोर-560048	संरचना इस्पात (मानक किस्म)	IS: 226-1975 संरचना इस्पात (मानक किस्म) की विशिष्टि (पांचवा पुनरीक्षण)

[सी एम डी/55 : 0370639]

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 21st June, 1985

S.O. 4514.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-0370639 particulars of which are given in the Schedule below has been cancelled with effect from 85-02-01 as the firm does not want to operate the licence.

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and date	Name & Address of the Licencee	Article/Process Covered by the licence cancelled	Relevent Indian Standards
1	2	3	4	5
1.	CM/L-0370639 1974-02-06	M/s Bangalore Wire Rod Mill, (A Unit of Transport Corporation of India Private Limited), Mahadevapur P.O., Whitefield Road, Bangalore-560048.	Structural Steel (Standard Quality)	IS:226-1975 Specification for structural steel (Standard quality) (fifth revision).

[CMD/55 : 0370639]

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1985

का. आ. 4515.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम/एल–0208327 जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिये गये हैं 1985–02–01 से रद्द कर दिया गया है और वापस ले लिया जाए ।

अनुसूची

क्रम सं.	लाइसेंस संख्या और दिनांक	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द लाइसेंस अधीन वस्तु/प्रक्रिया	सम्बद्ध भारतीय मानक
1	2	3	4	5
1.	सी एम/एल–0208327 69–09–30	मैसर्स इंडस्ट्रियल मिनरल्स एण्ड केमिकल्स कं. प्रा. लि., कुर्ला मारोल रोड चकला अंधेरी, बंबई–58 कार्यालय : 125, नारायण धुरू स्ट्रीट, नागदेवी, बंबई–3	बी एच सी ई सी	IS: 632–1978 गामा–बी एच सी (लिंडेन) पायसनीय सांद्र की विशिष्टि (चौथा पुनरीक्षण)

[सी एम डी/55 : 0208327]

New Delhi, the 21st August, 1985

S.O. 4515.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulation 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that licence No. CM/L-0208327 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 1985-02-01.

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and Date	Name and Address of the licensee	Article/Process covered by the licence cancelled	Relevant Indian Standards
1	2	3	4	5
1.	CM/L-0208327 69-09-30	M/s. Industrial Minerals and Chemicals Co. Pvt. Ltd., Kurla Marol Road, Chakala, Andheri, Bombay-58. Office : 125 Narayan Dhuru Street, Nagdevi, Bombay-3.	BHC EC	IS:632–1978 Specification for Gamma-BHC (Lindane) Emulsifiable Concentrates. (Fourth Revision)

[CMD/55 : 0208327]

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1985

का० आ० 4516.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि तालों की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस अनुसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निर्धारित की गई है और यह फीस 1981–10–01 से लागू होगी।

अनुसूची

क्रम सं.	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	प्रति इकाई	मुहर लगाने की फीस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ताले 2	IS 275–1961 तालों की विशिष्टि	एक नग	पैसे

[सं. सी एम डी/13 : 10]

New Delhi, the 26th August, 1985

S.O. 4516.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby notifies that the marking fee per unit for pad locks details of which are given in the Schedule hereto annexed, has been determined and the fee shall come into force with effect from 1981-10-01 :

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking fee per unit
1	2	3	4	5
1.	Pad locks	IS:275-1961 Specification for pad locks.	One Piece	5 Paise

[No. CMD/13 : 10]

नई दिल्ली, 28 अगस्त 1985

का. आ. 4517.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि सीसा चढ़े टिन कांसे की इंगटो और ढलाइयों की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस अनुसूची में दिए गए ब्योरों के अनुसार निर्धारित की गई है और यह फीस 1984-01-01 से लागू होगी ।

अनुसूची

क्र. सं.	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	इकाई	चिन्ह लगाने की प्रति इकाई फीस
1	2	3	4	5
1.	सीसों चढ़ टिन कांसे की इगटें और ढलाईयां	IS : 318-1981 सीसा चढ़े टिन कांसे की इंगटों और ढलाईयों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	1 किग्रा	6 पैसे

[सं. सीं एम डी/13 : 10]

New Delhi, the 28th August, 1985

S.O. 4517.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby, notifies that the marking fee per unit for leaded tin bronze ingots and castings details of which are given in the Schedule hereto annexed, has been determined and the fee shall come into force with effect from 1984-01-01.

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standards	Unit	Marking fee per unit
1	2	3	4	5
1.	Leaded tin bronze ingots and castings	IS:318-1981 Specification for leaded tin bronze ingots and castings (Second Revision)	One kg	6 Paise

[No. CMD/13:10]

का. आ. 4518.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के उपनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन मानक चिह्नों के डिजाइन, शाब्दिक विवरण तथा तत्संबंधी भारतीय मानक के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दिये गये हैं वे भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम 1952 और इसके अधीन बने नियमों तथा विनियमों के निमित 84-01-01 से लागू होंगे ।

अनुसूची

क्र. सं.	मानक चिह्न का डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	मानक चिह्न की डिजाइन का शब्दिक विवरण
1	2	3	4	5
1.	IS : 318	सीसा चढ़े टिन कांसे की इंगटें और ढलाईयां	IS : 318–1984 सीसा चढ़े टिन कांसे की इंगटों और ढलाइयों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या अंकित की गई है।

[सं. सी एम डी/13 : 9]

S.O.4518.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution, hereby notifies that the Standard Mark design of which together with the verbal description of the design and the title of the relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexed, has been specified.

This Standard Mark for the puspose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1984-01-01.

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the design of the Standard Mark
1	2	3	4	5
1.	IS:318	Leaded tin bronze ingots and castings	IS:318-1981 Specification for leaded tin bronze ingots and casting (Second Revision)	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13:9]

का. आ. 4519.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 8 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन 326 लाइसेंसों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, उनका अप्रैल 1984 में नवीकरण किया गया है।

अनुसूची

क्रम संख्या	सीएम/एल संख्या	वैध तक
(1)	(2)	(3)
1.	0000707	1985 05 31
2.	0004008	1985 04 15
3.	0017116	1985 06 31
4.	00171421	1985 00 31
5.	0040214	1985 04 15
6.	0012117	1985 03 31
7.	0042218	1985 03 31
8.	0000927	1985 03 31
9.	0061929	1985 03 31
10.	0002527	1985 03 31
11.	0094388	1985 03 31
12.	0108016	1985 03 31
13.	0103111	1985 03 31
14.	0108213	1985 03 31
15	0103315	1985 03 31
16	0106622	1985 02 28
17	0115623	1985 03 31
18	0118427	1985 02 28

(1)	(2)	(3)
19	0133928	1985 05 31
20	0140824	1985 05 31
21	0166945	1985 04 15
22	0178041	1985 04 15
23	0191538	1985 03 31
24	0196043	1985 04 30
25	0207224	1985 04 15
26	0240020	1985 04 15
27	0241628	1985 05 31
28.	0246535	1985 03 31
29.	0247439	1985 03 31
30.	0259243	1985 03 15
31.	0262030	1985 03 31
32.	0288957	1985 05 15
33.	0296047	1985 03 15
34.	0298657	1985 02 15
35	0299760	1985 03 31
36.	0300416	1985 03 31
37	0302319	1985 03 31
38.	0307733	1985 04 30
39.	0312019	1985 03 31
40.	0320725	1984 12 15
41.	0324329	1985 03 31
42.	0334433	1985 03 31
43.	0335435	1985 05 15
44.	0335738	1985 03 15
45.	0336336	1985 03 15
46.	0338037	1985 04 15
47.	0338138	1985 04 15
48.	0340428	1985 04 30
49.	0340630	1985 03 31
50.	0349446	1985 05 31
51.	0359146	1985 03 31
52.	0359853	1985 04 15
53.	0360333	1985 04 15
54.	0363945	1985 03 31
55.	0376247	1985 03 31
56.	0377853	1985 03 31
57.	0377956	1985 03 31
58.	0380945	1985 04 30
59.	0382242	1985 04 30
60.	0394855	1985 03 31
61.	0423634	1985 02 28
62.	0430025	1985 04 15
63.	0433839	1985 04 30
64.	0470643	1984 09 30
65.	0478356	1984 12 15
66.	0478861	1985 04 30
67.	0479863	1984 04 15
68.	0486456	1985 03 31
69.	0488258	1985 03 15
70.	0494253	1985 03 15
71.	0494354	1985 05 15
72.	0494455	1985 03 15
73.	0494657	1985 04 30
74.	0496560	1985 05 15
75.	0502529	1985 02 28
76.	0505131	1985 02 28
77.	0506838	1985 03 15
78.	0506840	1985 03 15
79.	0509644	1985 04 15
80.	0509745	1985 03 31
81.	0510023	1985 04 15
82.	0510124	1985 04 15
83.	0510528	1985 03 15
84.	0512128	1985 04 30
85.	0513332	1985 04 15
86.	0549353	1985 03 31
87.	0572752	1985 02 28
88.	0580347	1985 04 15
89.	0588080	1985 02 15
90.	0592253	1985 03 15
91.	0594459	1985 03 15
92.	0600024	1985 02 28
93.	0600327	1985 03 15
94	0603131	1985 03 31
95.	0603535	1985 04 15
96.	0603939	1985 04 15
97.	0605034	1985 04 30
98.	0609345	1985 04 30
99.	0611736	1985 04 30
100.	0616039	1985 04 30
101.	0663553	1985 01 15
102.	0669565	1985 04 15
103.	0669666	1985 05 15
104.	0670752	1985 01 31
105.	0672655	1985 04 15
106	0676259	1985 02 28
107.	0678566	1985 02 28
108.	0678869	1985 02 28
109.	0685260	1985 03 15
110.	0687264	1985 03 31
111.	0689775	1985 04 15
112.	0690859	1985 04 30
113.	0690960	1985 04 30
114.	0691053	1985 04 30
115.	0692762	1985 04 15
116.	0693380	1985 04 15
117.	0693562	1985 04 15
118.	0693865	1985 04 15
119.	0694867	1985 04 15
120.	0695263	1985 04 15
121.	0697368	1985 04 15
122.	0698774	1985 04 30
123.	0699776	1985 05 15
124.	0711134	1985 04 15
125.	0711558	1985 04 15
126.	0716750	1985 03 31
127.	0752243	1984 11 15
128.	0752647	1984 11 15

(1)	(2)	(3)
129.	0736958	1985 04 15
130.	0738457	1985 04 59
131.	0740747	1985 04 30
132.	0742044	1985 04 30
133.	0742145	1985 04 30
134.	0742650	1985 04 30
135.	0746557	1985 01 15
136.	0744961	1984 11 15
137.	0747054	1984 11 15
138.	0749967	1985 01 31
139.	0750144	1985 03 15
140.	0752047	1984 11 15
141.	0752249	1985 02 28
142	0753453	1985 02 28
143.	0754758	1985 02 28
144.	0757764	1985 02 28
145.	0758968	1985 03 31
146.	0761351	1985 03 15
147.	0764862	1985 03 31
148.	0766260	1985 03 31
149.	0766664	1985 03 31
150.	0767262	1985 03 31
151.	0767868	1985 04 15
152.	0768365	1985 04 15
153.	0768567	1985 03 31
154.	0768668	1985 04 15
155.	0768769	1985 04 15
156.	0769266	1985 04 15
157.	0769569	1985 04 15
158.	0769872	1985 04 15
159.	0772457	1985 04 30
160.	0778570	1984 05 31
161.	0820341	1985 04 15
162.	0821444	1985 04 15
163.	0836962	1985 04 15
164.	0837661	1985 01 31
165.	0838057	1985 02 28
166.	0839463	1985 02 28
167.	0840549	1985 04 15
168.	0841450	1985 03 15
169.	0841753	1985 03 15
170.	0842755	1985 03 15
171.	0845761	1985 03 15
172.	0847462	1985 03 31
173.	0848060	1985 03 31
174.	0848161	1985 03 31
175.	0848363	1985 03 31
176.	0849971	1985 09 15
177.	0851150	1985 03 31
178.	0851251	1985 03 31
179.	0852556	1985 04 15
180.	0852657	1985 04 15
181.	0852859	1985 04 15
182.	0853356	1985 04 15
183.	0853457	1985 04 15
184.	0853659	1985 04 15
185.	0853760	1985 04 15
186.	0853962	1985 03 31
187.	0854358	1985 04 15
188.	0855259	1985 04 15
189.	0855764	1985 04 15
190.	0856261	1985 04 15
191.	0856362	1985 04 15
192.	0858063	1985 06 30
193.	0860656	1985 04 15
194.	0860858	1985 04 15
195.	0861961	1985 05 15
196.	0862256	1985 04 15
197.	0862862	1985 04 15
198.	0863056	1985 04 15
199.	0863258	1985 04 15
200.	0863460	1985 04 15
201.	0866365	1985 04 30
202.	0867771	1985 03 31
203	0887373	1985 03 31
204	0897780	1985 03 15
205.	0912750	1985 03 31
206.	0923048	1985 10 15
207.	0933554	1985 04 15
208.	0968485	1985 02 15
209.	0940957	1984 11 15
210.	0941959	1985 02 15
211.	0943054	1985 02 28
212.	0944662	1985 02 28
213.	0946161	1985 02 28
214.	0947870	1985 03 15
215.	0948872	1985 03 15
216.	0950657	1985 03 15
217.	0950758	1985 03 15
218	0951558	1985 03 15
219.	0951659	1985 03 15
220.	0953865	1985 03 31
221.	0954261	1985 03 31
222	0954463	1985 03 31
223.	0954665	1985 03 31
224.	0954766	1985 03 31
225.	0957267	1985 03 31
226.	0957873	1985 03 31
227	0957974	1985 03 31
228.	0959473	1985 03 31
229.	0960660	1985 04 15
230.	0961056	1985 04 15
231.	0961460	1985 04 15
232.	0961965	1985 04 15
233.	0962563	1985 04 15
234.	0962664	1985 04 30
235.	0962866	1985 04 30
236.	0963363	1985 04 30
237.	0964163	1985 04 30
238.	0971867	1985 05 31
239.	1001512	1985 03 31
240.	1006330	1984 11 15

(1)	(2)	(3)
241	1009225	1984 11 30
242.	1016626	1985 03 31
243	1027732	1985 01 31
244	1029231	1985 02 15
245.	1033424	1985 07 31
246.	1039941	1985 02 28
247.	1040118	1985 03 15
248.	1041928	1985 03 15
249.	1043528	1985 03 15
250.	1043932	1985 05 15
251.	1044025	1985 05 15
252.	1045936	1985 03 15
253.	1047334	1985 03 15
254	1048437	1985 04 15
255.	1049439	1985 02 28
256.	1051224	1985 03 15
257.	1052226	1985 03 15
258	1053935	1985 04 15
259.	1054836	1985 03 31
260	1055131	1985 03 31
261.	1055333	1985 03 31
262.	1055838	1985 03 31
263.	1058036	1985 03 31
264.	1058238	1985 03 31
265	1058541	1985 03 31
266.	1059241	1985 04 15
267.	1059442	1985 03 31
268.	1059745	1985 03 31
269	1060023	1985 03 31
270	1060124	1985 03 31
271.	1060225	1985 03 31
272.	1060127	1985 03 31
273.	1060528	1985 03 31
274.	1060730	1985 03 31
275.	1062027	1985 10 15
276.	1062633	1985 04 15
277.	1063029	1985 03 15
278.	1063231	1985 04 15
279.	1063132	1985 04 15
280.	1063635	1985 04 15
281.	1063738	1985 04 15
282.	1063938	1985 04 15
283.	1064538	1985 04 15
284.	1065235	1985 04 15
285.	1066237	1985 04 30
286.	1068140	1985 04 15
287.	1072333	1985 04 15
288.	1072535	1985 04 15
289.	1072838	1985 04 15
290.	1074741	1985 05 15
291.	1095547	1985 03 31
292.	1095749	1985 03 31
293.	1116832	1984 09 30
294.	1119454	1985 04 15
295.	1137537	1984 12 15
296.	1149059	1985 01 15
297.	1153131	1985 02 15
298.	1162334	1985 02 28
299.	1162738	1985 02 28
300.	1165239	1985 02 28
301.	1168144	1985 03 15
302.	1169348	1985 03 15
303.	1169550	1985 03 15
304.	1171133	1985 03 15
305.	1171739	1985 03 15
306.	1172640	1985 03 31
307.	1172842	1985 03 31
308.	1173341	1985 03 31
309	1174341	1985 03 31
310.	1174442	1985 03 31
311.	1174745	1985 03 31
312.	1175648	1985 03 31
313	1176044	1985 04 15
314	1176749	1985 04 15
315.	1176951	1985 04 15
316.	1177751	1985 11 30
317.	1177953	1985 04 15
318.	1178652	1985 04 15
319.	1178854	1985 04 15
320.	1179452	1985 04 30
321.	1180336	1985 04 15
322.	1180437	1985 04 15
323.	1180639	1985 04 30
324.	1181944	1985 04 30
325.	1183948	1985 05 15
326.	1195046	1985 03 15

[सं० सी०एम०डी० 13:12]
बी० एन० सिंह, अपर महानिदेशक

S. O. 4519.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that 326 licences, particulars of which are given in the following Schedule, have been renewed during the month of April 1984.

THE SCHEDULE

Sl. No.	CM/L No.	Valid Upto
1	2	3
1.	0000707	1985 03 31
2.	0004008	1985 04 15
3.	0017118	1985 03 31
4.	00171421	1985 03 31
5.	0040214	1985 04 15
6.	0042117	1985 03 31

1	2	3
7.	0042218	1985 03 31
8.	0060927	1985 03 31
9.	0061929	1985 03 31
10	0062527	1985 03 31
11.	0094338	1985 03 31
12.	0102816	1985 03 31
13.	0103111	1985 03 31
14.	0103212	1985 03 31
15.	0103313	1985 03 31
16.	0106622	1985 02 28
17.	0115623	1985 03 31
18.	0118427	1985 02 28
19.	0133928	1985 03 31
20.	0140824	1985 03 31
21.	0166943	1985 04 15
22.	0178041	1985 04 15
23.	0191538	1985 03 31
24.	0196043	1985 04 30
25.	0207224	1985 04 15
26.	0240020	1985 04 15
27.	0241628	1985 03 31
28.	0246335	1985 03 31
29.	0247539	1985 03 31
30.	0259243	1985 03 15
31.	0262030	1985 03 31
32.	0288957	1985 05 15
33.	0296047	1985 03 15
34.	0298657	1985 02 15
35.	0299760	1985 03 31
36.	0300416	1985 03 31
37.	0302319	1985 03 31
38.	0307733	1985 04 30
39.	0312019	1985 03 31
40.	0320725	1985 12 15
41.	0324329	1985 03 31
42.	0334433	1985 03 31
43.	0335435	1985 03 15
44.	0335738	1985 03 15
45.	0336336	1985 03 15
46.	0338037	1985 04 15
47.	0338138	1985 04 15
48.	0340428	1985 04 30
49.	0340630	1985 03 31
50.	0349446	1985 03 31
51.	0359146	1985 03 31
52.	0359853	1985 04 15
53.	0360333	1985 04 15
54.	0363945	1985 03 31
55.	0376247	1985 03 31
56.	0377653	1985 03 31
57.	0377956	1985 03 31
58.	0380945	1985 04 30
59.	0382242	1985 04 30
60.	0394855	1985 03 31
61.	0423634	1985 02 28
62.	0430025	1985 04 15
63.	0433839	1985 04 30
64.	0470643	1984 09 30
65.	0478356	1984 12 15
66.	0478861	1985 04 30
67.	0479863	1985 04 15
68.	0486456	1985 03 31
69.	0488258	1985 03 15
70.	0494253	1985 03 15
71.	0494354	1985 03 15
72.	0494455	1985 03 15
73.	0494657	1985 04 30
74.	0496560	1985 03 15
75.	0502529	1985 02 28
76.	0505131	1985 02 28
77.	0506638	1985 03 15
78.	0506840	1985 03 15
79.	0509644	1985 04 15
80.	0509745	1985 03 31
81.	0510023	1985 04 15
82.	0510124	1985 04 15
83.	0510528	1985 03 15
84.	0512128	1985 04 30
85.	0513332	1985 04 15
86.	0549353	1985 03 31
87.	0572752	1985 02 28
88.	0580347	1985 04 15
89.	0588060	1985 02 15
90.	0592253	1985 03 15
91.	0594459	1985 03 15
92.	0600024	1985 02 28
93.	0600327	1985 03 15
94.	0603131	1985 03 31
95.	0603535	1985 04 15
96.	0603939	1985 04 15
97.	0605034	1985 04 30
98.	0609345	1985 04 30
99.	0611736	1985 04 30
100.	0616039	1984 04 30
101.	0663553	1985 01 15
102.	0669565	1985 04 15
103.	0669666	1985 04 15
104.	0670752	1985 01 31
105.	0672655	1985 04 15
106.	0576259	1985 02 28
107.	0678566	1985 02 28
108.	0678869	1985 02 28
109.	0685260	1985 03 15
110.	0687264	1985 03 31
111.	0689773	1985 04 15
112.	0690859	1985 04 30
113.	0690960	1985 04 30
114.	0691053	1985 04 30
115.	0692762	1985 04 15
116.	0693360	1985 04 15

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
117.	0693562	1985 04 15	172.	0847462	1985 03 31
118.	0693865	1985 04 15	173.	0848060	1985 03 31
119.	0694867	1985 04 15	174.	0848161	1985 03 31
120.	0695263	1985 04 15	175.	0848363	1985 03 31
121.	0697368	1985 04 15	176.	0849971	1985 09 15
122.	0698774	1985 04 30	177.	0851150	1985 03 31
123.	0699776	1985 05 15	178.	0851251	1985 03 31
124.	0711134	1985 04 15	179.	0852556	1985 04 15
125.	0711538	1985 04 15	180.	0852657	1985 04 15
126.	0716750	1985 03 31	181.	0852859	1985 04 15
127.	0732243	1984 11 15	182.	0853356	1985 04 15
128.	0732647	1984 11 15	183.	0853457	1985 04 15
129.	0736958	1985 04 15	184.	0853659	1985 04 15
130.	0738457	1985 04 30	185.	0853760	1975 04 15
131.	0740747	1985 04 30	186.	0853962	1985 03 31
132.	0742044	1985 04 30	187.	0854358	1985 04 15
133.	0742145	1985 04 30	188.	0855259	1985 04 15
134.	0742650	1985 04 30	189.	0855764	1985 04 15
135.	0746557	1985 01 15	190.	0856261	1985 04 15
136.	0746961	1984 11 15	191.	0856362	1985 04 15
137.	0747054	1984 11 15	192.	0858063	1985 06 30
138.	0749967	1985 01 31	193.	0860656	1985 04 15
139.	0750144	1985 03 15	194.	0860858	1985 04 15
140.	0752047	1984 11 15	195.	0861961	1985 04 15
141.	0752249	1985 02 28	196.	0862256	1985 04 15
142.	0753453	1985 02 28	197.	0862862	1985 04 15
143.	0754758	1985 02 28	198.	0863056	1985 04 15
144.	0757764	1985 02 28	179.	0863258	1985 04 15
145.	0758968	1985 03 31	200.	0863460	1985 04 15
146.	0761351	1985 03 15	201.	0866365	1985 04 30
147.	0764862	1985 03 31	202.	0867771	1985 03 31
148.	0766260	1985 03 31	203.	0887373	1985 03 31
149.	0766664	1985 03 31	204.	0897780	1985 03 15
150.	0767262	1985 03 31	205.	0912750	1985 03 31
151.	0767868	1985 04 15	206.	0923048	1985 10 15
152.	0768365	1985 04 15	207.	0933354	1985 04 15
153.	0768567	1985 03 31	208.	0938465	1985 02 15
154.	0768668	1985 04 15	209.	0940957	1985 11 15
155.	0768769	1985 04 15	210.	0941959	1985 02 15
156.	0769266	1985 04 15	211.	0943054	1985 02 28
157.	0769569	1985 04 15	212.	0944662	1985 02 28
158.	0769872	1985 04 15	213.	0946161	1985 02 28
159.	0772457	1985 04 30	214.	0949870	1985 03 15
160.	0778570	1984 05 31	215.	0948872	1985 03 15
161.	0820341	1985 04 15	216.	0950657	1985 03 15
162.	0821444	1985 04 15	217.	0950758	1985 03 15
163.	0836962	1985 04 15	218.	0951558	1985 03 15
164.	0837661	1985 01 31	219.	0951659	1985 03 15
165.	0838057	1985 02 28	220.	0953865	1985 03 31
166.	0839463	1985 02 28	221.	0954261	1985 03 31
167.	0840549	1985 04 15	222.	0954463	1985 03 31
168.	0841450	1985 03 15	223.	0954665	1985 03 31
169.	0841753	1985 03 15	224.	0954766	1985 03 31
170.	0842755	1985 03 15	225.	0957267	1985 03 31
171.	0845761	1985 03 15	226.	0957873	1985 03 31

(1)	(2)	(3)
227.	0957974	1985 03 31
228.	0959473	1985 03 31
229.	0960660	1985 04 15
230.	0961056	1985 04 15
231.	0961460	1985 04 15
232.	0961965	1985 04 15
233.	0962563	1985 04 15
234.	0962664	1985 04 30
235.	0962866	1985 04 30
236.	0963363	1985 04 30
237.	0964163	1984 04 30
238.	0971867	1985 05 31
239.	1001512	1985 03 31
240.	1006320	1984 11 15
241.	1009225	1984 11 30
242.	1016626	1985 03 31
243.	1027732	1985 01 31
244.	1029231	1985 02 15
245.	1033424	1985 07 31
246.	1039941	1985 02 28
247.	1040118	1985 03 15
248.	1041928	1985 03 15
249.	1043528	1985 03 15
250.	1043932	1985-05 15
251.	1044025	1985 05 15
252.	1045936	1985 03 15
253.	1047334	1985 03 15
254.	1048437	1985 04 15
255.	1049439	1985 02 28
256.	1051224	1985 03 15
257.	1052226	1985 03 15
258.	1053935	1985 04 15
259.	1054836	1985 03 31
260.	1055131	1985 03 31
261.	1055333	1985 03 31
262.	1055838	1985 03 31
263.	1056036	1985 03 31
264.	1058238	1985 03 31
265.	1058541	1985 0331
266.	1059341	1985 04 15
267.	1059442	1985 03 31
268.	1059745	1985 03 31
269.	1060023	1985 03 31
270.	1060124	1985 03 31
271.	1060225	1985 03 31
272.	1060427	1985 03 31
273.	1060528	1985 03 31
274.	1060730	1985 03 31
275.	1062027	1985 10 15
276.	1062633	1985 04 15
277.	1063029	1985 03 15
278.	1063231	1985 04 15
279.	1063332	1985 04 15
280.	1063635	1985 04 15
281.	1063736	1985 04 15
282.	1063938	1985 04 15
283.	1064536	1985 04 15
284.	1065235	1985 04 15
285.	1066237	1985 04 30
286.	1068140	1985 04 15
287.	1072333	1985 04 15
288.	1072535	1985 04 15
289.	1072838	1985 04 15
290.	1074741	1985 05 15
291.	1095547	1985 03 31
292.	1095749	1985 03 31
293.	1116832	1984 09 30
294.	1119434	1985 04 15
295.	1137537	1984 12 15
296.	1149039	1985 01 15
297.	1153131	1985 02 15
298.	1162334	1985 02 28
299.	1162738	1985 02 28
300.	1165239	1985 02 28
301.	1168144	1985-03 15
302.	1169348	1985 03 15
303.	1169550	1985 03 15
304.	1171133	1985 03 15
305.	1171739	1985 03 15
306.	1172640	1985 03 31
307.	1172842	1985 03 31
308.	1173541	1985 03 31
309.	1174341	1985 03 31
310.	1174442	1985 03 31
311.	1174745	1985 03 31
312.	1175848	1985 03 31
313.	1176244	1985 04 15
314.	1176749	1985 04 15
315.	1176951	1985 04 15
316.	1177751	1985 11 30
317.	1177953	1985 04 15
318.	1178652	1985 04 15
319.	1178854	1985 04 15
320.	1179452	1985 04 30
321.	1180336	1985 04 15
322.	1180437	1985 04 15
323.	1180639	1985 04 30
324.	1181944	1985 04 30
325.	1183948	1985 05 15
326.	1195046	1985 03 15

[No. C.M.D./13 : 12]

B.N. SINGH, Addl. Director General

आपूर्ति और वस्त्र मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1985

का० आ० 4520.—केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का LXI) के खण्ड 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री वी० बालासुब्रमनियन को कार्यभार सम्भालने की दिनांक से आगामी आदेशों तक के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

[संख्या 25012/30/85—रेशम]

विवेक कुमार अग्निहोत्री, अपर विकास (आयुक्त हथकरघा)

MINISTRY OF SUPPLY & TEXTILES

(Department of Textiles)

New Delhi, the 11th September, 1985

S.O. 4520.—In exerise of powers conferred by section 7 of Central Silk Board Act, 1948 (LXI of 1948) the Central Government is pleased to appoint Shri V. Balasubramanian, as Secretary Central Silk Board, Bangalore with effect from the date of assumption of charge of the post by him and until further orders.

[C.F. No. 25012/30/85-Silk]

V. K. AGNIHOTRI, Addl. Development Commissioner (Handlooms).

कृषि मंत्रालय

(कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1985

का० आ० 4521.—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बनाए गए स्थायी वित्तीय समिति विनियमों के विनियम 2 (iv) के अनुसरण में तथा ए० पी० सेस एक्ट 1940 की धारा 7 (2) में निहित उपबन्ध के अनुसरण में, शासी निकाय द्वारा इस निकाय के निम्नलिखित सदस्यों को 28 जून, 1985 से एक वर्ष की अवधि के लिए या उनके उत्तराधिकारियों के विधिवत चुने जाने की अवधि तक इनमें जो भी बाद में हो, स्थायी वित्त समिति के लिए सदस्य चुने गये हैं—

1. डा० के० एम० नायडू,
   निदेशक,
   गन्ना प्रजनक संस्थान,
   कोयम्बटूर

2. श्री बालासाहब विखे पाटिल,
   समद सदस्य (लोक सभा)
   4, डा० विशम्बर दास मार्ग,
   नई दिल्ली—110001

श्री बालासाहब विखे पाटिल,
लोक सभा सदस्य,
श्रीरामपुर, जि० अहमद नगर (महा०)

[सं०—2(1)/85—समन्वय—1]

एम० जी० मेनन, अवर सचिव,

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agricultural Research and Education)

New Delhi, the 9th September, 1985

S.O. 4521.—In pursuance of Regulation 2(iv) of the Standing Finance Committee Regulations framed by the I.C.A.R. and in pursuance of provision contained in Section 7(2) of the A.P. Cess Act, 1940 the following two members of the Governing Body have been elected by that Body to be members of the Standing Finance Committee for a period of 1 year w.e.f. 28th June, 1985 or till such time as their successors are duly elected, whichever is later:—

1. Dr. K. M. Naidu,
   Director,
   Sugarcane Breeding Institute,
   Coimbatore.

2. Shri Balasaheb Vikhe Patil,
   Member Lok Sabha,
   4, Dr. Bishamber Das Marg,
   New Delhi-110001

Shri Balasaheb Vikhe Patil,
Member Lok Sabha,
Shrirampur, Distt. Ahmednagar-(M.S.).

[F. No. 2(1)/85-CDN-I]

M. G. MENON, Under Secy.

परमाणु ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1985

का. आ. 4522.—केन्द्रीय सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के बम्बई स्थित मुख्यालय को, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में अधिसूचित करता है।

[संख्या 6/5/82-हिन्दी]

शैलेन्द्र पाण्डेय, उप सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

New Delhi, the 4th September, 1985

S.O. 4522.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules 1976, the Central Government hereby notifies the headquarters of M/s Indian Rare Earths Ltd., Bombay, more than 80 per cent staff whereof has acquised a working knowledge of Hindi.

[No. 6/5/82-Hindi]

SHAILENDRA PANDEY, Dy. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1985

का. आ० 4523.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, पत्र सूचना कार्यालय के शाखा कार्यालय, जोधपुर को, जिसके कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करते हैं।

[संख्या ई-11011/35/83-हिन्दी]

मुनि लाल, उप निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 3rd September, 1985

S.O. 4523.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the Branch Office, Jodhpur of Press Information Bureau, the staff whereof have arquired the working knowledge of Hindi.

[No. E-11011/35/83-Hindi]

MUNI LAL, Dy. Director (OL)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1985

का०आ० 4524—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुपालन में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मण्डल के निम्नलिखित अधिनस्थ कार्यालयों को, जहां के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करता है :—

1. सहायक इंजीनियर का कार्यालय, जालंधर
2. मण्डल चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय, जालंधर
3. मण्डल परिवहन अधीक्षक का कार्यालय, जालंधर
4. सहायक इंजीनियर का कार्यालय, पठानकोट
5. मण्डल इंजीनियर का कार्यालय, जम्मू तवी
6. क्षेत्र अधिकारी का कार्यालय, जम्मू तवी
7. मण्डल चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय, अमृतसर
8. सहायक इंजीनियर का कार्यालय, अमृतसर
9. सहायक यातायात अधीक्षक का कार्यालय, अमृतसर
10. सहायक इंजीनियर का कार्यालय, लुधियाना
11. सहायक मण्डल चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय, लुधियाना
12. सहायक यातायात अधीक्षक का कार्यालय, लुधियाना

[संख्या हिन्दी-85/रा. भा. I/12/1]

ए.एन. वांचू, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं
भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 28th August, 1985

S.O. 4524.—In pursuance of Sub-Rules (2) and (4) of Rules 10 of the Official Language (Use for the Official Purposes of Union) Rules, 1976 the Ministry of Railways (Railway Board) hereby notify the following subordinate offices of Ferozpur Division of Northern Railway, where the staff have acquired the woring knowledge of Hindi :—

(1) Office of the Assistant Engineer, Jalllandhar.

(2) Office of the Divisional Medical Officer, Jallandhar.

(3) Office of the Divisional Transport Superintendent, Jallandhar.

(4) Office of the Assistant Engineer, Pathankot.

(5) Office of the Divisional Engineer, Jammu Tavi.

(6) Office of the Area Officer, Jammu Tavi.

(7) Office of the Divisional Medical officer, Amritsar.

(8) Office of the Assistant Engineer, Amritsar.

(9) Office of the Assistant Traffic Superintendent, Amritsar.

(10) Office of the Assistant Engineer, Ludhiana.

(11) Office of the Assistant Divisional Medical Officer, Ludhiana.

(12) Office of the Assistant Traffic Superintendent, Ludhiana.

[No. Hindi-85|OL-I|12|1]

A. N. WANCHOO, Secy. Railway oBard, and Ex-Officio Joint Secretary to the Govt. of India.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 3rd September, 1985

CORRIGENDUM

S.O. 4525.—In the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) No. S.O. 4324 dated the 23/24th November, 1984 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 8th December, 1984, in line 3 for "(TN|6633)" read "(TN|16633)".

[No. S-35014(118)|84-SS.IV]

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1985

का. आ. 4526 :—मैसर्स दी तमिलनाडु टैक्सटाईल्स कारपोरेशन लिमिटेड, मोहना भवन, 15-हुजैर रोड, कोयम्बतूर-641018 (टी. एन./7510-ए.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है), ने अपनी मुख्य स्थापन और जयानकोण्डम, त्रिची जिला (टी. एन/7510-ए.), सिवगिरि, पेरियार जिला (टी. एन./16779) और अरुणुकोटाई, रामानाद जिला (टी. एन./16740) में स्थित पावरलूम के कम्पलैक्स के कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 10)), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस. 35014/185 85-एस. एस. 4]

New Delhi, the 3rd September, 1985

S.O. 4526.—Whereas Messrs. Tamil Nadu Textile Corporation Limited, Mohna Bhavan, 15, Huzur Road, Coimbatore-64108(TN|7510-A) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act), in respect of its main establishment and the Powerloom Complexes at Jayankondam, Trichy District (TN|7510-A), Sivagiri, Periyar District (TN|16779), and Aruppukottai, Ramnad District (TN|16740).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, and its three units from the operation if all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would

be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/ nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(185)/85-SS.IV]

का. आ. 4527.—मैसर्स इण्डियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, कैमिकल डिवीजन, पोस्ट—रिशरा, जिला—हुगली (डब्ल्यू. बी./1124/8217), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है), ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों से समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या

इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस०-35014/204/85-एस. एस.-4]

S.O. 4527.—Whereas Messrs Indian Explosive Limited, Chemical Division, Post : Rishra, Distt. Hooghly (WB/1124/8217) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/204/85-SS.IV]

का. आ. 4528.—मैसर्स फ्लैक्ट इण्डिया लिमिटेड, (एस. एफ.-इण्डिया लि.) पो. औ. और ग्राम—जलरूरा, जिला—24 परगना (डब्ल्यू. बी./9931), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन बीमा जीवन के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप

सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसका मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसका बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार, नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/200/85-एस०एस०-4]

S.O. 4528.—Whereas Messrs Falkt India Limited, (S. P. India Limited) P.O. and Village—Jalkhura, District 24 Parganas (W.B.|9981) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now therefore, in exercise of the powers confered by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed herete, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(200)85-SS.IV]

का. आ. 4529.—मैसर्स ईस्ट इण्डिया फार्मेस्टीकल वर्क्स लिमिटेड, 6-लिटल रूसैल स्ट्रीट, कलकत्ता-700071 (डब्ल्यू. बी./1152), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है), ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं :

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन

देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वा किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस. 35014/202/85-एस. एस. 4]

S.O. 4529.—Whereas Messrs East India Pharmaceutical Works Limited, 6, Little Russell Street, Calcutta—700071 (WB/1152) (hereinafter referred to as the said establishment have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

S.O. 4529.—Whereas Messrs East India Pharmaceutical the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such, employees than the benefits admissible under the Employes' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to expain their point of view.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/202/85-SS.VI]

का. आ. 4530.—मैसर्स हुगली फ्लौर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, 20-राउण्ड टैंक लैन रामकृष्टोपुर, हावड़ा (डब्ल्यू. बी./2601), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है), ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकूल है जो

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिति/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस.-35014/203/85-एस. एस. 4]

S.O. 4530.—Whereas Messrs Hooghly Flour Mills Company imited, 20, Round Tank Lane, Ramkrishtopur, Howrah, (WB|2601) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Sheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such, employees than the benefits admissible under the Emploeyes' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. 35014(203)|85-SS.IV]

का. आ. 4531 :—मैसर्स ग्रैफोन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, 40/सी., पिन्सैप स्ट्रीट, कलकत्ता-700072 (डब्ल्यू. बी./7221), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है), ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिमी बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिमी बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और किसी संशोधन

से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिति/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014/(201)/85-एस. एस. -4]

S.O. 4531.—Whereas Messrs Griffon Laboratories Private Limited, 40|B, Prinsep Street, Calcutta—700072 (W.B.|7221) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the condition specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner West Bengal maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In cas of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(201)|85-SS-IV]

का. आ. 4532 :—मैसर्स विरूधुन टैक्सटाईल मिल्स लिमिटेड, पो. बो. नं. 39, विरूधुनगर—626001, जिला रामनाडु, (टी.एन. 293), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है), ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/199/85-एस. एस.-II]

S.O. 4532.—Whereas Messrs Virudhunagar Textile Mills Limited, P. B. No. 39, Virudhunagar-626001, Ramnadu District (TN|293) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9 Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme and reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S.35014|199|85-SS IV]

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1986

का. आ. 4533 :—मैसर्स गैस्ट कीन विलियम्स लिमिटेड, 97-अब्दुल मार्ग, हावड़ा-711103 (डब्ल्यू. बी./5123), जिसके अधीन (1) 97-अब्दुल रोड, हावड़ा (डब्ल्यू. बी./107), और (2) क्यारी रोड, हावड़ा—711104, (डब्ल्यू. बी./228), स्थित उसकी शाखाएं भी हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3489, तारीख 16-9-1982 के अनुसरण में इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 2-10-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 1-10-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिमी बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस. 35014/135/पी. एफ. 2 एस. एस. 4]

New Delhi, 11th September, 1985

S.O. 4533.—Whereas Messrs Guest Keen Williams Limited 97, Andul Road. Howrah-711103 (WB|5123) including branches at (1) 97, Andul Road, Howrah (WB|197) and (2) 124 Currie Road, Howrah-711104 (WB|228) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of abour S.O. 3489 dated the 16-9-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 2-10-1985 upto and inclusive of the 1-10-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if one the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the permium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme of the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/135/82-PF.II(SS.IV)]

शुद्धिपत्र

का. आ. 4534—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 24 दिसम्बर, 1983, को प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 4676, दिनांक 28 नवम्बर, 1983 की अनुसूची की मद 1 की लाईन 2 और मद 8 की लाईन 2 में "पंजाब" के स्थान पर "हरियाणा" पढ़ें।

[संख्या एस-35014/278/83-पी. एफ.-II]

CORRIGENDUM

S.O. 4534.—In the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour), No. S.O. 4676, dated the 28th November, 1983 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 24th December, 1983, in line 3 of item 1 and line 3 of item 8 of the Schedule, for "Punjab" read "Haryana".

[No. S-35014|278|83-P. F. II]

शुद्धि पत्र

का. आ. 4535—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 31 मार्च, 1984 को प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 1118, दिनांक 14 मार्च, 1984 की अनुसूची की मद 1 की लाईन 2 और मद 8 की लाईन 2 में "पंजाब" के स्थान पर "हरियाणा" पढ़ें।

[संख्या एस-35014/3/84-एफ. पी. जी.]

CORRIGENDUM

S.O. 4535.—In the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation, (Department of Labour) No S.O. 1118, dated the 14th March, 1984 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 31st March. 1984, in line 3 of item 1 and line 3 of item 8 of the Schedule for "Punjab" read "Haryana".

[No. S-35014|3|84-FPG]

नई दिल्ली, 12 सितम्बर 1985

का. आ. 4536.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 16 सितम्बर, 1985 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है (और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय

जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबंध केरल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला मालापुरम के इरनाद तालुक में मालापुरम को राजस्व ग्राम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।"

[संख्या एस-38013/18/85-एस.एस-1]

ए. के. भट्टराई, अवर सचिव

New Delhi, the 12th September, 1985

S.O. 4536.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 16th September, 1985 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Kerala, namely :—

"The areas within the revenue village of,
Malappuram in Eranad Taluk of,
Malappuram District."

[No. S-38013/18/85-SS-I]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1985

का. आ. 4537.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की हरियाजाम कोलियरी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2 धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28-8-1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 3rd September, 1985

S.O. 4537.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Hariajam Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 28th August, 1985.

(ANNEXURE)

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 52 of 1984

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1) (d) of the I. D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Hariajam Colliery of M/s. Eastern Coalfields Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri R. S. Murthy, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 19th August, 1985

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012(169)/84-D.III(A) dated the 3rd August, 1984.

SCHEDULE

"Whether the demand of Bihar Colliery Kamgar Union that Shri Mohammed Israil Ansari, workman of Harijam Colliery of M/s. Eastern Coalfields Limited, P.O. Nirsha, Dist. Dhanbad be regularised as Vehicle Incharge in Excavation Grade 'B' is justified ? If so, to what relief he is entitled and from date ?"

The case of the workmen is that the concerned workman Mohammed Israil Ansari was appointed as Motor Vehicle Driver in Harijam Colliery and is placed in Cat. V. He has been working as Vehicle Incharge since 1981 and is maintaining and repairing all vehicles including Dumper Dozer Pay Loader etc. As vehicle Incharge the duties of the concerned workman is to supervise over all the functioning of the vehicle, to purchase and take delivery of spare parts of the vehicle. He repeatedly demanded for his regularisation as Vehicle Incharge but the management did not regularise him. He is an active member of Bihar Colliery Kamgar Union with which the local management is very much biased and as such he is not being regularised as vehicle incharge in Excavation Grade-B. When the management did not regularise him as vehicle Incharge in Excavation Grade-B, the union raised an industrial dispute before the ALC(C), Dhanbad but the same ended in failure and thereafter the present reference has been made by the Government of India Ministry of Labour. The action of the management in not regularising the concerned workman as Vehicle Incharge in Excavation Grade-B was illegal arbitrary unjustified discriminating and against the principles of natural justice. The concerned workman is entitled to be regularised as vehicle Incharge in Excavation Grade-B since 1981.

The case of the management is that there is no valid industrial dispute as no demand was raised by the sponsoring union with the management about the present demand. There is no excavation section in Harijam Colliery for placing the concerned workman in Excavation grade and even where there is any excavation section in a colliery there is no post of vehicle incharge in Excavation Grade-B. The excavation grade B is meant for entirely a different set of workers and job. Neither the Coal Wage Board Recommendation nor the subsequent NCWAs have any provision for the post of vehicle Incharge. The concerned workman is discharging the duties of Motor Vehicle Driver in Hariajam Colliery and is in Cat. V. The promotional channel from Motor vehicle driver from Cat. V is in Cat. VI in as Car and Lorry driver mechanic. The management has already car and lorry mechanics and presently there is no requirement for any additional machanic in Cat. VI. Lorries include trucks. Come of the vehicles have automatic unloading devices and are called Tipping trucks and dumping trucks. These tipping trucks are different from the dumper which are used in the excavation section as those dumpers are not operated on public high way but are used in quarries only for transporting over burden or coal. Even in excavation Section, excavation Grade-B is applicable to operators operating havey earth moving equipment like dumpers being used in the excavation Section, drills cranes dozers. These heavy earth moving equipment which are sophisticated and costly machine are repaired and maintained by excavation plant fitters, electricians, loaders turner etc. Tipping trucks or lorries do not fall in this category of excavation section. As the concerned workman is not employed in excavation Section, he cannot claim excavation Grade-B. There is no post of vehicle incharge either in excavation section or coal industries and no pay scale has been fixed for any such post. The management has the requisite supervisor and technical staff to look after the repair and maintenance of motor vehicles. The purchase and delivery of spare parts is handed by the staff of the stores department. The demand of the workmen for regularisation of the concerned workman as vehicle incharge in Excavation Grade-B is totally beseless and misconceived and the demand is without any justification and as such the concerned workman is not entitled to any relief.

The points for consideration are whether

(1) There is any post of vehicle Incharge in E & M Cadre or Excavation Section and

(2) Whether the concerned workman is performing the job of Excavation Grade-B.

The workman have examined two witnesses in support of their case and the management have examined one witness in support of their case. Besides that the workman have produced documents which have been marked Ext. W-1 to W-16 and the documents produced on behalf of the management have been marked Ext. M-1 to M-3.

Admittedly, the concerned workman was appointed as Motor Vehicle driver and is in Cat. V. WW-2 who has come to support the concerned workman has stated in his evidence that the designation of the concerned workman is driver. MW-1 has also stated that the concerned workman is tipping truck driver of Hariajam Colliery and is performing the duties of Driver only. He has stated that there is no post of vehicle Incharge in his colliery and that the concerned workman was never appointed as Vehicle Incharge. According to him the channel of promotion of the driver is to the post of Driver-cum-Mechanic. WW-1 who is the concerned workman has stated that since 1981 he is working as vehicle Incharge in Hariajam Colliery. The first question to be decided is whether there is any post or designation of Vehicle Incharge either in the E & M Cadre or in the excavation cadre, On perusal of the coal Wage Board Recommendation and three NCWA it will appear that there is no designation of vehicle Incharge either in E & M Cadre or in excavation cadre. However the workman have adduced documentary evidence to show that the concerned workman was designated as Vehicvle Incharge. Ext. W-1 is a letter dated 13-7-81 which shows that the Manager of Hariajam Colliery had addressed the Fairdeal Auto spare Burdwan by which one vehicle part was requisitioned through Md. Israil (the concerned workman) who was being sent to collect it. Ext. W-2 is a requisition through the Manager, Hariajam Colliery to the Agent for the purchase of some parts and that the Agent had approved it and the amount of Rs. 721/- was paid to the concerned workman to bring those parts. Ext. W-9 series are requisition for spare parts by the Manager of Hariajam Colliery and the Agent was requested to sanction the amount for the purpose of the parts. Ext. W-10 is a requisition from the Manager, Hariajam Colliery to Fair deal Auto Spares Burdwan for the supply of spare parts on credit which was be delivered to the concerned workman and the signature of the concerned workman was attested to take delievry of those spare parts. Ext. W-11 date 28-7-81 is a requisition from the Agent, Hariajam Colliery to M|s. Chand Mall Auto spare Dhanbad by which the concerned workman was authorised to collect Leyland Tipping trucks and the speciman of the concerned workman was attested by the Agent. Ext W-15 and W-16 are also requisition by the Manager, Hariajam Colliery for some spare parts and the Agent was requested to sanction the amount for the purchase of the spare parts. On all these exhibits there is a signature of the concerned workman describing himself as vehicle incharge. It will appear that the requisition were either being made by the Manager or the Agent and there was no need for the concerned workman to sign on all those requisition. It appears from the evidence of WW-1 that he had taken photo copies of these Exhibits from the orginal. He has stated that after taking the photo of the original he had returned originals to the office. The case of the management is that the concerned workman obtained those originals from the office but did not return them back and before taking photo copies from the original the concerned workman had put his signature on all those documents designating himself as vehicle Incharge and thereafter taking its photo copy. MW-1 who is a Manager of Harijam Colliery in his evidence has stated that Ext. W-2 and W-9 series were prepared by the Store Keeper bearing the signature of MW-1. He has tsated that

when he had signed those documents there was no signature of the concerned workman on those exhibits and that the signatures of the concerned workman on it were made subsequent to his signature. He has also stated that the concerned workman was not required to sign on those documents. On perusal of the documents which I have mentioned above it appears that the statement of MW-1 is correct as there was no scope or requirement of the concerned workman signing those documents. It appears that the concerned workman has purposely signed giving his designation as Vehicle Incharge in order to establish that he is working as Vehicle Incharge.

Ext. W-4, W-5, W-6 are challans nuder the signature of the Manager to M/s. New Bombay Volcanising, Nirsa. These also bear the signature of the concerned workman but no designation of the concerned workman as vehicle Incharge is mentioned in it and as such this document cannot be used to show that the concerned workman was working as Vehicle Incharge.

Ext. W-8, W-8/1, W-8/2, W-8/3, W-12, W-13 and W-14 are orders of Sunday duty allotment charts. This contains the signature of the Engineer and Manager and it also bears the signature of the concerned workman describing himself as vehicle Incharge Hariajam Colliery. MW-1 has denied that the Sunday duty allotment chart was prepared by the concerned workman and he used to allot the work to the drivers. Although this Sunday duty allotment chart contain the signature of he concerned workman Sunday duty allotment chart Book Ext. M-1 which is for the period from 25-9-83 to 29-7-84 does contain the signature of the concerned workman. If the concerned workman was actually required to sign the Sunday duty allotment charts and was actually preparing the said charts he would have signed on each date in Ext. M-1 also. Thus on consideration of Ext. M-1 it appears that the signatures on Ext. W-8 series and Ext. Ext. W-12, 13 and 14 were subsequently but by the concerned workman describing himself as Vehicle Incharge. Ext. W-3 is an Office order dated 23-11-81 from which it appears that the trade test and interview of Gorachand Mahato, Dumper Driver (T) was to be held on 2-12-81 and copy of the said office order was sent to the members of the interview committee. It will appear from W-3 that a copy was sent to the concerned workman describing him as vehicle Incharge so that he may make available one dumper for the trade test. Ext. W-7 is also an office order dated 2-11-81 by which the Senior P.O. Hariajam Colliery had fixed the date of trade test and interview of Gorachand Mahato, and all the concerned were informed. It will appear that a copy was sent to Md. Israil describing him as Vehicle Incharge and was asked to make available one dumper at 4 P.M. on 6-11-81. These two documents of the management described the concerned workman as Vehicle Incharge. MW-1 has stated that "C.C. to Md. Israil Ansari Vehicle Incharge 2. C.C. Shri Gorachand Mahato Hariajam Colliery " have been subsequently inserted after the signature of MW-1 but no explanation is coming as to how there was such entry in Ext. W-7. The entries in Ext. W-3 stated to be subsequent insertion does not appear to me to be correct and it appears that the said entry was already there in Ext. W-7. Thus although the documents on which the concerned workman appears to have put his signature appear to be a subsequent insertion Ext. W-3 and W-7 in my opinion show that the concerned workman was described as Vehicle Incharge by the management although there was no such post or designation. In view of the above discussion I hold that the concerned workman was being described as Vehicle Incharge but there is no post or designation of any vehicle Incharge in E & M cadre of Excavation Section.

The description of a workman by certain designation is not very material specially when there is no such designation or post in colliery. We have to see the actual work being performed by the concerned workman so as to examine the cadre and the category to which he belongs. The claim of the workmen is that the concerned workman was performing the job of Vehicle Incharge in excavation grade-B. I have already stated above that there was no post or designation of vehicle Incharge in any of the cadres and as such the mere designation will not lead us to any conclusion. Let us therefore see if the concerned workman was performing the job of exacavtion Grade-B. The grouping of excavation workers (as in NCDC) is stated at page 56 of NCWA-I and the categories of the excavation section of NCDC is also stated at page 55 Appendix VII of C.W.B. Volume II. WW-1 has stated about the duties being performed by him as Vehicle Incharge and they are the following as stated by him.

1. As Vehicle Incharge he looks after the repair and maintenance of Dumper, Pay loaders of the Colliery.
2. He used to purchase the parts of those vehicles from the market for repairing job.
3. He along with engineer and manager decides as to which of the vehicle was to be given to which of the drivers.
4. He used to take trade test of drivers.
5. He allots duties to the drivers of the vehicles and supervise their work.
6. He repairs the vehicles with his own hands.
7. He maintains the Sunday maintining list.

According to WW-2 it will appear that the concerned workman used to distribute duties on the pay Loader and Dumper and other vehicles and was Incharge of Maintenance of the said vehicle. He has also stated that the concerned workman used to forward the leave petition of the drivers and used to take the test of the drivers for promotion. He has also stated that the concerned workman used to purchase parts of the vehicles from the market and used to make repair of the vehicles in case of need and also used to supervise all vehicles. On perusal of the grouping of excavation worker in NCWA-I it will appear that he was not working as drill operator, excavation plant electrician, excavation plant loader, excavation plant turner in Excavation Grade-B. An excavation plant Fitter Grade-I of excavation grade-B according to the job description is highly skilled workman possessing atleast 7 years experience in the accurate fitting and assemblying of various parts of excavation equipment besides general repairs and maintenance. He must be able to read and use instruments for accurate measurement and should undertake independent repair jobs. Excavation plant mechanist Grade-I of excavation Grade-B is highly skilled workman possessing not less than 8 years experience in the operation and handling of all kind of workshops tools like lathes, drills, shapers, planners generators and other high precision machine. He should be experience in the use of precesion measuring instrument including the use of the gauges and should turn out the job independently. Tractor/Dozer Operator in excavation Grade-B is a skilled workman possessing not less than five years experience in the operation and handlings of crawler or wheel type dozers of not less than 150 H.P. He should have general knowledge of the mechanism of the tractors and undertake minor running repairs. He should hold valid licence for tractor driving. I have stated above the job description of some of the designation of Excavation Grade-B in which the claim may be made by the concerned workman but not of the requirement of the job description stated above appear to be performed by the concerned workman, and as such I find it really difficult to earmark him in any of those jobs which are included in Excavation Grade-B.

WW-2 has stated that he took over charge of Terex Pay Loader on 23rd June from the concerned workman and the said Terex pay Loader was brought in the mines in November/December, 1979. Thus it appears that the concerned workman had not worked on the said terex pay loader even for more than a month even if he had worked at all on it and since then he is not working on the Pay loader. It will appear from his evidence that generally each driver is set up to work on a particular vehicle and as such the assertion of the concerned workman that he used to distribute wor to the driver on a particular vehicle does not appear to be correct. He has also stated that there are 4/5 mechanic fitters in the workshop and as such I do not think that there was any need of the concerned workman to work as Mechanic fitter. No paper has been filed to show that the concerned workman used to forward leave application of the drivers. It will also appear that there is one

foreman to look after and supervise the work in the workshop. Although it is asserted that the concerned workman used to take test of driver there is no paper or document to show that he used to take the test. he document Ext. W-3 and W-7 merely show that the concerned workman was asked to produce a vehicle for the test, and he was not a member of the Committee. WW-2 has stated that there is a colliery store where store keeper and Asstt. Store Keeper work and as such it will appear that the concerned workman was only deputed to bring the spare parts which were required for use as a Messenger or carreer as he was a driver and the parts had to be brought on some vehicle. WW-2 has clearly stated that he has not seen any paper to show that the concerned workmen used to repair any vehicle. The concerned workmen has not produced any document to show that he was asked to repair any vehicle. Had he repaired any vehicle there must have been some order in writting to show that the concerned workman wes reparing vehicles. Admittedly, the concerned workman is not a mechanic and has no training for it. Most important part of evidence of WW-2 is towards the close of his cross-examination. He has stated that Pay loader is worked in the quarry and in railway siding. The concerned workman does not work at a place where WW-2 is working and as such it is clear that the concerned workman is not working in the excavation section where WW-2 works in the quarry on the pay loader. WW-1 has stated in his cross-examination that there was no Excavation Section in the colliery and as such I do not understand as to how the concerned workman is claiming excavation Grade-B although there is no excavation Section in the colliery. He is not doing the job which is done by the workman of excavation Grade-B.

WW-1 has stated that he does not know if a driver is promoted to the post of Driver Mechanic but MW-1 has clearly stated that the promotional channel from the post of Driver is to the post of Driver Mechanic in Cat. VI. Ext. M-3 is the order dated 18-11-83 which also shows that one Manbodh Rewani Driver was promoted as Driver-Cum-Mechanic in Cat. VI. Thus the concerned workman can claim his promotion to his own cadre namely as Driver-cum-Mechanic in Cat. VI. It is admitted that the cadre of the concerned workman was not changed from E & M cadre to excavation grade, and I have already discussed above that the concerned workman is not performing the job of Excavation Grade-B and as such the concerned workman although described as Vehicle Incharge cannot be entitled to excavation Grade-B.

In the result, I hold that the demand of Bihar Colliery Kamgar Union that the concerned workman Mohommed Israil Ansari of Hariajam Colliery of M/s. E.C.L. be regularised as Vehicle Incharge in Excavation Grade-B is not justified and that he is not entitled to any relief.

This is my Award.

I.N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012 (169)/84-D. III (A)]

A.V.S. SARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1985

का. आ. 4538 —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारत कोकिंग कोल लि. के धनसार सेल्स केन्द्र के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-9-1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 9th September, 1985

S.O. 4538.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Dhansar Sales Centre of Messrs Bharat Coking Coal Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd September 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 23 of 1985

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1) (d) of the I.D. Act., 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Dhansar Sales Centre of Messrs. Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers : Shri R. S. Murthy, Advocate.
On behalf of the workmen : Shri J. P. Singh, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 28th August, 1985

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012|364|84-D.III(A), dated, the 18th March, 1985.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Kusunda Area No. VI, Messrs Bharat Coking Coal Limited, P.O. Kusunda, Distt : Dhanbad in dismissing Shri N. K. Chouhan, Sales Assistant of Dhansar Sales Centre from service with effect from 26-11-1983 is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled?"

The case of the workmen is that the concerned workman Shri N. K. Chouhan was a permanent workman as Sales Assistant since 17-5-82 posted at Dhansar Sales Centre of Kusunda Area No. VI of M|s. B.C.C. Ltd. A chargesheet dated 29-1-83 was served upon him alleging that he in collusion with another Sales Assistant Shri A.K. Dutta and the Peon Lalan Nonia has misappropriated a sum of Rs. 41.245.14P. being the cash realised from the customers on 24th and 25th of January, 1983, at Dhansar Sales Centre and falsely reported that the theft was committed of the said amount from the locked drawer of the table kept in the office and as such they were charged for misconduct fraud and dishonesty. The concerned workman submitted his explanation. The management was not satisfied with his explanation and an order was made for holding a domestic enquiry against the concerned workman along with two others. The Enquiry Officer after holding the enquiry submitted his report holding the concerned workman guilty of the charges levelled against him. The disciplinary Authority accepted the findings ofthe Enquiry Officer and passed an order of dismissal of the concerned workman and the said order was communicated to him by a letter dated 25/26-11-83. The concerned workman was attached to B shift which started from 2 P.M. to 10 P.M. on the relevant dates. The Area Office accepted the cash deposits only upto 11 A.M. which did not fall within the duty hours of the concerned workman and as such he could not be charged with such duties of depositing money at the area office which is at a distance of about 8 K. M from the Sales Centre either before or after his duty hours. In the absence of the office Incharge from the office Shri Lalan Nonia Peon was authorised to receive the money from the Sales Assistant at the end of their duty hours and issued receipts for the same. The concerned workman

had handed over the cash collection of his shift on 24th and 25th of January, 1983 on the respective dates to Shri Lalan Nonia Peon and obtained receipt for the same. Shri R. K. Sahay, the Senior Sales Officer who had lodged FIR before the Police had detailed knowledge of the working system of the Sales centre, arrangements made at the Sales Centre for receipt, custody and transit of cash and as such he had reasons to believe that it was a case of theft of money by unknown persons from the office. There was absence of security arrangement at the Sales Centre. The non-cooperative attitude of the concerned area office staff, resulted in accumulation of fund at the Sales Centre. The theft was caused due to the lapses of the management. During the duty hours the concerned workman was only to receive the adjustment money in cash or to make refund by cheque of the amount of difference on the basis of actual weight of coal in the trucks and to prepare statement of cost realised from the customers. The concerned workman was not charged with duty of keeping the amount of money in his own custody or for depositing the same in the area Office. The money collected in the Sales Centre used to be controlled by Shri R. K. Sahay Senior Sales Officer who was incharge of the office and he had instructed Shri Lalan Nonia Peon of the office to keep such money in the drawer of table under lock and key. The concerned workman had received Rs. 18,891.44P. only on 24-1-83 which he had handed over to Shri Lalan Nonia at 10 P.M. on the same day. The said amount should have been sent by Shri R. K. Sahay in charge to the Area Office in the morning hours of 25-1-83 but he did not do so. The concerned workman had received Rs. 7890.39 P. on 25-1-83 as adjustment money and this money was handed over to Shri Lalan Nonia at 10 P.M. on the same day. The next day 26-1-83 being the Republic day was a holiday and money collected on 25-1-83 could not be deposited by Lalan Nonia and as such the adjustment money collected on 24-1-83 and 25-1-83 remained in the Sales Office in the drawer under lock and key of Lalan Nonia. Shri Lalan Nonia from the beginning of this case has admitted that the concerned workman had handed over the adjustment amount to him and he had granted receipt for the same on 24-1-83 and 25-1-83. In the beginning the management came out with a case of theft of the aforesaid amount from the Sales Centre. The Sales Centre did not have any iron safe in the office. There was a cash box which had already been shifted to the Area Office in October, 1982 and was brought back in the Centre on 25-1-83. The said cash box contains some unaccounted money, they key of which was with Shri R. K. Sahay Incharge of the Sales Office and as such the money collected in the Sales Office was not kept in the said box on 25-1-83. The evidence on the enquiry record does not establish charge against the concerned workman and the findings of the enquiry officer is perverse based on mere surmises and conjectures. It is submited that on the above facts the action of the management in dismissing the concerned workman from service is not justified and the workman is entitled to be reinstated with full back wages with effect from 16-11-83.

The case of the management is that the concerned workman was employed as a Sales Assistant at Dhansar Sales Centre during the year 1982 and 1983 till his dismissal from service with effect from 26-11-83. The concerned workman was on duty in Dhansar Sales Centre on 24th and 25th of January, 1985 in the Second shift commencing from 2 P.M. and ending at 10 P.M. The concerned workman was to receive application from the customers, check the same, issue money receipt, prepare delivery order and statement of demand draft and to send the same to the Area Cash Office on the next date along with the statements of cash realised from the customers against the respective sales orders. The cash amounting to Rs. 22640.67P. and 7698.97P. realised from the customers along with statement were to be deposited on the next day but the same was not deposited by the concerned workman and reported that the above amount has been stolen from the drawer of the table. The concerned workman was to keep the cash realised from the customers in the iron safe but he did not keep the same in the iron safe. The concerned workman in connivance with Shri A. K. Dutta Sales Assistant and Shri Lalan Nonia Peon misappropriated the money amounting to Rs. 41,245.25P. being cash realised from the customers on 24th and 25th January, 1983 and falsely reported about the theft of the same. There was also allegation that the concerned workman did not deposit the cash realised by him in time on earlier occasions also. The chargesheet was issued against the concerned workman dated 29-1-83 by the General Manager Kusunda Area for misconduct under Clause 17(a), 17(d), 17(q) and 17(v) of the Model Standing Orders. The concerned workman submitted his explanation which was found to be unsatisfactory. The other two persons also who were charged along with the concerned workman also submitted their explanation which were also found to be unsatisfactory. The General Manager, Kusunda Area appointed Shri S. N. P. Sinha, Personnel Manager as the Enquiry Officer. The enquiry Officer held the enquiry in which the concerned workman and others fully participated. The enquiry was held in accordance with the principles of natural justice and the concerned workman was given full opportunity to defend himself and to examine his defence witnesses. After holding the enquiry the Enquiry Officer submitted his report finding the concerned workman guilty of all the charges framed against him. The General Manager, Kusunda Area who is the disciplinary authority accepted the findings of the Enquiry Officer and passed the order of dismissal of the concerned workman. The concerned workman was accordingly dismissed from service with effect from 26-11-83. On the above facts it is submitted on behalf of the management that the action of the management in dismissing the concerned workman from service is justified and that he is not entitled to any relief.

Earlier the management had prayed that the issue of the validity and the fairness of the domestic enquiry held against the concerned workman be decided as a preliminary issue and accordingly the fairness and validity of the domestic enquiry was first heard and decided Shri J. P. Singh, Learned Advocate appearing on behalf of the workmen and conceded that the domestic enquiry was fair and proper and accordingly it was held on the preliminary issue that the domestic enquiry held in the case against the concerned workman was fair and proper. Thereafter the case was set for hearing on merit and the case was heard on merit, with reference to all the papers which were found on the record of the domestic enquiry.

The question to be determined is whether the charges of misconduct levelled against the concerned workman were established and whether the punishment of dismissal inflicted upon him was just and proper.

It is the admitted case of the parties that the concerned workman Shri N. K. Chouhan was a Sales Assistant at Dhansar Sales Centre and received Rs. 18,891.44P on 24-1-83 and Rs. 7,890.39P on 25-1-83 which had not been deposited in the area office. The management has produced papers to show the actual amount of money realised on 24-1-80 and 25-1-84 from the Sales Assistant. The defence of the concerned workman is that it was not his duty to deposit the amount realised at the Sales Centre in the Area Office on the next date of realisation. The specific case of the concerned workman is that Shri R. K. Sahay Sales Officer who was Incharge of the Sales Centre had directed him to deposit the realised amount with the Peon Lalan Nonia and accordingly he had deposited the amount on 24-1-83 and on 25-1-83 with Lalan Nonia and had obtained receipt (ext. W3 and W-3/1) for the same. The two receipts were filed before the Enquiry Officer and it was the specific defence of the concerned workman that as he had deposited the amount realised by him he was not responsible for it. Lalan Nonia who was even chargesheeted along with the concerned workman had given his statement before the Enquiry Officer and had accepted to have received the amount on 24-1-83 and 25-1-83 from the concerned workman on the direction of the Sales Officer. On behalf of the management it is stated that the Peon cannot be entrusted with the custody of the realised amount and that he could not be directed to deposit the said amount at the area office. It is true that a Peon should not be entrusted with the custody of large amount of money but we have to consider whether the Peon was actually keeping the amount in his

custody and depositing the same in the area office. The four witnesses examined on behalf of the management have no doubt tried at the first instance to deny that the Peon did not use to deposit the cash amount of the Sales Centre at the area office but it appears that the truth could not be suppressed. MW-1 is Shri R. K. Sahay, Senior Sales Officer who was incharge of Dhansar Sales Centre. He has said in question No. 53 that the time for deposit of cash and draft in the area office was 11.00 A.M. of the next date of realisation and that the said time was insisted by the area office. Thus it appears that the cash and draft etc. used to be deposited in the area office on the following day. It will appear from the statement of Shri A. K. Sah, MW-3 Cashier of the area office, that Lalan Nonia had brought money on 22-1-83 and 24-1-83 and he had (MW-3) informed Lalan Nonia that there were some soiled notes and the said fact has also been noted by the Enquiry Officer in his enquiry report at page-12. A suggestion was made to MW-1 that Lalan Nonia used to deposit the money to which he denied but it appears that from the statement of MW-3 that Lalan Nonia used to deposit the money at the area office since long before the alleged date of occurrence. The above facts, therefore lend support to the defence version of the concerned workman that Lalan Nonia used to deposit the cash amount in the area office on the following day. It will appear that the duty hours of the concerned workman during the relevant period was from 2 P.M. to 10 P.M. and the cash amount was to be deposited before 11.00 A.M. of the following day which was not the duty hour of the concerned workman. From the facts which have come out in the statement and the method of working of the Sales Centre it appears that as the duty hours of the second shift ended at 10.00 P.M. and those persons were again to present themselves for their duty at 2 P.M. on the next day, the amount of cash was accepted by the Peon and the same was deposited by him at about 11.00 A.M. on the next day and one could not expect the concerned workman to go to the area office which was at a distance of 8 K.M. from the Centre to deposit the cash when it was not his duty hours.

The management has referred to Ext. M-12 (which was marked Ext. 21 by the E. O.) to show the duty of the Assistants of the Sales Centre in the second shift. The said order of the Sales Officer Shri R. K. Sahay is dated 9-11-82. It appears that the said arrangement was for a period of one month from 8-11-82. It shows that the preparation of Cash statement and depositing of the cash in the area office was on the duty basis of the persons working in the second shift. It is further stated that the responsibility of depositing the cash would be with the staff of the second shift. This document has been criticised on behalf of the concerned workman as not having been circulated to the staff concerned as it does not bear the signature of any of the staff of the Sales Centre. With reference to Ext. M-13 which was another office order of the Sales Officer it was submitted on behalf of the workman that the said office order was circulated and as such the assistants available had signed on it and it was the practice of the office that the office order used to be shown to the Assistants and their signatures used to be obtained. It is true that the Office Order Ext. M-12 is not signed by any of the Assistants and as such the concerned workman may have the advantage of putting forward the said defence. But more important fact in respect of Ext. M-12 is that it was effective for only one month from 8-11-82 and as such even if the Assistants, were aware of this office order the said order had lost its force after the date of expiry of the said order. The management has not produced any other office order to show that the Sales Assistants of the 2nd shift working in the Sales Centre had to deposit the cash amount realised by them on the following day. I hold therefore that the management has not produced any document to show that at the relevant time it was the duty and concern of the concerned workman to deposit the cash amount realised at the Sales Centre on 24-1-83 and 25-1-83 in the area office on the following day.

In view of the discussion made above it will appear that the management has not adduced any evidence to show that it was the responsibility and concern of the concerned workman to deposit the cash amount of the Sales Centre in the area office on the next date of its realisation. I further hold that the concerned workman had deposited the amount of Rs. 18,891.44p and Rs. 7,890.39P. with the Peon Lalan Nonia on 24-1-83 and 25-1-83 respectively which he had realised as adjustment money from the customers. As the concerned workman had deposited the said amount with Lalan Nonia, he cannot be saddled with any charge of dishonesty and fraud of the management's cash.

It is the case of the management that even in the past the concerned workman used to deposit the amount collected by him after delay. The management has filed statement Ext. M-20 to show that the amount collected at the Sales Centre, Dhansar by the concerned workman were not deposited on the next day of the receipt of the money and that the same was deposited sometime thereafter. On perusal of Ext. M-20 it, no doubt, appears that the amount which had been collected by the concerned workman was not deposited on the next day but was deposited sometime thereafter. In this connection it will appear from the evidence in the case that although there were two or three persons in the Sales Centre who used to collect the money but all of them did not go individually to the area office to deposit the amount collected by each of them. Ext. M-19 is another statement of the amount of collection at Sales Centre Dhansar by Shri A. K. Dutta and it appears that he had also deposited the amount not on the due date but on some day thereafter. It will appear that even on 24-1-83 and 25-1-83 the amount was collected by Shri A. K. Dutta, the concerned workman had another person and according to the management the amount had to be deposited by the concerned workman. It is apparent therefore that only one of them was to deposit the amount in the area office. It has not been established that the amount shown in Ext. M-20 was actually deposited by the concerned workman or some other Sales Assistant of Dhansar Sales Centre at the area office and as such there is no evidence that the concerned workman was the person responsible for the late deposit of the amount shown in Ext. M-20. Ext. M-12 dated 9-11-82 will show that the Sales Officer Shri R. K. Sahay had ordered that he should get the receipt of draft and cash on daily basis but it appears that the Sales Officer was not strictly supervising the deposit of the amount of the Sales Centre at the area office otherwise there would not have been delay in the deposit of the amount on many dates. Shri R. K. Sahay himself stated in his statement before the E. O. in answer to question No. 62 that several times the amount of collection of centre was deposited two or four days after the receipt of the money. In accordance with Ext. M-12 it was the duty of the Sales Officer to see that the cash receipts were received by him everday so that he could check if the amount was deposited in time but it appears that the Sales Officer has kept silent over his part of the duty. It will also appear from the evidence of Shri R. K. Sahay himself that sometimes there were delay by him in signing the cash statement and as such there might have been delay in depositing the collected amount in the area office. Considering all the materials it appears that the delay of few days in depositing the amount was in the knowledge of the Sales Officer who was incharge of the Sales Centre and it had almost become a practice of depositing the amount after a few days of the collection on some occasions. No evidence has been adduced that the delay in the deposit of the amount was without any cause and as such it appears that the management has fallen heavily upon the concerned workman for delay in depositing the amount when he was being charged with the allegation of having misappropriated the amount of collection of 24-1-83 and 25-1-83. Although it is established that the amount collected at the Sales Centre by the concerned workman was deposited late in the area office, it has not been established that it was because of the concerned workman that the said amount had not been deposited in time. As such this charge also does not appear to have been established against the concerned workman. I hold therefore that the management had not adduced evidence to establish the charges and as such the findings of the enquiry officer appear to be perverse.

In the result, I hold that the action of the management of Kusunda Area No. VI of M/s. B.C.C. Ltd. in dismissing Shri N. K. Chouhan, Sales Assistant of Dhansar Sales Centre from service with effect from 26-1-83 is not justified and as such the concerned workman is entitled to be reinstated in service from the date of his dismissal i.e. from 26-11-83 with all back wages and consequential benefits.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer.

[No. L-20012(364)/84-D. III(A)]

A.V.S. SARMA, Desk Officer.

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1985

का. आ. 4539.—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उत्प्रवास संरक्षक, तिरुवेन्द्रम के कार्यालय में सहायक, श्री आर. श्रीनिवासन को 19 से 30 सितम्बर, 1985 तक उत्प्रवास संरक्षक, तिरुवेन्द्रम के सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[संख्या जैड-11025/29/85-एमई प्रेषण-II]

New Delhi, the 4th September, 1985

S.O. 4539.—In exercise of the powers conferred by Section 3, read with Section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorises Shri R. Srinivasan, Assistant in the Protector of Emigrants' Office, Trivandrum to perform all functions of Protector of Emigrants, Trivandrum with effect from 19-9-85 to 30-9-85.

[No. Z-11025/29/85-Emig. II]

का. आ. 4540.—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री ननतु सरकार, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, कलकत्ता को 23 सितम्बर से 25 सितम्बर, 1985 तक आवेदकों की उत्प्रवास हैसियत, अर्थात् "उत्प्रवास नहीं" के रूप में हैसियत का निर्धारण करने के लिए, उत्प्रवास संरक्षक के सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करती है।

[संख्या जैड-11025/29/85-एमई प्रेषण-II]

S.O. 4540.—In exercise of the powers conferred by Section 3, read with Section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorises Shri Nantu Sarkar, Regional Passport Officer, Calcutta to exercise all powers of Protector of Emigrants to decide the emigrant's status, viz, status as an "Not emigrant," of the applicant with effect from 23rd September to 25th September, 1985.

[No. Z-11025/29/85-Emig. II]

का. आ. 4541.—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते, हुए, केन्द्रीय सरकार, उत्प्रवास संरक्षक, कोचीन के कार्यालय में सहायक श्री के. एन. एस. नायर को 20 सितम्बर, से 26 सितम्बर, 1985 तक उत्प्रवास संरक्षक, कोचीन के सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[संख्या जैड-11025/29/85-एमई प्रेषण-II]

S.O. 4541.—In exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorities Shri K.N.S. Nair, Assistant in the Office of Protector of Emigrants, Cochin, to perform all functions of Protector of Emigrants, Cochin with effect from 20th September, to 26th September, 1985.

[No. Z-11025/29/85-Emig. II]

का. आ. 4542.—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उत्प्रवास संरक्षक, दिल्ली कार्यालय में सहायक श्री बृज मोहन को 23 सितम्बर, 1985 को उत्प्रवास संरक्षक, दिल्ली के सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[संख्या जैड-11025/29/85-एमई प्रेषण-II]

S.O. 4542.—In exercise of the powers conferred by Section 3, read with Section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorises Shri Brij Mohan, Assistant in the office of Protector of Emigrants, Delhi to perform all functions of Protector of Emigrants, Delhi on 23rd September, 1985.

[No. Z-11025/29/85-Emig. II]

का. आ. 4543.—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उत्प्रवास संरक्षक, मद्रास के कार्यालय में सहायक, श्री सुन्दर लाल को 20 सितम्बर से 26 सितम्बर, 1985 तक उत्प्रवास संरक्षक, मद्रास के सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[संख्या-जैड-11025/29/85-एमई प्रेषण-II]

S.O. 4543.—In exercise of the powers conferred by Section 3, read with Section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorise Shri Sunderlal, Assistant in the Office of Protector of Emigrants, Madras to perform all functions of Protector of Emigrants, Madras with effect from 20th September to 26th September, 1985.

[No. Z-11025/29/85-Emig. II]

का. आ. 4544.—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्रम मंत्रालय के उत्प्रवास विभाग में सहायक श्री बी. एस. मानिक को 23 और 24 सितम्बर, 1985 को उत्प्रवास संरक्षक, चंडीगढ़ के सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[संख्या जैड-11025/29/85-एमई प्रेषण-II]

अमित दास गुप्ता, अवर सचिव

S.O. 4544.—In exercise of the powers conferred by Section 3, read with Section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorises Shri B. S. Manik, Assistant in the Emigration Division, Ministry of Labour to perform all functions of Protector of Emigrants, Chandigarh on 23rd and 24th September, 1985.

[No. Z-11025/29/85-Emig. II]

AMIT DAS GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1985

का. आ. 4545—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय, श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या का. आ. 830 दिनांक 12 फरवरी, 1985 द्वारा तांबा खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 1985 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 1 अक्तूबर, 1985 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं. एस-11017/7/85-डी-I (ए)]

New Delhi, the 4th September, 1985

S.O. 4545.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. 830 dated 12th February, 1985 the Copper Mining Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 1st April, 1985;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from 1st October, 1985.

[No. S-11017|7|85-D.I(A).]

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1985

का. आ. 4546.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखण्ड (vi) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1074 दिनांक 22 फरवरी, 1985 द्वारा मेग्नेसाइट खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 7 मार्च, 1985 से छः मास की कालावधि के लिए उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 7 सितम्बर, 1985 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं. एस.-11017/8/85-डी-I (ए)]

New Delhi, the 5th September, 1985

S.O. 4546.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 1074 dated the 22nd February, 1985 the Magnesite Mining Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from 7th March, 1985;

And whereas the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 7th September, 1985.

[No. S-11017|8|85-D.I(A)]

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1985

का. आ. 4547.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33ग की उपधारा (2) के अधीन दायर किया गया आवेदन पत्र, जिसका उल्लेख इससे उपाबद्ध अनुसूची में किया गया है, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1973, तारीख 26 मई, 1977 में विनिर्दिष्ट, केन्द्रीय सरकार, श्रम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष लंबित पड़ा है।

और सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि उपरोक्त आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार श्रम न्यायालय, कानपुर के क्षेत्राधिकार के अन्दर उत्तर प्रदेश के राज्य से संबंधित है। इस न्यायालय का गठन श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचनाओं संख्या का. आ. 2029, तारीख 6 जून, 1984 और का. आ. 2212 तारीख 26 जून, 1984 द्वारा किया गया था;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33-ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त श्रम न्यायालय, नई दिल्ली से उक्त आवेदन पत्र के संबंध में कार्यवाहियों को वापस लेती है और उसे उक्त श्रम न्यायालय, कानपुर को अंतरित करती है और उक्त श्रम-न्यायालय, कानपुर उन कार्यवाहियों पर उसी प्रक्रम से कार्यवाही करेगा, जिस पर वह उसे स्थानांतरित की गई है और विधि के अनुसार उनका निपटान करेगा।

अनुसूची

केन्द्रीय सरकार श्रम न्यायालय, नई दिल्ली के पास लंबित पड़े उन मामलों की सूची जिसे केन्द्रीय सरकार, श्रम न्यायालय, कानपुर को स्थानांतरित किया जाना है

क्रमांक	श्रम न्यायालय आवेदन संख्या	मामला
1.	एल. सी. ए. संख्या 73/85	श्री प्रेम चन्द बनाम उत्तरी रेलवे.

[संख्या एस-11026/3/85-डी-I (ए)]
एस. एस. एस. अय्यर, अवर सचिव,

New Delhi, the 6th September, 1985

S.O. 4547.—Whereas the application filed under sub-section (2) of section 33C of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) mentioned in Schedule hereto annexed, is pending before the Central Govt. Labour Court, New Delhi, specified in the notification of the Ministry of Labour No. S.O. 1973 dated the 26th May, 1977;

And Whereas, it has been brought to the notice of the Government that the above application relates to the State of Uttar Pradesh within the jurisdiction of Central Government, Labour Court, Kanpur

constituted, vide notifications of the Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour, No. S.O. 2029 dated the 6th June, 1984 and S.O. No. 2212 dated the 26th June, 1984;

NOW therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 33-B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government here by withdraws the proceedings in relation to the said application from the said Labour Court New Delhi and transfers the same to the said Labour Court, Kanpur and the said Labour court, Kanpur shall proceed with the proceedings fromthe stage at which they are transferred to it and dispose the same in accordance with the law.

SCHEDULE

List of case pending with the Central Government Labour Court, New Delhi to be transferred to the Central Government Labour Court, Kanpur.

Serial No.	Labour Court Application No.	Case
1.	LCA No. 73/	Shri Prem Chand versus Northern Railway.

[No. S-11020/3/85-D.I.(A)]

S.H.S. IYER, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1985

का. आ. 4584.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1282 दिनांक 14 मार्च, 1985 द्वारा जिंक उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 19 मार्च, 1985 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 19 सितम्बर, 1985, से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[फा. संख्या एस-11017/9/85-डी-I(ए)(i)]

768 GI/85—27

New Delhi, the 13th September, 1985

S.O. 4548.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S. O. No. 1282 dated the 14th March, 1985, the Zinc Mining Industry to be a public utility service for a period of six months, from the 19th March, 1985;

And, whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 19th September, 1985.

[No. S-11017/9/85-D.I(A) (i)]

का. आ. 4549.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1281 दिनांक 14 मार्च, 1985 द्वारा सीसा उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 24 मार्च, 1985 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 24 सितम्बर, 1985 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[फा संख्या एस.-11017/9/85-डी.-I (ए) (ii)]

ण. ह. सु. अय्यर, अवर सचिव

S.O. 4549.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S. O. No. 1281 dated the 14th March, 1985 the Lead Mining Industry to be a public utility service for a period of six months, from the 24th March, 1985;

And, whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Governmnet hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 24th September, 1985.

[No. S-11017/9/85-D.I(A) iii)]

S.H.S. IYER, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1985

का. आ. 4550.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एक्जे क्यूटिव अफसर कैंटोनमेन्ट बोर्ड के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, के पंचाट को प्रकाशित करती है।

New Delhi, the 6th September, 1985

S.O. 4550.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur' in industrial dispute between the employees in relation to the Executive Officer, Cantonment Board, and Shri Kamal Nayan, Pandey, Ward Boy.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 15 of 1980

In the matter of dispute between :

Shri K. N. Pandey r|o J59|40 Factory Colony near Ganaghat Chungi Tagore Road, Kanpur.

AND

The Ministry of Defence, New Delhi.

PRESENT

Shri Mangallvadekar representative for the workman and Shri B.C. Tondon representative for the Management.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, Vide its notification No. L-12012(1)/79-D.II (B), dated 26th March, 1980, has referred the following dispute for adjudication:-

Whether the action of the Executive Officer, Cantonment Board, Kanpur in terminating the service of Shri K.N. Pande, Ward Boy with effect from 10-6-78 is fair, legal and just? If not, to what relief the workman is entitled?

It is common ground that the workman Shri K. N. Pandey joined as Ward Boy in the hospital of Cantonment Board and his service were terminated on 10-6-78. According to the management, the workman was appointed in the first instance for a period of one year only. In support of his contention he has filed the order of G.O.C. in chief central command dated 30-12-75 paper No. 7 of list filed by the Management on 23rd December, 0 whereby he had sanctioned temporary appointments of the ward boy for a period of one year only in the first instance. In pursuance of that post was offered for appointment and letter No. 6 of the above said list dated 19th June 76 intimating him that on the basis of his name having been sponsored from the employment exchange and subsequent interview, the workman was selected for temporary post of ward boy. He was offered to join within 3 days and intimated that his appointment would be purely temporary and his appointment is liable to be terminated at any time. The workman joined on 11-6-76 as ward boy in the hospital. It may be mentioned here that in this offer of appointment no time limit was ordered regarding service or date of termination is mentioned. The management issued a termination letter Ext. M-8 to the workman intimating that his services were no more required w.e.f. 10-6-77 and a copy of this letter is Ext. M-2. The management has further filed a letter from the medical officer inchonge addressed to GOC Chief Cantonment Board Kanpur intimating him that the workman has been released from the service from 9-6-77 afternoon. That letter is exhibit M-3. The management's another letter is Ext. M-4 dated 29-6-77 addressed to Shri K. N. Pandey is that in view of the sanction accorded by Central Command that the service as ward boy which further extended for another one year expiring on 10-6-77 and ultimately Ext M-5 dated 7-6-78 intimating the workman that his services were no more required with effect from 10-6-78.

On reference made by the President Cantonment Board, Kanpur, on 26th May, 77 i.e. before the expiry of term of one year of the workman lieutinent General G.O.C. Central Command intimated him vide paper Ext. M-6 dated 11-6-77 that as the ward boy was appointed on 11-6-77, the santcion will be expired on 10-6-77 and on 13-12-76 the sanction has been accorded for retention of the staff including the ward boy for a period of one year from the date of expiry from the previous sanction. Thus the sanction exists upto 10-6-78. The management has filed the attendance register of the cantonment civil hospital Kanpur for the month of June, 77 in which the workman has signed his attendance upto 6th June and on 7, 8 and 9 th June the workman is shown to be on election duty and there after, it is mentioned relieved from 9-7-77 afternoon. This attendance register is ext. M-7.

The case of the management is that from 7th June 77 he had proceeded on Home Guard Duty in the General Election and was not there on duty on 9th in the hospital to be relieved in the after noon. Further it is the case of the workman that he was never intimated that his services had been terminated w.e.f. 9-6-77 vide Ext. M-3 as mentioned in the said letter (Ext. M-3). It is also the case of the workman that he was never intimated about Ext. M-2 that his services will be no more required w.e.f. 10-6-77. It apears that the Executive Officer, Cantonment Board, Kanpur though original signing of ext. m-2 on 11-5-77 which original is paper No. 5 as per list dated 23-12-80 filed shows that on that very letter Cantonment Board Executive Officer approved this but put up a letter for G.O.C. Central Command enquiring about the extension. The workman's case is that as he had no information that his service were terminated on 9-6-77 after noon he was on official duty as Home Guard in the General Flection he continued in service till 10-6-78 out of termination by which time he had completed more than 240 days and as no notice or retrenchment compensation as required under section 25F was given to him, the termination is void abinitio and he will be deemed to be in continuing in service and would be entitled to all back wages with consequential benefits thereon.

The workman has also averred that after his termination 4 persons were appointed whose names are given in para 3 of the workman's affidavit para 3 which too infringes the provisions of sec. 25G and H as he was not called to work being senior to the workman who were working after the termination. The workman has filed Ext. W-1 alongwith his affidavit which shows that the workman was required to join election duty w.e.f. forenoon on 9-6-77 and reported back to duty on 25-6-77. Thus he will be deemed to be on duty from 7-6-77 to 25-6-77 unless proved that in between on 9-6-77 his services were terminated to his knowledge.

The counsel for the management has argued that the service of the workman were terminated on 9-6-77 and he was reappointed on 29-6-77. The workman/management witness Shri Ayub Khan affirmed that the workman was reappointed. The witness referred to the letter of reappointment as letter dated 29-6-77 ext. M-9 which speaks of extension of service for further period of one year Word extension used in the letter connotes continuous from existing service and not creation of new service or reappointment from 29th June 77 the date of the letter. The management witness in cross examination has admitted that the workman had again on election on 7-6-77 and he was sent by the management for the said election duty being required by the District Commandent Home guard. He further admitted that the management pays for the period an employee is required on election duty and in case in between that period the services comes to an end or breaks the management does not pay for the subsequent period. He voluntarily said that the workman was appoined on 29-6-77 but he was paid full salary for the month of June 1977. If he was out of service from 10-6-77 to 28-6-77, why was he paid for these period. This fact supports the contention that the workman that he continued in service and was not reappointed and was simply given a extension of one year. The services of the workman is in the nature of excess payment, as voluntarily said by the witness, in all about 20 days pay was paid to the workman. He had however, admitted that after realising that very payment was made, no demand has been made from the workman uptill now.

The workman admitted that in the original register of attendance dt. 5-6-77 attendance noted has been scored out and above it C.L. has been written and written and it is not signed by any officer. The workman in his cross examination has admitted that when he returned from the election duty in his atendence register word relieved was written but he did not consider it proper to raise any objection as he relieved from 7-6-77. He has further stated that he did not care to call office of the notice board as he was working in the hospital. When cross examined on the point on being gainfullly employed after 10-6-78 the workman stated that he did not try for employement nor he was gainfully employed any where during all that period. He specifically stated that he did not try for service as his case was pending. He has admitted that his wife has rickshaw licence and that she gets her rickshaw plied by drivers he maintains from the earning of her wife rickshaw. He has admitted that after 10-6-78 no ward boy was employed in the hospital and he has no knowledge if the post of ward boy has been abolished or not.

The management did not cross examined the workman on the point of receipt of any letter allegedly sent to the workman and relied by the workman. In view of these circuisrances the services of any of the letters proving workman being relieved from 9-6-77 and reappointing him on 29-6-77, it will be deemed that he continued in service without break as his election duty from 9-6-77 will be deemed duty. The worman though temporary having completed more than 240 days in the span fro m1J-6-76 to 10-6-78 and even during the period 29-6-77 to 10-6-78 and he should have been paid retrenchment compensation as required under section 25F and that having not been done, the termination which comes in the difiinition in the definition of retrenchment will be deemed illegal and inoperative in the absence of notice pay and retrenchment compensation.

The result is that the workman will be re employed with full back wages.

I, therefore, hold on the point of gain fully employment of the workman that the workman did not try for service as his case was pending and as his wife supported him from the earning by rickshaw plying, it can not be said that the workman was gainfully employed and he is consequently entitled to full back wages.

In the instant case it is established that the workman did not work elsewhere during the period he was out of service and appl the rulings te would entitled for back wages for the period he was out of employment.

I, accordingly hold that the action of the Executive Officer Cantonment Board, Kanpur in terminating the services of Shri K. N. Pandey is illegal, unjust and fair.

The result is that the workman will be deemed in continuous service and is entitled to reinstatement with full back wages.

I give my award accordingly.

Let six copies of this award be sent to the Government for publication.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
[No. 5-13012(1)/79-D.II (B)]
HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1985

का. आ. 4551—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, सिटी बैंक एन. ए. नई दिल्ली के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26 अगस्त, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 6th September, 1985

S.O. 4551.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Citi Bank N.A., New Delhi and their workmen, which was received by the Central Government on the 26th August, 1985.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL

NEW DELHI

I.D. No. 3/79

In the matter of dispute between : General Secretary, First National Citi Bank Staff Association, 3, Sansad Marg, New Delhi

Versus

The Management City Bank N.A, 3, Sansad Marg, New Delhi

APPEARANCES :

Shri S. K. Basaria for the workmen.

Shri J. K. Mehra Advocate for the Management.

AWARD

Central Government, Ministry of Labour on 18-1-79 vide Order No. L-12011/108/78-D.II.A made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the Management of Citibank (N.A.), New Delhi is justified in promoting Neena Suresh, Prem Seth, N. K. Khullar in supersession of their seniors in violation of the procedure laid down in promotion policy ? If not, to what relief the senior workmen are entitled ?"

The workmen pleaded that there was a mutually established promotion policy in the Citi Bank N.A. under which seniority list was maintained for every category and only senior-most person in the City irrespective of the department/section where he worked was to be given promotion. Clerks and Stenographers were grouped together and Head Clerks and Sepical Assistants had separate seniority list. The senior-most person in the City irrespective of Department/Section where he worked was said to be legally entitled for promotion in the Higher Category. This promotion policy was being followed since 1971 but the Management violated the promotion policy. Mrs. Neena Suresh working as Clerk-cum-Typist at No. 27 of Seniority List was appointed Special Assistant on 1-12-77 superseding 26 persons senior to her in the category of Clerks and Head Clerks including Mr. S. L. Aggarwal, Mr. S. S. Narula, Mrs. Vibha Dev and Mr. B. F. Bhatty, Mrs. Neena Suresh in being made Special Assistant bye-passed the seniors and she was promoted direct from Clerk to Special Assistant.

3. Prem Seth was Clerk-cum-Typist who was made Special Assistant on 15-12-77 superseding Mr. N. K. Nayyar and Mr. N. K. Khullar who were senior to him in the category of Clerks and Head Clerks (in order of seniority) S. L. Aggarwal, S. S. Narula Mrs. Vibha Dev, Mr. B. F. Bhatty and Prem Seth became Special Assistant from clerk i.e. two steps. Later N. K. Khullar, Clerk-cum-Typist was made Special Assistant on 1-4-78 ignoring rights of Senior-most Clerks named N. K. Nayyar and B. F. Bhatty.

4. The workmen referred to the promotion of S. L. Aggarwal, Mrs. Vibha Dev and S. S. Narula, Head Clerks to Special Assistant on 1-4-78, 1-4-78 and 10-1-78 respectively indicating that this involved supersession of Mr. B. F. Bhatty Senior-most Head Clerk working in the bank.

5. The workers Union claimed that B. F. Bhatty and N. K. Nayyar be promoted as Special Assistant retrospectively from the date of promotion of Neena Suresh, Prem Seth and N. K. Khullar and should be paid arrears of pay between Clerks and Special Assistants and the promotion of Neena Suresh, Prem Seth and N. K. Khullar be declared as illegal, unconstitutional and unjustified being against the promotion policy of the bank.

6. The Management of the City Bank N.A. contested the claim and asserted that the dispute referred to this Tribunal

was not maintainable because it was not an 'Industrial Dispute'. There was only one category of Clerks and they all continued to remain in the same cadre of workman enjoying clerical grade. There was said to be no mutually established promotion policy in the bank and a Clerk could be assigned additional duties Head Clerk and Special Assistants and these duties attract special allowance. It was said to be the Management's function to assign such additional duties to any suitable person and the assignment of special allowance duties could not be termed as 'promotion as both Head Clerks and special Assistantes continue to belong to the category of clerk all workmen. It was Management's prerogative to assign special allowance duties.

7. The matter has been tried. The Management filed the affidavit of Shri Rajeshwar Kumar, Assistant Manager who has been cross-examined by the workman. The workman examined Mr. K. L. Malhotra, President of the Union and Federation of employees. The workman filed documents. Written arguments of both the parties are on record.

8. During the pendency of this reference a complaint under section 33 (a) of the I.D. Act was made by Union of workman on 4-5-81 wherein it was pleaded that Mangement action violating the established service conditions deliberately and promoted S.C. Bhatia on 1-2-81, Ashok Bhasin on 14-4-81 and Ashok Saxena on 14-4-81 to the post of Special Assistant ignoring the principles of established policy of seniority and the eligible clerical cadre promotion to Special Assistant. That complaint was registered as ID 141/81.

9. The Management contested that complaint and asserted that the complaint could not be entertained and there was no contravention of Section 33 (a) of the I.D. Act and that it was purely a Management prerogative to assign allowance carrying position to any suitable person. This Award shall also deal with the complaint registered as I.D. 141/81.

10. The Annexures I and II with the claim statement indicate the promotion policy and the seniority list relied upon by the workman as under:—

"PROMOTION POLICY FOR CLERKS, HEAD CLERKS, TYPIST, STENOGRAPHERS AND SUBORDINATE STAFF

(a) A senioriy list will be kept up-to-date in each city separately for clerks, and head clerks. The clerical list will include all allowance positions other than head clerks and special assistants, such as audit clerks, accounting machine operators, etc. Special assistants include tellers who receive the special assistants' allowance.

1. (d) All staff members will have access tothese seniority and one of typists—will be maintained.

1. (c) For subordinate staff, two separate seniority lists will be maintained; one of head peons, and one of their subordinate staff.

1. (d) All staff members will have access to these seniority lists.

2. (a) Seniority will be determined as follows :

No. of years in FNCB plus 2 years for graduates and/or holders of National Diploma in Commerce.

plus 1 year for successfully completing part I of the CAIB/CAIIB Exam.

plus 1 year for successfully completing Part II of the CAIB/CAIIB Exam.

2.(b) Seniority will be counted from the date of joining FNCB service and the service should be uninterrupted. Where interruption has been because of the Second World War, Credit will be given for pre-war service as is being done at present.

3. When an HC position falls vacant, or a new HC position is created, the senior-most clerk will first be considered irrespective of the department in which the clerk is working. When an S.A. position falls vacant, or a new SA position is created, the senior most HC will be considered.

4. (a) Where the senior-most clerk/head clerk so considered qualifies he will be appointed HC/SA respectively. However, if in the assessment of the Management, the employee concerned is not qualified to hold the higher post because of previous consistent negative attitude to work and to the organisation, the next senior employee on the list will be considered for the vacancy, and unless he disqualified, the selection process will not proceed further down the seniority list.

4. (b) Management will share with the individual so disqualified the reasons for such a decision.

5. Management will use its discretion re-disqualification with the greatest of care. If the staff cooperate full with the staff development program, which includes inter-departmental transfers, participation in training programs, handling new assignments, etc., the possibility of any individual demonstrating a negative attitude to his present assignment or development will not ordinarily arise. The ability of Management to administer meaningfully a promotion policy for clerical ranks based largely on seniority is dependent on all employees involving themselves fully in the Bank's development programs so that they are prepared to effectively discharge their new duties. Without such development, promotion by seniority will result in deteriorating work effectiveness and management will have to revert to the earlier practice of selecting those who demonstrate interest in their growth.

6. When a vacancy occurs in clerical position typists stenographers will be first considered for a clerical position, based on seniority listing, provided they meet the requirements-educational, language, clerical test, and other of the new post. If not Typist|senographer qualifies, subordinate staff head peons be next considered, based on seniority listing, provided they meet the requirements—education, language, clerical test, and typing of the new post. If not subordinate staff-head peon qualifies, other subordinate staff will be considered, based on seniority, provided they meet the requirements-educational, language, clerical test, and typing of the new post.

Clause 4(a), 4(b) and 5 re-disqualification for higher posts spelt out earlier, are applicable here.

7. Typists and subordinate staff will be considered for stenographer's position where such a vacancy exists, based on seniority listing, provided the typist/subordinate staff meets the typing, language, and stenography requirements of the new post.

In considering subordinate staff, those on the head peon list will first be considered before moving down to other subordinate staff.

Clauses 4(a), 4(b), and 5 re-disqualification for higher posts, spelt out earlier, are applicable here.

8. Subordinate staff will be considered for typist's position where such a vacancy exists, based on seniority listing, provided the subordinate staff meets the educational and language requirements of the new post.

Clauses 4(a), 4(b) and 5 re-disqualification for higher posts spelt out earlier, are applicable here.

9. No individual can be forced to accept a promotion nor can he be forced to participate in development programs. However, refusal to accept a position or non-participation may disqualify the individual from being considered for another post or another vacancy.

10. No individual will receive more than one promotion within a two-year span.

11 In appointing individuals to senior clerical positions, it is vital that individuals and jobs are matched Management will use its discretion in making such placements to facilitate placements, management will plan these promotions half-yearly except in unforeseen circumstances.

12. Management full believes that with the active cooperation-involvement of the staff, an effective development program can be instituted which will make the administration of the above policy possible.

ANNEXURE 2

Seniority List as on ...-2-77

Head Clerks

Name	Date appointed as clerk-cum-Typist	Date Promoted Head Clerk
1. Mr. S.L. Aggarwal	1-5-69	12-2-74
2. Mr. S.S. Narula	20-6-69	18-2-74
3. Mrs. Vibha Dey	1-9-69	11-4-74
4. Mr. B.F. Bhatty	8-12-69	1?-6-74

Clerk-Cum-Typist

Name	Date Appointed	
1. Mr. N.K. Nayyar	12-1-63	
2. Mr. N.K. Khullar	14-3-69	
3. Mr. Prem Seth	16-4-70	
4. Mrs. P. Roy Chowdhary	4-6-70	
5. Mr. Ashok Narang	15-11-70	(Passed CAIIB Part I)
6. Mr. Tas... m Ahm..d	27-1-11	
7. Mr. Ashok Kapoor	25-3-71	
8. Mr. R.K. Gupta	8-4-7'	(Passed CAIIB Part I)
9. Mrs. V...na Dua	1-6-7'	
10. Mr. Prem Sharma	26-6-69	(Non Graduate)
11. Mr. C.M. Arora	5-9-69	(Non Graduate)
12. Mr. S.K. Ma..i	1- 1-7.	
13. Mr. Manmohan Gerowara	1-11-71	
14. Mrs. H. Nath	8-11-71	
15. Mr. R. Suresh	15-11-71	
16. Mr. Ramesh Anand	3-12-71	
17. Mr. Ashok Saxena	13-12-71	
18. Mr. C. Dutta	10-1-72	
19. Mr. J.L. Aneja	10-1-72	
20. Mrs. Abha Sar..hana	10-1-72	
21. Mr. H. C. Grover	10-1-72	
22. Mrs. Manju Junzja	16-?-72	
23. Mr. S.K. Tan..on	25-2-72	
24. Mr. V.K. R..hilla	13-3-82	
25. Mr. P.K. Khara	30-3-72	
26. Mr. C.P. Kapoor	3-4-72	
27. Mrs. Neena Suresh	18-7-72	
28. Mr. Ashok Bhasin	6-10-72	
29. Mr. I.M. Gupta	6-10-72	
30. Mrs. Vijay Chopra	11-12-72	
31. Mr. A.N. Tiwari	2-11-73	
32. Miss Rumjhum Nath	27-1-74	
33. Mrs. Madhu Sehgal	13-2-74	
34. Mrs. Sunita Bawa	13-2-74	
35. Mr. Daya Singh	11-4-74	
36. Mrs. Neena Saxena	10-4-74	
37. Mr. Vir Vikram	10-6-74	
38. Mr. Ashok Chowdhary	5-8-74	
39. Mr. Surinder Chopra	9-8-74	
40. Mr. [illegible] Malik	16-9-71	
41. Mr. R.P. Sharma	16-9-71	
42. Mr. U. Shankar	16-9-71	
43. Janak Abrol	[illegible]	

11. The Management case is that the policy of promotion was not finalised in 1970 and the Minutes of that meeting were circulated and the matter was still floating between the Management and the workmen and the bank never agreed to rest positioning of clerks on allowance carrying positions on the basis of seniority alone.

12. The matter is no longer resintegra. In I.D. 104/1980 between the parties the question related to ignoring of claims of Shri P. Balasubramaniam and B. P. Malik and promotion of junior B. K. Malhotra to the post of Authorised Signer and in my Award dated August 7, 1985 I referred to the Minutes of the meeting relating to promotion policy dated 22-3-73 in paras 7 and 8 of my Award as under :—

"7. The only agreed-upon Minutes in respect of promotion policy are the Minutes of Meeting with PNCB Staff Association Executive Committee on March 22, 1973 wherein Mr. L. S. Bencari, G.M., Mr. J. J. Menezes, P.M. and Mr. Viney Sawhney, AS were present for the Management. Mr. K. L. Malhotra, Mr. K. L. Seth, Mr. H. K. Khera, Mr. P. Balasubramaniam, Mr. R. C. Gupta, Mr. J. M. Nigam and Mr. C. P. Kapur were present for the workmen.

8. Para 15 of the Miniutes requires to be extracted and is as under :—

"(15) OFFICIATING ALLOWANCE POSITIONS-CLERICAL AND OFFICIAL

Mr. Malhotra reiterated that the senior most person in the department should be paid officiating allowance as far as possible so that the employee concerned was able to benefit. He enphasized that the senior most employees in the same department should officiate in case the officer was on leave and he be paid the officiating allowance as per the Bipartite. Settlement Mr. Bencari stated that as far as the clerical positions were concerned it was his understanding that the same practice was being followed in New Delhi but in case of official positions the employee should become eligible for officiating allowance only if the strictly performed official functions. According to him no employee could automatically claim allowance for his officer who was on leave."

13. It was observed by me in para 9 of that Award that the Management in para 15 aforesaid clearly indicated that in case of clerical cadre officiating allowance post seniority alone was considered at Delhi but the same could not be accepted in relation to promotion to officer-cadre, and seniority alone could not be the basis for promotion to officer-cadre.

14. There appears to be semantic confusion between the parties even though the language used is English by both the parties. The Management believes in policy of hire and fire and no work no pay and Management power to manage affairs in any manner subject only to Law, Awards, Bank settlements. The employees on the other hand believe in convention order understanding and further believe in predictability and certainty in the matter of their conditions of service and everything is interpretted by the parties in the context of their pre-conceived notions aforesaid.

15. The Management undoubtedly considers seniority and maintains list of seniority in the clerical cadre it does not recognise Special Assistants and Head Clerks to be separate cadres from that of Clerks and does not accept Head Clerks and Special Assistants as categories apart. In my opinion, the Management cannot have it both ways. If Special Assistants and Head Clerks do not form a category apart from Clerks and are not sub-cadres in the Clerical Cadre, the Management maintaining seniority lists has to give efficiating chance to the senior-most person unless he is unfit so long as the working is in the clerical cadre itself but no employee could automatically claim promotion to officer-cadre.

16. In the reference I.D. 104/80 the right of the Management to create a Special cadre of SSRPs intermediate between the Clerkts and Officers was upheld and promotion to that intermediate cadre was accepted on selection basis but it is impossible to accept the idea that within the clerical cadre which includes allowance carrying position of Head Clerks and Special Assistants that seniority is meaningless and that the Management can assign these allowance carrying functions to anyone it likes. I hold that by convention, agreement and practice the Management accepted the policy of considering seniority in clerical cadre for these allowance carrying positions and it is not the case that the persons seniors to Mrs. Neena Suresh, Prem Seth and Mr. N .K. Khullar were unfit for doing the work of Special Assistant in the clerical cadre to enable them to have the Special Assistant allowance.

17. Similar is the case with the allowance carrying post being given to S.C. Dutta, Ashok Bhasin and Ashok Saxena on 1-2-81 and 14-4-81. I hold that the senior persons in the clerical cadre were wrongly ignored and when not found wanting had to be given the allowance carrying positions of Special Assistants which were given to their juniors.

18. However in the matter of actual grant of relief it is to be seen that these persons who actually worked and get special assistant allowance should not be denied the advantage conferred on them when they actually worked in those positions. A relief to be given to the senior-most persons who would have been appointed will be the grant of monetary benefits as if he had been given the allowance carrying special assistant position for the period in question.

19. A reference may be made to the memorandum of settlement dated 17-9-84 between the Management of 55-A Clase Banks and the All India Bank Employees and National Confederation of Bank Employees where in relation to filling of the post of special assistants it is indicated that suitability will be determained in member banks having the post of special assistant by interview of senior employees with weighaage of qualification and that written test system if in existence may continue and that such suitability may be tested on the basis of interview with a period of probation for 6 months.

20. It may be clerified that this settlement of 17-9-84 is prospective and applies with full force to the period from which it operates but this is on the basis of treating special assistants as a separate category of employees, on promotion from the clerical cadre and that could always have been done if the Management had the view that special assistants were a category apart and were holding promotion post but the Management of Citi Bank always argued and urged that Special Assistants were not a specific cadre or sub-cadre but merely held allowance carrying positions the workmen shall also have Rs. 500/- as costs of this reference from the Management.

Further it is ordered that requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

August 16, 1985

O.P. SINGLA, Presiding Officer

[No. L-12011/108/78-D. II(A) D IV(A)]

K.J. DYVA PRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1985

का० आ० 4552.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, बंबई पत्तन न्यास के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं. 1 बंबई के पंचाट को प्रकाशित करती है।

New Delhi, the 9th September, 1985

S.O. 4552.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Trustees of the Port of Bombay and their workmen.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I BOMBAY

Reference No. CGIT-1 of 1985

PARTIES :

Employers in relation to the Trustees of the Port of Bombay.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the employer—Mr. Parekh, Advocate.

For the workmen—Mr. Kelkar, representative for the Union.

INDUSTRY : Ports and Docks STATE : Maharashtra

Bombay, the 12th day of July, 1985

AWARD

This is a reference under Section 10 sub-section 2 of the Industrial Dispute Act, where the parties agreed to make a reference to this Tribunal and the terms of reference were also specified. These terms are as below :—

"Having regard to the nature of duties of the Crew of the Harbour Flotilla and the Docks Flotilla of the Port Department of the B.P.T. and the system of posting the crew prevalent in the said flotillas, is the demand that the special allowance of Rs. 8 per month granted to the Crew of the Harbour Flotilla in terms of the settlements arrived in the course of conciliation proceedings dated 5th October 1981 and 14th January, 1984 should be raised and brought on part with the rate of caisson allowance of the crew of the Docks flotilla justified ? If so, from what date and on what conditions should the enhanced rate be made effective ?"

2. It will thus be seen that the claim is for Harbour Flotilla crew for grant of an allowance which is being granted and paid to the Dock Flotilla crew. There appears to be in the docks, crew considered under two broad divisions, the Harbour Flotilla crew and Dock Flotilla crew, though both of them are engaged in more or less the same kind of work and mann floating crafts of the Port Trust.

3. The Bombay Port Trust Flotilla Workers Association filed a statement of claim setting out the agreed terms of reference. It said that both these divisions work under the Deputy Conservator and have "a common cadre right from the lower post to the highest post in class-III and IV cadre". A majority of workers are "topas, Bhandary, Lascar, Greaser and Scrumy" and they have a common seniority for non-certificate holders occupations and also for certificate holder posts. In the case of occupations requiring a certificate, the seniority is based on the date of the grant of certificate, and not the date of entry. It was also stated during the hearing that the crew is interchangeable.

4. According to the union, these workmen of the Dock Flotilla section were being paid a special allowance as they are required to do extra duty than normal duty. Even with regard to the Harbour Flotilla crew, it was their contention that they were also required to perform several duties beyond their duty list and therefore contended that they were justified in claiming this special allowance. This special allowance, they say is on account of the various duties required to be performed beyond the duty lists.

5. The Port Trust raised a preliminary contention that the reference was not maintainable in view of the fact that a valid and subsisting agreement between the concerned workmen and the employer was existing. When the said agreement was entered into on the 11th April 1984 between the four main Federations and the Government of India in Ministry of Shipping, by which certain allowances were granted, pursuant to clause 25 of the settlement, the employees had agreed that "no demand relating to any matters covered by the current and previous wage settlements" will be raised by the Federations or their affiliates for receipt of any benefit under the settlement, except as specified either in the settlement or which were already under adjudication, arbitration or Government decision. The second contention was with regard to the non-termination of the settlement dated 5th October, 1981. That settlement, according to the Port Trust was to be in force for a period of 3 years and was not terminated, and is valid and subsisting. On merits, its contention is that the Flotilla crew of the employer is generally designated in two groups, Harbour Flotilla and Dock Flotilla. The Harbour Flotilla operate vessels in the Harbour. Where as the dock flotilla operate vessels inside the Dock basins and in the channels leading to the docks and near Harbour Wall berths. It then referred to the Caisson Allowance, which was also referred to by the union, but which I do not think is necessary to be referred to at all or is relevant. It then pointed out that by the settlement dated 5th October, 1981, a special pay of Rs. 8 p.m. was paid to Class-III and IV crew of Pilot and Mooring Launches. That during the subsistence of that settlement, a charter of demand was served and a flash strike was resorted to on 13-1-1984, when the

settlement of 14th of January, 1984 was arrived at. The allowance for the entire flotilla crew was agreed because, the employer says, it was presurised to do so. Besides, it is pointed out that the harbour flotilla crew are in receipt of Rs. 6 p.m. as maintenance allowance over and above the Rs. 8 special allowance. This was payable to Laskars, who constitute "a very large section of the Crew in both the Harbour and Dock Flotillas."

6. The Port Trust contended that it was not ture, that the Harbour Flotilla crew performed any duties beyond their duty list or for that reason they are entitled to any special allowance. Therefore, according to it, there was no justification.

7. Both sides did not lead any oral evidence, but argued the case on the basis of the statement of claim and written statement and whatever also was produce. It will be apparent from what is contended by the union and what is not disputed by the Port Trust is that whereas the dock flotilla crew is in enjoyment of an allowance, which at present stands at the figure of Rs. 22, the Harbour flotilla crew gets an allowance of Rs. 8 which was subsequeutly raised to Rs. 9 and laskars among them get an additional Rs. 6 as maintenance allowance, which in all makes Rs. 15.

8. What is however, quite clear is that these workmen belong to the same department having common seniority, and it was not disputed were interchangeable. In other words, persons from the Dock flotilla can be transferred to the Harbour flotilla and vice-versa. For all purposes they were held on par, may be for promotion or for any other consideration arising out of seniority. Whatever may be the historical reasons for introduction of Caisson Allowance, the reasons why special allowance is being paid to the dock flotilla crew is not discernible or clear from the contention advanced by the union or justifications submitted by the Port Trust. The union has claimed that allowance is granted for doing extra duty or work over and above the duty list, which both the Harbour flotilla as well as the Dock flotilla crew is doing. That is denied by the Port Trust. In other words, therefore, both the Dock Flotilla and Harbour Flotilla crew are doing their duties. In the circumstances, it is not clear for what reason the Dock flotilla crew alone is getting a special allowance while the Harbour flotilla crew is not. There does not appear to be any reasonable, patent or discernible cause for not granting and not treating equally the Harbour flotilla crew, which otherwise similarly stand. No distinction has been shown in their duty. If they are, therefore, interchangeable, then it is better that this difference disappears. It would, therefore, be proper to grant the same allowance to the Harbour Flotilla crew which is also granted to the Dock Flotilla, in other words, Rs. 22 including all allowances. This is made clear that no extra allowance of Rs. 6 for maintenance which is granted to Laskars will therefore be available and the grant of Rs. 22 would be all inclusive.

9. As far as the preliminary contentions raised regarding the maintainability of the reference for reasons of the bar of 1984 settlement and the 1981 settlement, the Port Trust having agreed to make the reference under Section 10(2) it is difficult to see how this contention can be pressed. Beyond raising it, though undoubtedly a question of law and facts particularly with regard to the 1981 settlement no further contentions were raised or pressed.

10. Award accordingly.

R. D. TULPULE, Presiding Officer

[No. L-31013/4/84-D. IV (A)]

K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1985

का०आ० 4553.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सिंगरेनी कौलरीज कम्पनी लि० मन्डामरी डिविजन के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है।

New Delhi, the 6th September, 1985

S.O. 4553.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Hyderabad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri Division and their workmen.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

BETWEEN

The Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri Division, Adilabad District (A.P.)

AND

The Management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri Division, Adilabad District (A.P.)

APPEARANCES :

None—for the Workmen.

Sarvasri K. Srinivasa Murthy, H. K. Saigal and Kumari G. Sudha, Advocates—for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-22012/32/84-D.III (B) dated 12-12-1984 referred the following dispute under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri Division and their Workmen, to this Tribunal for adjudication.

"Whether the demand of Tandur Coal Mines Labour Union for confirmation of Shri Vydula Laxma Reddy, Badli worker in K. K. 5A Incline, with retrospective effect from 1-7-1983 is justified ? If so, to what relief is the workmen concerned entitled ?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 105 of 1984 and notices were issued to both the parties.

2. The claims statement was filed by the workmen on 3-1-1985 and for Vakalat and Counter of the Management posted to 27-2-1985. On 27-2-1985 the Management filed their Vakalat and Counter. Workmen and their representative called absent. For enquiry it was posted on 28-3-1985. From 28-3-1985 onwards the workmen and their representative called absent till 9-7-1985. Inspite of giving several adjournments the workmen and their representative did not contest their case. Hence I find that the workmen are not interested in proceeding with the case for the reasons best known to themselves, the reference is terminated and award is passed accordingly.

Award passed.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him, corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 9th day of July, 1985.

Sd/-

Industrial Tribunal

Appendix of Evidence

NIL.

Dated : 16-7-1985.

J. VENUGOPALA RAO, Presiding Officer

[No. L-22012/32/84-D.III (B)]

SHASHI BHUSHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 सितम्बर 1985

का. आ. 4554.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार वैस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की मोहन कोयलरी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, 2, बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28 अगस्त, 1985 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 13th September, 1985

S.O. 4554.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Mohan Colliery of M/s. Western Coalfields Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 28th August, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 2 BOMBAY

Reference No. CGIT-2/20 of 1985

PARTIES :

Employers in Relation to the Management of Mohan Colliery of Western Coalfields Limited Kanhan Area

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri P. S. Nair, Advocate.

For the Workmen.—Shri S. P. Singh, General Secretary Bharatiya Koyla Khadan Karamchari Sangh.

INDUSTRY : Coal Mines State : Madhya Pradesh

Bombay, dated the 14th August, 1985

AWARD

By their order No. L-22011/18/82-D.III (B) dated 24-8-1983 the following dispute was referred to the Central Government Industrial Tribunal at Jabalpur which was subsequently ordered to be transferred to this Tribunal by order No. S-11025(1)/85-D.IV(B) dated 8-2-1985 :—

"Whether the action of the management of Western Coalfields Ltd., Kanhan Area in relation to their Mohan Colliery in keeping Shri Laxmi Prasad in clerical Grade III is justified ?"

"Whether the action of the management of Western Coalfields Ltd., Kanhan Area in relation to their Mohan Colliery in stopping Shri Sukhlal S/o Shri Devi Din from work in February, 1980, is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. Although it is a common reference, it deals with two subject matters which in fact are not linked with each other. The employer however being the same namely Western Coalfields Limited, Kanhan Area, this might be the reason why there is amalgamation of the two disputes.

3. The first part of the order of reference relates to non-promotion of the workman namely Shri Laxmi Prasad to Clerical Grade II. The contention of the Union who is espousing the cause of the workman is that Shri Laxmi Prasad is engaged in the Stores to work as Store Keeper/Clerk in Mohan Colliery where he is required to maintain records of issue and receipts of the materials for the mine working in the prescribed register. It is stated that the job is covered under Recommendation of Central Wage Board NCWA II in the Clerical Staff grade nomenclature and appendix VI on page 54 as Store Keeper and Store Clerk. It seems that the workman is working since 1978. On 9-7-1978 a charter of demands was submitted by the Union in which one of the demands was that Shri Laxmi Prasad be given second grade and after discussions, it is alleged, the management had agreed accordingly. The grievance of the workman is that in spite of this assurance Grade II was not given to the workman and he still serves as Clerk Grade II. This has led to the present dispute.

4. Shri Sukhlal S/o Shri Devi Din, according to the Union was employed by the management as Departmental piece Rated in group IV from 6-2-1979 to stak|remove the loose blasted stone to a place specified by the management. It is urged that the job was regular perennial and permanent and that it shill exists. The Union contends that although the workman was employed from 6-2-1979 till 20-2-1980 when he was stopped from work and although the management employed 32 new hands thereafter no employment was given to Shri Sukhlal which amounts to anything other than exploitation and hence the relief as claimed.

5. In the case of the first workman namely Shri Laxmi Prasad the facts are not much in dispute. However, it is the plea of the maangement that when the mangement agreed to give him promotion to Grade II, he was asked to work as Reliever Attendance Clerk which the workman refused to do as a result of his refusal he still continues to work as Issue Clerk in Grade III and there remains no question of granting him promotion.

6. Regarding Shri Sukhlal S/o Shri Devi Din the management denies to have stopped him from work. It is the contention of the management that in the year 1980 he worked for 12 days in the month of January and 8 days in the month of February and thereafter he never reported for duty nor was he available for work. It is further urged that since the name of the workman was never sponsored by the Employment Exchange he has no right for employment.

7. In the light of the above pleadings the following issues arise for determination and my findings thereon are :—

Issues	Findings
1. Whether the action of the management of W.C.L. Kanhan Area in relation to their Mohan Colliery in keeping Shri Laxmi Prasad in Clerical Grade III is justified	Yes
2. Whether the action of the management of W.C.L. Kanhan Area in relation to their Mohan Colliery in stopping Shri Sukhlal S/o Shri Devi Din from work in February 1980 is justified?	No
3. If not relief and costs ?	As per order.

REASONS

8. The fact that the management had agreed to promote Shri Laxmi Prasad to the clerical grade II as per the demands of the Union and as per the discussions stands undisputed. The management has brought on record the agenda as per the demands dated 9-7-1978 and also the assurance given by the managament to promote the workman. In view of this assurance normally there should not have been any hitch but the very record indicates that when he was offered a job in clerical grade II as a Reliever Attendance Clerk the workman refused to accept the posting on the ground that he wanted to continue in the same post. When the workman wanted promotion and wanted to be placed in the clerical grade II, he should not have insisted upon a particular post in the grade and should have agreed to accept the offer which he failed to do. Consequently by his refusal to work as Reliever Attendance Clerk the management is absolved of the responsibility to promote him to Clerical Grade II as per the assurance given to the Union when the workman could never have insisted upon to continue in the same post and at the same time demanded promotion as per assurance. The result is that non-promotion is the consequences of the act of the workman himself for which he has himself to be blamed and no action can lie against the management who had committed no fault. Therefore the workman Shri Laxmi Prasad is not entitled to any relief.

9. In the case of Shri Sukhlal S|o Shri Devi Din, the termination if is in the nature of retrenchment, he would be entitled to relief, only if it attracts Section 25F read with Section 25B of the Industrial Disputes Act. Admittedly the workman joined the service on 6-2-1979 and according to him he was retrenched from service on 20-2-1980 during which period he was working for 4 or 5 days in a week. Against this the case of the management is that he has not worked more than 10 or 12 days during the relevant period but they have not produced any record nor there is any evidence of person supervising the work etc. There is therefore no reason why the word of the workman should be disbelieved particularly when the evidence is that the work continued and the management was in need of workers to perform the work. It is contended that it was not the management who stopped the workman from working but it was the workman himself who failed to attend to his work. However, in the light of the order of reference where the fact that the management stopped the workman from working is presumed, the plea of the management would be unacceptable and once we hold that the workman was doing underground work in the mine as stated by him and he was working four or five days in a week as Departmental Piecerated worker from 6-2-1979 to 17-2-1980, all the requirements under Section 25B of the Act namely the work for more than 190 days during the period of one calendar year before 17-2-1980 and absence of procedure under Section 25F of the Act are established and the workman would be entitled to the relief prayed for. Once the service is admitted, it was the duty of the management to produce the records showing that the workman had not put in more than 190 days during the relevant calendar year which they failed to do.

10. It is stated that the workman has no right to continue because he was not sponsored by the Employment Exchange. No doubt its true that the name of the candidate has to be sponsored by the Employment Exchange but if the workman is found to be fulfilling he terms of Section 25B read with Section 25F of the Industrial Disputes Act non-sponsoring by the Employment Exchange cannot curtail his rights. The management should have insisted upon the sponsoring by the Employment Exchange at the inception when he was asked to work as casual labourer but that time they did not insist upon such requirements and now therefore they cannot take shelter of non-sponsoring by the Employment Exchange. The workman therefore since Section 25F is not complied with and since it amounts to termination-cum-retrenchment is entitled to all the relief namely reinsattement with full back wages.

Award accordingly.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer

[No. L-22011|18|82-D.III (B)]

का. आ. 4555.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्ज इण्डस्ट्रीयल डैवलपमैन्ट कॉर्पोरेशन लि. के श्री पी. के. जैना रेजिंग कान्ट्रेक्टर ऑफ डुन्गरी लाइमस्टोन माइन्ज के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, भुवनेश्वर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28 अगस्त, 1985 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 4555.—In pursuance of section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Bhubaneswar, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Shri P. K. Jena Raising Contractor of Dungri Limestone Mines of M|s. Industrial Development Corporation of Orissa Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 28th August, 1985

INDUSTRIAL TRIBUNAL, BHUBANESWAR

BETWEEN

The employer in relation to the management of Shri P.K. Jena, Raising Contractor of Dungri Limistone Mines, At|P.O. Dungri Rist, Sambalpur (Orissa).

AND

Their workmen Second Party

APPEARANCES :

Shri G. Pujari, Advocate. For the first party

Shri K.C. Dev Sharma, Authorised representative. For the Second party

AWARD

Dispute referred to by the Central Government for adjudication under Section 7-A read with Sub-section (1) of Section 33-B of the Industrial Disputes Act, 1947, vide Notification No. L-29012|3|77-D. III (B) dated 18-2-1984 of the Ministry of Labour & Rehabilitation, Department of Labour, reads thus :

"Whether the action of Shri P.K. Jena, Raising Contractor of Dungri Limestone Mines of Messrs Industrial Development Corporation of Orissa Ltd. in dismissing his following workmen on different dates in 1973 was justified? If not to what relief are the workmen concerned entitled?

S. No Name

1. S|Shri Benedik Tete
2. " Johani Tate
3. Kulabati
4. Kalement Dung Dung
5. Holyani Kulu
6. Turlain Badaik
7. Lorence Belong
8. Miriam Belong"

2. It is not in dispute and is admitted by both the parties that the second-party workmen, eight in number, were working under the first-party in the Lime Stone Mines at Dungri for some time. The case of the first-party management is that the second-party workmen Johani Tate, Lorence Belong and Miriam Belong worked from 20-5-1973 and the rest from 14-10-1973 and of them, Banedik Tete, Johani Tate, Kalement Dung Dung, Holyani Kulu, Turlain Badaik and Lorence Belong absented themselves from duty unauthorisedly with effect from 8-11-1973 and the rest two, viz., Kulabati and Mirliam Belong from 11-11-1973 for which letters were issued to them under certificate of posting directing to submit their explanations for unauthorised absence and to resume their duties forthwith, failing which their names were to be struck off. Since no response was made to the aforesaid letters, letters were issued afresh directing the workers to resume their duties forthwith, but it was of no effect, and as a result, their names were struck of with effect from 10-12-1973. On the other hand, the case of the second-party workmen is that they started working under the first-party from 1972 and not from 1973. Their further case is that they having demanded payment of wages as per the provisions of the Minimum Wages Act, employment was refused to them with effect from 16-12-1983 (figure '83' appears to be a mistake for '73'). Such being the rival pleadings of the parties, the only question that arises for consideration in this case is whether it is a case of voluntary abandonment of service or a case of refusal of employment.

3. None was examined for the second-party workmen. The first-party examined its Manager who exhibited the copies of the relevant letters issued to the second-party workmen vide Exts. A to A|7, Exts. B to B|2, Exts. C to C|7 and Exts. D to D|2 to lend support to his statement that the second-party workmen Benedik Tete, Johani Tate, Kalement Dungdung, Holyani Kulu, Turlain Badaik and Lorence Belong absented themselves from duty unauthorisedly form 8-11-1973 and the rest two, viz. Kulabati and Mariam

Belong from 11-11-1973 for which twice letters were issued under certificate of posting directing them to submit their explanations for their unauthorised absence and to resume their duties forthwith, and that there being no response made to the letters, their names were struck off with effect form 10-12-1973. This evidence is not challenged inasmuch as not a single question is asked in cross-examination regarding the receipt or non-receipt of the aforesaid letters by the workmen. Not a single question is also put and no evidence is aduced to show that these workers worked from 1972 till 16-12-1983. All that is asked in cross-examination is regarding the non-payment of wages as per the provisions of the Minimum Wages Act. To this, the reply of the Manager is in the negative. Such being the reply and there being nothing on record to show that the workers worked from 1972 till 16-12-1983, and taking into consideration the evidence of the Manager which is supported by Exts. A, B, C and D series, I am of the view that it is not a case of refusal of employment but a case of voluntary abandonment of service, particularly when this view of mine finds support from the failure report wherein mention is made that at the time of conciliation the workers refused to work under the contractor. Such being my finding, the reference has to be answered in the affirmative.

4. In the result, the action of Shri P. K. Jena Raising Contractor of Dungari Limestone Mines of Messrs Industrial Development Corporation of Orissa Ltd. in terminating the services of the workmen S|Shri Banedik Tete, Johani Tate, Kulabati, Kalement Dung Dung, Holyani Kulu, Tarlain Badaik, Lorence Belong and Miriam Belong on different dates in 1973 was justified.

5. Award is passed accordingly.

K. C. RATH, Presiding Officer
[No. L-29012|3|77-D. III (B)]
SHASHI BHUSHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1985

शुद्धि-पत्र

का०आ० 4556—भारत के राजपत्र में पृष्ठ 2633 पर का०आ० संख्या 2221, तारीख 18-5-1985 के अधीन प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के तारीख 3 मई, 1985 के आदेश सं०-एल-51037/2/83-आई०एंड ई० (एस०एस०) के पैरा एक की आठवीं पंक्ति में "बंगलौर" के स्थान पर "बम्बई" पढ़ा जाए।

[एल०-51037/2/83-आई एंड ई० (एस० एस०)]
अशोक गुप्त, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 9th September, 1985

CORRIGENDUM

S.O. 4556.—The last word of paragraph one of the Government of India, Ministry of Labour Order No. L-51037/2/83-I&E(SS) dated the 3rd May, 1985 published in the Gazette of India dated 18-5-1985 under S.O. No. 2221 at page 2634, may be read as "Bombay" in place of "Bangalore."

[No. L-51037|2|83-I&E (SS)]
ASOK GUPTA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1985

का० आ० 4557—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार महाकालि कोलियरि, वेस्टर्न कोलफिल्डस लि० के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, सं० 2, बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28 अगस्त, 85 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 9th September, 1985

S.O. 4557.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Mahakali Colliery of Western Coalfields Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 28th August, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/49 of 1985

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Mahakali Colliery, Sub-Area No. IV of Western Coalfields Limited.

AND

Their Workmen.

INDUSTRY : Coal Fields STATE : Maharashtra

Bombay, the 7th August, 1985

AWARD

(Dictated in the Open Court)

By their Order No. L-22012(44)/84-D.V dated 19-6-1985 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

"Whether the management of M/s. Western Coalfields Limited, Wardha Valley Area, in respect of Mahakali Colliery, Sub-Area No. 6 at Chandrapur (M.S.) is justified in terminating the services with effect from 8-1-1984 of the two workmen namely Shri Maikal Kondaya, Loader and Shri Ram Chandra Babaya, Hookman ? If not, to what relief the said workmen are entitled ?"

2. It seems that the termination of service with effect from 8-1-1984 of the two workmen in question gave rise to the present controversy. However on receipt of the order of reference both the parties have settled the dispute the terms of which have been incorporated in the precipe filed under the signature of both parties. In pursuance of the settlement they are requesting to pass the award accordingly. Since the parties admitted the voluntariness of the settlement and also as the terms are reasonable and fair, there should not be any objection to pass award.

3. It is therefore directed that the two workmen namely S|Shri Maikal Kondaya, Loader and Ram Chandra Babaya, Hookman shall be re-employed by the management within 10 days of the Award of the Tribunal. This is without back wages. There shall be no liability of any payment from 8-1-1984 till the date of re-employment. However the management agrees to give continuity of service to these workmen. There shall be no other claim whatsoever by either parties in this regard.

Award accordingly.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer
[No. L-22012(44)/84-D. (V)]
R. K. GUPTA, Desk Officer

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1985

का. आ. 4558—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार प नार्थ टिसरा कोलियरी लोडना लोस मैसर्स बी. सी. सी. एल., धनबाद के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 4.9.85 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 12th September, 1985

S.O. 4558.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of North Tisra Colliery, Lodna Area of M|s. Bharat Coking Coal Ltd., Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th September, 1985.

PRESENT :

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer.

Reference No. 51 of 1984

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I. D. Act., 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of North Tisra Colliery, Lodna Area of M|s. BCCL, Dhanbad and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers : Shri S. K. Singh, Personnel Manager, Lodna Area.

On behalf of the workmen : Shri H. N. Singh, General Secretary, Koyala Ispat Mazdoor Panchayat, Jharia.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 29th August, 1985

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-24012(11)|84-D.IV(B) dated the 3rd August, 1984.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of North Tisra Colliery, Lodna Area of M|s. BCCL, Dhanbad in retiring Sri Rabi Lochan Chatterjee, Store Issue Clerk from services with effect from 18-12-1982 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

Soon after the receipt of the order of reference notices were duly served upon the parties. Both the parties appeared and filed their W. S. documents etc. The case proceeded along with its course. Thereafter a few adjournments were granted to the parties for filling Settlement. Ultimately on 30-7-85 both the parties appeared before me and filed a memorandum of settlement. I have gone through the terms of settlement which appears to be fair and proper and beneficial to both the parties. Accordingly I accept the same and pass an Award in terms of the settlement which forms part of the Award as Annexure.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-24012(11)/84-D.IV(B)]

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, DHANBAD

Ref. No. 51|84

Employers in relation to the management of North Tisra Colliery

and

Their workmen.

PETITION OF COMPROMISE

The humble petition on behalf of the parties to the above reference most respectfully shewth :—

1. That the parties above-named have amicably settled the dispute on the following terms and conditions :

TERMS OF SETTLEMENT

(a) That Shri Rabilochan Chatterjee, Ex. Store Clerk, North Tisra Colliery will be referred to Apex Medical Board of assessment of his age immediately.

(b) The age assessed by the above Board shall be binding on both-workman|concerned Union and Management.

(c) That Shri Rabilochan Chatterjee will be allowed to join his duties if his age is assessed less than the age of superannuation i.e., 60 years.

(d) That in case of gap found in between the date on which the above workman was superannuated or will be superannuated and the age decided by the above Board he shall be entitled to get 50 per cent of the wages for intervening period, wages shall include proportionate attendance bonus.

Under the facts and circumstances stated above the Hon'ble Tribunal will be graciously pleased to accept the settlement as fair and proper and will be pleased to pass the Award in terms of the settlement.

For the Workmen

Sd|- Illegible

witnesses :—

Sd|- Illegible

Presiding Officer

Central Govt., Industrial Tribunal (No. 2)Dhanbad

For the Employer

S. K. SINGH,

P. M. Loda Area.

DECLARATION

I, Rabilochan Chatterjee, do hereby declare and state that the contents of the terms of settlement were explained to me and I fully agree with the terms of settlement.

Rabi Lochan Chatterjee

का. आ. 4559.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार व नार्थ टिसरा कोलियरी लोडना क्षेत्र मैसर्ज बी. सी. सी. एल., डाकखाना खास जीनागोरा जिला धनबाद के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 4.9.85 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 4559.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of North Tisra Colliery, Lodna Area of M|s. Bharat Coking Coal Limited, P.O. Khas Jeenagora, Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th September, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer.

Reference No. 55 of 1984

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I. D. Act., 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of North Tisra Colliery, Lodna Area of M|s. B. C. C. Ltd. and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers : Shri S. K. Singh, Personnel Manager, Lodna Area.

On behalf of the workmen : Shri H. N. Singh, General Secretary, Koyala Ispat Mazdoor Panchayat, Jharia.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 29th August, 1985

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour and Rehabiliation in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-24012(9)|84-D.IV(B) dated the 24th August, 1984.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of North Tisra Colliery, Lodna Area of M|s. BCCL, PO Khas Jeenagora, Distt. Dhanbad in terminating the lien of Shri Santu Gope on his post and keeping him on Badli list is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

Soon after the receipt of the order of reference notices were duly served upon the parties, parties appeared and filed their respective W. S. documents etc. Thereafter a few adjournments were granted to the parties for filling settlement. Ultimately on 30-7-85 both the parties appeared and filed before me a memorandum of settlement. I have gone through the terms of settlement which appears to be fair and proper and beneficial to both the parties. Accordingly I accept the same and pass an Award in terms of the memorandum of settlement which forms part of the Award as Annexure.

I. N. SINHA, Presiding Officer
[No. L-24012(9)|84-D.IV(B)]

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, AT DHANBAD

Reference No. 55|84

Employers in relation to the management of North Tisra Colliery

And

Their workmen.

PETITION OF COMPROMISE

The humble petition on behalf of the parties to the above reference most respectfully shewth :—

1. That the parties above-named have amicably settled the dispute on the following terms :—

TERMS OF SETTLEMENT

(a) That the concerned workman Sri Santu Gope will be treated as permanent workman and his status as "Badli" workman will be changed.

(b) That the continuity of service of the concerned workman will be maintained and the intervening period from the date of unauthorised absence till the date of his resumption of his duty will be treated as leave without wages.

(c) That the concerned workman will not claim for any other benefit.

Under the facts and circumstances stated above the Hon'ble Tribunal will be graciously pleased to accept the settlement as fair and proper and will be pleased to pass the Award in terms of the settlement.

For the Workmen
Sd./- Illegible
Witness :
Sd./- Illegible

For the Employers
Sd./- Illegible

Sd./- Illegible
S. K. SINGH,
P.M.
Lodna Area.

DECLARATION

I, Sri Santu Gope, do hereby declare and state that the contents of the terms of settlement were explained to me and I fully agree with the terms of settlement.

Signature L.T.I. of
Santu Gope

का. आ. 4560 .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार व लापण्गा कोलियरी मैसर्ज सैण्ट्रल कोलफील्ड्स लि., डाक. लापण्गा, जिला हज़ारीबाग, के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-9-85 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 4560.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Lapanga Colliery of M|s. Central Coalfields Limited, P. O. Lapanga, Hazaribagh, and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th September, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 35 of 1985

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Lapanga Colliery of Central Coalfields Ltd. and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers : Shri R. S. Murthy, Advocate.

On behalf of the workmen : Shri R. Tewari, Organising Secretary, Colliery Karamchari Sangh.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 29th August, 1985

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-24012(76)|84-D.IV(B) dated the 10th April, 1985.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Lapanga Colliery of M|s. Central Coalfields Ltd., P. O. Lapanga Distt. Hazaribagh in denying grade II to Shri Kharati Lal as Magazine Incharge, is legal and justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

In this reference both the parties did not file their respective W. S. documents etc. Thereafter several adjournments were granted to the parties. Ultimately on the next date i.e. on 5-7-85 both the parties appeared and filed a memorandum of settlement before me. I have gone through the terms of settlement which appears to be fair and proper and beneficial to both the parties. Accordingly I accept the same and pass an Award in terms of the settlement which forms part of the Award as Annexure.

I. N. SINHA, Presiding Officer
[No. L-24012(76)|84-D.IV(B)]

R. K. GUPTA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, DHANBAD

In the matter of :

Reference No. 35 of 1985

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Lapanga Colliery of Central Coalfields Limited, Po : Lapanga Distt. Hazaribagh.

AND

Their workman.

JOINT PETITION OF EMPLOYERS AND WORKMEN FOR COMPROMISE.

1. The above mentioned employers as well as workmen most respectfully beg to submit this joint petition of compromise as follows :

2. That the employers as well as the workmen have jointly discussed and negotiated the matter covered by the aforesaid reference with a view to arriving at a mutual and amicable overall settlement.

3. That as a result of the aforesaid discussions and negotiations, the parties have agreed to settle the matter on the following terms and conditions :—

(a) It is agreed that the Management shall place Shri Kharati Lal, the workman concerned as Magazine Clerk in Clerk Gr. II w.e.f. 1-1-1983.

(b) That it is agreed that the workman concerned shall be paid arrears of wages between the post of Clark G. III and Clerk Gr. II as a result of Clause (a) above.

(c) That it is agreed that this is in full and final settlement of all the claims of the workman concerned arising out of the above reference.

4. That the parties consider that the above settlement is fair, just and reasonable to both the parties.

It is, therefore jointly prayed by both the parties that the Hon'ble Tribunal may be pleased to give an award and dispose of the above reference in terms of the joint compromise petition.

Organising Secy,
Colliery Karamchari Sangh,
Kuranpura Area.
for and on behalf of the
workman.
Dated :—4-7-1985
Place : Bankakana

Project Officer/Agent.
Lapanga Colliery.
Central Coalfields Limited.
for & on behalf of the Employer.

Signed this day i.e. 4th day of July, 1985.

Witnesses :

1. Shri Kharatilal, Workman concerned.

Rai S. Murthy
Advocate for Employee
Sd/-

Presiding Officer, Central Govt. Industrial Tribunal No. 2
Dhanbad.

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1985

का. आ. 4561.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26.8.85 प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 11th September, 1985

S.O. 4561.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Reserve Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 26th August, 1985.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 225/83

In the matter of dispute between :

Gurcharan Singh & 39 others

Versus

Reserve Bank of India, New Delhi.

APPEARANCES :

Smt. K. S. Shere Joint Legal Adviser and Shri P. S. Bindra—for the Management.

Shri K. T. Ahantharaman—for the workmen.

AWARD

Central Government, Ministry of Labour on 22nd August, 1983 vide Order No. L-12011/76-82D.II(A) made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the demand of Shri Gurcharan Singh and 39 other workmen (as per Annexure) employed as Tikka Mazdoors by the Reserve Bank of India, New Delhi for their absorption in the existing regular temporary vacancies by the management of the Bank is justified ? If so, to what relief are the workmen concerned entitled and from what date ?".

ANNEXURE

Sr. No. Name of the workmen

1. Shri Gurcharan Singh
2. Shri Rajendar Kumar
3. Shri Suraj Pal
4. ShriJaswant Singh
5. Shri Girish Kumar
6. Shri Lal Chand
7. Shri Raj Kumar
8. Shri Shiv Mohan Lal
9. Shri Jitender Kumar
10. Shri Deep Chand
11. Shri Kishan Lal I
12. Shri Joginder Sharma
13. Shri Sukhdev
14. Shri Bijender Kumar
15. Shri Baljit Singh
16. Shri Moris David
17. Shri Bhav Nidhi Sharma
18. Shri Raju
19. Shri Mohinder Singh
20. Shri Hari Dutt
21. Shri Hira Lal
22. Shri Tilak Raj
23. Shri Om Prakash I
24. Shri Sukh Pal Singh
25. Shri Kashmir Singh
26. Shri Dharam Vir Singh
27. Shri Jugal Kishore
28. Shri Karan Singh
29. Shri Hari Bhagwan
30. Shri Shyam Bir
31. Shri Mohan Chand
32. Shri Fakir Chand
33. Shri Om Prakash II
34. Shri Ranbir Singh
35. Shri Suresh Kumar
36. Shri Bal Kishan
37. Shri Davinder Kumar
38. Shri Brij Lal
39. Shri Kishan Lal II
40. Shri Ishwar Singh"

2. The 40 workmen Gurcharan Singh and others filed statement of claim asserting that they had been working in the Delhi Office of the Reserve Bank of India in posts carry-

ing designation of Peon, Daftri, Khidmadkar, Cash Mazdoor, Darwan, Security Guard and Pump Operator, etc. which posts generally have a pay-scale of Rs. 295-550 and that to cater to the situation arising out of unfilled posts of those categories as also to leave and other vacancies in the bank, the Management edicted the practice of employing them on daily wages post calling them Ticca Mazdoors at Rs. 14 per day on leave days and Rs. 8 on Saturdays with no payment on Holidays.

3. The workmen claimed that they were empanelled as Ticca Mazdoor by the Bank since October, 1977 and have been continuously performing the duties of one or more posts referred to above depending upon specific job assigned to them by the Bank Authorities day to day and there was absolutely no difference in the duties performed by regular employees having the same designation. Dharam Vir Singh is said to have been already absorbed against regular vacancy in the Bank and Mohinder Singh and Hari Bhagwan were said to have died after the reference made and the details of work of other employees were given in the annexure to the claim.

4. The workmen concerned assert that they had been rendering faithful and satisfactory services continuously to the bank for the past 6 years and their continuation on daily wage basis was unfair labour practices on the part of the Bank and was gross exploitation of the workmen. They claimed that they should be treated as regular employees forthwith and appointed against regular vacancies existing|arising in the posts mentioned by them and that on regularisation they should be given benefit available to regular employees from the date of their original appointment as Ticca Mazdoors. The further relief claimed is that the Reserve Bank of India may be restrained from either resorting to direct recruitment from the open market or re-designation of the regular employees till such time all the workmen concerned were appointed against regular vacancies.

5. The Management of Reserve Bank of India contested the claim. Preliminary objections were raised including the one that the dispute in question was not 'Industrial Dispute' and that it had not been espoused by any Group or class of Class IV employees of the Bank at New Delhi and that individual dispute not so espoused by a Trade Union or Substantial number of workmen could not be treated as an 'Industrial Dispute'.

6. On facts it was pleaded that the sevrices of these workmen were utilised as Ticca Mazdoors and they were not regular employees of the Bank and they were purely casual labour to whom employment is offered for a particular day if there is work on that day even though they came daily to find out if work was available. A ratio of one Mazdoor to 4 Coin|Note Examiners is maintained in a section of Cash Department and the number of Mazdoors required on a particular day depend upon the number of Coin|Note Examiners engaged in the Note Examination Sections on that day. The bank employed regular Mazdoors who are full-time employees including adequate number of leave reserves. However, it is quite possible that on a particular day there may not be adequate number of Mazdoors to assist the Coin|Note Examiners in which event it becomes necessary to engage the services of casual labour-Ticca Mazdoors who were employed. Ticca Mazdoors on any particular day, if willing, were also sent whenever there was vacancy in other department and they were willing to do the job.

7. In the statement filed by the Management it was said that 12 Ticca Mazdoors had already been absorbed in regular employment and that it was the policy of the Bank to absorb them as soon as necessary formalities completed and posts were available and their lists were maintained on seniority basis. The remaining Ticca Mazoors would be considered for regular absorption in the Bank Services as ad when the regular vacancies of Mazdoors etc. were in the Bank.

8. The following issues were framed :

(i) Whether the present is Industrial Dispute ?

(ii) As in terms of reference.

9. The workmen filed affidavit of Ishwar Singh and Gurcharan Singh and they have been cross-examined. Mr. N. K. Gauri Personnel Officer filed his affidavit for the Management and he has been cross-examined by the workmen.

10. I have heard the representatives of the workmen and the Management.

11. The Ticca Mazdoors were absorbed in the regular strength of the Bank services are the following 26 persons with date of appointment/regularisation given against each.

S. No.	Sr. No. of the list	Name	
1.	1	S/Sh. Gurcharan Singh	Since appointed as Mazdoor 3-7-84
2.	2	Rajinder Kumar II	Since appointed as Mazdoor 3-7-84
3.	3	Suraj Pal	Since appointed as Peon 22-2-84
4.	4	Jaswant Singh I	Since appointed as Peon 22-2-83
5.	5	Girish Kumar	Since appointed as Peon 4-7-84
6.	6	Lal Chand	Since appointed as Peon 4-7-84
7.	7	Raj Kumar	Since appointed as Peon 22-2-84
8.	8	Shiv Mohan Lal	Since appointed as Peon 22-2-84
9.	9	Jitender Kumar Sharma	Since appointed as Mazdoor 3-7-84
10.	10	Deep Chand Sharma	Since appointed as Peon 22-2-84
11.	11	Krishan Lal I	Since appointed as Mazdoor 3-7-84
12.	12	Joginder Sharma	Since appointed as Peon 3-7-84
13.	14	Bijender Kumar	Since appointed as Mazdoor 3-7-84
14.	15	Balbir Singh	Since appointed as Peon 22-2-84
15.	16	Morris David	Since appointed as Mazdoor 3-7-84
16.	17	Bhav Nidhi	Since appointed as P/T Mazdoor 9-7-84
17.	18	Raju	Since appointed as Mazdoor 3-7-84
18.	20	Hari Dutt	Since appointed as Mazdoor 3-7-84
19.	22	Tilak Raj	Since appointed as Mazdoor 3-7-84
20.	23	Om Parkash	Since appointed as Mazdoor 3-7-84
21.	24	Sukhpal Singh	Since appointed as Mazdoor 3-7-84
22.	25	Kashmir Singh	Since appointed as P/T Mazdoor 9-7-84
23.	26	Dharamvir Singh	Since appointed as Peon 2-6-84
24.	32	Faqir Chand	Since appointed as Mazdoor 3-7-84
25.	33	Om Parkash II	Since appointed as Mazdoor 9-7-84
26.	40	Ishwar Singh	Since appointed as Mazdoor 3-7-84"

12. Mr. Anantharaman urged that the only requirement for raising an Industrial Dispute is that a particular class of workmen should sponsor that dispute and in regard to the

condition of service the workmen affected themselves had to raise the dispute and there was no requirement that a very large number of workmen should do so. These workmen approached the class IV Union in the Reserve Bank but that Union refused to take up their case and then they presented a Joint Memorandum to the Management and they formed category apart and have raised this dispute. In 1985 the Labour jurisprudence was said to have advanced so much that these workmen could not be allowed to work continuously for years without getting benefits available to regular employees doing the same work and if the class IV Union of the Reserve Bank at New Delhi failed to take up their case, it could not be said that the case could not be espoused by these 40 persons collectively as a class.

13. On merits, the argument of the Ld. Advocate for the workmen was that it was wholly unfair for the Management to force these persons to work on daily basis in different capacities in the bank and to depend on this labour force for completion of regular work and deny them wages and benefits available to regular employees. These persons did not demand creation of vacancies but only wanted to be regularised against temporary existing vacancies and not being denied vacancies by those being vacancies given to those who did not have the work experience of these persons behind them.

14. I am afraid the workmen must loose on the preliminary issue. A dispute must be espoused either by a Union of workmen or a substantial body of workmen. If the class IV Union of the Reserve Bank refuses to take up their case it means to be satisfied with the procedure adopted by the bank for their regularisation and it does not want the Management to give up the present practice of the bank having waiting lists for each category of employees and making selection from those waiting list. Further, the Management gives reservation to Scheduled Caste and Scheduled Tribes employees in making the appointments in different categories of employments to fulfil constitutional obligations is that respect.

15. There is an Award of the Central Government Industrial Tribunal Calcutta in reference No. 14/77 where Tapan Bhattacharjee, Subrata Roy and 73 others Ticca Mazdoors had raised a dispute and had claimed permanent absorption in regular service of the Reserve Bank Calcutta and by his Award dated 3-12-79 Shri S. K. Mukherjee Presiding Officer of that Tribunal Calcutta refused to accept the dispute as properly espoused when no Union took it up nor any Substantial body of workmen espoused the dispute and only those 75 workmen themselves took up their case to the Industrial Tribunal. Paras 9 and 10 of that Award explain how the Reserve Bank of India took up the matter with recognised class IV employees' Union and the Union thereafter did not press the matter :

9. It has further been stated by the Bank as follows :

"It will not therefore be correct to state that their services have been engaged on "no work no pay basis. Their services are engaged as casual labour as and when a need arises for their services. The Ticca Mazdoors are paid at the rate of Rs. 7 per diem on week days and Rs. 4 on Saturdays. If they work continuously for 5 working days or more they are paid on a pro rata basis in relation to the wages drawn by regular employees in the cader at the minimum of the scale. These scales were fixed by the Bank after taking into consideration representation by the All India Reserve Bank Workers' Federation the recognised All India Union of Class IV employees of the Bank."

A person who is included in the list of Ticca Mazdoor has no right to be appointed against a permanent vacancy in the Bank. A specimen of a written advice issued to these who were empanelled is enclosed (Annexure IV) which shows that mere inclusion of their name in the waiting list does not entitle them to any appointment in the Bank. The ticca mazdoors are in the nature of casual workers and are not employees of the Bank.

The issue relating to absorption of Ticca Mazdoors in question was initially taken up by the Reserve Bank Worker's Union, Calcutta which is a recognised Union to represent Class IV staff of the Bank. The decision of the Bank was communiacted to the said Union in the background of certain Central Government Regulations to meet requirements in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribes candidates in prescribed percentages vis-a-vis claims of Ticca Mazdoors and the issue was discussed and finalised (Annexure V and VII) and in pursuance there to 28 Ticca Mazdoors out of total 87 have already been absorbed in regular service of the Bank. As the dispute is settled, it cannot be questioned by a small faction having no representative character to take up the dispute.

10. The concerned workmen are class IV employees of the Bank. It is contended on behalf of the Management that the dispute is not an industrial dispute as it has neither been espoused by a substantial number of class IV employees of the Bank nor by a trade Union or Association having a representative charatcer. The dispute has been sponsored by the Reserve Bank of India Staff Association, an unrecognised and unrepresentative Association. The Bank has two recognised unions, one for Class III employees and the other for Class IV employees. Those are recognised unions. The Reserve Bank of India Staff Association, Calcutta, having its office at 1/1K, Rani Harsamukhi Road has sponsored the dispute. It is claimed that the said union is composed of Class III and Class IV employees and the strength of its membership is 155. It appears from the rejoinder of the union that there are 3,313 persons working in Calcutta offices including Class III and Class IV staff. The union is, therefore, not a representaive body of Class IV employees. It is also contended on behalf of the management that the concerned workmen are not members of the Reserve Bank of India Staff Association, Calcutta which itself is a splinter union. It is then contended that there is no evidence that the concerned workmen made any request to the union to espouse their cause. A dispute becomes an industrial dispute only if it is taken up by a union of which the concerned workmen is a member and the union has a representative character. Then it is urged that there is no resolution of General Body of the sponsoring union to espouse the cause of the concerned workmen".

16. There is a great risk in allowing small number of persons calling themselves a category apart raising an Industrial Dispute because the matter raised by them can have repercussions on other employees and intending candidates for employment. It is for this reason that the industrial jurisprudence has always insisted on an Industrial Dispute being espoused by a Trade Union or a Substantial body of workmen apart from disputes which become eligible under section 2(A) of the I. D. Act.

17. I am of the clear opinion that the present dispute raised by 40 affected Ticca Mazdors is not an Industrial Dispute espoused by a Substantial boy of workmen when there are 600 to 700 class IV employees of Reserve Bank of India, New Delhi, and the Class IV employees' Union at New Delhi has refused to espouse their dispute. The dispute does not qualify as an 'Industrial Dispute' and cannot be adjudicated upon.

18. The demands made by the 40 ticca mazdoors in this reference are opposed to the interest of Farashes. Weighting-listed Khidmatkars and other categories of class IV employees. This is the reason why class IV Reserve Bank Employees' Union or substantial body of class IV workmen do not espouse this dispute for adjudication. The demands raised disturb industrial peace, by endangaring others' employment-opportunities and are not directed merely at the Management and its purac. The Management has evolved policy of gradual absorption of these ticca mazdoors in regular employment, first by abolishing rotation-system and then by absorbing already the majority of the ticca mazdoors who raised the dispute. The policy has met with class IV employees' Union approval, and they and the substantial body of class IV employees refuse to espouse this dispute, the dispute does not qualify as 'Industrial Dispute' for want of espousal by 'workmen'. I refuse to adjudicate on this dispute and cannot give any relief to the claimants. Award is made accordingly.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

Dated : August 13, 1985.

O. P. SINGLA, Presiding Officer
[No. L-12011/76/82-D.II (A)]

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1985.

का. आ. 4562.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकारी, यूनाईटिड बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली का पंचाट को प्रकाशित करता है, जो केन्द्रीय सरकार को 26.8.85 प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 11th September, 1985

S.O. 4562.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the United Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 26th August, '85.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NEW DELHI.

I. D. 96|81

In the matter of dispute between : K. C. Sharma represented by the United Bank of India Sramik Karamcharai Samity.

Versus

United Bank of India, New Delhi.

APPEARANCES :

Shri B. Chattopadhyay for the workman.

Miss Geeta Sharma Advocate for Management.

AWARD

Central Government, Ministry of Labour on 21-7-81 vide Order No. L-12012|139|80-D.II. A made reference of the following dspute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Management of United Bank of India in not considering Shri K. C. Sharma as senior Peon and in consequence not putting him to work as cycle peon which now attracted the cycle allowance of Rs. 20|- p.m. is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. Mr. K. C. Sharma, Sub-staff at Connaught Circus Branch was appointed probationer by the United Bank of India vide letter of appointment No. PD|Con|PBZ|3433 dated 29-9-72. He was confirmed vide letter No. PD|NB|Con|132. He was allowed benefit of Staff Provident Fund and allotted No. SPF|10800. His case is that on account of Union Rivalry and the Management favouring the other Union Mr. K. C. Sharma was denied the work as Cycle Peon which attracted cycle allowance of Rs. 20|- PM on account of his seniority and his junior was allowed to work as cycle peon with cycle allowance of Rs. 20|- PM. The Union requested this Tribunal that the action of the Management was antilabour and that an Award be made directing the Management for considering K. C. Sharma as senior Peon entitled to work as cycle peon with allowance of Rs. 20|- PM to him since the date the same was given to his junior Mr. B. K. Ghosh.

3. The Management contested the claim and asserted that both Mr. Sharma and B. K. Ghosh were appointed on the same date and the name of B. K. Ghosh appeared earlier in the merit list but by mistake on the part of despatch clerk the appointment letter and confirmation letter were issued to Mr. K. C. Sharma before Mr. B. K. Ghosh and that actually B. K. Ghosh was senior and any inter-union rivalry alleged was irrelevant. The Management communicated that decision about legitimate claim of Mr. Ghosh to seniority and cycle allowance.

4. The matter has been tried. The Management filed the affidavit of Shri R. K. Roy, Personnel Officer United Bank of India and the workman cross-examined him. The workman K. C. Sharma filed his own affidavit and the Management asked a few questions from him in cross-examination. Written arguments have been filed by the workman and Management reply by Miss Geeta Sharma has been by oral submissions. The Management has shown that Mr. B. K. Ghosh joined temporarily earlier on 1-5-71 and that K. C. Sharma joined temporarily in June, 1971. These facts are not disputed. The only question is whether the confirmation and seniority given earlier to K. C. Sharma could be set at naught or whether substantial justce have been done by the Management to B. K. Ghosh and this Tribunal should not interfere.

5. This Industrial Tribunal does not deal with matters technically or legally alone and substantial justice is the purpose and rationale of decisions of this Industrial Tribunal to maintain industrial peace and harmony. B. K. Ghosh has enjoyed cycle allowance and unless what has been done is unfair it need not be disturbed.

6. In view of the fact that Mr. B. K. Ghosh and K. C. Sharma were appointed on the same day and in temporary service B. K. Ghosh joined earlier on 1-5-71 while the workman K. C. Sharma joined later in June, 71. I am of the clear opinion that the Management in this case was not actuated by any unfair or malafide motives in granting cycle allowance and Cycle Peon Post to B. K. Ghosh and K. C. Sharma's complaint in without substance. No inter-union rivalrykas at the back of the decision taken by the Management and the Management of United Bank of India tried to be fair to B. K. Ghosh and not that it noted unfairly to K. C. Sharma. The action of the Management of United Bank of India in granting cycle allowance of Rs. 20|- to Mr. Ghosh and not considering K. C. Sharma for that cycle allowance is not unjustified and K. C. Sharma is not entitled to any relief.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

August 13, 1985

O. P. SINGLA, Presiding Officer
[No. L-12012|139|80-D.II(A)]

का. आ. 4563—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकारी, बैंक आफ महाराष्ट्र के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26.8.85 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 4563.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Bank of Maharashtra and their workmen, which was received by the Central Government on the 26th August, 1985.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA. PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL. NEW DELHI

I.D. No. 34/84

In the matter of dispute :

BETWEEN

Shri Krishan Kanhaiya represented by Union of the Maharashtra Bank Employees, 898, Nai Sarak. Chandni Chowk, Delhi-6.

Versus

Bank of Maharashtra through the Asstt. General Manager, North Zone-I, 6/30-31, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi.

APPEARANCES :

Shri Ramesh Kadam—for the workman.

Shri S. S. Rana, Advocate—for the Management.

AWARD

Central Government, Ministry of Labour on 30-3-84 vide Order No. L-12012/280/83-D.II(A) made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the maangement of Bank of Maharashtra in terminating the services of Shri Krishan Kanhaiya is justified? If not to what relief the workman is entitled?"

2. Mr. Krishan Kanhaiya was appointed Peon in Chandni Chowk Branch, Bank of Maharashtra and then was transferred to Branch Office Meerut (U.P.). Later he was posted as Daftry on account of his seniority. Krishan Kanhaiya claims that he was elected as Joint Secretary in December, 1979 in the U.P. Bank Workers Organisation in Annual general body meeting held on 5th December, 1979 and that his trade union activities were not liked by the Management and the Management at the instance of other Union affiliated to AIBEA started harassing him with the sole motive of victimisation.

3. Mr. Krishan Kanhaiya Peon appeared for promotion as a clerk but his result was with-held by the Management and he was suspended on 14-8-81. On 28-9-81 the Management served him charge-sheet containing the allegations:

(a) On 3rd March 81 he refused to clean the table/chair of the Branch ;

(b) On 14th June, 1981 he refused to sit late for overtime;

(c) He refused to wear uniform on different dates;

(d) Without prior information he remained absent on 11-7-79, 27-7-79, 16-8-79, 6-9-79, 28-9-79 in 1979 15-7-81 to 25-7-81 in 1981.

4. The Union of Maharashtra Bank Employees in its statement of claim asserts that the allegations were levelled simply for victimisation of the employee and there was no satisfactory evidence of the Maangement to prove the charges and that during the pendency of the enquiry the Management abruptly terminated his services. The enquiry was started on 3-4-82 but on 17-1-83 Krishan Kanhaiya's services were terminated vide No. AXI/ST/477/83 in terms of paragraph 522(1) of Sastry Award offering three months' emoluments in lieu of notice and indicating that he shall be paid retrenchment compensation under the Law.

5. The workman's Union pleaded that the payment of dues was not made to him in time and that the Management played with the career of the employee in utter violation of principles of natural justice and provisions of Section 25-F of the I.D. Act and that the action taken by the Management was unfair and improper and an act of victimisation to ruin his career.

6. It was only before the Asstt. Labour Commissioner (Central) that the Management pleaded that the workman had committed forgery and had written complaints against the Bank Manager to the Management in the name of customers. But the documents in that respect were not produced in onciliation and the Assistant Labour Commissioner (Central) in his failure report the Ministry of Labour mentioned that no details regarding act of forgery or criminal act for misconduct on his part were given and he was not satisfied and recommended the making of this reference to this Tribunal.

7. The workman requested that Krishan Kanhaiya be reinstated w.e.f. the date of his termination of service with full back-wages and continuity of service and that he be treated as a clerk from the date of declaration of result of other employees which was with-held arbitrarily in his case and his salary be got refixed in the new scale and be paid arrears and that he should be extended all benefits to which he is entitled as per the Bipartite Settlement as modified upto date alongwith suitable costs.

8. The Maangement of the Bank of Maharashtra contested the claim and asserted that the Management bona fide thought that the employee is cantankerous and it was not desirable to retain him in service and the Management bona fide terminated his services in accordance with the regulation which permitted such termination and it was not necessary to dismiss him by way of punishment. The action of the Management was said to be bona fide under para 522 of Sastry Award.

9. The Management of the said bank was said to be interested in proper Management and the Union activities of the workman were not at all relevant and the bank action had no concern to Union activities. He was suspended on 14-8-81 on information that he had indulged in very grave acts of misconduct. A charge sheet was issued to him on 28-9-81 and the charges were very grave and it was undesirable to allow him to work.

10. The misconduct alleged against him was of such a serious nature that no reasonable employer could tolerate the misconduct alleged against him. Shri R. S. Chinchalkar was appointed as Enquiry Officer and then Divisional Manager, Delhi and North was appointed Enquiry Officer. The Management had the power and could not be prohibited from terminating his service before completion of enquiry when Management received letters purporting to have been sent by various customers of the branch in which serious complaints were made against the Branch Manager, Meerut Branch where the concerned workman was working. The Management made bona fide enquiry and it was revealed that the complaints were false and frivolous and the concerned workman was instrumental in making these complaints in a systematic manner with some ulterior motive. With a view to probe the matter further, these letters were handed over to two different hand-writting experts and they gave information that the complaint letters received in the branch were written by the concerned workman. It was in this situation that the Management thought it proper to terminate the services of the workman on 17-1-81 in terms of para 522 (1) of the Sastry Award The retrenchment compensation and notice-pay were given to him. He had also been paid the gratuity and P.F. dues and the Management action being bona fide and in accordance with law could not be interfered with.

11. The matter referred to the Tribunal has been tried. The Management filed the affidavit of S. Neelakanthan Staff Officer, of the Management Bank at Karol Bagh who has been cross-examined by the workman and the workman filed his own affidavit and was subjected to cross-examination by the Management.

12. After the evidence of the Management had been closed on 1-4-85 the Management made an application to examine Shri V.K. Sakhuja. Hand-Writting Expert to prove that certain complaints allegedly by customers were in fact scribed by Krishan Kanhaiya himself and that was the cause why his services were terminated by the Bank and that it was a case of loss of confidence in the workman.

13. By my order dated June 5, 1985 I held that the Management could not lead evidence to establish workman's misconduct before this Tribunal when the termination of service was not on basis of proved misconduct but only on the ground of loss of confidence. In the last para 7 of my order I observed as under:—

"7. The question in this case is of termination of service simplicitor by the Management, and not by way of disciplinary action, and, therefore, the Management cannot justify its action before the Tribunal by saying that this was done by way of disciplinary action and not by way of discharge simplicitor. The Management made its judgement whether to discharge the workman or to take disciplinary action against him initially, when it

issued order of discharge and did not proceed with the enquiry, and did not make subsequent charges against the workman for disciplinary action and disciplinary enquiry thereon. I disagree with the Management that the Management can lead evidence before this Tribunal to establish grounds for disciplinary action against the workman for his removal from service, when it is not a case of removal from service for established-charges at all. The termination of service by the Management is by an action simplicitor and that, of course, can be on ground of loss of confidence, but it is not the Management's case that it is a case of proved mis-conduct and, therefore, the Management is not allowed to prove workman's misconduct by leading evidence. However, the experts report already filed is on record and may be used by the Management to urge that it was a case of loss of confidence. Application of Management disallowed."

14. The writen arguments of the parties are on record and have been perused. Reference may be made to the Supreme Court judgement in 1985 (2) SCC 349 Sant Raj and Another Vs. O.P. Singla and another where Sant Raj and Itwari Lal had their services terminated by Management of Lufthansa German Airlines on the ground of loss of confidence. There was a plea of the Management that these two loaders at Delhi Air Port working with them were involved in smuggling of goods of evasion of custom duty and these loaders worked in the custom area. The plea of the Management was found to be not without substance and the ground of loss of confidence was upheld but the Presiding Officer, Labour Court held that there was violation of Section 25-F of the I.D. Act, 47 for non-payment of retrenchment compensation.

15. The Hon'ble Supreme Court in its judgement para 6 observed as under:—

"6. Dr. Chitale, Learned counsel who appeared for the respondents attempted to take us through the evidence with a view to persuading us that the employer even if it acted contrary to law, should not be burdened with reinstatement because it had lost confidence in the appellants. The employer is a foreign air-transport company. The workman were loaders posted at Delhi Airport. In this far-fetched hierarchical relationship, loss of confidence if it is to be considered a relevant factor would have hardly impressed us."

16. In this particular case the ground of loss of confidence in Krishan Kanhaiya a daftry fails to inspire any confidence. The charges levelled against him were not such as involved any sensitive banking matter and so far as the charges relating to forgery in making of complaints against the Branch Manager were concerned, they were never conveyed to this workman and his explanation was not taken and the action was taken by the Management only on opinion evidence of two hand-writing experts and opinion of hand writing experts even if it is considered unbiased is weak evidence when it is not subjected to cross-examination.

17. I am clearly of the opinion that the Management action of termination of service of Shri Krishan Kanhaiya on the ground of loss of confidence does not inspire confidence. He was general Secretary of a Union and was due for promotion on account of having cleared the promotion test and his complaint that his union activities were not liked by the Management appears to have substance and in any case in the factual situation aforesaid recourse to termination of service on ground of loss of confidence appears to be an oblique and perverted manner of dealing with him and does not impress as a genuine bonafide conduct of the Management. The termination of service by the Management on the alleged grant of loss of confidence w.e.f. 14-8-81 is held to be unjustified and is quashed and he is reinstated in service with full back wages and continuity of services. Management shall also release his result of promotion to clerical cadre and take necessary action thereafter on his right to promotion.

18. However, the Management will be entitled to take disciplinary action against the workman and that right of the Management is not affected by this Award. The workman shall also get Rs. 500/- as costs from the Management of this reference.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwared to the Central Government for necessary action at their end.

Dated: August 14, 1985.

O.P. SINGLA, Presiding Officer

[No. L-12012/280/83-D. II(A)]

N.K. VERMA, Desk Officer

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985